

ग्रामीण पुस्तकालय विकास और शिक्षा प्रसार

“अज्ञानियों के द्वार तक नि शुल्क ज्ञान को ले जाना, उनको सत्य
पथ पर अग्रसित करना—इस प्रकार के दान के समान कुछ नहीं है। पहा
तक कि सम्पूर्ण विश्व भी दे देना इसकी समता नहीं कर सकता।”

—मनु

ग्रामीण पुस्तकालय विकास और शिक्षा-प्रसार
Rural Library Development & Education Extension

गोपीनाथ कालभोर

रचना प्रकाशन, जयपुर

ग्रामीण पुस्तकालय विकास और शिक्षा प्रसार
गोपीनाथ कालभोर

प्रथम संस्करण 1990

प्रकाशक

विनोद कुमार गुप्ता

रचना प्रकाशन

254 शास्त्री सदन, लू टटो का रास्ता,
विशनपोल बाजार, जयपुर-302001

सर्वाधिकार-लेखकाधीन

मूल्य 125-00

मुद्रक

डॉ एम प्रिंटस, ग्रॉन्डो का रास्ता,
विशनपोल बाजार, जयपुर-302001

अनुक्रमणिका

स्व कथन

1	भारतवर्ष में ग्रन्थालय परम्परा	1
2	भारत में ग्रामीण शिक्षा एवं पुस्तकालय	29
3	ग्रामीण विकास के आधार ग्राम पुस्तकालय	53
4	ग्रामीण पुस्तकालयों से लाभ	56
5	अध्ययन म्थलो की आवश्यकता	61
6	पंचायतों और पुस्तकालय विकास	65
7	प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम में पुस्तकालयों की भूमिका	72
8	कृषकों के लिए पुस्तकालयों का उपयोग	82
9	युवा कृषक मन और पुस्तकालय प्रसार	89
10	पुस्तकालय प्रसार की आवश्यकता	95
11	ग्रामीण पुस्तकालय भवन व फर्नीचर	104
12	पुस्तकालय प्रसार सेवा में पुस्तकालयाध्यक्ष का योगदान	109
13	मध्य प्रदेश में पुस्तकालय व्यवसाय सीमाये एवं सम्भावनाएँ	126
14	विद्यार्थी और पुस्तकालय उपयोग	135
15	पठन-रचि पुस्तक भंडे एवं पुस्तकालय	143
16	वैचारिक क्रान्ति बनाम बुक माइण्डनेस	148
17	दूषित होता पुस्तकीय पर्यावरण	152
18	राष्ट्रीय विकास के लिए ग्रन्थालय	157
19	पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकें और उनका चयन	167
20	अध्ययन और स्वास्थ्य	175
21	मध्य प्रदेश में लोक ग्रन्थालयों का संचालन व संगठन	180
22	अश्लील साहित्य का फैलाता जहर	185
23	पुस्तकालय विज्ञान के जनक डा० रंगनाथन	188
24	पंचवर्षीय योजनाओं में प्रौढ शिक्षा एवं पुस्तकालय	192
25	वर्तमान भारत में ग्रामीण पुस्तकालयों का भविष्य	204

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट 2

परिशिष्ट 3

स्व-कथन

अपनी बात कहने से पूर्व मैं उन लोगों से यह बात स्पष्ट कर देना अधिक प्राथमिकता का विषय है जो पुस्तकालय विज्ञान के अध्ययन, अध्यापन, आन्दोलन तथा विकास का बीड़ा उठाये देश की प्रगतिशील राष्ट्रों की दौड़ में ऊँचा उठा देना चाहते हैं फिर भी ग्रामीण भारत की जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो पाँच राज्य ग्रन्थालय विधान पारित करवा कर साप्ताहिक पुस्तकालय प्रणाली से अपने प्रदेश की शहर, नगर, खण्ड एवं ग्रामीण जनता को ज्ञान का आस्वादन करवा रहे हैं वे निश्चित ही धर्मवाद के पात्र हैं, किन्तु शेष भारत की बात करें तो सवत्र उदासीनता, उपेक्षा एवं हीनभावना का दृष्टिकोण ग्रन्थालय विकास के प्रति दिखाई पड़ता है।

ज्ञान, विज्ञान एवं शोध के क्षेत्र में निरन्तर विस्फोटक स्थितियों का अनुभव लेते हम गुजर रहे हैं। वृत्ति काय से सगाकर गृह-सत्तार के काय तक में विज्ञान के आविष्कारों से वेहद प्रभावित हैं किन्तु विचारों की तरह में गहरे तक हम ज्ञान की चाह लेने, साक्षरता का अप्रक्षित परिणाम देखने गाँव में निरक्षर हैं तो हमें आज भी वहाँ का किसान निरक्षर व शिक्षा प्राप्ति के प्रति निराश दिखता है। आज भी वे गाँव जहाँ स्वतंत्रता के बाद ग्राम-पंचायतों में प्रौढ शिक्षा व ग्राम-बाचनालय सक्रिय दिखाई पड़ते थे अब सुनसान दिखते हैं।

परिवर्तन के नाम पर बहुत कुछ बदला है गाँवों में, किन्तु अध्ययन के नाम पर खोले गये ग्रन्थालयों की स्वप्निल दुनिया गाँवों से अपना दामन छुड़ाकर न जाने किस दिशा में भटक गई है। यदि लोगों को अभी तक ग्रन्थालयों की उपयोगिता, उनके उद्देश्य एवं उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब है कि पुस्तकालय विकास में लग उत्तरदायित्वपूर्ण विभागों, संस्थाओं एवं व्यवसायियों के उत्थान में कुछ कमी रह गई लगती है। एक ओर लोगों में जागरूकता की कमी को हम दोषी मानें तो दूसरी ओर ग्रन्थालयों के संगठन व प्रशासन की निष्क्रियता को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।

पुस्तकालयों की प्राचीन काल से ही अति-महत्वपूर्ण सामुदायिक केन्द्र के रूप में बौद्धिक-उत्पादकता एवं ज्ञान प्राप्ति का साधन माना जाता रहा है। इसके प्रमाण रहे हैं मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक शिक्षा-केन्द्र (नालंदा, तक्षशिला के पुस्तकालय)

कालय) जिनके साहचर्य से दश विदेश के शिक्षार्थी पाण्डित्य और ज्ञान के क्षेत्र में ससार प्रतिष्ठ हुए ।

सम्यक्ता, सस्कृति, साहित्य, कला एवं आध्यात्मिक ज्ञान में क्याति नाम भारत अपनी विविधताओं में झूटा रहा है । अनेक सम्प्रदायों एवं सम्प्रदायों के संरक्षक राष्ट्र ने सदय ही शान्ति, अहिंसा एवं सद्भाव के वातावरण में अपनी वैभवशाली परम्परा को बनाये रखने का प्रयत्न किया और करता आया है ।

इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर आर्य-जनता का निरक्षरता के अभिशाप से मुक्त कराने का सब प्रथम प्रयास बड़ोदा नरेश ने अपने 'राज्य' में सावजनिक-पुस्तकालयों का जाल बिछाकर किया था । दूसरा प्रयास भारत में ग्रन्थालय विज्ञान के पुरोधा डॉ॰ एस॰ आर॰ रंगनाथन ने राज्य में ग्रन्थालय विज्ञान पारित करने का प्रयत्न किया । जीवन के अन्तिम समय तक वे सावजनिक ग्रन्थालयों के विकास पर जोर दे रहे, किन्तु उन्हें अत्यल्प सफलता ही मिली । ग्रन्थालय विज्ञान शिक्षा के विकास में उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त हुई, किन्तु ग्राम-ग्रन्थालयों का उनका सपना ग्रन्थालय अधिनियमों के सम्पूर्ण देश में लागू न हो सकने के कारण पूर्ण नहीं हो सका ।

इस बात की कमी हम आज भी महसूस कर रहे हैं कि शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं व्यवस्था होने पर भी साक्षरता का प्रतिशत देश में बहुत कम है । लोगों में ग्रन्थालयों के अभाव में पढ़ने की रुचि भी मरती जा रही है । लोक-ग्रन्थालयों की प्रौढ़ शिक्षा में जो भूमिका होनी चाहिए थी वह उसे नहीं मिल सकी । साथ ही जो अभिनय ग्रन्थालयों की प्रौढ़ शिक्षा के अभियान में मिलना चाहिए था वह राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण में नहीं मिल सका । सम्भवतः पुस्तकालय नीति और शिक्षा-नीति में शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है । ग्रन्थालय विकास और प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रमों में भी प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान अधिक केन्द्रित हुआ, अनिश्चित ग्रन्थालयों के और अब भी पकाशित ग्रन्थों की बिक्री न होने, अध्ययन रुचि में कमी हान और सत् साहित्य के प्रचार-प्रसार में ग्रन्थालयों की कमी का महसूस किया जा रहा है ।

इन्हीं कुछ मुद्दों पर ध्यान देते हुए मैंने ग्रामों में ग्रन्थालयों के विकास पर यह ग्रन्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । ग्रन्थ में भारत में ग्रन्थालय परम्परा से लेकर ग्रन्थालयों के भविष्य तक विभिन्न मसलों पर विवरण प्रस्तुत किया है । इस क्षेत्र में शासन एवं जनता की व्यापक अध्ययन की आवश्यकता महसूस कराना ही ग्रन्थ का उद्देश्य है । ग्रन्थालयों तथा वाचनालयों के अभाव में ग्रामीणों की जो दशा और दिशा है उसका वर्णन लगभग पूरी पुस्तक में है । ग्रन्थालय एवं ग्रन्थालय

व्यवसायी इस दिशा में क्या कर सकते हैं, यह भी सचेत स्थान-स्थान पर है। सरकारी नीतियाँ अभी तक क्या रही हैं इनका बर्णन भी कुछ लेखों में किया है।

70% ग्रामीण जनता को शैक्षणिक वातावरण देने तथा ग्रन्थों को उपयुक्त सम्मान तथा ग्रन्थालय विज्ञान में प्रशिक्षित व्यवसायियों को अवसर मिलने की दिशा में यह एक लघुतम प्रयास है।

इस प्रयास में जिन विद्वान लेखकों की कृतियाँ का उपयोग किया गया है उनके प्रति लेखक अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। अनुभव व अध्ययन से उपजी पीड़ा को व्यक्त करने में मेरे जिन मित्रों, प्राध्यापकों एवं परिवार जनों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। लेखों की पाण्डुलिपियाँ टंकित करने में 'मधु-टायपिंग, खण्डवा' एवं 'दलात्स टायपिंग केंद्र' के व्यवस्थापकों ने जो तत्परता व शीघ्र सेवा का परिचय दिया वह प्रशंसनीय रहा। पाण्डुलिपि के अंतिम स्वरूप को तैयार करने में सहघमिणी श्रीमती पुष्पलता कालभोर का विशेष सहयोग विस्मृत नहीं कर सकता। लेखन में समय असमय की पीड़ा को उठाकर भी उनके द्वारा दिए सहयोग से ही यह ग्रन्थ आप तक पहुँचाने में सफल हो सका हूँ।

अंत में ग्रन्थ के प्रकाशक 'रचना प्रकाशन' जयपुर का मैं हृदय से आभार मानता हूँ कि उनके कुशल व्यवस्थापन एवं सुन्दर-मुद्रण के उपरान्त यह ग्रन्थ आप सभी तक पहुँच पाया।

प्रस्तुत ग्रन्थ में जो भी कमियाँ रह गयीं हो तो पाठकों से अपेक्षा है, वे अपने बहुमूल्य सुझाव देकर ग्रन्थ की कमी का पूरा करने में सहयोग कर उपकृत करेंगे। ग्रन्थ की नुटियाँ के लिए ग्रन्थकार स्वयं उत्तरदायी है।

'गोपीनाथ कालभोर'

भारतवर्ष में ग्रन्थालय परम्परा

प्रस्तावना—

पुस्तक+आलय = पुस्तकालय अर्थात् पुस्तक रखने का भवन, या स्थान। यह तो याकरण की दृष्टि से शाब्दिक अर्थ हुआ। इसे ही दूसरे शब्दों में हम, पुस्तक संग्रह करके रखने का स्थान मानते हैं। किंतु मात्र पुस्तक का संग्रह पुस्तकालय की परिधि में नहीं आता। जैसा कि हिंदी विश्वकोश में लिखा है “पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री जैसे—पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएँ, मानचित्र नक्शे, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोनरिकार्ड्स, स्लाइड्स एवं अन्य पठनीय सामग्री संग्रहीत रहती है।”¹

पुस्तकालय शब्द की विस्तृत जानकारी ब्रिटनिका-विश्वकोश में भी परिभाषा से मिलती है। कोश के अनुसार, “मुद्रित या लिखित सामग्री के उस संग्रह को पुस्तकालय कहते हैं जो कि अध्ययन या अनुभवान या सामान्य पठन या दोनों उद्देश्य के लिये व्यवस्थित और संगठित किया गया हो।”²

भारत में पुस्तकालय आन्दोलन के जनक डा० एस० आर० रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय कमचारी, पाठक एवं पुस्तक की त्रिमूर्ति हैं। इनमें से कोई एक, पुस्तकालय के निर्माण में संगठन में सहायक नहीं हो सकता। यदि किसी पुस्तकालय में पाठक एवं कमचारीगण नहीं हैं तो वह केवल पुस्तक का संग्रह है। वह पुस्तकालय तभी है जब कमचारी, पाठक को उसकी पुस्तक खोजने में सहायता करे तथा प्रत्येक पुस्तक अपने पाठक को मंगती रहे। इस प्रकार पुस्तकालय अपने वास्तविक अस्तित्व में तभी आता है जब उक्त त्रिमूर्ति (पाठक, पुस्तक एवं कमचारी) सोद्देश्य एवं दूसरे का सहायता दे।

एक पुस्तकालय का निर्माण सामाजिक संगठन द्वारा प्रत्येक समुदाय के हित में “सामाजिक संस्था” के रूप में किया जाना चाहिये। जैसा कि बालाडिल कहते हैं “पुस्तकालय ही संसार के सच्चे विश्व विद्यालय हैं” अतः हमें समाज शिक्षा के प्रसार प्रचार एवं विकास में पुस्तकालयों की भूमिका को समझना चाहिये।

पुस्तकालयों की भूमिका—

वह जमाना उद गया जब पुस्तकें “सुरक्षाय” थी ‘अध्ययनाय’ नहीं। अब हम स्वतंत्र गणतंत्र के स्वतंत्र नागरिक हैं जिन प्राप्ति के पूर्ण अधिकार हमारे पास हैं अतः सबों के लिये उपलब्ध हो आये ग्रन्थालय सेवा का पूर्ण लाभ लें। पुस्तकालय अपनी भूमिका में निम्नांकित कार्य पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं।

- (अ) शिक्षा विकास (Educational Development)
- (ब) निरक्षरता मिटाने में सहायक (Helpful in illiteracy)
- (स) राष्ट्रीय विकास में पूरक (Supplement in National Development)
- (द) मानव चरित्र का विकास (Development in Human character)
- (इ) ज्ञान का प्रसार एवं प्रचार (Ext & publicity of knowledge)
- (फ) अध्ययन प्रवृत्ति का प्रोत्साहन
- (क) ज्ञान का संरक्षण (Preservation of knowledge)
- (ख) अध्ययन रुचि का निर्माण में सहायक
- (ग) सभ्यता एवं सभ्यता के रक्षक

पुस्तकालय का जन्म—

पृथ्वी पर मानव विकास की नदी घाटी सभ्यता एवं सभ्यता की ऐतिहासिक परम्पराओं के साथ ही पुस्तकालयों के जन्म का इतिहास जुड़ा है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मिश्र असीरिया, मिस्र, ग्रीस, रोम व सिक्किम के इतिहास को उठाकर देखें तो हम मालूम होगा कि विश्व का सबसे प्राचीन पुस्तकालय असीरिया के सम्राट अशूरबनी पाल का था। इसमें रखी हुई पुस्तकें आज की कागज की पुस्तकें जैसी नहीं थीं। ये मिट्टी की चौकोर पट्टियाँ थीं जिन पर कीलक (सोदकर) लिपि में लिखावट की गई थी, जिनकी संख्या लगभग 20,000 थी। इन मिट्टी की पट्टियों को आज भी हम लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित देख सकते हैं।

प्राचीन काल का दूसरा प्रसिद्ध पुस्तकालय मिश्र के सिक्किम नगर में था। इसकी शुरुआत सिक्किम महान् के कुछ समय बाद ही हुई थी। इस पुस्तकालय की पुस्तकें खोल में लपट कर बाँध दी जाती थीं। अर्थात् पुस्तकें पचाशूत नामक पत्र पर हाथ से लिखी जाती थीं और जिन्हें खोलो में हिफाजत से रखा जाता था। यह काल पैपाइरस, पाचमट एवं वेल्जूम का था।

भारतवर्ष में पुस्तकालयों की परम्परा—

भारतवर्ष भी अपनी सभ्यता एवं सभ्यता के वैभवशाली इतिहास में अभूत पूर रहा है। आर्यों के भारत आगमन के पूर्व जिस सभ्यता का इस धरती पर विकास हुआ था उसे हम सब से पुराने सभ्यता के नाम से जानते हैं। इतिहासकार इस तथ्य को प्रकट कर चुके हैं कि सिंधु घाटी के निवासी ही अपने प्रगतिशील समय में विश्व व्यापार के निमित्त दूर दूर तक गये एवं अपने उद्योग व्यापार कला-कौशल एवं साहित्य को फैलाते गये। इन सभ्यतावासियों ने ही मिश्र एवं असीरिया को फलाते गये। इन सभ्यतावासियों ने ही मिश्र एवं असीरिया में अपने परिवारों को बसाया और बाद में कई हजार वर्ष बाद जब वे ही आर्यों के रूप में भारत आये तो उन्होंने अपने आप को भारत के मूल निवासी के रूप में मान लिया। इस अन्तराल में इस धरती पर अनेक जातियाँ का प्रादुर्भाव हुआ चुका था।

आर्यों के भारत आगमन के उपरांत ग्रन्थों से युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से समस्यामूलक प्रश्न है। किन्तु आर्यों के द्वारा स्थापित उपनिवेश एवं क्रमशः राज्यों का विस्तार इस बात की पुष्टि करता है कि भारत की छवि को निर्मित करने में इनका अनुकरणीय सहयोग रहा। आर्यों की बोल चाल की भाषा संस्कृत थी एवं उनके पवित्र ग्रन्थ वेद कहलाते थे। शिक्षा का स्वरूप निःशुल्क था तथा विद्यार्थियों अथवा शिष्यों को गुरुकुलो, गुरुगृहों तथा प्रासादों में शिमा दी जाती थी। वैदिक परम्पराओं के अनुसार ब्रह्म का अध्ययन, श्रुति के माध्यम से होता था। लेखन सामग्री के अभाव में पुस्तकें ताड़ पत्रों, भोज पत्रों एवं वृक्ष की छालों पर लिखी जाती थी। एक पुस्तक का लिखने में कई वर्ष लग जाते थे तथा गुरु अपने शिष्यों से उस पुस्तक की प्रतिलिपि करवाते थे। इस प्रकार कठिन परिश्रम के उपरांत पुस्तकें अध्ययन हेतु उपलब्ध होती थी।

पुस्तकालय फिर भी गुरुगृह तक ही सीमित थे। ये ग्रन्थ गुरुमा की धरोहर थे जिन्हें परम्परागत रूप से सुनकर, पढ़कर ब्रह्मत्व कर लिया जाता था ताकि आने वाली पीढ़ी को इन दुर्लभ ग्रन्थों का ज्ञान प्राप्त हो सके। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, तदुपरांत उपनिषद् लिखे गये। स्मृति काल में वेद एवं उपनिषद् के अतिरिक्त आरण्यको, कल्प निरुक्त, व्याकरण, धर्म, दशन एवं राजनीति इत्यादि ग्रन्थों का निमाण हुआ। इसके साथ ही ग्रन्थ संग्रह बढ़ते गये एवं वैदिक ग्रन्थों के पुस्तकालयों का विकास होता गया। इसे हम वैदिक काल के पुस्तकालयों की कहानी ब्रह्मता की अतिशयोक्ति नहीं होगी।

पुस्तकालयों को अपने सही अस्तित्व में आने में जिन जिन युगों से निकलकर माना पड़ा इसकी कहानी भी रोचक है। मोटे तौर पर भारतीय पुस्तकालयों की कहानी का निम्न चार खण्डों में विभाजित कर सकते हैं।

- (1) प्राचीन काल के पुस्तकालय—(छठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक)
- (2) मध्यकाल के पुस्तकालय—(14 वीं शताब्दी से 16 वीं शताब्दी तक)
- (3) आधुनिक काल के पुस्तकालय—(16 वीं शताब्दी से 19 वीं शताब्दी तक)
- (4) वर्तमान काल (स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद) 1947 से आज तक।

प्राचीन काल के प्रमुख पुस्तकालय निम्नलिखित थे।

- (1) 'स्मृति' पुस्तकालय (वैदिक काल)
- (2) नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय (425 ई. और 625 ई. के मध्य)
- (3) विक्रम शिला विद्यापीठ (12 वीं शताब्दी)
- (4) उदत्तपुरी विद्यापीठ पुस्तकालय
- (5) वल्लभी पुस्तकालय (559 ई.)
- (6) चालुक्य पुस्तकालय
- (7) जेतवन सघाराम

(8) तक्षशिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय

(9) भोज पुस्तकालय (12 वीं सदी) (घारानगरी)

(अ) प्राचीन पुस्तकालय—

वर्तमान युग साहित्य कला एवं विज्ञान की दृष्टि से आविष्कारों का युग है। सम्पूर्ण जगत् विश्लेषण की भूमिकाओं से निपटता सुक्ष्म से सुदृढतम कायकलाओं की ओर बढ़ रहा है किंतु अतीत काल इस युग से कहीं अधिक उन्नतशील, विकासोन्मुख एवं समृद्ध था ऐसा प्रतीत होता है। यद्यपि लेखन उपकरणों की कमी, आर्थिक संकट एवं आपसी मनमुटाव के कारण, परिस्थितियों से संपन्न करना ही मानव का उद्यम था फिर भी बौद्धिक विकास हेतु ज्ञान पोषिका को धातु पत्रों, प्रस्तर खण्डों भोज पत्रों एवं पेड़ की छालों पर हस्तलिपि से तैयार किया जाता था मनुष्य में मानावन की जीजिविषा अनूठी थी। विद्वज्जनों को लिखन का शौक था वे अथक परिश्रम करके पत्थरों एवं धातु पत्रों को खादते थे, इटा पर लिखकर उन्हें पकात ५ अक्षर भाज पत्र एवं ताड़ पत्र को लेखनापयुक्त बनाने के लिये बहुत श्रम किया करते थे।

अशाक महान (272-232 ई पू) के काल में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों ने माध्यम से मध्य एशिया में खूब जोरों से चल रहा था। चीन, तिब्बत ब्रह्मा लका जावा सुमात्रा, जापान एवं नेपाल आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार इतना बढ़ा कि भारत में स्थान-स्थान पर बौद्ध मठों एवं मूर्तों का निर्माण हुआ, मन्दिरा एवं उनमें पुस्तकालयों का विकास हुआ जो बौद्ध धर्म के शिक्षा केन्द्र बन रहे बौद्ध धर्म के प्रचार ने चीन और भारत में प्रगाढ़ मैत्री उत्पन्न की। परिणाम स्वरूप शिक्षा का आदान प्रदान दोनों देशों के मध्य होता रहा।

ईसा के जन्म के 67 वर्ष बाद चीन के सम्राट मिंगटो ने भारतवर्ष में बौद्ध भिक्षुओं को बुलाने के लिये अपने दूत भेजे। दूत कश्यप मातंग और धर्म रक्षक नामक दो आचार्यों का अपने साथ चीन देश ले गये। ये दोनों आचार्य अपने साथ बहुत से ग्रन्थ भी ले गये और वहाँ पहुँच कर बौद्ध धर्म के अनेक ग्रन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया।¹ बौद्ध धर्म एवं उनकी शिक्षा दीक्षा से प्रभावित होकर अनेक विदेशी यात्री भारत आये जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रन्थों एवं हिन्दू धर्म ग्रन्थों का अध्ययन किया, उन ग्रन्थों की लिपि दूसरी भाषा में की, साथ ही अपने यात्रा सम्मरण भी लिखते रहे। ऐसे यात्रियों में चीन के प्रमुख यात्री फाह्यान व्हेन सांग एवं इत्सिंग का नाम पहले आता है। इन चीनी यात्रियों के सम्मरणों से पता लगता है कि “भारत में 5,000 मठ या विद्यालय थे जिनमें 2,92,930 विद्या र्थी पढ़ते थे।”² इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि जब देश भर में इतने शिक्षा केन्द्र थे तो उनमें सम्बद्ध पुस्तकालय भी अवश्य रहें होंगे। ह्वेन सांग के यात्रा वृत्तान्त के अनुसार “नालन्दा विश्वविद्यालय के अधिकार

मे 200 से अधिक गाव थे जो अनेक राजाओं ने दान दिये थे। वहाँ 90,000 विद्यार्थी और 9500 अध्यापक रहते थे चारों ओर ऊँचे ऊँचे विहार और मठ बन हुए थे। वहाँ कई बड़े बड़े पुस्तकालय और छ बड़े बड़े विद्यालय थे। विद्यार्थियों को नि शुल्क भोजन, वस्त्र, औषध, निवास एवं शिक्षा मुफ्त दी जाती थी। मध्य काल की यह शिक्षा व्यवस्था बेशक आश्चर्यचकित कर देने वाली है। एक विश्व विद्यालय में 90,000 छात्रों का अध्ययनरत होना अवश्यमेव कोतुक प्रकट करता है। ऐसे शिक्षणालयों में स्थित पुस्तकालयों के विकास पर एक दृष्टिपात करें तो कोई अत्युक्ति न होगी।

यह उन भारत-स्थित पुस्तकालयों की कहानी है जिन्हें देरान, उनमें सप्रहित ग्रन्थों का पारायण एवं ज्ञानाजन करने बसा जावा, सुमात्रा, चीन तिब्बत, भूटान आदि दूर-दूर के विदेशी धर्म प्रचारक व्यापारी एवं शिक्षावलम्बी आते थे। भारत में यह काल मनुकृति-सम्प्रदाय एवं ज्ञान-विज्ञान से द्विगुणित होकर शोभा पा रहा था। अनेक देशी-विदेशी आचार्यों ने इन पुस्तकालयों में निहित ग्रन्थों से अपने को सारावोर कर लिया। जीवन की अमूल्य राशि "ज्ञान" का पाकर अज्ञान के अंधकार से दूर अपनी शनिभारों विखेरता ज्ञान का सूरज विश्व-भ्रमण कर भारतीय धर्म सस्कृति के दीप स्तम्भों को प्रकाशित एवं प्रचारित करता था, प्रत्येक धर्म प्रेमी इन पुस्तकालयों से सहज ही प्रभावित होता था। उत्तर में तक्षशिला, नालंदा, वागणसी एवं कनौज काठियावाड़ में वल्लभी, महाराष्ट्र में पठन, नासिक करडवई और वतमान में प्र उज्जयिनी कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ शिक्षा दी जाती थी और उनके निजी पुस्तकालय भी थे। ऐसे प्रणिभा के ज्ञानागार थे ग्रन्थालय निश्चय ही भारतीय सस्कृति की अनमोल धरोहर के प्रतीक थे जिनके बारे में थोड़ा कुछ जानना बुरी बात नहीं है।

(अ) तक्षशिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय—

बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाये जान जाने सीक्कि एवं धार्मिक विषयों के लिए तक्षशिला में एक विश्व विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म एवं ज्ञान विज्ञान से सम्बंधित पुस्तकें जैसे समीत, चित्रकला, धनुर्विद्या, ज्योतिष, औषधि एवं चिकित्सा शास्त्र इत्यादि विषयों को पढ़ाने के लिये विश्व-विद्यालय के सनिकट ही एक सम्पन्न पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में समस्त वेद, आगुर्वेद धनुर्वेद, ज्योतिष, तक, त न, व्याकरण, चित्रकला, वास्तुकला, कृषि, व्यापार पशुपालन आदि विषयों का अच्छा संग्रह था।

अच्छ नम्रह एवं विद्वान आचार्यों की प्रतिष्ठा दूर-दूर तक फैली हुई थी। व्याकरणाचार्य पाणिनी, कूटनीतिन चाणक्य, कुशल प्रशासक सम्राट चंद्रगुप्त एवं पुष्पमित्र इती विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे। इन्हीं लब्ध प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ अन्य अनेकी विदेशी छात्रों का यहाँ ताता लगने लगा था। यह विश्वविद्यालय उस समय विद्याध्ययन का प्रमुख स्थल था किन्तु ज्ञान एवं हुणा जैसे आततायियों के कारण इस विशाल पुस्तकालय व शिक्षण संस्थान का अन्त हो गया।

(ब) नालंदा विश्व विद्यालय पुस्तकालय—

प्राचीनकाल का यह द्वितीय प्रमुख विश्वविद्यालय पुस्तकालय था जिसे “धम्मगज” नाम से जाना जाता था। इसके “रत्नोदधि” ‘रत्नसागर’ एवं “रत्नरजक” नाम के तीन प्रमुख विभाग थे। आज जिस प्रकार केन्द्रीय पुस्तकालय में, “भाषा विज्ञान” ‘साहित्य’, ‘विज्ञान’ एवं “कला विभाग” विषय होत ह और इही प्रमुख विभागों में पुन वर्गीकरण कर उन्हें अलग अलग विषयों में विभाजित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार उक्त वि० वि० पुस्तकालय में भी विषय वर्गीकरण के अनुसार पुस्तकों का व्यवस्थापन किया जाता रहा होगा।

बुध्दसागर ने नालंदा विश्व वि० के पुस्तकालय के बारे में लिखा है कि इस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय नौ मजिला था जिसकी ऊँचाई करीब 300 फीट थी। इसमें बौद्ध धर्म सम्बन्धी सभी ग्रन्थें थीं। प्राचीन काल में इतना बड़ा ग्रन्थालय कदाचित ही नहीं रहा होगा।⁶

वर्तमान विश्व में भी मैं नहीं समझना कि इतना बड़ा विशाल पुस्तकालय भवन कहीं अस्तित्व में हो जिसकी ऊँचाई 300 फीट हो। पुस्तकालय में ग्रन्थ व्यवस्थापन के दृष्टिकोण से संग्रहित ग्रन्थ विषयक्रम से पत्थर के फलक पर अक्षरों में बहुमूल्य वस्तुओं से घाबरकर व्यवस्थित रखे जाते थे। प्रत्येक आचार्य पर पुस्तकालय के एक एक विभाग का दायित्व होता था।

चीनी यात्री बुध्दसागर के निवास काल में शीलभद्र इस विश्व विद्यालय विहार के प्रधान आचार्य थे। अन्य आचार्यों एवं शिक्षकों में धम्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, जीमिन, नानचन्द्र तथा शीघ्रबुद्धि प्रभृति के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन समस्त विद्वानों ने नालंदा महाविहार में निवास करते हुए अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की थी। स्थिरमति ने 9 संस्कृत ग्रन्थों की रचना की, 6 तिब्बती भाषा में अनुवाद किये तथा तिब्बती भाषा में अनुवादित 90 पुस्तकों का सशोधन परिवर्धन और सम्पादन किया था। दूसरे विद्वानों और आचार्यों ने भी अनेक ग्रन्थों, ग्रन्थ टीकाओं एवं आलोचनाओं की रचना की थी। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग ग्रन्थ निर्माण, लेखन एवं सम्पादन कला में भी प्रवीण थे।

इस विश्वविद्यालय की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी जिसका लाभ प्राप्त करने चीनी यात्रियों के अतिरिक्त जापान, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया एवं बुखारा इत्यादि देशों से भी अध्ययन करने आये थे। फाहियान अपने साथ ताड़पत्र पर निते 520 ग्रन्थ ले गया था। इतिहास ने 500 बौद्ध ग्रन्थों को चीन भेजा था। एक हजारों ग्रन्थ विदेशी घमावलम्बी इस पुस्तकालय से चारों छिन्न ल गये। सब प्रयत्न हुए के सरदार मिहिरकुन ने इस वि० वि० एवं पुस्तकालय का अतिग्रन्थ किया किन्तु 470 ईस्वी में जलान्तिय ने नालंदा वि० वि० पुस्तकालय की क्षति को पूरा किया।

“सम्राट महिपाठ (980-1026 ई.) के शासनकाल के पौनर्वे वष में यहाँ “अष्टाधिका प्रतापरिमिति” की प्रतिनिधि तैयार की गई। यह प्रति अब भी केम्ब्रीज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसके एक वर्ष बाद महिपाठ वही शासन काल में इसी पुस्तक की एक प्रति और तैयार की गई। यह प्रति बंगाल की एशियाटिक सासायटी के पुस्तकालय में सुरक्षित है।”⁸

नालंदा विहार की अव्यवस्था शासक पायपाल के बाद हुई। नालन्दा के निवृत्त विष्णु शिला नामक एक दूसरे महाविहार की उन्नति इसकी अवस्था में विशेष सहायक हुई। “1205 ई. में बग्नियार खिलजी के आक्रमण ने इस पुस्तकालय की घुरी दशा कर दी थी। शेष यथा जो जलाकर उसके सैनिक पानी गरम करते रहे और नष्ट रहे।”

नालंदा के ध्वंसावशेषों में 1864 में वेस्टन माशेल की बालादित्य का जो शिलालेख प्राप्त हुआ था उससे निश्चित होता है कि नालंदा विहार भीषण अग्निकाण्ड के कारण जलकर भस्म हो गया उसके साथ ही उसका विशालकाय प्रसिद्ध पुस्तकालय भी भस्म हो गया। कहा जाता है कि पुस्तकालय में इतने अधिक ग्रंथ थे कि पुस्तकालय बराबर एक मास तक खुलता रहा था।⁸ उपरोक्त दोनों प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों का पढ़ने से मात्र पड़ता है कि अल्फ्रेड हैमस की पुस्तक “पुस्तकालयों का इतिहास” में मदनमोहन ने लिखा है कि बग्नियार खिलजी के आक्रमण से पुस्तकालय नष्ट हुआ जबकि श्यामनारायण कपूर ने अपने लेख “प्राचीन भारत के पुस्तकालय” में स्पष्ट किया है कि पुस्तकालय भीषण अग्निकाण्ड से नष्ट हुआ।

एक अन्य पुस्तकालय इतिहास लेखक द्वारा प्रसाद शास्त्री ने अपनी पुस्तक “भारत में पुस्तकालयों का उद्भव और विकास” में लिखा है “बौद्ध भिक्षुओं और जैन साधुओं ने कुछ कारणों से भगड़ा हुआ। कहा जाता है कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने जन साधुओं के ऊपर अशुद्ध जल फेंक दिया था अतः क्रोध होकर जन साधुओं ने कुछ दहकते कोयले इस पुस्तकालय पर फेंक दिये फलतः “रत्नादधि” में संप्रहित ग्रंथ जलकर राख हो गये। इस प्रकार नालंदा के इस पुस्तकालय का अस्तित्व सदा के लिए जाता रहा।”⁹

यह बात बड़ा बड़ा सत्य है इसके प्रमाण हेतु हम उस काल के इतिहास की उठाकर देखना होगा। किंतु यदि हम एक दूसरे पहलू से साँचें कि जहाँ शिक्षा एवं ज्ञान की पान की गरिमा इतनी मात्र थी कि वहाँ का प्रत्येक गाँव, शिक्षार्थी भावनिष्ठ होकर विद्यालय की शोभा एवं श्री को वनात थे, शालिग्राम थे, वही लोग अपने धर्म में तैयार साहित्य श्री को कैसे नष्ट कर सकते थे। यह बात युक्ति संगत नहीं लगती। हाँ यह माना जा सकता है कि आक्रमणकारियों के डर से उन्होंने यह माँचा हो कि ये ग्रंथ उनके हाथ न लग पायें, अतः उन्होंने आपस में

विवाद सड़ा कर उस पुस्तकालय को जलाने में मदद पहुँचायी होगी ताकि दुश्मन के हाथ ज्ञान राशि का संचित कोश न जाये।

(स) विक्रमशिला विद्यापीठ पुस्तकालय—

इस विद्यापीठ की स्थापना मगध-राज धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। विक्रमशिला में भी नालन्दा वि वि ही के समान तिब्बत, चीन और मंगोलिया आदि देशों के विद्वान शिक्षा प्राप्ति हेतु आया करते थे। इनका प्रमुख उद्देश्य नानाजन के साथ साथ ग्रन्थों का अपनी भाषा में अनुवाद कर उन्हें अपने साथ ले जाना भी था।

यह विद्यापीठ एक पहाड़ी पर बनाया गया था। जिसके साथ छोटे बड़े 108 मठ भी बनाये गये थे। 12वीं सदी में यहाँ 8000 बौद्ध भिक्षु विद्यार्थी रहा करते थे। इसी बात की पुष्टि द्वारका प्रसाद शास्त्री ने इस प्रकार से की है। "12वीं शताब्दी में लगभग 30,000 बौद्ध भिक्षु विद्यार्थी यहाँ रहा करते थे। इस महान पुस्तकालय की प्रशंसा आक्रमणकारियों ने भी की है। इस पुस्तकालय का भी कक्ष चित्रकला से सुसज्जित था। इसका भी विश्वेश वस्तियार खिलजी के द्वारा ही हुआ। 10 'तत्वावत इन नसीरी के अनुसार सभी बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया था। इस पुस्तकालय में हिन्दू धर्म के अनेक ग्रन्थ थे। खिलजी की पुस्तक में पात हुआ था कि सम्पूर्ण मठ एक महाविद्यालय था।' 11 विद्या के क्षेत्र के रूप में विक्रमशिला विद्यापीठ की सफलता एवं प्रसिद्धि का प्रमाण इस बात में मिलता है कि उमने बहुत बड़ी सरया में प्रतिभाशाली विद्वान एवं शिक्षाशास्त्री पैदा किए, विलक्षण धर्मात्माओं एवं विशेषज्ञों का जन्म दिया। जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा ज्ञान तथा धर्म के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धांत कायम किये और इन्हीं सिद्धांतों एवं योगदान के आधार पर तिब्बत जैसे एक पूरे देश की सभ्यता तथा सस्कृति का वस्तुतः निमाण हुआ।

(द) वल्लभी विश्वविद्यालय पुस्तकालय—

"वल्लभी वि वि सौराष्ट्र के मैनक वंश के राजाओं की कृपादृष्टि से अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना गुणमति एवं स्थिरमति ने की थी। इस विश्वविद्यालय में इतना अच्छा पुस्तकालय था कि उससे प्रसन्न होकर राजा ने विशेष रूप से पुस्तकों खरीदने के लिए अनुदान दिया था।" 12

गुणमति एवं स्थिरमति चूँकि नालन्दा विश्वविद्यालय में आचार्य रह चुके थे, अतः उनकी शिक्षा प्रसार एवं ज्ञान की पिपासा ने उन्हें इस सरम्पती मन्दिर की स्थापना हेतु प्रेरणा प्रदान की। उनकी बुद्धि चालुय से विश्वविद्यालय ग्याति पाता गया एवं पुस्तकालय बभूवपूर्ण होता रहा।

(इ) चालुक्य पुस्तकालय—

यह पुस्तकालय चालुक्य राजा रामनारायण के मंत्री मधुसूदन के द्वारा

बनाया गया था। दक्षिण का यह चालुक्य पुस्तकालय अपने समय का सम्भ्रांत पुस्तकालय था जिसके नये छ (पुस्तकालयाध्यक्ष) सरस्वती भांडारिक नियुक्त थे, इनका ओहदा शिक्षकों के बराबर ही था। शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के पद समान प्रतिष्ठा के समझे जाते थे। “उनकी स्थिति भारतवर्ष के आधुनिक कालिजों के क्लार्क लायब्रेरियनो जैसी सोचनीय नहीं थी।”¹³

वर्तमान भारत के पुस्तकालयाध्यक्षों की स्थिति अब उम्र में बेहतर होती जा रही है, उन्हें भी समान कार्य हेतु समान वेतन, पद एवं प्रतिष्ठा की अभिलाषा है।

प्राचीन भारत की संस्कृति, कला एवं साहित्य को सुरक्षित रखने, उसके विकास तथा प्रसार-प्रचार में इन विश्व विद्यालयों ने बहुत बड़ी भूमिका का निवाह किया। कला एवं दर्शन के नये मूल्यों को प्राप्त कर भारत ने नये क्षेत्र में निपुणता हासिल की।

12वीं सदी में भी कुछ प्रमुख पुस्तकालय ऐसे थे जिन्हें हम भुला नहीं सकते। राजा भोज का राजकीय पुस्तकालय भी इनमें से एक था। राजा भोज स्वयं एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार कवि, लेखक एवं कला अनुरागी था। उसके दरबार में कवियों लेखकों और विद्वानों को समुचित आतिथ्य-सत्कार दिया जाता था। उसका राजकीय पुस्तकालय अपने समय में अत्यंत प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। यह पुस्तकालय संस्कृत ग्रंथों व शिलालेख संग्रहालय के रूप में अधिक प्रसिद्ध था। चालुक्य राजा का धारानगरी पर अधिकार के बाद सिद्धराज न राजा भोज के सुप्रसिद्ध पुस्तकालय को धारानगरी से हटाकर अहिलवाड-बड़ौदा राज्यांतगत प्रसिद्ध पाटन नगर में स्थापित किया और चालुक्य वंश के राजनीय पुस्तकालय में सम्मिलित कर दिया।

बड़ौदा राज्य में आधुनिक पुस्तकालयों के विकास का मूल शायद ये ही पुस्तकालय थे जिनके रहने से बड़ौदा राज्य के निवासियों ने पूरा लाभ प्राप्त किया होगा। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता के ये मूल प्रतीक अपनी शतधा किरणें बिखेरते रहे, जिसे विश्व के अनेक धर्मों संस्कृतियां एवं कलाप्रेमी विद्वानों ने समेटा। जिन लोगों से इनकी पत्तली प्रशस्ति असहनीय हो गई उन लोगों ने ऐसे ‘सरस्वती भण्डारों’ संचालनों उपाधियों, मठों एवं पीठों के तमाम पुस्तकालयों को ध्वंस कर दिया।

ऐसे लोगों में मुस्लिम राजा (बादशाह) सबसे अग्रणी थे। नादिरशाह तो दिल्ली का पूरा पुस्तकालय उठावा ले गया था। मुकर्रात ने सिकंदर से “भगवद्गीता” की पोथी भारत से अपने साथ लाने को कहा था। इसके अनिर्दिष्ट अंग्रेज शासकों की सभ्य लूट और चतुराई नीति से अनेक दुर्लभ ग्रंथ देश के बाहर चले गये, सीधी, शान्त एवं भावुक जनता दबती रह गई। इण्डिया आफ़िम लाइब्रेरी, ब्रिटिश म्यूजियम जैसे विशाल पुस्तकालयों में भारतीय हस्तलिखित

ग्रंथ काफी मात्रा में है। इनमें अधिकांश देव भाषा संस्कृत में ही है। भारत से दुर्लभ ग्रंथों का बाहर जाने का कारण आपसी वैमनस्यता, साम्प्रदायिक विद्वेष एवं शासकों की नीतियाँ प्रमुख रही। राजाओं ने यश और छत्रपति बनने के लालच में आपस में युद्ध किये और भारत की गुलामी का इतिहास निमाण करने में सहायक रहे। मुस्लिम शासकों ने भारतीय पुस्तकालयों का अन्त कर दिया।

(A) मध्यकाल के कुछ प्रमुख पुस्तकालय निम्नलिखित थे—

- (1) नगरकोट या पुस्तकानय (14वीं शताब्दी)
- (2) महमूद गँवा का पुस्तकालय (सन् 1450)
- (3) धक्कर महान् का पुस्तकालय
- (4) आदिल शाही पुस्तकालय
- (5) सरम्बनी महल पुस्तकालय तजौर
- (6) हैदरअली का पुस्तकालय
- (7) जयपुर के पुस्तकालय

(B) मध्यकाल के पुस्तकालय—

मध्यकाल में विद्वान् आचार्यों एवं भावी भारत प्रेमियों ने जहाँ तहाँ बचे हुए दुर्लभ ग्रंथों का अपने जीवन से अधिक महत्त्वपूर्ण समझ कर सहेला। मुस्लिम सुल्तानों एवं हिन्दू राजाओं में कुछ जो कलाप्रेमी एवं साहित्य अनुरागी थे उन्होंने अपने निजी पुस्तकालयों की व्यवस्था अपने राजभवनों में ही कर रखी थी। शिक्षा की कोई सावजनिक श्रृंखला पद्धति न होने के कारण पुस्तकालयों का महत्त्व था ही नहीं। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की पढ़ाई मदरसों एवं मकतबों में होती थी। इनमें सत्रण पुस्तकालय ही कुछ अंश तक कार्यशील थे।

फिरोज तुगलक ने जब 14वीं शताब्दी में नगर कोट पर चढ़ाई की तो उसे एक संस्कृत ग्रंथों का पुस्तकालय प्राप्त हुआ जिसमें दशन, भविष्य तथा ज्योतिष सम्बंधी ग्रंथ बहुतायत में थे। बहमनी राज्य का मंत्री महमूद गँवा के पास 3000 पुस्तकों का एक अच्छा पुस्तकालय था। यह उसका निजी पुस्तकालय था जिसमें फुरमत ने समय बहूँ अपने विद्वानों के साथ पुस्तकालय में अपना समय बिताता था। 1481 में एक पहलूत्र में महमूद गँवा की हत्या कर दी गई तभी से राज्य की अवस्था हुई जिसमें पुस्तकालय की व्यवस्था समाप्त हो गई।

मुगल शासकों में बाबर हुमायूँ, धक्कर सभी विद्वान् पुस्तकप्रेमी एवं विद्या व्यसनी थे। कहते हैं हुमायूँ की मृत्यु उसके निजी पुस्तकालय की सीढ़ियाँ से गिरकर हुई थी। उसने शेरशाह के आमोद गृह को पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया था। इतना प्रेम अवश्य ही विद्वता का परिचायक है।

हुमायूँ की मृत्यु के उपरान्त उसने पुत्र धक्कर ने मसाधारण आर्थिक मूल्यों वाली हजारों पुस्तकें (लगभग 25000) अपने निजी ग्रंथालय में रखी थीं

जो वेशकीमती वस्तुआ से जिल्द की गई थी। सुंदर पाण्डुलिपियां से भरा यह पुस्तकालय अनेक विषयों की पुस्तकों से सुशोभित था। “अकबर ने पुस्तकालय की व्यवस्था में परिवर्तन किया था और ग्रंथों को वर्णबद्ध या श्रेणीबद्ध किया था। किताबों को विषयों और मूल्यों के आधार पर विभाजित किया गया और कैटलॉगिंग की गई। उसकी लायब्रेरी सुव्यवस्थित थी और प्रत्येक अनुभवी व्यक्तियों को दिया जाता था। लायब्रेरी का प्रमुख अध्यक्ष निजाम कहलाता था, उसके अधीन मुह्तमीम या दरोगा होता था और उसके अनेक सहायक होते थे जो किताबों के आगम निगम को रजिस्टर में चढ़ाते थे।” शाही पुस्तकालय में अनुवाद काय हेतु विद्वत् आचार्यों की नियुक्ति की गई थी “कृष्ण जोशी के निर्देशन में संस्कृत ग्रंथों का फारसीयन भाषा में गंगाधर और महेश महानंद अनुवाद करते थे। शाही पुस्तकालय के लिये महाभारत महाकाव्य का अनुवाद नगीबखान की देखरेख में फारसी में, बदायूँ के मौलाना अब्दुल कादिर और यानेश्वर के शेख मुल्तान द्वारा किया गया था। रामायण का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया तथा चार वेदों में से एक वेद “अथर्ववेद” का “अंतरवन” के नाम से अनुवाद किया गया था। अबुल फजल के बड़े भाई ने भास्कराचार्य की ‘लीलावती’ का फारसी भाषा में अनुवाद किया था।

पुस्तकों पर स्वर्ण एवं जरी का काम साथ ही रंगीन चित्रकारी इस बात का द्योतक है कि मुद्रण काय एवं छपाई सर्वाङ्गुष्ट होती थी। यह बहुत आश्चर्य है कि इस काल की जिल्दसाजी कला का अब कहीं कोई अस्तित्व नजर नहीं आता।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट विदित होता है कि अकबर के शासन काल में शिक्षण संस्थाओं एवं शाही पुस्तकालयों में वर्गीकरण, सूचीकरण, संगठन एवं पुस्तकालय प्रबंध की तकनीक का प्रचलन था, साथ ही भौतिक ग्रंथवर्णना के अनन्त उच्चस्तर की जिल्दसाजी, पृष्ठ सजावट एवं सुवाच्य लेखन कला का ज्ञान भी उच्च भली प्रकार था। पुस्तकालय प्रशासन का भी उच्च अनुभव था तभी तो पुस्तकालयाध्यक्ष के अधीन मुह्तमीम और उनके अथ सहायकों के द्वारा पुस्तकों का लेन देन यह जाहिर करता है कि वे पुस्तकालय प्रशासन के सिद्धान्तों को जानते थे और उनका अनुसरण करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अकबर महान् स्वयं इतना कुशाग्र बुद्धि शासक था जिसने पुस्तकालय विज्ञान के विषयों (तकनीक) का पूरा से ही भारत में प्रादुर्भाव कर दिया था।

अहमदाबाद में बड़ी लायब्रेरी थी। यहां के मदरसे की लायब्रेरी “शाम ये बुरहानी” कहलाती थी। फिगाली मदरसा 1654 में स्थापित हुआ। हिनायत बरस मदरसा 1699 में स्थापित हुआ। काठियावाड़ के शेख इब्राहीम वाले मदरसे में शानदार समृद्ध लायब्रेरी थी।¹⁴ मोहम्मद शाह उहमनी द्वितीय के चतुरमत्री महमूद गवा ने बीदर में एक कालेज का निमाण किया था जिसमें

विद्याविद्या के उपयोग हेतु 3000 हस्तलिपियाँ थीं। नादिरशाह ने जब आक्रमण किया तो सार मुगलकाल के शाही पुस्तकालयों का वह फारस ले गया। इस प्रकार औरंगजेब के आक्रमण न आदिलशाही पुस्तकालय को नष्ट किया।

दक्षिण भारत के पुस्तकालय—

दक्षिण भारत में हिंदु राजाओं के अच्छे पुस्तकालय थे, जिनमें तंजौर का पुस्तकालय (सरस्वती महल) प्रमुख था जो आज भी अपने आप में एक विशाल पुस्तकालय है जिसका मुवाबला संस्कृत ग्रंथों के पुस्तकालयों में भारत का अन्य पुस्तकालय नहीं कर सकता है। इस पुस्तकालय की स्थापना तंजौर के नायकों द्वारा की गई थी। शाहजी भोसले ने 1675 और 1850 के बीच इस राज्य में अपने शासन के समय इस पुस्तकालय को बहुत अच्छा बनाया। इसके विकास एवं विस्तार के लिए सरफोजी भोसले विशेष रूप से उत्तरदायी थे।

मैसूर के महाराजा चिक्कादेराव (1662-1704) के पास भी अच्छी लायब्रेरी थी जिसे बाद में टीपू सुल्तान के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। एक और जहाँ टीपू ने विजय श्री पाने के लिए दूसरे राजाओं के अंगार उड़ाये वही उसने अपने शासन काल में पुस्तकालयों के विकास एवं ग्रंथ अध्यायन को महत्व दिया। टीपू के विवाह समारोह पर हैदर अली ने अपने पुत्र से पूछा कि इस विवाह पर्व पर तुम्हें क्या उपहार दिया जाय तो टीपू का बहना था, मैं एक पुस्तकालय की स्थापना करना चाहता हूँ। तभी हैदर अली ने अपने प्रधानमंत्री पुणिया को बुलाकर यह आदेश दिया था कि मेरा पुत्र एक भव्य पुस्तकालय चाहता है अतः एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण किया जाए और अनुवादकों की नियुक्ति की जाये। तभी पुणिया ने नुरुल हसन को प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया तथा विविध राष्ट्रां से सूचीकार, सदाशिव विशेषण एवं शोधकर्ताओं को अपने पुस्तकालय कार्य के लिए बुलाया था। इस पुस्तकालय खोजने के बारे में टीपू सुल्तान ने कहा था “मेरा यह खजाना सोने और चाँदी के राजने से बढ़कर है इसे किसी को भी छूटना या समाप्त नहीं करना चाहिए।” इस दिवास्वप्न के साथ 1799 में जब अंग्रेजों द्वारा उसकी हार हुई। तब उसका विशाल पुस्तकालय जो अंग्रेजों, फ्रेच, पारसियन एवं वैदिक साहित्य से परिपूर्ण था, अंग्रेजों के हाथ लगा। अंग्रेज ने उसमें से 2000 चुने हुए महत्वपूर्ण ग्रंथ लंदन ले गये और “इण्डिया आफिस लायब्रेरी” की स्थापना की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश भर की अरबी एवं फारसी भाषा की महत्वपूर्ण पोथियाँ भी इस पुस्तकालय में पहुँचाई गयी थीं।

जयपुर के राजा सवाई जयसिंह (1699-1743) के पास अनेक दुर्लभ पुस्तकें थीं। हिंदू शिक्षण सस्थाओं की लाइब्रेरी भी अच्छी थी। यहाँ प्राचीन दशन चिकित्सा, धर्म, इतिहास तथा विभिन्न विज्ञानों का संकलन था। कतिपय

लाइब्रेरी सस्कृत की हस्तलिपियां से सज्जित थीं जिनमें अधिकांश वन सम्बन्धी रिवाजसंघ थे। जय बनियर बनारस पहुँचा तो कविन् आचार्य ने उसका स्वागत विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में किया जहाँ बृहत् पैमाने पर हस्तलिपियां का संचालन था।

उपरोक्त बात से मालूम पड़ता है कि बनारस भी अपने समय का विद्याध्ययन का प्रमुख केन्द्र था। काशी विद्यापीठ के पुस्तकालय भी देश की शिक्षा के केन्द्र बिन्दु थे जहाँ देश विदेश के आचार्यों, साधु सन्ता न आकर अध्ययन व ज्ञानाजन किया था। बाराणसी के बाग़े में अबुल फजल ने आइने अकबरी में लिखा है कि अनादिकाल से यह हिन्दुस्तान का मुख्य विद्या केन्द्र था। देश के सुदूरतम भागों के लोग बड़ी सरया में विद्या प्राप्त करने यहाँ आते थे और बड़ी श्रद्धापूर्वक लगन से अध्ययन करते थे। आज भी यह नगर शिक्षा का विशेष रूप से सम्स्कृत साहित्य की शिक्षा का देश में प्रमुख स्थल है।

हमें यह मानना पड़ेगा कि मध्यकाल में मुगल शासकों के द्वारा जनता की रुचि एवं पुस्तकालयों के विकास पर ध्यान दिया गया ताकि राजा सुखी एवं शिक्षित हो। सभी मंदिरों एवं विद्यापीठों में उनके निजी पुस्तकालय होते थे। इनके अतिरिक्त मुगल सम्राटों तथा उच्च अधिकारियों एवं अमीरों ने भी पुस्तकालयों की स्थापना की। मुगल सम्राट शाही पुस्तकालय (Imperial Lib) के विकास में रुचि प्रकट करते थे। शेख फैजी के पुस्तकालय में 4,600 पुस्तकें थीं।

इन सब विवरणों से स्पष्ट होता है कि पूर्व मध्यकाल में हिंदु सम्राटों ने एवं धर्मबलम्बियों ने शिक्षा एवं साहित्य निर्माण के द्वारा ज्ञान विज्ञान में सफलता प्राप्त की और पुस्तकालयों का निर्माण कर अपनी सस्कृति को विश्व के समक्ष पुनी पुस्तक के रूप में रख दिया ताकि सभी मानव जाति के लोग भारतीय सांस्कृतिक धरोहर से कुछ प्राप्त कर सकें, भारत की दान नीलता, शांति प्रियता ने उससे अपनी मौलिक देन छीन ली और अब भिखारी बन पूर्व की ओर देख रहा है।

मध्यकाल में भी साहित्य का व्यापार जारी ही होता रहा। मुगल शासक अवश्य ही शिक्षा प्रेमी, कला प्रेमी एवं अध्ययन में रुचि रखने वाले थे और कुशल प्रशासक भी किन्तु भारत पर होने वाले निरन्तर ख़तरों के कारण एवं आतंकवाद के कारण उनके सपने अधूरे ही रहे, जो कुछ था वह भी आक्रमणकारियों द्वारा लूट लिया गया।

(C) आधुनिक काल के पुस्तकालय—(17 वीं से 19 वीं शताब्दी)

पूर्व में लिखा जा चुका है कि भारत में पुस्तकालयों की परम्परा कोई नयी नहीं है, किन्तु आज की दशा में जो प्रगति हमने की है वह पहले से कहीं अधिक रोचक एवं ऐतिहासिक है। भारत में मुद्रण कला का प्रसार नहीं हुआ था।

पुतगालियो के गोवा आगमन के बाद ईसाई धर्म सम्बन्धी पुस्तकों का मुद्रण जोगे स चल पड़ा था। सर्वप्रथम माशमैन नामक पातगाली पादरी न गावा में अपना 'प्राप्रा खाना खोला'। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारी दस्ते भी अब तब भारत के बड़े बड़े शहरो जैसे कलकत्ता, मद्रास, एव बम्बई में फैल चुके थे। 1712 में डनिश मिशनरिया ने टान्क्वेबर्ग में एक प्रेस स्थापित किया। उहाँन 'एपोस्टाइल्स क्रीड' नामक पुस्तक तमिल में छापी। यह भारतीय भाषा की प्रथम मुद्रित पुस्तक थी। चूँकि यहाँ अभी तक गुरुगृहा, भक्तवा, मदरसा में शिक्षा दी जाती थी जिनके साथ उनके निजी पुस्तकालय भी थे। कुछ राजाध्या के राज्या में भी पुस्तकालय थे किन्तु ईसाइया एव अंग्रेज व्यापारियों के आगमन से इनका विकास न हो सका। ईसाई धर्म प्रचारक व कम्पनी के अधिकारियों ने वही वहाँ छोटे-छोटे विद्यालय स्थापित किये जिनके साथ पुस्तकालय भी थे। धर्म की लड़ाई में पोतगाली एव फ्रांसिसी पिछड़ गये और अंग्रेजों ने अपना पैर जमा लिया। भारतीय जनता की धार्मिक रुढ़िवादिता से अंग्रेजों का अपने धर्म प्रचार में बड़ी प्रभाव नजर नहीं आया अतः उन्होंने भारत की धर्म प्राण जनता का धर्म के साथ शिक्षा दान का भी संकल्प ठान लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के 1813 ई. के पत्र के अनुसार भारत में शिक्षा प्रचार को कम्पनी ने अपना उत्तरदायित्व समझ कर माना। इसके आधार पर 1781 में कलकत्ता मदरसा, सन् 1791 में बनारस संस्कृत कालेज तथा 1800 में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना हुई। इनमें पुस्तकालय भी स्थापित कर दिये गये। 1808 में बम्बई सरकार ने भारतीय जनता की अंग्रेजी साहित्य में रुचि बढ़ाने हेतु पुस्तकालयों को रजिस्टर्ड किया, जिससे कि पुस्तकें मुफ्त में बाँटी जा सकें, इसके साथ ही पुस्तकालय विकास की शुरुआत हुई। यद्यपि इस प्रकार के लाख पुस्तकालय देशी रियासतों जैसे इन्दौर स्टेट एव टावनकोर में 19 वीं शताब्दी के अन्त तक थे। अंग्रेजों ने गांव गांव नगर नगर पुस्तकालयों के आन्दोलन को बढ़ाया किन्तु इसके पछे हिन्दू संस्कृति एव धर्म के अनमोल खजाने को बर्बाद कर इंग्लैंड भेजत गये। हिन्दू जनता अंग्रेजी शिक्षा एव नौकरी पक्ष में खुश थी।

1867 में ब्रिटिश सरकार ने कानून पास करने पुस्तकालय आन्दोलन को जबरदस्ती जनता पर लाद दिया। यह भी साहित्य की बर्बाद करने का एक अच्छा तरीका था। विरोधियों का खुश करने के लिये अंग्रेजों ने यत्र-तत्र पुस्तकालयों की स्थापना की। इनको नेटिव जनरल साइब्रेरी कहा जाता था। सबसे पहले 1884 ई. में बलगाव और 1854 में धारवाड में ये नेटिव लायब्रेरिज स्थापित की गईं। जुवली पुस्तकालय भी दश के अनेक भागों में महारानी ब्रिक्टोरिया के जुवली महोत्सव में खोले गये। इसी समय दश के कोने कोने में कई लाख पुस्तकालय भी स्थापित हुए।

1800 में बलकृष्ण म सावजनिक पुस्तकालयों की शासकाय दफ्तरी, मयिमण्डला के भी विभागीय पुस्तकालय मील गये। पुस्तकालय विकास के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। 1902 में इम्पीरियल लायब्रेरी की स्थापना हुई। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, पाठशालाओं में भी पुस्तकालयों का स्थापित किया गया। सबसे प्रथम 1857 में बलकृष्ण विश्वविद्यालय में 1869 में बम्बई विश्वविद्यालय में 1876 में अलीगढ़ एव 1882 में पंजाब विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना हुई। 1903 में मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय का शुभारम्भ हुआ।

सावजनिक पुस्तकालय आन्दोलन का प्रथम थो गणेश 1910 में बड़ौदा राज्य के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड ने पुस्तकालय संस्थान की स्थापना कर दिया। उन्होंने अपनी प्रजा की शिक्षित जनता हेतु पूरे राज्य में सावजनिक पुस्तकालयों का जाल फैला दिया। चलते फिरते पुस्तकालय भी ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकें पहुँचाने हेतु निर्मित किये। शिक्षण सभाओं, अनुसंधान सभाओं एव प्रयोगशालाओं में भी अनेक पुस्तकालय स्थापित हुए। इस काल में जनता एव सरकार के मिले जुले पुस्तकालय देश भर में कायम थे। ब्रिटिश काल में ही अग्रिम भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना स्वर्गीय के.एम. असदुल्ला के नेतृत्व में 1935 में हो चुकी थी। देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों दिल्ली, मद्रास, बनारस एव अलीगढ़ में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रशिक्षण भी प्रारम्भ किया गया। देश के प्रकाण्ड विद्वानों ने पुस्तकालय विज्ञान के साहित्य को लिखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुस्तकालय विज्ञान साहित्य के निमाण में प्रकाण्ड पंडित मुलुके हुए विषय वैज्ञानिक स्वर्गीय डा. एस. आर. रंगनाथन का अभूतपूर्व योगदान था। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान विषय पर लगभग 50 पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में लिखीं। भारत में ये पुस्तकालय विज्ञान विषय के जन्मदाता माने जाते हैं। इस प्रकार पुस्तकालयों के इतिहास में एक ठोस प्रवृत्ति का निर्माण हुआ। इस काल में कुछ न्याय प्राप्त पुस्तकालय अपने अस्तित्व में थे जिनका विवरण देना यहां प्रासंगिक होगा।

(1) इण्डिया आफिस लायब्रेरी—

सन् 1799 में टीपू सुल्तान की पराजय के बाद उसका विशाल पुस्तकालय जो वैदिक साहित्य अंग्रेजी प्रेच व परशीयन साहित्य से परिपूर्ण था, अंग्रेजों के हाथ लगा और व उस पुस्तकालय की 2000 चुनी हुई पुस्तकें लंदन ले गये और इण्डिया आफिस लायब्रेरी की स्थापना की। मुलामी के काल में शिक्षा प्रसार के नाम पर इस पुस्तकालय की स्थापना भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक, धार्मिक एव साहित्यिक ज्ञान राशि का सग्रहित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह उद्देश्य उद्गार करने का सबसे प्रथम प्रयास प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राबर्ट औरम ने

किया था जो उस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कुशल इतिहासकार था। यह ग्रामिण ब्रिटिश शासन काल में भाग्य की गतिविधियाँ का लेखा जोखा रखने का मर्मिय स्वरूप था। इसकी स्थापना ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा 1809 में की गई थी। 1946 के बाद से इस पुस्तकालय को कामनवेलथ सम्बन्धी पुस्तकालय कार्यालय के नाम से पुनारा जाना है। इसका उपयोग केवल नियमित पाठकों या छात्र सदस्यों को ही करने दिया जाता है।¹⁶ इण्डिया ग्रामिण लायब्रेरी बनने के पूर्व इसका नाम 'पब्लिक रिपोजिटरी सेक्टर' रखा गया था। 18 फरवरी 1808 में 'इण्डिया हाऊस' का लजनहाल स्ट्रीट लन्दन में स्थित किया गया। प्रमत्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण पाण्डिया, पाण्डुलिपिया, मूर्तियाँ, एवं दुर्लभ ग्रन्थ सामग्री यहाँ आकर जमा हो गई।

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के बाद देश भर की घरघरी एवं फारसी भाषा की पाण्डुलिपियाँ एवं पुस्तकें भी इस पुस्तकालय में अंग्रेजी में पहुँचा दीं। इस पुस्तकालय में लगभग 2 लाख पुस्तकें हैं, जिसमें 60,000 पुस्तकें अंग्रेजी एवं यूरोपीय भाषाओं की हैं, शेष प्राच्य भाषाओं की। भारतीय प्राच्य संस्कृति एवं साहित्यिक ज्ञान का यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है।

इस पुस्तकालय में भारतीय ज्ञान संग्रह के पाँच विभाग बनाये गये हैं जिनमें प्रथम (1) मुद्रित ग्रन्थ विभाग (2) हस्तलिखित ग्रन्थ विभाग (3) भारतीय चित्रकला विभाग (4) फोटा एवं अन्य दुर्लभ वस्तु संग्रह। ये सभी विभाग संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, तिब्बती, खोतानी, बंगला, गुजराती, मराठी, उडिया एवं पश्चिमी भाषा के ग्रन्थों एवं चित्रकला के संग्रह से परिपूर्ण हैं। फोटा विभाग में भारतीय शिल्प वस्तुकला और पुरातत्त्व से सम्बन्धित लगभग 2300 निगटिव प्लेट्स और लगभग 30,000 विभिन्न चित्रों का संग्रह एकत्रित है। इसमें 95 भाषाओं की पुस्तकें सुरक्षित हैं।

वर्तमान में यह पुस्तकालय किंग चार्ल्स स्ट्रीट स्थित "ग्रेट हाऊस" में स्थापित है। भारत सरकार इन दुर्लभ ग्रन्थों को वापस अपने देश मगाने के कई बार प्रयास कर चुकी है किंतु सफलता नहीं मिल सकी है। ये ही गौरव ग्रन्थ विदेशों में भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास एवं साहित्य के अध्ययन के मौलिक ग्रन्थ हैं जिनके सहारे भारत से अधिक भारत की जानने में विदेशियों ने सफलता प्राप्त की।

(2) राष्ट्रीय पुस्तकालय कसकत्ता (National Library)—यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जिसे इम्पीरियल लायब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 8 मार्च 1836 को हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज से प्राप्त 4675 पुस्तकों से इसका शोध शुरु हुआ था। 20 अप्रैल 1890 को नगर पालिका समिति ने इसका प्रशासन अपने हाथ में लिया और जुलाई में एक निःशुल्क वाचनालय खोला। चलते फिरते वाचनालय (Mobile Reading Room) के साथ एक रिफरन्स लायब्रेरी की भी स्थापना की गई। बंगाल सरकार ने 5 हजार रुपये का अनुदान पुस्तकालय के पुनर्गठन एवं व्यवस्थापन हेतु दिया।

वलक्ता पब्लिक लायब्रेरी एव इम्पीरियल लायब्रेरी दोनों को 1902 में मिला दिया गया और नये सिरे से पुस्तकालय पत्रक सूचिया तैयार की गई। 30 जनवरी 1903 को जन-सामाजिक सेवा के लिये इसे मुक्त द्वार प्रणाली (Open Door System) से युक्त कर दिया। पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकान्याध्यक्ष ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष श्री जॉन मैक फारलेन बनाये गए। पुस्तकालय प्रमश इनकी योग्यता, अनुभव और कार्यपटुता से प्रसिद्धि प्राप्त करता गया। 1904 में दरभंगा के जमींदार सैयद सदरुद्दीन अहमद का निजी संग्रह पुस्तकालय को भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ। इसमें 1500 छप हुई तथा 850 हस्तलिखित ग्रंथ थे।

इसकी सिल्वर जुबली 9 फरवरी 1953 को मनायी गयी, तभी "डिलिवरी आफ बुक्स एक्ट" द्वारा भारतीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित ग्रंथों की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजने का कानून अनिवार्य कर दिया। एक्ट को पास हुए 26 वर्षों में किंतु भारत में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक पुस्तकें एवं समाचार पत्र शायद ही पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ भेजे जाते हैं। पुस्तकालय का आधुनिकतम तरीका से सज्जित एवं तकनीकी दृष्टियों से व्यवस्थित किया गया है। वर्तमान में पुस्तकालय की संग्रह संख्या लगभग 14 लाख करीब है। अध्ययन कक्ष में एक साथ दो सौ लोगों के बैठने का व्यवस्था है। 350 के लगभग कमचारी कार्यरत हैं। देश की 14 भाषाओं की पुस्तकें यहां संग्रहित हैं।

(3) आसफिया स्टेट लायब्रेरी हैदराबाद—

यह पुस्तकालय 1871 में हैदराबाद रियासत में स्थापित किया गया था। इस पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की 9 लाख पुस्तकें, 13, 804 दुर्लभ ग्रंथ जो पाचमेट पत्र (बमडे का बना हुआ) एवं हिरण की खान पर बने हुए हैं। ये दुर्लभ ग्रंथ शीघ्र सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत छात्रों, अनुसंधानकर्त्ताओं के उपयोगाक्षित तत्काल अध्ययन हेतु दिये जाते हैं। लगभग दो हजार की एक पुस्तक में पूर्ण गीता लिखी हुई है जो यहां उपलब्ध है। 1487 ए. डी की एक अनुपम पुस्तक इस पुस्तकालय में सुरक्षित है। सबसे प्राचीन 1072 ए. डी की प्रकाशित पुस्तक इस पुस्तकालय का विशेष आकर्षण है। यहां पर 15वीं शताब्दी की एक पुरानी पुस्तक "इण्डस्ट्रीयल साइंस" रखी हुई है जिसमें कागज एवं स्याही बनाने की विधियां दी गई हैं। यह कोयल पैदा करने वाली दुर्लभ पुस्तक भारतीय सभ्यता की प्रगति की प्रतीक है।

चूंकि हैदराबाद रियासत एक समय की समृद्धशाली रियासत थी और व्यापार, व्यवसाय एवं साहित्यिक गतिविवियों में भी अग्रणी रही। पाचमेट पत्र की पुस्तक का होना इस बात की प्रतीक है कि भारत के ग्राहरी दशों से व्यापारिक सम्बंध थे तभी ये ग्रंथ यहां तक आये। हैदराबाद का ही सालाराम म्यूजि-

विया या जो उस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कुशल इतिहासकार था। यह आफिम ब्रिटिश शासन काल में भारत की गतिविधियाँ का लेखा जाँचा रखने का मन्त्रि स्यल था। इसकी स्थापना ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा 1809 में की गई थी। 1946 के बाद से इस पुस्तकालय को वामनबेत्थ सम्बन्धी पुस्तकालय वायालय के नाम से पुकारा जाता है। इसका उपयोग केवल नियमित पाठ्य या छात्र सदस्यों को ही करने दिया जाता है।¹⁵ इण्डिया आफिम लायब्रेरी बनने के पूर्व इसका नाम "पब्लिक रिपोजिटरी सेंटर" रखा गया था। 18 फरवरी 1808 में 'इण्डिया हाऊस' को लज्जाहाल स्ट्रीट लंदन में स्थित किया गया। प्रमत्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण पौधिया, पाण्डुलिपियाँ, मूर्तियाँ, एवं दुर्लभ ग्रन्थ सामग्री यहाँ आकर जमा हो गई।

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के बाद दश भर की अरबी एवं फारसी भाषा की पाण्डुलिपियाँ एवं पुस्तकें भी इस पुस्तकालय में अंग्रेजों ने पहुँचा दी। इस पुस्तकालय में लगभग 2 लाख पुस्तकें हैं, जिसमें 60,000 पुस्तकें अंग्रेजी एवं यूरोपीय भाषाओं की हैं शेष प्राच्य भाषाओं की। भारतीय प्राच्य सस्कृति एवं साहित्यिक ज्ञान का यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है।

इस पुस्तकालय में भारतीय ज्ञान मण्डल के पाँच विभाग बनाये गये हैं जिनमें प्रथम (1) मुद्रित ग्रन्थ विभाग (2) हस्तलिखित ग्रन्थ विभाग (3) भारतीय चित्रकला विभाग (4) फोटो एवं अन्य दुर्लभ वस्तु संग्रह। ये सभी विभाग सम्पूत, अरबी फारसी, उर्दू, तिब्बती, खोतानी, बंगला, गुजराती, मराठी, उडिया एवं पश्तो भाषा के ग्रन्थों एवं चित्रकला के संग्रह से सम्पूत हैं। फोटो विभाग में भारतीय शिल्प वस्तुकला और पुरातत्त्व से सम्बन्धित लगभग 2300 निगेटिव प्लेट्स और लगभग 30,000 विभिन्न चित्रों का संग्रह एकत्रित है। इसमें 95 भाषाओं की पुस्तकें सुरक्षित हैं।

वर्तमान में यह पुस्तकालय किंग चार्ल्स स्ट्रीट स्थित 'ग्वाइट हाऊस' में स्थापित है। भारत सरकार इन दुर्लभ ग्रन्थों को वापस अपने देश मगाने के कई बार प्रयास कर चुकी है किन्तु सफलता नहीं मिल सकी है। ये ही गौरव ग्रन्थ विदेशों में भारतीय-सस्कृति, धर्म, इतिहास एवं साहित्य के अध्ययन के मौलिक ग्रन्थ थे जिनके सहारे भारत से अधिक भारत को जानने में विद्वानों ने सफलता प्राप्त की।

(2) राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता (National Library)—यह भारत का एवमान राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जिस इम्पीरियल लायब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 8 मार्च 1836 को हुआ थी फोर्ट विलियम कालेज से प्राप्त 4675 पुस्तकों से इसका श्री गणेश हुआ था। 20 अप्रैल 1890 को नगर पालिका समिति ने इसका प्रशासन अपने हाथ में लिया और जुलाई में एक निशुल्क वाचनालय खोला। चलते फिरते वाचनालय (Mobile Reading Room) के साथ एक रिफरन्स लायब्रेरी की भी स्थापना की गई। बंगाल सरकार ने 5 हजार रुपये का अनुदान पुस्तकालय के पुनर्गठन एवं व्यवस्थापन हेतु दिया।

कलकत्ता पब्लिक लायब्रेरी एव इम्पीरियल लायब्रेरी दोनों को 1902 में मिला दिया गया और नये सिरे से पुस्तकालय पत्रक सूचिया तैयार की गई। 30 जनवरी 1903 को जन-सामान्य की सेवा के लिये इसे मुक्त द्वार प्रणाली (Open Door System) से युक्त कर दिया। पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष श्री जॉन मैक फारलेन बनाये गये। पुस्तकालय क्रमशः इनकी योग्यता, अनुभव और कार्यपटुता से प्रसिद्धि प्राप्त करता गया। 1904 में दरभंगा के जमींदार सैयद सदरुद्दीन अहमद का निजी संग्रह पुस्तकालय को भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ। इसमें 1500 छपे हुई तथा 850 हस्तलिखित ग्रंथ थे।

इसकी सिल्वर जुबली 9 फरवरी 1953 को मनायी गयी, तभी "डिलिवरी आफ बुक्स एक्ट" द्वारा भारतीय प्रकाशका द्वारा प्रकाशित ग्रंथों की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजने का कानून अनिवार्य कर दिया। एक्ट को पास हुए 26 वर्ष हो चुके हैं किंतु भारत में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक पुस्तकें एवं समाचार पत्र शामद ही पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ भेजे जाते हैं। पुस्तकालय को आधुनिकतम तरीके से सज्जित एवं तकनीकी दृष्टीया से व्यवस्थित किया गया है। वर्तमान में पुस्तकालय की संग्रह सरया लगभग 14 लाख करीब है। अध्ययन कक्ष में एक साथ दो सौ लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 350 के लगभग कमचारी कार्यरत हैं। देश की 14 भाषाओं की पुस्तकें यहाँ संग्रहित हैं।

(3) आसफिया स्टेट लायब्रेरी हैदराबाद—

यह पुस्तकालय 1871 में हैदराबाद रियासत में स्थापित किया गया था। इस पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की 9 लाख पुस्तकें, 13, 804 दुर्लभ ग्रंथ जो पाचमेट पेपर (चमड़े का बना हुआ) एवं हिरण की खाल पर बने हुए हैं। ये दुर्लभ ग्रंथ शीघ्र सन्दर्भ सेवा के अतगत छात्रों, अनुसंधानकर्त्ताओं के उपयोगाक्षित तत्काल अध्ययन हेतु रिये जाते हैं। लगभग दो डेढ़ की एक पुस्तक में पूर्ण गीता लिखी हुई है जो यहाँ उपलब्ध है। 1487 ए. डी. की एक अनुपम पुस्तक इस पुस्तकालय में सुरक्षित है। सबसे प्राचीन 1072 ए. डी. की प्रकाशित पुस्तक इस पुस्तकालय का विशेष आकर्षण है। यहाँ पर 15वीं शताब्दी की एक पुरानी पुस्तक "इण्डस्ट्रीयल साइंस" रखी हुई है जिसमें कागज एवं स्याही बनाने की विधियाँ दी गई हैं। यह कौतूहल पैदा करने वाली दुर्लभ पुस्तक भारतीय मस्तिष्क की प्रगति की प्रतीक है।

चूँकि हैदराबाद रियासत एक समय की समृद्धशाली रियासत थी अन्न व्यापार व्यवसाय एवं साहित्यिक गतिविधियाँ भी प्रचलित रही। पाचमेट पेपर की पुस्तकें का होना इस बात की प्रतीक है कि भारत के ग्राहरी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध थे तभी ये ग्रंथ यहाँ तक आये। हैदराबाद का ही मान्यारनग म्यूजि-

यम भागत का विशाल एक व्यक्ति द्वारा मग्रहित संग्रहालय है जो प्राचीन सस्कृति एवं कला का अनूठा संगम है ।

(4) माणिक्य स्मारक वाचनालय खण्डवा—

राष्ट्र प्रसिद्ध वीर योद्धा एवं यशस्वी साहित्यकार दादा भाग्यनलाल चतुर्वेदी की नगरी खण्डवा में 1883 में हरिनाथ चटर्जी के सभापतित्व में “मारिस टेस्टोमार्ईनक फण्ड कमटी” की स्थापना हुई । श्री चटर्जी के ही प्रयास से “मारिस ममोरियल लायब्रेरी” आरम्भ हुई ।

यद्यपि भारत में उस समय अंग्रेजों का सघन साम्राज्य छाया हुआ था । उन्होंने ज्ञानवर्धन के लिए देश भर में नेटिव लायब्रेरीज की स्थापना की थी । इसी प्रकार की लायब्रेरी मण्डलेश्वर राज्य में थी जो 1881 में ही खण्डवा लायी गयी थी । ‘उक्त लायब्रेरी को किराये के मकान में संचालित किया जाता था । लेकिन भवन निर्माण के उपरान्त यही लायब्रेरी मारिस ममोरियल लायब्रेरी में समाहित कर दी गई ।’¹⁶

स्व श्री हरिनाथ जी चटर्जी की धर्मियतनामे के अनुसार 5 000 रु बाचनालय को प्राप्त हुए थे । उसी समय के खण्डवा के प्रसिद्ध अभिवक्ता स्व श्री माणिक्य चंद जी जैन की स्मृति में स्वाधीनता के उपरान्त इस वाचनालय का नाम “माणिक्य स्मारक वाचनालय” रखा गया । उनके निकट सम्बन्धी श्री विमलचन्द्र जैन ने उत्साहपूर्वक इस पुस्तकालय को 2500 रुपये की धन राशि प्रदान की ।

लोगों के व्यक्तिगत दान से भी इस पुस्तकालय का कई पुस्तकें प्राप्त हुई ।

1937 में, स्व श्री भगवन्तराव जी मण्डलाई की प्रखर सूक्त वृक्ष से 14 000 रु की धन राशि ग्रहण स्वरूप लेकर वाचनालय के निम्न भाग में बैंक का निर्माण हुआ । जो कि आग चलकर वाचनालय की आय का स्रोत बना ।¹⁷

1948 में भवन की प्रथम मजिल के निर्माण में 1100 रु की धन राशि तुलसी पुण्य तिथि उत्सव समिति खण्डवा ने प्रदान किये ।¹⁸

तत्कालीन केन्द्रिय वार्षिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विभाग में श्री स्व हुमायूँ कबीर का कदापि विस्मृत नहीं कर सकते जिन्होंने वाचनालय के कला भवन के विस्तार हेतु 8000 रु की धनराशि केन्द्रीय शासन से उपलब्ध करायी थी । सन् 1960-61 से जिला शिक्षा अधिकारी, नगर पालिका परिषद् तथा जनपद सभा से अनुदान प्राप्त होता है । इन अनुदानों में जनपद सभा खण्डवा द्वारा प्रति वर्ष 500 रु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 500 रु तथा नगर पालिका परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष 1000 रु नियमित रूप से प्राप्त होता है । केन्द्रीय शासन से 1960-61 एवं 1967-68 में सिर्फ 2000 रु की राशि का अनुदान हुआ ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा आयोग 46 पुस्तकें निशुल्क प्राप्त हुई हैं । वाचनालय 5 से 18 अंग्रेज तक वाचनालय भवन में किये

इस वष वाचनालय समिति ने 1969-70 का नवीनतम "ब्रिटैनिका विश्व कोश" के समस्त खण्ड खरीदे जिसके अध्ययन की सुविधा भी वाचनालय में की गई है।¹⁰ केन्द्रीय राज्य शिक्षा मंत्री श्री भक्त वत्सल ने इसकी हीरक जयन्ती समारोह के समापन पर कहा था "देश में कई समस्याओं की अकाल मृत्यु हो जाती है। इस वाचनालय के कार्य-वर्त्ता गए एव खण्डवा के नागरिक धर्मवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस सस्था को 86 वर्ष जीवित रखकर अकाल मृत्यु से बचा लिया।¹¹ और आज यह समाज सेवा सस्था अपने सौ वर्ष पूरे करने जा रही है। इन गौरवशाली वर्षों में जिन नव्य प्रतिष्ठित नेताओं, साहित्यकारों एवं दार्शनिक व्यक्तियों ने इस वाचनालय को एक श्रेष्ठ स्थान दिया यह उनकी ही वारणी में इस प्रकार है।

"फारिस मेमोरियल लायब्रेरी जैसी प्राचीन सस्था का निरीक्षण कर मुझे बड़ा हृष हुआ है। खण्डवा नगर के शिक्षित समाज की जितनी प्रशंसा की जाये, इस पुस्तकालय के चलाने के लिए वह छोटी है। मैं पुस्तकालय की उत्तरोत्तर उत्थिति की शुभकामना करता हूँ।"¹²

वाचनालय को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें पुस्तकों का चुनाव अध्ययन की सुंदर व्यवस्था और कार्यकर्त्ताओं का अदम्य साहस देखकर खण्डवा नगर की सांस्कृतिक चेतना का आभास मिला। इतने छोटे से नगर में इस प्रकार की जागरूकता और कमठता का देखकर मैं चकित हूँ। मा. भारती के निष्ठावान सेवकों को हृदय से साधुवाद देता हूँ।¹³

शिवमंगल सिंह सुमन इस प्रकार इस पुस्तकालय को श्री जयप्रकाश नारायण, पुरुषोत्तमदास टण्डन भुवनेश्वर प्रसाद सिंहा, नन्द दुनोर वाजपयी, विद्योगी हरि, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय इत्यादि महापुरुषों ने अपने आशीर्वाद से सुशोभित किया।

वर्तमान में इस पुस्तकालय में लगभग 20,000 ग्रंथ हैं। हिन्दी दैनिक 13, हिन्दी मासिक 20, अंग्रेजी 4 पाक्षिक 10 साप्ताहिक, हिन्दी रमराठी 16 पत्र एवं पत्रिकाएँ आती हैं। इसकी सदस्य संख्या 1500 है। प्रतिदिन 200 पाठक अध्ययन का लाभ लेते हैं। एक दिन में प्रातः 8 से 11 एवं शाम 5 से 8 बजे तक पचास से 60 पुस्तकें निगमित होती हैं। पुस्तकालय में बाल विभाग एवं महिला विभाग की स्वतंत्र व्यवस्था है। एक चलित महिला वाचनालय भी है। जिसका उद्घाटन 11 त्रिपाठी महिला वर्ष में श्रीमती एम. एम. कुच द्वारा किया गया था। 22-9-59 से पुस्तकालय के विशेष वाचनालयों में कृति दर्पण एवं समीक्षा दर्शन का भी समावेश किया गया है। पुस्तकालय में 1930 के पूर्व के अलेखों का इस वाचनालय में अभाव है।

प्रारम्भ से अभी तक बालकों के समागम विकास को दृष्टिगत रखते हुए बालकों के लिए निःशुल्क पुस्तक प्रदान प्रणाली अपनायी जाना गयी है। यह इस

पुस्तकालय की गौरवशाली विशेषता है। इस प्रकार म प्र का प्रति प्राचीन साव जनिक किन्तु सामाजिक साम्प्रतिक एवं राजनैतिक चेतना का केन्द्र यह पुस्तकालय लोक हिताय महत्वपूर्ण है। ऐसे सभी पुस्तकालयों पर शासन को ध्यान देना चाहिये।

इस पुस्तकालय के विकास पर जितना शासन न ध्यान नहीं दिया उमस वही बढ़कर यही की जाता नेता साहित्यकार एवं अधिकारी वर्ग ने महत्व दिया सजाया सवार है। भद्रिप्य म यदि इस लोक पुस्तकालय म प्रौढ पाठशालाओं का काम भी हो तो इसकी उद्देश्य पूर्ति सही प्रथो म हा सन्ती है। इस ओर शिक्षित समाज क जिम्मेदार लोगो को साचना चाहिए। इसी सेवाना का ओर अधिक विस्मृत किया जाना चाहिए।

(5) केन्द्रीय पुस्तकालय बडौदा—

भारत म बडौदा वह पहला राज्य है जहाँ दश मे सवप्रथम शिक्षा के महत्त्व का समझन एवं जनता म पान की विभिन्न शाखा प्रशाखाओं के प्रति जाग्रति लान हेतु 1910 मे तत्कालीन महाराज सर सयाजीराय गायकवाड न पुस्तकालय के विकास एवं उनके आन्वेषण को आम बढान का सूत्रपात किया। बडौदा स्टेट, शहर एवं जनता की सुशाली ओर शिक्षा के विकास हेतु एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई। प्रारम्भ म इसे बडौदा स्टेट पुस्तकालय कहत थे। बडौदा महाराज न इस पुस्तकालय क लिय 20,000 रुपय ग्रन्थो का संग्रह भेंट किया। इस केन्द्रीय पुस्तकालय का पूरा व्यय राज्य की ओर स दिया जाता था। पुस्तकालय सवा जनता के लिये निरुक्त थी। पुस्तकालयाध्यक्ष बोडन महोदय ने यहाँ वर्गीकरण, सूचीकरण की पद्धतिया को अपनाकर सदन सेवा को अधिक महत्व दिया। इस पुस्तकालय से सम्बद्ध कई चल पुस्तकालयो (Traveling Library) का निर्माण किया गया जो दूर दूर तक गावो म पुस्तकें पहुँचाने का काम किया करते थे।

पुस्तकालय मे भाषा सग्या के आधार पर दो प्रमुख भाषा मराठी एवं गुजराती के बड विभाग कर दिये किन्तु भाषा एवं शिक्षा की व्यापकता के कारण क्रमश पुस्तकालय मे अंग्रेजी भाषा की 51,677 40,380 गुजराती की पुस्तकें, 31907 मराठी की पुस्तकें, 4681 हिन्दी की एवं 1817 पुस्तकें उर्दू एवं भाषा साहित्य की थी। इस प्रकार कुल मिलाकर इस पुस्तकालय की संग्रह सग्या 1,30784 हो गई, वतमान म लगभग 2 लाख तक ग्रन्थ सरया पहुँच चुकी है।

श्री बोडन महोदय इस पुस्तकालय विकास योजना के अध्यक्ष नियुक्त किय गये। इस प्रकार धीरे धीरे बडौदा राज्य म 1946 तक 1500 सस्थायें हो गई जिनमे 4 जिला पुस्तकालय 72 तालुका एवं नगर पुस्तकालय ओर शेप ग्राम पुस्तकालय एवं पाचनालय थे। बोडन महोदय जिहे महाराजा गायकवाड अमेरिका स लेकर आय थे की देख रेख म ही इस पुस्तकालय भवन का निर्माण हुया। पश्चात्य

शैली से निर्मित इस भवन में अत्याधुनिक ढंग की ग्रंथ भण्डार व्यवस्था को महत्व दिया गया। पुस्तकालय में सभी भाषों के विभाग भिन्न भिन्न रखे गये। वाचन एवं पत्र पत्रिका विभाग भी सुंदर ढंग से स्वतंत्र व्यवस्थापित किये गये। 1910 में ही बोडन साह्य ने पुस्तकालय-विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जिससे राज्य भर में प्रशिक्षित ग्रंथपाल नियुक्त किये जा सके। बालका के अध्ययन को महत्व देने हेतु बाल पुस्तकालय कक्ष को मनमोहक एवं आकर्षक बनाया गया ताकि बालक अधिक सग्या में आकर मन को रमाये। कक्ष का आकर्षण बच्चा के मन लाभदायी सिद्ध हुआ और सैकड़ों बच्चे पुस्तकों पढ़कर लाभ उठाने लगे।

बड़ौदा स्टेट में प्रारम्भ में गाँव पुस्तकालय प्रायः गाँवों की पाठशालाओं में खोले गये थे। लेकिन धीरे-धीरे सन् 1930 से उनके लिये स्वतंत्र भवन बनवाने के लिये पुस्तकालय विभाग न महायत्न देनी शुरु की तो सन् 1946 तक 194 पुस्तकालयों के अपने निजी भवन भी हो गये थे। इस प्रकार इस राज्य में पुस्तकालयों का विकास अत्यन्त क्रमबद्ध रूप से नियोजित होता रहा।

(6) मुदाबर्गेश औरियन्ट पब्लिक लायब्रेरी पटना—

पूर्वी भारत का यह महत्वपूर्ण पुस्तकालय अरबी, फारसी, उर्दू एवं संस्कृत के प्राचीन और दुर्लभ पाण्डुलिपियों के संग्रह की दृष्टि से इस क्षेत्र का श्रेष्ठ प्राप्ति पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय की स्थापना सन् 1888 में हुई थी। प्रारम्भ काल में इस पुस्तकालय में केवल 6500 पुस्तकें थी जिनमें 400 पाण्डुलिपियाँ थी। सन् 1981 में देसला (बिहार) के अल इसलव पुस्तकालय द्वारा 7000 पुस्तकों के दान में इस पुस्तकालय में पुस्तकों की सग्या बढ़ी।

वर्तमान काल में मुदाबर्गेश औरियन्ट पब्लिक लायब्रेरी में पाण्डुलिपियों मुद्रित पुस्तकें, पत्रिकाएँ तथा समाचार पत्रों की कुल संख्या 49,898 है जिसमें अरबी पाण्डुलिपि 4,106 फारसी पाण्डुलिपि 3,883 उर्दू पाण्डुलिपि 283, हिन्दी और संस्कृत पाण्डुलिपि 35 तुर्की पाण्डुलिपि 20 ताइ पन पर लिखी पाण्डुलिपि 200, अरबी, फारसी और उर्दू पुस्तकें 23,944, अंग्रेजी पुस्तकें 9682 जर्मन पुस्तकें 982 फ्रेंच पुस्तकें 875 लेटिन पुस्तकें 12 इटालियन पुस्तकें 3 स्पेनिश पुस्तकें 21 पत्र पत्रिकाएँ एवं समाचार पत्र 5911 हैं। इस पुस्तकालय में 1269 ई की रची एक कुरान की प्रति सुरक्षित है।

उपरोक्त विवरण यह स्पष्ट करता है कि यह पुस्तकालय, अरबी, फारसी, मध्यकालीन एवं भारतीय इतिहास एवं इस्लामी संस्कृति के ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पाण्डुलिपि विभाग एवं वाचनालय कक्ष में प्रतिदिन आने वाले पाठकों की संख्या क्रमशः 20 और 50 है। शोध एवं अनुसंधान के लिए पाण्डुलिपियाँ फोटो स्टेट प्रतियों, माइक्रो फिल्म इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

इसकी उपयोगिता और इसके अन्तराष्ट्रीय महत्व का ध्यान में रखते हुए इसे 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाने के लिए सार्वजनिक में विधेयक स्वीकृत किया

गया है। इस प्रकार के विधेयक प्रत्येक राज्य में स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मृति के साहित्य संरक्षक पुस्तकालयों के लिए पास होना चाहिये ताकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा हो सके।

(7) भण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुस्तकालय पूना—

इस प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर की स्थापना 6 जुलाई 1917 को डा. सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर के 80 वें जन्म दिन पर उनके मित्रा एवं शिष्या के सद्प्रयास से हुआ था। संस्थान के उद्घाटन के दिन ही डॉ. भण्डारकर ने अपने निजी ग्रंथों एवं शोध पत्रिकाओं का बहुमूल्य 2600 ग्रंथों का विशाल संग्रह संस्था का भेंट कर दिया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगभग 20,000 हस्तलिखित संस्कृत एवं प्राकृत ग्रंथों का दुर्लभ संग्रह संस्था का दिया। अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद् की योजना को क्रियाविस्त करने हेतु पूना में प्रथम अधिवेशन किया और मेधावी युवकों की शास्त्र शुद्ध शोध पद्धति सिखाकर सहायन कार्य के लिये स्नातकोत्तर अध्ययन और संशोधन विभाग प्रारम्भ किया सम्प्रति आज तक निरंतर गतिशील है। अति प्राचीन ग्रंथों, दुर्लभ पाण्डित्य की फाटा कापी कर यहां सुरक्षित रख ली गई हैं। इन पाण्डित्यों की शोध स्तर पर आवश्यकता होती है तो इनकी पुनर्फोटो कापी बनाकर माइक्रो फिल्म रूप में स्वयं के खर्च पर अनुसंधानकर्ता को भेजी जाती है। अभी तक इस प्रकार का लेन देन विदेशों से भी बहुत हुआ है। यह संस्थान शोध अनुसंधान का शास्त्रोक्त दृष्टि से भारत में अनूठा केन्द्र है।

(8) नेटिव सेट्टल लायब्रेरी धारवार —

ब्रिटिश शासन की नींव जमाने के बाद, बम्बई मद्रास हैदराबाद एवं कर्नाटक में शिक्षा हेतु सब प्रथम दृवली एवं धारवार में 1826 में स्कूल खोले गये। इन स्कूलों के खुलने के साथ ही लोगों में साक्षरता बढ़ी अतः उन्हें स्थायी बनाने हेतु पुस्तकालयों की आवश्यकता महसूस की गई। अतः सर्वप्रथम एक शिक्षक के सद्प्रयास से सन् 1854 में धारवार नेटिव सेट्टल लायब्रेरी की स्थापना की गई। 1882 में इस पुस्तकालय में 451 पुस्तकें थी जिसमें 414 अंग्रेजी 30 मराठी और 7 बंनड की थी। ये पुस्तकें चंदे से ही प्रय की गई थी। पुस्तकालय में कोई व्यवस्थित कार्य प्रणाली का अनुसरण नहीं होता था दो अंग्रेजी मुखवार इसमें आते थे, और कुछ सदस्यों के द्वारा भेंट कर दिये जाते थे। ये सभी पत्र अधिकांश अंग्रेजी के होते थे। उसी समय धारवार में “म्युनिसिपल जनरल लायब्रेरी” भी चलती थी। 1920 में धारवार में ही “संतेस धर्माथ” वाचनालय की स्थापना की गई।

(9) कोनेमारा (स्टेट केन्द्रीय) लोक पुस्तकालय मद्रास²⁸—

यह पुस्तकालय भारतीय स्वाधीनता के पूर्व का, मद्रास राज्य का, साथ ही भारतवर्ष के ब्रिटिश काल का चौथा या पाचवें क्रम का प्राचीनतम पुस्तकालय है। इस

पुस्तकालय की स्थापना साठ बौनेमारा के शासनावाल 1886-1891 में जब वे मद्रास राज्य के राज्यपाल थे व नाम से हुई थी। एंग्लो इटालियन पद्धति से इसकी संरचना की गई और 5-12-1896 को मद्रास सरकार की मांग पर चोला गया था।

स्वाधीनता के उपरान्त 1948 के मद्रास लोक पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार जो कि 1 अप्रैल, 1950 से प्रभावित हुआ इस 'स्टेट सेटल लायब्रेरी' का दर्जा दे दिया गया। 10 सितम्बर, 1955 से इस पुस्तकालय को भारत के तीन प्रमुख सांख्यिक पुस्तकालयों में से एक घोषित कर दिया गया। 1954 के 'डिलिवरी ब्राफ बुक्स अधिनियम' के प्रावधानानुसार 10 मई, 1954 को या इसका बाद जो भी सामग्री भारत में प्रकाशित होगी वह इस पुस्तकालय को मिलेगी। 15 सितम्बर 1965 से यह यूनेस्को रेफरेंस केंद्र के रूप में सेवा कर रहा है। 21-3-1966 से इसे पुस्तकालय विभाग संस्थान की एक विंग से जोड़ा था। यह यू एन आ क सभी ग्रो एव एजेंसीओ के प्रकाशन का भी एक महत्वपूर्ण डिपॉजिटरी सेंटर है। सन् 1973 की 7 अगस्त से बाल विभाग का कार्य भी इस पुस्तकालय में प्रारम्भ किया गया है।

इस पुस्तकालय में एक समय में 340 पाठक बैठकर अध्ययन करत हैं इतनी क्षमता का पुस्तकालय वाचनालय कम है। लोक पुस्तकालय अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष इस पुस्तकालय को 8,870 पुस्तकें 3686 पत्रिकाएँ एवं 249 समाचार पत्र प्राप्त होते हैं। यहां पुस्तक संग्रह, भ्रमणार्थी, सम्मेलन एवं पुस्तकों के उपयोग का लेखा भी रखा जाता है जिससे यह सामग्री में पता लगा जाना है कि सदस्य पाठक ने किस समय किसकी और कौनसी पुस्तकें ली हैं, उन उन्हें कौन लौटाना है। इस तरह ध्यानुको द्वारा इसी गद व सम्मेलन पाठकों द्वारा न जाद गद पुस्तकों की पूर्ण लेखा पंजी यहां रिकार्ड रूप में रखा जाना है। इस प्रकार के कार्य में ग्रन्थी का योग्यता का इच्छित ध्यान देकर करना ही ठीक माना है।

इस प्रकार बानमारा सांख्यिक पुस्तकालय का अब गणराय पुस्तकालय का प्रमुख अंग बन गया है वर्तमान में इन पुस्तकों की संख्या 2,96,715 है जिसमें 54,809 पत्रिकाओं व सजिन्त प्रकाशनों हैं। इन पुस्तकालय के सम्मेलन की संख्या 1,11,08 है। सन् 1977-78 में इन पुस्तकालयों पर 1,90,000 रुपये खर्च किए गये, स्थापना विभाग में 3,67,700 एवं ग्रन्थियों में 30,500 रुपये खर्च किया। कुल मिलाकर 5,88,200 रुपये पुस्तकालय के व्यवस्थापन में खर्च हुए। तमिलनाडु सरकार का ध्यान इस पुस्तकालय को जानने के लिए सामान्य नियम है जिन्हें प्रत्येक पुस्तकालय को पालना है।

(अ) सामान्य नियम—

(2) पुस्तकालय में

113.35

9/5/62

अन्य दिन के अवकाश हेतु प्रति नियुक्त अधिकारी द्वारा सप्ताह के नोटिस पर "फोटो स्टैंड जाज गजट" एवं पुस्तकालय सूचना पट्ट पर सूचना लगा दी जाती है।

(2) पुस्तकालय के खुलने का समय प्रातः 10-30 से 8 बजे शाम तक होगा।

(3) 17 वर्ष से कम आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुमति के बिना पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

(4) सदस्य इसी शर्त पर पुस्तकालय में प्रवेश करेंगे कि वे स्वच्छ कपड़े एवं स्वस्थ मन वाले हों।

ऐसे ही अनिवार्य व सामान्य नियमों का पालन कर ग्रन्थालय सेवा को अधिक साधक बनाने में यहाँ के कर्मचारीगण एवं सदस्यगण सभी अनुकूल प्रयास करते हैं।

बहुत समय से इस ग्रन्थालय का भारत सरकार का राष्ट्रीय केन्द्रीय ग्रन्थालय घोषित कर दिया गया था जिसे राष्ट्रीय ग्रन्थालय जैसे ही कार्यक्रम अपने क्षेत्र में सम्पन्न करने थे। इस कार्य में ग्रन्थालय कहाँ तक सफल हो सका है इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी फिर भी यह ग्रन्थालय देश का बहुत बड़ा सांख्यिकीय ग्रन्थालय है जिस पर हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए।

(10) सेट्टल स्टेट लायब्रेरी भोपाल-5—

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का यह केन्द्रीय पुस्तकालय है जिसे 'मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय' के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तकालय की स्थापना स्वाधीनता के बाद 13 अगस्त 1955 को की गई थी। भोपाल राज्य में पूर्व से स्थापित हमीदिया लायब्रेरी जो 1818 में स्थापित हुई थी, उसकी हजारों पुस्तकें (जिनकी सूची देना यहाँ उपयुक्त नहीं लगता) एवं साज-सामान इस पुस्तकालय को दिया गया।

मुल्तान जहा वेगम को हमीदिया स्टेट लायब्रेरी की उक्त पुस्तकें देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यह पुस्तकालय स्वाध्याय व जन रचि के अध्ययन का एक केन्द्र बन गया। स्थापना के समय इस पुस्तकालय में सिर्फ 3500 पुस्तकें उपलब्ध थीं किन्तु इनकी तुलना में सदस्यों की संख्या एक हजार थी। इस बात से यह अदार्श सहज ही लग जाता है कि आज के पाठकों की तुलना में आज से 24 वर्ष पूर्व के पाठक अधिक अध्ययनशील थे और स्वाध्याय के लाभ को जानते थे। इसके विपरीत वर्तमान में हम देखें तो हमें पता चलता है कि पुस्तकालय के पास परिपुष्ट पुस्तक भण्डार (62,260) है किन्तु पाठकों की संख्या मात्र 2118 ही रह गई है, अर्थात् 24 वर्ष में इस पुस्तकालय में पाठकों ने दोगुनी वृद्धि का श्रेय पाया है।

पुस्तकालयों के विकास में दिनोदिन वृद्धि होती जा रही है किन्तु हमें देखने में आ रहा है कि पाठकों में पुस्तकालयों में अध्ययन की रचि कम एवं ठलो व पॉकेट बुक्स, उपन्यासी पुस्तकों के पढ़ने में अधिक बढ़ती जा रही है।

भोपाल राजधानी के इस केन्द्रीय पुस्तकालय में प्रतिदिन 150 पुस्तकों का आगमन निगमन होता है। सदस्य पाठकों के अध्ययन हेतु 200 सीटों की क्षमता वाला एक उपकरण (फर्नीचर) युक्त कमरा उपलब्ध है। पुस्तकालय में मुक्त द्वार प्रणाली (open Access System) की व्यवस्था है जिसके द्वारा पाठक अपनी स्वयं की इच्छा से ग्रंथ भण्डार में जाकर अपनी इच्छित पुस्तक प्राप्त कर पढ़ सकता है और यदि वह पाठक उक्त पुस्तक घर पढ़ने के लिये ले जाना चाहता है तो उसे आउन प्रणाली के द्वारा पुस्तकालय के नियमानुसार पढ़ने के लिए दी जाती है।

यहाँ पर जो पुस्तकें नय की जाती हैं, वे एक पुस्तक चयन समिति की अनुमति पर ही खरीदी जाती हैं। सदस्य भी ऐसे समय अपनी मांग (पुस्तक) चयन समिति के समक्ष रख सकते हैं ताकि उन्हें भी क्रय करने पर विचार किया सके किंतु अन्तिम निर्णय समिति का ही होगा।

पुस्तकालय में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 रुपये की पुस्तकें नय की जाती हैं। इन पुस्तकों की देख रखा, व्यवस्थापन, संगठन एवं पुस्तकालय प्रशासन हेतु, (1) क्षेत्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष (2) पुस्तकालयाध्यक्ष (3) दो बुक लिफ्टर (4) दो केटलागर (5) पांच लिपिक नमचारी एवं छ भृत्य कार्यरत हैं।

उपरोक्त सभी ग्रन्थालय सेवाओं के सहयोग एवं सहकार से पुस्तकालय दिनों दिन वृद्धि पा रहा है मन्वयन शील संस्था का स्वरूप पा रहा है, निश्चित ही इसके उज्ज्वल भविष्य की आशा की जा सकती है।

पाठकों को देश-विदेश, ज्ञान विज्ञान, धर्म दर्शन, साहित्य कला एवं विविध मनोरंजन प्रदान कराने हेतु पुस्तकालय के वाचनालय में लगभग 76 पत्र-पत्रिकाएँ हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी इत्यादि भाषा में मगयी जाती हैं।

वर्तमान में क्षेत्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष श्री तिवारा के नेतृत्व में यह पुस्तकालय फल फूल रहा है एवं राजधानी का गौरव बनता जा रहा है। शासन से पुस्तकालयों एवं उनके कर्मियों के विकास के प्रति कुछ अपेक्षाएँ हैं ताकि अच्छे साहित्य को पढ़ने हेतु अच्छे पाठक बनाये जा सकें।

(11) इन्दौर जनरल लायब्रेरी इन्दौर — 26

भारतवर्ष के पुस्तकालयों के इतिहास में मध्य प्रदेश के इन्दौर शहर की सावजनिक संस्था द्वारा संचालित यह पुस्तकालय, सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक अभ्युदय का प्रतीक है।

104 वर्ष पूर्व स्थापित इस नान मंदिर के विकास की कहानी, इन्दौर के शैक्षणिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की कहानी है। 92 रुपये प्रतिमास की शासकीय सहायता से 1854 में तत्कालीन होलकर नरेश श्रीमन्त्र तुकोजीराव द्वितीय ने इस संस्था की स्थापना की एवं 'किताब घर' इस संस्था का नाम रखा।

आज इस पुस्तकालय को एक सौ चौसीस वर्ष हो रहा है। यह पुस्तकालय अपनी प्राचीनता एवं भव्यता में श्रेष्ठ है। इस पुस्तकालय को 104 वर्ष पूरे होने पर साहित्यानुसंधान एवं समाज सेवीयों ने नवीन भवन बनाने हेतु जनता एवं शासन से सहयोग की अपील की थी। उन्होंने इंदौर शहर के शासन से सहयोग की जो इच्छा प्रकट की वह निवेदन इस प्रकार था "संस्था न नये भवन की जो योजना बनाई है, जिसमें एक विशाल सभागृह, महिला तथा बालकों के वाचनालय के लिये स्वतन्त्र कक्ष, सार्वजनिक ग्रन्थालय और अन्य सुविधा की जा सकेगी। इस भवन निर्माण के लिये अनुमानित ढाई लाख की राशि की आवश्यकता होगी। हम कार्य को पूरा करने के लिए इस नगर के धनी मानों, उद्योगपतियों, समाज सेवीयों, शिक्षा प्रेमीयों एवं सांस्कृतिक कार्यकर्त्तियों के सहाय सहयोग की आवश्यकता है।

इस प्रकार इंदौर जनरल लायब्ररी को नवीन भवन प्रदान करने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण श्री टी. व्ही. रंगे, कृ. अ. चित्तले, मनोहरसिंह जी महता, चन्दन सिंह जी भरकतिया एवं एन. डी. जाशी के नेतृत्व में किया गया। श्री व्ही. एम. नामजोशी द्वारा पुस्तकालय भवन का रेखाचित्र प्रस्तावित किया जो निम्नानुसार है।

उपरोक्त भवन का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया।

ग्रन्थालय भवन—1,60,000

ग्रन्थालय पर्यावरण—10,000

ग्रन्थालय पुस्तकें—90,000

पुस्तक सरप्राय—28,088

सदस्य सभा—1600

उपरोक्त स्थिति आज से 20 वर्ष पूर्व 'इंदौर जनरल लायब्ररी' की थी। वर्तमान में यह पुस्तकालय राजवाड़ा चौक में स्थित एक विशाल भवन में स्थापित है। वर्तमान में इस पुस्तकालय की पुस्तक भण्डार संख्या 43,387 है। पुस्तकालय में आने वाले दैनिक साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक एवं त्रैमासिक पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी 23 हिन्दी 89 एवं मराठी 23 एवं अन्य इस प्रकार 88 विभिन्न पत्रिकाएँ आती हैं। एक दिन में वाचनालय में लगभग 200 पुरुष एवं 100 से 125 तक बालक आकर पुस्तकालय की साहित्य का लाभ प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय की वर्ष 1978 तक कुल सदस्य संख्या 1735 तक पहुँची है। पुस्तकालय में दश विभागों से नाना प्रकार के विषयों की पत्रिकाएँ भी समय-समय पर भेंट स्वरूप प्राप्त होती रहती हैं।

पुस्तकालय भवन में एक बाल विभाग एवं महिला विभाग है। महिलाओं के लिये शहर में पुस्तकें पढ़वाने हेतु चल वाचनालय खोला गया है जिससे बनिता विश्व ज्ञान प्राप्त कर रहा है। यह योजना संस्था द्वारा नारी जागरण के हेतु निःशुल्क चलाई जा रही है।

भारतवर्ष चूँकि निरक्षरता के दायन से वर्द्ध वर्षों से झुलसता रहा है अतः

सभी भारतवासियों को चाहिये कि वे इस प्रकार का सग्याग्रा की स्थापना कर पुण्य कर्मों और राष्ट्रीय समस्या का हल निकाले। सरकार को भी इस और ध्यान देना चाहिये।

वृत्तात वष में ग्रन्थालय को मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग की ओर से 15,173 रु. अनुदान के रूप में प्राप्त हुए वह गत वष की अपेक्षा अधिक है। दि इंदौर जन, लाय, 124 वा वार्षिक वृत्तात 77—78

सन् 1977-78 में ग्रन्थालय सदस्यता से पुस्तकालय को 7017—75 पैसे, श्री इंदौर साव ग्रन्थालय ट्रस्ट द्वारा 4000 = 00 रुपये विविध 2662 = 10 रुपय की राशि प्राप्त हुई।

ऐसे विशाल एवं मध्य प्रदेश के अति प्राचीन पुस्तकालय पर हमें गव है और इसमें भी अधिक गव है उन महानविभूतियों पर जिन्होंने उसे सरस्वती के ज्ञान मन्दिर को अस्तित्व म लाकर इंदौर जैसे महानगर 39 शैक्षणिक, सांस्कृतिक सामाजिक एवं कलात्मक गतिविधियों को विविध रंग दिया एवं बालका एवं युवकों के स्वाध्याय का प्रवर्धन किया। भावी पीढ़ी इसका लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहनी जा सकती।

सन्दर्भ सामग्री

- 1, हिंदी विश्व कोश पक्षा से प्राग तक खण्ड 7 पृ 293,
- 2 ब्रिटनिका विश्वकाश खण्ड 14 पृ 2
- 3 हिन्दुस्तानी, इलाहाबाद अकादमी प्रेस, 1953 पृ 451
- 4 ओभा मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ 115
- 5 हिन्दुस्तानी (नैमा) प्राचीन भारत के पुस्तकालय, 6 (4) अक्टू 1936 पृ 454
- 6 हिन्दुस्तानी (वमा) प्राचीन भारत के पुस्तकालय, 6 (4) अक्टू 1936 पृ 455
- 7 हैसल (अल्फ्रेड) पुस्तकालयों का इतिहास (हिंदी) परिशिष्ट (अ) भोपाल, हिंदी ग्रन्थ अकादमी 1972 पृ 263 अनुवाद मदनसिंह परिहार,
- 8 कपूर (श्यामनारायण) प्राचीन भारत के पुस्तकालय हिन्दुस्तानी, (नै) इलाहाबाद, एक्डमी प्रेस 6 (4) अक्टू 36 पृ 456
- 9 शास्त्री (द्वारका प्रसाद) भारत में पुस्तकालयों का उद्भव और विकास पृ 29
- 10 शास्त्री (द्वारका प्रसाद) भारत में पुस्तकालयों का उद्भव और विकास पृ 30
- 11 परिहार (मदनसिंह) अनु देविण अल्फ्रेड हैसल पृ 264
- 12 गोखल (बी जी) प्राचीन भारत पृ 144
- 13 कपूर (श्यामनारायण) प्राचीन भारत के पुस्तकालय, हिन्दुस्तानी (नै) इलाहाबाद एक्डमी प्रेस, 1936 पृ 460

- 14 शुक्ल (अशोक) मध्य भारतीय सांस्कृतिक अनुशीलन पृ 334
 - 15 Pears Encyclopaedia 73 rd Ed General Information P L 60
 - 16 विध्याचल (सा) 1—1—70 पृ 2
 - 17 विध्याचल (सा) 1—1—70, पृ 6
 - 18 विध्याचल (सा) 1—1—70 पृ 2
 - 19 जागरण 10—4—1970
 - 20 कमवीर 4 अप्रैल 1970
 - 21 विध्याचल जन 8—1—70
 - 22 हीरक जयन्ती समारोह विशेषांक, खण्डवा माणिक्य स्मारक वाचनालय, पृ 5
 - 23 हीरक जयन्ती समारोह विशेषांक, खण्डवा माणिक्य स्मारक वाचनालय पृ 6
 - 24 कोनेमारा केन्द्रीय ग्रन्थालय विवरण प्राप्त सूचना के आधार पर
 - 25 मौलाना आजाद केन्द्रीय राज्य ग्रन्थालय, भोपाल—श्री तिवारी से सूचना प्राप्त
 - 26 श्री इन्दौर जनरल लाइब्रेरी से प्राप्त सूचना के आधार पर—
-

भारत में ग्रामीण-शिक्षा एवं पुस्तकालय

स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा एवं प्रयास—

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था “शिक्षा से मेरा अभिप्राय वज्जे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है।”¹

शिक्षा एक ऐसा सस्वार है जो मानव जीवन का समग्र विकास तथा मानव के व्यक्तित्व विकास में सहयोगी होती है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में शिक्षा का प्रचार-प्रसार बहुत कम था। जनता को शिक्षित करने उनमें अध्ययन के प्रति रुचि जाग्रत करने की दृष्टि से कुछ स्वायत्त व समाज सेवा संस्थाओं ने सावजनिक पुस्तकालयों की स्थापना पर जोर दिया। ग्रामीण शिक्षा को प्रसारित करने व ग्रामीण जन-जीवन को शिक्षित करने की दृष्टि से “अंग्रेजों के समय शिक्षा देने वाली अनेक संस्थाएँ थी जो सरकार, ईसाई मिशनरियों, भारतीय समाज सुधार संगठना और राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खोली गई थी। किन्तु ये सभी संस्थाएँ भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि इनमें ग्रामीण शिक्षा की समस्या पर कोई विचार नहीं किया गया था।”² फिर भी वू कि ब्रिटिश-शासन काल में भारतीय-क्षेत्र कई स्वतंत्र रिमायतों में बढ़ा हुआ था अतः इन रिमायतों के प्रमुखा को अपनी जनता की शिक्षा, रहन-सहन, खान पान व उनकी सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। पराधीनता तथा निरक्षरता के इस अंधकार काल में भी देश के सजग व्यक्तियों, नेताओं तथा तत्कालीन राजपुरुषों ने अपनी जनता को, अपने ग्रामीण भारत को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया।

बहोदा राज्य के महाराजा सर सराजीराव गायकवाड ने अपनी रिमायत में अनिवार्य शिक्षा देने के साथ-साथ 1910 में पुस्तकालयों का एक स्वतंत्र विभाग स्थापित करवाया और पूरी रिमायत में जिला, तालुका, नगर एवं ग्राम पुस्तकालयों की स्थापना करवायी। इन पुस्तकालयों को खोलने के पीछे महाराजा का एक ही उद्देश्य था, कि मनुष्य बौद्धिक प्राणी है और वह शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन की अनिवार्यता व अपने अस्तित्व को समझ सके।

महाराजा इस प्रयास में सफल हुए। इतना ही नहीं उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण भी प्रारम्भ करवाया ताकि सभी प्रकार के पुस्तकालयों को संचालित करने में प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सके ताकि ये लोग निरक्षर ग्रामीण जनता का शिक्षा सम्बन्धी उचित माग दर्शन भी दे सके।

प्रचार धीरे धीरे बढ़ीदा राज्य में सन् 1947 तक 1500 मस्थाए हो गई जिनमें 4 जिला पुस्तकालय, 72 तालुका एवं नगर पुस्तकालय और शेष ग्राम-पुस्तकालय तथा वाचनालय थे। ग्राम पुस्तकालय प्रायः गावा की पाठशालाओं में खोल गये थे। लेकिन धीरे धीरे सन् 1930 से राज के लिए स्वतन्त्र भवन बनाने के लिए पुस्तकालय विभाग ने सहायता देने की शुरुआत की ता सन् 1947 तक 194 पुस्तकालयों का भवन निर्माण भी हो गया था।³

इस प्रकार भारत में ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयासों का विस्तार हुआ। यद्यपि बड़ोदा स्टेट का यह प्रयास एक भ्रान्तालनकारी यशस्वी प्रयास था जिसने भारत में ग्रामीण भ्रान्तालन को स्वल्प प्रदान किया, किन्तु इसमें पढ़ने भी पाठशालाओं की बसी का पुनः करने का उद्देश्य से दश का बहुत भाग में पुस्तकालयों का माध्यम से नामों को साक्षर करने निमित्त बनाने का काम प्रारम्भ हो चुका था।

19वीं शताब्दी "मद्रास, बम्बई और बंगाल का प्रांतों में कुछ राष्ट्रीय मध्य काल में पाठशालाएँ ऐसे बालकों का अधः सामयिक शिक्षा देने के लिए खोली गई जो मजदूरी के कारण पढ़ नहीं सकते थे। सन् 1909 में ऐसे सम्प्रदायों की संख्या मद्रास प्रांत में 775, बंगाल प्रांत में 1048 और बम्बई प्रांत में केवल 107 थी। जन प्रतिनिधियों का ध्यान भारत में कृषि निरक्षरता की ओर गया और प्रौढ शिक्षा के विकास के लिए कदम उठाए गये और बच्चों के लिए कुछ पुस्तकालयों की स्थापना की गई।⁴ लोक पुस्तकालयों को खोलने में इन यूरोपीयनों का भागदशन का सश्रीय योगदान भी रहा। 19वीं शताब्दी के अन्त तक रियासतों की राजधानियों में लोक पुस्तकालय स्थापित हो चुके थे। जिनमें जिला लोक पुस्तकालय का नगर पुस्तकालय प्रमुख था। ब्रह्म और बंगालों के बांझ रियासतों में भी अपने लोक पुस्तकालय स्थापित हो चुके थे।

'1867 में एक और 'Press and registration of Books Act' पास हुआ। इसमें व्यवस्था थी कि प्रत्येक प्रकाशक प्रादेशिक सरकार का उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति निशुल्क भेजे। 1902 में एक और एक्ट कलकत्ता पब्लिक लायब्रेरी (1935) को इम्पीरियल लायब्रेरी घोषित करने से सम्बन्धित था, पास हुआ।⁵

उपरोक्त सभी क्रिया कलाप इस बात के सूचक थे कि शिक्षा में सहयोग देने के लिए तथा देश की जनता को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विकास, में सक्षम बनाने के लिए लोक-पुस्तकालयों का होना आवश्यक है। इस तरह के प्रयास व्यक्तिगत आधार पर भी किये गये। "सन् 1915 में दिवंगत सर एम. विश्वेश्वरय्या ने जब वे मैसूर के दीवान थे, गावों में पुस्तकालय चलाने की व्यवस्था की थी। कुछ वर्षों तक सरकार के नेतृत्व में सफलता पूर्वक कार्य भी हुआ।"⁶ व्यक्तिगत प्रयासों से भारतीय जनता को शिक्षित करने, गाव-

गाव ग्रन्थालय एवं चल-ग्रन्थालय खोलने व पम्पघर तथा भारतीय ग्रन्थालय जगत के विश्व प्रसिद्ध विद्वान डा एम आर रगनाथन का बहुमूल्य योगदान युग युगान्तर तक भुलाया नहीं जा सकता।

“पुस्तकालय जगत में प्रविष्ट होने और यूनिवर्सिटी कालेज लाइब्रेरी से लौटने के तुरन्त बाद डॉ रगनाथन ने 1926 में पुडुकोट्टाह का फ्रेन्स में भाषण दिया जो प्रकाशित हुआ। इसके बाद डा रगनाथन ने कई निबन्ध लिखे जिनका उद्देश्य जन-साधारण तथा पुस्तकालय सचालका का पुस्तकालयों की ओर ध्यान आकर्षित करना, ग्रन्थ देशों की पुस्तकालय सेवाओं के विशिष्ट प्रतिमानों पर प्रकाश डालना, पुस्तकालय सेवा में सुधार करने की दृष्टि से सुझाव देना तथा कतिपय नवीन सेवाओं को प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर जोर देना था।”⁷ उक्त सभी मुद्दों का प्रकाशित लेखों में ग्रामीण पुस्तकालय सेवा एवं प्रौढ शिक्षा के लिए ग्रन्थालयों का उपयोग उल्लेखनीय है।

इतना ही नहीं डा रगनाथन का यह सपना था कि भारत के सम्पूर्ण ग्राम पुस्तकालयों से जोड़ दिये जाव ताकि ग्राम के छोटे-बड़े, ऊँच नीच सभी प्रकार के लोग बिना किसी भेदभाव के पचायत भवनों के ग्रन्थालयों, चौपालों पर बैठकर देश की ताजा राजनीति पर चर्चा कर सकें, विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकें। गावा के ग्रन्थालयों में इस प्रकार का साहित्य ग्रामीणों के अध्ययनाथ पहुँचाया जाव जा, कृषि, उद्योग, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की जानकारी दे। ग्रन्थ एवं ग्रन्थालयों पर उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों व नियमों ने ग्रन्थालय जगत में तहलका मचा दिया था। उनका यह बयान कि प्रत्येक पाठक को उसका वांछित ग्रन्थ प्राप्त होना चाहिए।”⁸

इसी नियम के आधार पर उनका मानना था कि जिस प्रकार शिक्षा व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है वैसे ही हर व्यक्ति को अध्ययन का अधिकार है और प्रत्येक छपने वाली पुस्तक के लिए उसका पाठक होता है और प्रत्येक पाठक के लिए कोई न कोई ऐसी पुस्तक होती है जो उपयोगी होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पुस्तक मिले ऐसा एक मान साधन ग्रन्थालय ही हो सकता है। वह ग्रन्थालय चाहे गावों का हों नगर, तालुका का हो जिला, प्रान्त या कि देश का हो सभी में पाठकों के उपयोग की पुस्तक होगी। इन ग्रन्थों को पाठकों तक पहुँचाने का कार्य ग्रन्थालय प्रणाली का है। भारतीय परिवेश की शैक्षणिक आवश्यकताओं तथा ग्रामीण परिस्थितियों के अनुरूप ग्रन्थालय प्रणाली लागू करने का उनका प्रयास मृत्यु पयन्त चलता रहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम-पुस्तकालयों की आवश्यकता व बारे में अपनी पुस्तक में लिखा कि ‘इंग्लैण्ड में लगभग 80 प्रतिशत लोग नगरों में रहते हैं। इस कारण वहाँ ग्रामीण पुस्तकालयों का विकास द- से हुआ। इसके विपरीत भारत की लगभग 75 प्रतिशत जनता

ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, अतः भारतीया के लिए पुस्तकालय सेवा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर करती है।⁹

जहाँ एक ओर बड़ोदा में प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य धापित कर ग्रन्थालय विकास कार्यक्रमों को भी लागू किया गया। प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट¹⁰ पास हुआ, इम्पीरियल लायब्रेरी विधेयक पास हुआ, वहीं बड़ोदा नरेश के उत्कृष्ट प्रयास से गोपालकृष्ण गोखले ने केन्द्रीय धारा सभा में सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा लागू करने की सिफारिश की। “उस समय देश में केवल 6 प्रतिशत साक्षरता थी और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों में से केवल 23.8 प्रतिशत भारतक और 2.7 प्रतिशत बालिकाएँ इस शिक्षा से लाभ उठा रहे थे।”¹⁰

शैक्षणिक विकास की यह प्रगति अत्यल्प थी। तभी प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य बनाने के लिए बम्बई, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में भी प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पास किया गया। क्रमशः राष्ट्रीय जन जागरण में तीव्रता आती गई और शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की भाव प्रबल होती गई। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार भी निरंतर होता गया साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भी नये नये विश्व विद्यालय अस्तित्व में आये। इसके बावजूद डा. रगनाथन जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे वह था ग्राम-ग्राम पुस्तकालयों का जाल बिछे, मावजनिक-ग्रन्थालय प्रणाली लागू हो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रन्थालय कानून बने साथ ही राज्यों में ग्रन्थालय अधिनियम पारित किए जाएँ ताकि निरक्षरता जैसी विमारी को सदैव के लिए देश से निकासित किया जा सके। इस उपक्रम में उन्होंने ग्रन्थालय विमान पर ग्रन्थ, व लेख लिखे साथ ही अपने ओजस्वी भाषणों से ग्रन्थालयों की उपयोगिता को प्रतिपादित करने में सलग्न रहे। उन्होंने समस्त एशिया शैक्षणिक सम्मेलन के सम्मुख जिसका अधिवेशन सन् 1930 में बनारस में हुआ था, आदेश पुस्तकालय अधिनियम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अधिनियम में राज्य में मावजनिक पुस्तकालयों की स्थापना व रक्षण प्रणाली का दायित्व तथा शहर, ग्राम व अन्य प्रकार की पुस्तकालय सेवाओं का विकास उप-विधित था।¹¹

यद्यपि तत्कालीन सरकार ने भारतीय ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु आवश्यक कदम उठाये किन्तु भारत के जागरूक नागरिकों ने निरक्षर जनता की चिन्ता करते हुए उन्हें ग्रन्थों के अध्ययन की सुविधाएँ देने हेतु ग्राम वाचनालयों, चल ग्रन्थालयों व पुस्तकालयों की स्थापना पर विशेष जोर दिया। डा. रगनाथन, ने भारत में ग्रन्थालयों के विकास हेतु “आदेश पुस्तकालय अधिनियम” के आधार पर एक विधेयक मद्रास विधान सभा में 1933 में प्रस्तुत किया। इसी वर्ष भारतीय ग्रन्थालय सघ का गठन भी हुआ। इसी प्रकार से कई विधेयक डा. रगनाथन द्वारा अलग-अलग प्रदेशों में ग्रन्थालय विकास के लिए प्रस्तुत किये गये। सरकार ने

इन विधेयको पर विचार करने की जरूरत नहीं भगम्भी । “1939 में बम्बई में थी ए ए ए फंजी की अध्यक्षता में “पुस्तकालय विकास समिति” की नियुक्ति हुई । समिति ने 1942 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । जिसमें उसने पुस्तकालयों के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए किंतु देश के स्वाधीन होने तक उनको व्यवहार में नहीं लाया जा सका । 1940 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार ब्यूरो ने यह निर्णय लिया कि प्रौढ़ शिक्षा की समस्याओं को हल करने की दृष्टि से पुस्तकालय खोले जाने चाहिए ।”¹²

ग्रन्थालय विकास की उपरोक्त गतिविधियों के क्रमशः मद होने तक देश में अनेक स्तर की शिक्षा का शुमारम्भ हो चुका था । कई विश्वविद्यालय खुल चुके थे और उनसे सम्बद्ध ग्रन्थालय भी । समस्या यह थी कि शिक्षा के साथ ग्रन्थालयों का सम्बन्ध अभी तक ठीक से नहीं हो रहा था । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तैयार होने पर केन्द्रों की वाचनालय सुविधायें अवश्य प्रदान कर दी गई थी, परन्तु इसका दायरा कम था अतः ग्रन्थालय सघों ने अस्तित्व में आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कई बैठकों में भाग लिया और कांग्रेसी नेताओं की शिक्षा में ग्रन्थालयों की उपयोगिता तथा सावजनिक ग्रन्थालय अधिनियमों की अनिवार्यता से अवगत कराया । स्वतन्त्रता के पूर्व तक देश के विभिन्न राज्यों में ग्रन्थालय विकास का संकल्प लिए निर्माकित राज्य पुस्तकालय सघों की स्थापना हुई ।

(1) बड़ौदा पुस्तकालय सघ	1910
(2) पंजाब पुस्तकालय सघ	1915-1929 में पुनः स्थापित
(3) मद्रास पुस्तकालय सघ	1928
(4) कर्नाटक पुस्तकालय सघ	1929
(5) बिहार पुस्तकालय सघ	1930
(6) बंगाल पुस्तकालय सघ	1931
(7) आंध्र पुस्तकालय सघ	1931
(8) आन्ध्र प्रदेश पुस्तकालय सघ	1938
(9) केरल पुस्तकालय सघ	1942
(10) बम्बई पुस्तकालय सघ	1944
(11) उत्तर प्रदेश पुस्तकालय सघ	1944
(12) पूना पुस्तकालय सघ	1945
(13) दिल्ली पुस्तकालय सघ	1946

1946 में ही डा. रमनाथन ने “National Library System A plan for India” ग्रन्थ का प्रकाशन करवाया । इसमें उन्होंने राष्ट्र में पुस्तकालयों के विकास तथा सम्पूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रीय ग्रन्थालय प्रणाली के निर्माण पर प्रकाश डाला । इसके साथ ही मद्रास, कोचिन, नावणकोर तथा बम्बई के लिए पुस्तकालय विधेयकों के प्राप्ति के राज्य-स्तर पर पुस्तकालय विकास कार्यक्रम की

रूपरेखा तैयार की, जिनका प्रकाशन भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूरे वर्षों में हो चुका था। भारतीय जन जीवन को शिक्षित, जागरूक व राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा से युक्त बनाने के उद्देश्य से शिक्षा प्रचार व प्रसार की तीन तरह की प्रयत्न विधियाँ अंग्रेजों, राष्ट्रीय कांग्रेस व समाज सदियों व पुस्तकालय विकास के पक्षधरों ने अपनायी। इस प्रयास में अपने अपने तरीके से सभी लोग एकजुट होकर लगे रहे। अंग्रेजों को अपने प्रशासन-तन्त्र को चलाने हेतु पढ़े लिखे बाबूओं की आवश्यकता थी तो भारतीय नेताओं को नागरिकों को जागरूक व सजग बनाने की, और इन्हीं दोनों के बीच ग्रन्थालय विकास की धारा भी पूरे देश में गतिमान होती रही। इस प्रकार भारत में तीन तरह से शिक्षा का व्यापक विकास के प्रयास हुए।

(1) अंग्रेज शासन की शिक्षा प्रणाली।

(2) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व समाज सेविद्या द्वारा प्रस्तुत प्रणाली।
तथा

(3) पुस्तकालय-संगठन द्वारा किए जाने वाले प्रयास।

1—अंग्रेज शासन द्वारा शिक्षा के लिए किये गये प्रयासों और महत्वपूर्ण आयामों के गठन की जानकारी निम्नानुसार है।

(1) बुड का घोषणा पत्र— (1854)

(2) हुटर कमीशन— (1882-83)

(3) लाड कजल, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग तथा अधिनियम

(4) मटलर कमीशन— (1917-1919)

(5) हुटाग-समिति— (1927-1929)

(6) एथर्ट बुड रिपोर्ट— (1936-1937)

(7) सार्जेंट रिपोर्ट— (1944)

प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षा के साथ ही बच्चों के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत में सुदृढीकृत शैक्षणिक विकास (1944) सम्बन्धी प्रतिवेदन में सिफारिश की कि पूरे प्राथमिक शिक्षा भी दी जावे। यद्यपि महाराष्ट्र के नूतन बाल शिक्षा सन्ध 1920 ने इसकी शुरुआत पहले ही कर दी थी किन्तु 1930 में मैडम माटसरी के भारत आगमन के बाद पूरे प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि हुई। 1950-51 में पूरे प्राथमिक विद्यालयों (आगमन बाड़ी शिशु संगोपन केन्द्र बाल मन्दिर) की संख्या 303 थी जिसमें 866 शिक्षक थे और लगभग 28000 बच्चों की शिक्षण व्यवस्था थी। इस साल में कुल शिक्षा व्यय का लगभग 0। प्रतिशत, पूरे प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया गया सन् 1957 के लगभग पूरे प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 3500 हो गई जिसमें 6500 शिक्षक थे और 2,40,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।¹³

प्रारम्भिक वर्षों में इनका कार्य क्षेत्र नगरीय में अधिक और गाँवों में कम रहा किन्तु बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में आगमन बाड़ियों की स्थापनाओं में वृद्धि हुई। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का विकास क्रमशः निम्नानुसार हुआ।

बम्बई— "1824 तक दशवी विद्यालयों की संख्या 216 हो गई थी जिनमें 12 हजार से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे।"¹⁴

मद्रास— "सम्पूर्ण प्रान्त में 1852 में 1,185 मिशन स्कूल थे, जिनमें 38005 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे।"¹⁵

उत्तर प्रदेश— "इन जिलों में 50 बम्बे एवं 14,572 ग्राम थे स्कूलों की संख्या 3,127 थी और उनमें 27,853 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। हल्वाबन्दी स्कूल प्रणाली के अन्तर्गत 1854 में 758 विद्यालय थे जिनमें 17 हजार छात्र पढ़ते थे।"¹⁶

बम्बई के शिक्षा बोर्ड एवं बंगाल के शिक्षा परिषद बनने के बाद कुछ के घोषणा पत्र में ही शिक्षा विभाग एवं उनके संगठन का प्रावधान रखा गया था। "1856 के अन्त तक भारत के सब प्रान्तों में शिक्षा विभाग की स्थापना का कार्य पूरा किया जा चुका था और वे शिक्षा कार्य में व्यक्त हो गये थे।"¹⁷

1937 से 1947 तक की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के आँकड़े निम्नानुसार हैं।

प्राथमिक शिक्षा

प्रांत	शिक्षा पाने वाले बालक नागरिक क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र		शिक्षा पाने वाली बालिकाएँ नागरिक क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	
बिहार	17			
बम्बई	9	134	110	5,100
मध्य प्रदेश	34	1031		
पूर्वी पंजाब	37	1,420		
मद्रास	16	31	12	1,607
उड़ीसा	1	1		
उत्तर प्रदेश	36	1,371	3	3
पश्चिमी बंगाल	1			
दिल्ली	1	7		
योग	152	3995	125	6710

माध्यमिक शिक्षा—1937 में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 13056 और उनमें शिक्षा का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या 22,87,872 थी। 1947 में यह संख्या क्रमशः 11,907 और 26,81,981 थी।

2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं समाज सेवी मन्त्रियों ने भी प्राथमिक एवं माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए प्रमुख समितियों का निर्माण किया साथ ही

प्रौढ शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दन हेतु प्रौढ पाठशाला एवं वाचनालय भी खोले ।

“1937 में ही भारत में “इण्डियन एडल्ट एजुकेशन सोसाइटी” की स्थापना हुई । इसके पूर्व 1935 में भारत में आठ-प्रांता में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शासन सभाला गया था । लोक प्रिय मन्त्री मण्डला ने उस समय के साठ बत्तीस कराड निरक्षरों को साक्षर बनाने का आन्दोलन चलाया । इसके परिणामस्वरूप प्रौढ शिक्षा की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई । केवल बिहार में ही 18,878 केन्द्रों पर 11,68,325 व्यक्ति साक्षर हुए । 1939 में भारत में प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 5978 तथा इनके अध्ययन कक्षाओं की संख्या 1,92,539 थी ।”¹⁸

1937 से 1942 के बीच प्रौढ शिक्षा का विकास निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है—

प्रांत	प्रौढ शिक्षा केंद्र	छात्र
आसाम	10,000	61,16,713
बंगाल	32,574	6 80 178
बिहार	100526	27,74,595
बम्बई	6432	1 39,000
सी पी	77	1 692
मद्रास	354	19,265
उड़ीसा	2547	64,108
पंजाब	10,929	3,62,322
उत्तर प्रदेश	21,300	14,00 000 %

% प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय के पृष्ठ 33-34 से उद्धृत ।

अभी तक जबकि देश के 13 प्रांतों में ग्रन्थालय सभों का गठन हो चुका था । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शक्ति में आ गई थी, कई प्रदेशों का शासन उसने हाथ में आ चुका था । देश में डा रंगनाथन सत्तराम भाटिया, खान बहादुर असदुल्लाह एवं अन्य ऐसे ग्रन्थपाल व लाकज्जन ऐसे थे जो अपने अपने क्षेत्रों में खुले मन व समर्पित भाव से ग्रन्थालयों की स्थापनाएँ करते जा रहे थे और प्रयासरत थे । कुछ सभ ऐसे थे जो ग्रन्थपालों के लिए ग्रन्थालय साहित्य भी प्रकाशित कर रहे थे । मद्रास ग्रन्थालय सभ डॉ रंगनाथन के लेखा का प्रकाशन कर रहा था और पंजाब ग्रन्थालय सभ लाहौर से “माडन लायब्रेरियन” नाम की वार्षिक पत्रिका प्रकाशित हो रही थी ।

राष्ट्रीय कांग्रेस के सन् 1937 में प्रभावशील होने के उपरान्त बहुतेरे प्रांतों में ग्रन्थालय सभों ने सरकारी प्रयासों से ग्रन्थालय चलाये जाने की मांग रखी । इनमें से कुछ प्रादेशिक सरकारों ने ग्रन्थालय सभों की मांगों को स्वीकार कर राज्य

शिक्षा-विभाग को ग्रामीण पुस्तकालय खोलने का आदेश प्रदान किया। ग्रन्थालय परामर्श समिति¹⁹ ने भी अपने ऐतिहासिक प्रतिबदन में यह बात स्पष्ट की है। मद्रास ग्रन्थालय सघ (1929) ने ग्रन्थालयों के विकास हेतु काफी प्रयास किए जिसका श्रेय डा. रंगनाथन को जाता है। उनकी अद्वितीय क्षमता के कारण ही— “1942 में भारतीय पुस्तकालय सघ ने डा. रंगनाथन से एक अग्र विधेयक की रूपरेखा तैयार करने की प्रार्थना की। उन्होंने विधेयक की रूपरेखा बनाई जिसे “आदर्श सार्वजनिक पुरतकालय विधेयक” कहते हैं। इस विधेयक का बम्बई में समस्त भारतीय पुस्तकालय सघ के पाचवें अधिवेशन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। विधेयक पर अधिवेशन में बहस तो हुई परंतु कोई निश्चित पथ नहीं उठाया गया।”²⁰

ऐसे ही अधिनियम बनाने या विधेयक प्रस्तुत करने के प्रयास अनेक राज्यों के ग्रन्थालय सघों द्वारा डा. रंगनाथन के सहयोग से किए जिनका विवेचन हम स्वाधीनता काल में शिक्षा एवं ग्रन्थालयों के विकास के समय करेंगे।

उपरोक्त सभ्य विवेचन में हमने देखा कि भारत वष पर अंग्रेजों के शासन काल में शिक्षा के साथ ग्रन्थालयों के विकास पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा के साथ उपलब्धि के नाम पर हमें विश्व विद्यालयीन व महाविद्यालयीन शिक्षा में ही ग्रन्थालयों के दर्शन होते हैं। शेष पाठ शिक्षा कार्यक्रमों में ग्रन्थालयों के उपयोग का जिक्र मिलता है जसा कि हिन्दी विश्व कोष में लिखा है कि “वसिक शालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों में तो अभी पुस्तकालयों का विकास नहीं हुआ है। परंतु माध्यमिक शालाओं एवं विद्यालयों के पुस्तकालयों का सार्वजनिक विकास हो रहा है।”²¹

यह बात तो सर्वविदित है कि स्कूलों में आज भी ग्रन्थालय सक्रिय नहीं हैं। ग्रामों के पुस्तकालयों की स्थिति तो और भी खराब है। जहां तक ग्रन्थालयों

- 19 ‘The need for public libraries so conceived and dedicated has been felt all the more keenly in India after independence. There is a remarkable unanimity of opinion among all national leaders that facilities for reading books must be brought within the means of all citizens and particularly of villagers. It is believed that this will prevent their world of learning from being limited to personal experiences and observations. Reading will widen their horizon before the barriers of space and time.’ Report of advisory Committee for libraries, Govt. of India, Ministry of education & youth services 1970, P. 32

“इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता देने के लिए” अखिल भारतीय-प्राथमिक शिक्षा परिषद (All India Council for elementary Education Council 1975) का निर्माण किया गया, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वार्षिक सहायता अनुदान दिया गया और पिछली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा पर लगभग 1005 करोड़ रुपये व्यय किए गये।”²⁵

प्रथम पंच वर्षीय योजना से लेकर पांचवी पंचवर्षीय योजना तक प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान निम्नांकित तालिका से हम लगा सकते हैं।”²⁶

वर्ष	विद्यालय संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	व्यय (करोड़ों में)
1950-51	2,09,671	1,82,93,967	5,37,918	36.49
1955-56	2,78,135	2,29,19,734	6,91,249	53.73
1960-61	3,30,397	2,66,42,253	7,41,695	73.44
1961-62	3,51,530	2,94,74,377	7,94,747	82.67
1962-63	3,66,262	3,12,86,929	8,32,996	92.94
1963-64	3,77,106	3,31,03,271	8,81,438	99.01
1964-65	3,85,250	3,35,78,000	9,06,900	105.8
1965-66	3,91,064	5,04,70,000	9,44,377	
1976-77	4,66,264	6,84,80,000	13,36,104	
1977-78	4,77,037	7,69,70,300	13,54,460	

उपरोक्त तालिका इस बात का संकेत देती है कि 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता को भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लाभ निश्चित रूप से मिला। शिक्षा को और भी आगे बढ़ाने जैसे माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भी प्रयास स्वाधीनता के बाद बेहतर हुए।

‘माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ 1950-51 में कुल 20,884 माध्यमिक विद्यालय, 52,32,009 विद्यार्थी, 2,12,000 अध्यापक तथा 30 करोड़ 74 लाख रुपये का व्यय राशि थी, वहीं 1963-64 में विद्यालयों की संख्या 88,584, विद्यार्थियों की संख्या 2,46,77,747 तथा अध्यापकों की संख्या 8,49,782 हो गई। इनकी व्यय राशि 1 अरब 63 करोड़ 93 लाख रुपये तक जा पहुँची।’²⁷

शिक्षा का इतना व्यापक विस्तार होने के उपरान्त भी “यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बत्तीस वर्ष होते जा रहे हैं परन्तु आज भी हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की 15 प्रतिशत जनसंख्या और माक्षर हुई।”²⁸

द्वारा शैक्षणिक प्रक्रिया में सहयोग करने का प्रश्न है वह एक अच्छी शिक्षण प्रणाली में ही संभव है। दूसरे यह कार्य प्रौढ शिक्षा के अंतर्गत ग्रंथालयों की ग्रंथमयता सम्झने में होगा। प्रद्युम्न कुमार गौड़ ने लिखा है कि "यह विचारणीय है कि शिक्षा प्रक्रिया का सीधा सम्बंध व्यक्ति से होता है क्योंकि व्यक्ति ही शिक्षित होता है और ऐसे ही शिक्षित व्यक्तियों से समाज बटता है अतः व्यक्ति की आवश्यकताओं और उसकी प्रसन्नता और समृद्धिशीलता प्रौढ शिक्षा अभियान में ही सर्वोपरि होगी परन्तु इनकी संरचना में पुस्तकालयों का योगदान भी महत्वपूर्ण है।" 22

इस महत्त्व को शायद अंग्रेज सरकार नहीं समझ पायी थी, किन्तु भारतीय नेता शिक्षा विद व समाज सुधारकर्त्ता इनके महत्त्व को जानते थे, उन्होंने ही ग्रंथालयों के समग्र विकास पर विचार किया होता तो संभव था आज पूरा राष्ट्र ग्रंथालयों का लाभ अपने ग्राम, शहर व शैक्षणिक जीवन में करता।

"स्वातंत्र्योत्तर काल में ग्रामीण शिक्षा एवं ग्रंथालय" —

एक लम्बे जद्दोजहद और स्वातंत्र्य संघर्ष के उपरान्त भारतीयों ने अपने देश को पराधीनता की जजीरा से मुक्त किया। सुव्यवस्थित रूप से भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हुआ। 23 कांग्रेस जनो तथा राष्ट्रीय चेतना के दीवाना न सत्ता हस्तारण के लिए कांग्रेसी पर दबाव डालता। 1942 में पूरे देश में इतिहास प्रसिद्ध 'भारत छोड़ो' आन्दोलन छिड़ गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को कांग्रेसी द्वारा संघर्षशील भारतीयों को सत्ता सौंप दी गयी।

भारत अब पूर्ण स्वतंत्र था और उसे अपने देशवासियों को, प्रजातांत्रिक ढंग से जीने के लिए शिक्षा, कृषि उद्योग, व्यापार एवं विज्ञान में भाग बढ़ाना था। तत्कालीन सरकार का ध्यान नागरिकों को शिक्षित करने एवं उन्हें गरीबी से उबारने की ओर गया। भारत में शिक्षा के गिरे हुए स्तर को ध्यान में रख सविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शिक्षा की विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया। इस उद्देश्य से स्वतंत्र भारत के सविधान की 45 वीं धारा में स्पष्ट रूप से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की घोषणा की गई। 24

-
- 24 "The state shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this constitution for the free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years"—Article 45 of the constitution adopted by free India on January 26, 1950

“स लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता देने के लिए” अखिल भारतीय-प्राथमिक शिक्षा परिषद (All India Council for elementary Education Council 1975) का निर्माण किया गया, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वार्षिक सहायता अनुदान दिया गया और पिछली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा पर लगभग 1005 करोड़ रुपये व्यय किए गये।²⁵

प्रथम पंच वर्षीय योजना से लेकर पांचवी पंचवर्षीय योजना तक प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान निम्नांकित तालिका से हम लगा सकते हैं।²⁶

वर्ष	विद्यालय संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	व्यय (करोड़ों रु० में)
1950-51	2,09,671	1,82,93,967	5,37,918	36 49
1955-56	2,78,135	2,29,19,734	6,91,249	53 73
1960-61	3,30,397	2,66,42,253	7,41,695	73 44
1961-62	3,51,530	2,94,74,377	7,94,747	82 67
1962-63	3,66,262	3,12,86,929	8,32,996	92 94
1963-64	3,77,106	3,31,03,271	8,81,438	99 01
1964-65	3,85,250	3,35,78,000	9,06,900	105 8
1965-66	3,91,064	5,04,70,000	9,44,377	
1976-77	4 66,264	6,84,80,000	13,36,104	
1977-78	4,77 037	7,69,70,300	13,54,460	

उपरोक्त तालिका इस बात का संकेत करती है कि 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता की भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लाभ निश्चित रूप से मिला। शिक्षा को अगर भी आगे बढ़ाने के लिए माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भी प्रयास स्वाधीनता के बाद बेहतर हुए।

‘मध्यमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ 1950-51 में कुल 20 884 माध्यमिक विद्यालय, 52,32,009 विद्यार्थी, 2 12000 अध्यापक तथा 30 करोड़ 74 लाख रुपये की व्यय राशि थी, वहाँ 1963-64 में विद्यालयों की संख्या 88,584, विद्यार्थियों की संख्या 2,46,77,747 तथा अध्यापकों की संख्या 8,49 782 हो गई। इनकी व्यय राशि 1 अरब 63 करोड़ 93 लाख रुपये तक जा पहुँची।’²⁷

शिक्षा का इतना व्यापक विस्तार होने के उपरान्त भी “यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बत्तीस वर्ष होते जा रहे हैं परन्तु आज भी हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की 15 प्रतिशत जनसंख्या और साक्षर हुई।”²⁸

निरन्तरता निवारण के लिए निरन्तर प्रयासरत भारत सरकार के समाज शिक्षा मुहिम चलवायी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलवाये और युवक गोष्ठियो व महिला समितियों की स्थापना की।

प्रौढ शिक्षा का प्ठमुखी कार्यक्रम, शिक्षक आयोग (Education Commission) ने प्रस्तुत किया जिसके अनुसार नीचे लिखे कार्यक्रम निश्चित किए गये।

(1) निरक्षरता का उन्मूलन (2) अनवरत शिक्षा (3) पत्राचार पाठ्यक्रम (4) पुस्तकालय (5) विश्वविद्यालयों की भूमिका (6) मगठन व प्रशासन।

‘शिक्षा आयोग’ न वयस्क-शिक्षा से सम्बंधित पुस्तकालयों व विषय में नीचे लिखे विचार प्रस्तुत किए हैं।

(1) वयस्का के पुस्तकालय प्रगतिशील होने चाहिए।

(2) उक्त पुस्तकालयों को वयस्का को शिक्षित एवं आकर्षित करना चाहिए।

(3) विद्यालयों के पुस्तकालयों को भावजनिक पुस्तकालयों के साथ समेलित कर देना चाहिए और उनमें वच्चा एवं नव साक्षरों की रुचियों को ध्यान में रखकर पुस्तकों का संग्रह किया जाना चाहिए।

(4) दश भर में पुस्तकालयों की स्थापना के सम्बंध में “पुस्तकालय-सलाहकार समिति” की सिफारिशों पर अमल किया जाना चाहिए।

(5) जहां तक संभव हो पुस्तकालयों में टर्परिवाडों, ग्रामोफोन रिकार्डों, फिल्मों तथा अन्य उपयोगी साधनों का संग्रह होना चाहिए।²⁹

इन्हीं उद्देश्यों को प्रौढ शिक्षा विकास में सहयोगी बनाने के लिए प्रथम-पंच वर्षीय योजना में सम्पूर्ण देश में पुस्तकालयों का विकास करने की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थालय (कलकत्ता) के अलावा राज्यों में केन्द्रीय ग्रन्थालय, क्षेत्रीय ग्रन्थालय एवं जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर एक-एक सावजनिक ग्रन्थालय स्थापना का निर्णय लिया गया।

निर्णयानुसार प्रथम योजना काल में “9 स्टेट सेंट्रल लायब्ररी, 96 जिला पुस्तकालय तथा 52 विद्यमान जिला पुस्तकालयों के विकास के लिए 88,91,499 रुपये स्वीकृत किए गये थे। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, पंजाब राजस्थान सौराष्ट्र पेप्स भोपाल, बिहार प्रदेश में स्थापित किये गये तथा 96 जिला पुस्तकालयों में से आसाम में 7, पश्चिम में 17, बिहार में 12, मध्यप्रदेश में 22, राजस्थान में 24, सौराष्ट्र में 5, भोपाल में 2 तथा बिहार प्रदेश में 7 स्थापित किये गये।”³⁰

मान को एक परम्परा की श्रृंखला का स्वरूप देने में शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। इस शिक्षा द्वारा ही मनुष्य अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति करता है। शिक्षा ही मानव को पशु-स्तर से ऊंचा उठाकर श्रेष्ठ

सांस्कृतिक प्राणी बनाता है। श्रीव माध्यमा से प्राप्त शिक्षा दश के विकास में निश्चित ही सहयोगी बनकर अपने निमित्त नामगर्वा को गौरवशाली पद प्रदान करती हैं। एक दश में निमित्त एवं नाना नामगर्वा की सरया व आधार पर ही उस दश की उन्नतिशील अवस्था का ज्ञान लिया जा सकता है। अतः राष्ट्र की जनता को सर्व-व्यापी शिक्षा देने का मकल्प लेकर उनमें व्याप्त प्रतिष्ठा का काल की निपनता एवं शिक्षा को दूर करने का मकल्प पंचवर्षीय योजनाओं ने लिया।

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल की प्रगति के आधार पर ही द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में देश के पूरे 320 जिला में पुस्तकालय मंत्रालय शुरू करने की योजना बनी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 416 ग्राम-पंचायतों 5000 चरित ग्रंथालय तथा 1250 वाचनालयों के लिए 10,10,000 (दस लाख, दस हजार) रुपये अनुदान का रूप में स्वीकृत किए गये। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान दश में ग्रंथालय के समुचित योजनाबद्ध व्यवस्थापन पुनर्गठन एवं संचालन हेतु भारत सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय परामर्श समिति का निर्माण किया। तथा ग्रंथालयों के विकास का उत्तरदायित्व सारा गया। चौथी योजना काल में ही योजना आयोग ने ग्रंथपालों का एक 'नायकारी दल' नियुक्त किया जिन्हें देश में जन-ग्रंथालय-सेवा के विकास की योजना बनाकर देनी थी। 'इस दल ने देश में जन पुस्तकालय मंत्रालय के विकास की एसी योजना दी है कि जो अगले दस वर्षों में प्रत्येक 2000 की जनसंख्या वाले गाँवों में पहुँच जायगी तथा जन-पुस्तकालयों का वार्षिक व्यय 22 करोड़ रुपये होगा।' 11

किन्तु अफसोस रहा कि बाद के वर्षों में इस योजना पर सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जबकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू का योजना काल के दौरान ही यह सपना था कि हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि देश के हर ग्राम में कम से कम एक पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए और लोगों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। वास्तव में, प्रत्येक पुस्तकालय स्वयं में ही विश्व विद्यालय होना चाहिए।

परंतु यह नहीं हो सका और न ही हो रहा है और न ही हो सकने की सम्भावनाएँ दिखाई पड़ती हैं। कारण स्पष्ट है कि जहाँ ग्रंथालय अधिनियम राज्य सरकारों ने पारित कर दिये हैं वहाँ ही जन-ग्रंथालयों को सूचारु रूप से चलाने में सुविधा है, दूसरे राज्यों में नहीं। एक बार जिन राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम लागू हुए हैं वहाँ गाँव-गाँव, जिला, राज्य व केन्द्रीय ग्रंथालय से उनका सम्बन्ध बना हुआ है और वहाँ सारा प्रपञ्च राज्य ग्रंथालय समितियों द्वारा होता है जो बिना अधिनियम वाले प्रदेशों में सम्भव नहीं है।

यद्यपि डॉ रमनाथन ने दश के अनसो प्रदर्शों के लिए ग्रन्थालय अधिनियम बनाये और उन्हें पारित करने का प्रयत्न भी किया किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। वे राज्य जहाँ ग्रन्थालय अधिनियम पारित करने हेतु प्रयास किए गये निम्नानुसार हैं।

वर्ष	राज्य	वर्ष	राज्य
1946	मद्रास, केन्द्रीय प्रांत	1957	आन्ध्र प्रदेश
1947	कोचीन, ट्रावनकोर बम्बई	1958	पश्चिमी बंगाल
1948	संयुक्त प्रांत	1958	उत्तर प्रदेश (मशोधित)
1953	हैदराबाद	1960	केरल
1957	मध्य प्रदेश	1961	मैसूर

उपरोक्त विधेयकों के अतिरिक्त कश्मीर एवं दिल्ली राज्यों के लिए प्रो पी एन कौल ने 1951 एवं 1955 में ग्रन्थालय विधेयकों के प्रारूप प्रस्तुत किए किन्तु इन्हें आज तक पारित नहीं किया जा सका है।

वे प्रदेश जहाँ ग्रन्थालय अधिनियमों के लागू होने से शिक्षा में प्रगति व ग्रन्थालयों के विकास में वृद्धि हुई है निम्नानुसार है।

राज्य	विधेयक पारित वर्ष
(1) मद्रास	1948
(2) आन्ध्र प्रदेश	1960
(3) मैसूर	1965
(4) महाराष्ट्र	1967
(5) पश्चिमी बंगाल	1979

इस प्रकार सम्पूर्ण भारत वर्ष में सिर्फ पांच राज्यों में ग्रन्थालय अधिनियम पास हो सके हैं। जहाँ इन विधेयकों पर जोर कायबाही हुई है उन प्रदेशों का शिक्षा प्रतिष्ठान भी अन्य विधेयक विहीन राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक रहा है। यह सब ग्रन्थों की अध्ययन सुविधा से ही सम्भव हो सका है। सरकार को चाहिए कि वह इन पांच राज्यों की तरह देश के सभी राज्यों में अधिनियमों को पारित करने की स्वीकृति दें तब पुस्तकालयों की दुनिया में अन्तिम घाव साथ ही भारत का प्रत्येक नागरिक डॉ० रमनाथन के स्वप्न “ग्रन्थ सबके लिए है” ‘ग्रन्थों को पाठक मिल और पाठकों को ग्रन्थ’ का साकार रूप मिल सके। पुस्तकालयाध्यक्ष प्रभात कुमार बनर्जी का मन है कि ‘यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश से निरक्षरता का अभिशाप पूर्ण रूप से दूर हो तो हम प्रत्येक जिले तथा ग्रामों में पुस्तकालयों की स्थापना का

प्रयास करना होगा। यहाँ पर जो माहित्य रखा जायेगा, उससे दशवासिया का बहुत लाभ होने की संभावना है और इसमें वे शिक्षा के पत्रों से मुक्त हो सकेंगे।³⁰

जो राज्य ग्रन्थालय विधेयको का सुख भाग रहे ह उन्होंने निश्चित ही अपन नागरिका को शिक्षा के शिकजे से छुड़ाकर शैक्षणिक सम्कार के वातावरण में डाल दिया है। इस और ग्रन्थालय मघा का कदम उठाना चाहिए। हमने देखा है कि शिक्षा के गुणात्मक विकास, शिक्षा की द्रुपित प्रणाली, व शिक्षा के गिरत हुए स्तरों पर विचार करन हेतु अभी तक सरकार द्वारा कई आयोग एवं समितियाँ की स्थापना की गई व कई विधेयक भी राष्ट्रीय स्तर पर पास किये कि राष्ट्रीय नीति में आ-मूल धूल परिवर्तन कर बहतर-शिक्षा प्रणाली बनायी जाव। पर इन सबमें हमने देखा कि ग्रन्थालयों के विकास का, उनके व्यवसाय व व्यक्तियों का ध्यान नहीं रखा जाता है। शिक्षा आयोगों के गठन, कमिशनो की सिफारिशों के बावजूद देश में ग्रन्थालयों की दशाएँ ठीक नहीं है। पूव में हम देख चुके हैं कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में ग्रन्थालयों को बिल्कुल भी स्थान नहीं मिला। प्रौढ शिक्षा में कुछ ग्रन्थालयों का महत्व बढ़ा और विश्व विद्यालय व शोध अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपनधिध्या के लिए सरकार ने "सूचना क द्रा व प्रलेखन अनुमजान के द्रो "को खालन पर ध्यान दिया।

जन मामांय के लिए चाहें वह ग्रामीण हो चाहें शहरी ग्रन्थालयों की सुविधा आज भी दुर्लभ है। इतने बड़े राष्ट्र में जहाँ 70% जनता ग्रामीण क्षेत्रों की निवासी है और जहाँ सिर्फ पांच राज्यों की जनता ग्रन्थालय अधिनियमों का लाभ ल रही हो तब शेष 24 राज्यों की ग्रामीण व शहरी जनता का क्या होगा, चिन्ता का विषय है। निम्नांकित तालिका से उन राज्यों की जनता की साक्षरता के प्रतिष्ठान का अनुमान होगा। (1) ग्रन्थालय अधिनियम लागू है और जहाँ (2) ग्रन्थालय अधिनियम नहीं है।

(1) के राज्य जहाँ ग्रन्थालय अधिनियम द्वारा पुस्तकालयों की सुविधा उपलब्ध है। जहाँ नहीं है।³¹

राज्य	साक्षरता प्रतिशत	राज्य	साक्षरता प्रतिशत
केरल	69.75	राजस्थान	22.57
महाराष्ट्र	45.77	बिहार	23.35
तमिलनाडु	45.40	उत्तर प्रदेश	25.44
मैसूर	30.83	मध्यप्रदेश	26.37
आंध्र प्रदेश	28.52	हरियाणा	31.91

उपरांत तालिका से स्पष्ट है कि ग्रन्थालयों के उपयोग से मान-रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जहाँ शिक्षा ता है परन्तु ग्रन्थालय विधेयक

के अभाव में श्रेष्ठ ग्रन्थालय सेवाओं का अभाव है वहाँ की जनता का साक्षरता स्तर क्या है। "यह आशा की गई है कि 1983-84 तक भारत से निरक्षरता को समाप्त कर दिया जाएगा। चूँकि प्रारम्भिक तथा प्रौढ़ शिक्षा एवं दूसरे सन्निकट सम्बन्धित हैं। अतः इन दाना कार्यक्रमों को साथ-साथ चलाना चाहिए। यह सभी सम्भव होगा जब गांव गांव स्कूल ग्रन्थालय व लोक-पुस्तकालय खुलेंगे और उनका भरपूर लाभ ग्रामीण जनता, बाल-युवा व महिलाएँ प्राप्त करेंगी।

यद्यपि ग्रामीण शिक्षा का प्रारम्भ करने हेतु उच्च शिक्षा की सुविधा देने के लिए आनन्द, अन्नमलई व विश्व भारती ग्रामीण विश्व विद्यालयों की स्थापना की गई जिस पर 1970-71 में 27.61 लाख रुपये व्यय किये गये।¹⁴ इतने विशाल राष्ट्र में ग्रामीणों की उच्च शिक्षा पर यह व्यय बहुत कम है। ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने निम्नलिखित पन्द्रह सस्याओं को "हुरल इस्टीमेट" में बनाने के लिए चुना है।

- (1) श्री निकेतन (पश्चिमी बंगाल) (2) माँधी ग्राम (तमिलनाडु),
- (3) जामिया नगर (दिल्ली) (4) उदयपुर (राजस्थान) (5) विरोली (बिहार)
- (6) त्रिवपुरी (उत्तर प्रदेश), (7) मनोहर (गुजरात), (8) कोयम्बटूर (तामिलनाडु)
- (9) गरमोती (महाराष्ट्र), (10) अमरावती (महाराष्ट्र) (11) राजपुर (पंजाब)
- (12) वर्धा (महाराष्ट्र), (13) हनुमानगढ़ी (मैसूर),
- (14) डवनूर (केरल) (15) दन्तोर मन्नूरवा ग्राम (म. प्र.)¹⁵

इन ग्रामीण शिक्षा संस्थानों में कई प्रकार के व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम चलाये जाते हैं। फिर भी शिक्षा की बुनियादी अवस्थाओं में जनसामान्य को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने के कारण प्रयास में सरकार आज तक असफल रही है। शिक्षा के विकास व निरक्षरता निवारण के अभियान में नयी-नयी योजनाएँ अस्तित्व में आती गई हैं परन्तु स्वरूप सुविधाओं के नाम पर क्षेत्र बड़े हैं कार्यों का व्यावहारिक स्वरूप सिमटता रहा है। इसी योजनाओं में से केन्द्र सरकार ने "नेहरू युवक केन्द्रों" की स्थापना की, जिनमें ग्रामीण-युवकों के लिए पुस्तकालय व अध्ययन कक्षों की व्यवस्था की। इनसे नवयुवक-मंडलों को सम्बद्ध कराकर उनके सांस्कृतिक परिदृश्य को बदलने का प्रयास किया है। नेशनल बुक ट्रस्ट तथा राजाराम मोहनराय फाउण्डेशन लायब्रेरी ने सावजनिक ग्रन्थालयों को पुस्तकों के वितरण का कार्य सौंपा है ताकि ग्रामीण पाठशालाओं में बालकों के अध्ययन हेतु पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जा सकें। ये सभी कार्यक्रम ग्रन्थालय अधिनियमों के लागू न हो सकने से देश के 16 राज्यों में कारगर सिद्ध नहीं हो सके हैं। देश की अब तक लागू छह पंचवर्षीय योजनाओं में पुस्तकालयों के विकास के बारे में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। जमा कि श्री अजय कुलश्रेष्ठ ने लिखा है। 'जनवरी, 1985 तक 16 राज्यों में से 12 राज्यों अर्थात् 75% क्षेत्र में राज्य के द्वितीय पुस्तकालय स्थापित हो गये। 9 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में से 5

अर्थात् 55 प्रतिशत में केन्द्रीय पुस्तकालयों की स्थापना हुई। 377 जिलों में 205 जिला में अर्थात् 63 प्रतिशत भाग में जिला के क्षेत्रीय पुस्तकालय हाँ गये। इसी प्रकार 5223 विकास खण्डों में से 139 अर्थात् 27 प्रतिशत क्षेत्र में विकास खण्ड पुस्तकालय तथा 5, 66, 878 ग्रामों में से 28, 317 ग्रामों में अर्थात् 5 प्रतिशत ग्रामों में पुस्तकालयों की स्थापना हो गई थी।³⁶

ग्रन्थालय विकास की उपरोक्त प्रगति में 27 प्रतिशत ग्रन्थालय विकास खण्डों में एक 5 प्रतिशत ग्रन्थालय ग्रामों में विशेष प्रगति के परिचायक नहीं है। इनमें निरन्तर वृद्धि की आवश्यकता है और यह वृद्धि ग्रन्थालय अधिनियमों तथा शिक्षा-आयोगों की विशेष अनुशंसाओं पर ही सम्भावित है। "उचित एवं व्यवस्थित पुस्तकालय सेवा का पुस्तकालय विधान द्वारा मायता व व्यवस्था महत्वपूर्ण है। उचित पुस्तकालय विधान एवं जागरूक पुस्तकालय संघ भारत में पुस्तकालयों की उत्थिति में स्थायी योगदान प्रदान कर सकते हैं।"³⁷ भारतीय पुस्तकालय संघ के 32वें अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन मन्तरपुर के अध्यक्षीय भाषण में संघ के तत्कालीन अध्यक्ष टी. एम. राजगोपालन³⁸ ने आशावाचित होकर कहा कि हमारा देश 21वीं सदी की ओर कदम बढ़ा रहा है सब निश्चित ही चौथी पंचवर्षीय योजना में गठित योजना आयोग का "अध्ययन-दल" ग्रन्थालय तथा सूचना-प्रणाली के आधुनिकीकरण पर महत्वपूर्ण कदम उठायेगा। हम आशा करते हैं कि नई शिक्षा प्रणाली में ग्रन्थालयों के विकास पर निश्चित ही सोचा जावेगा।

"ग्रामीण पुस्तकालय विकास में बाधक तत्त्व"

शिक्षा, अध्ययन, ग्रन्थ और ग्रन्थालय मानव जीवन के विकास की वे अतर्हीन सीढ़ियाँ हैं जिनके सहारे वह ज्ञान विज्ञान अध्यात्म दशन और जीवन के धार्मिक सुख की आनन्दभूति प्राप्त कर सकता है। शिक्षा, जिसकी पाने के लिए हम जीवन पयत्न भटकते रहते हैं, स्वतन्त्र भारत के सर्वमानिक स्वरूप के लिए नागरिकों को प्राप्त करना आवश्यक है। बिना पढ़े लिखे वह प्रातात्मिक व्यवस्था में स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर सकता अतः उसका शिक्षित होना ही जागरूक नागरिकता का परिचायक है।

हमने पिछले अनुच्छेद में देखा कि अंग्रेजों के शासन से सत्ताच्युत होने के बाद भारत के लिए एक बड़ी समस्या थी ग्रामीण निरक्षर जनता को साक्षर बनाने की। अपनी जनता का जागरूक, पढ़ा लिखा एवं सफल जीवन यापन करने की दृष्टि से सरकार ने उनका पन्ध लिखने की व्यवस्था करवाई। जहाँ पाठशालाएँ नहीं थी वहाँ पाठशालाएँ खुलाई, प्रोडो व लिए प्रौढशालाएँ व ग्रन्थालयों की व्यवस्था की, माय ही साक्षर हुए लोगों को निरन्तर ज्ञान विज्ञान के अध्ययन से जोड़े रखते हुए उनकी रुचि का साहित्य पत्र-पत्रिका की कोशिश की किन्तु यह कुछ समय तक ही चलता रहा। बाद के वर्षों में शिक्षा मुख्य हो गई और ग्रन्थों का अध्ययन, मनन

के अभाव में थ्रेश्ट ग्रन्थालय सेवाओं का अभाव है वहाँ के स्तर क्या है। "यह आशा की गई है कि 1983-84 तक को समाप्त कर दिया जावगा। चूंकि प्रारम्भिक तथा प्रौढ़ निक्ट सम्बन्धित हैं। अतः इन दोनों कार्यक्रमों का साथ-साथ यह सभी सम्भव होगा जब गांव गांव स्कूल ग्रन्थालय व और उनका भरपूर लाभ ग्रामीण जनता, बाल युवा व महिला

यद्यपि ग्रामीण शिक्षा की प्राप्ताहित करने हेतु देने के लिए, धानद, अन्नमलई व विश्व भारती ग्रामीण स्थापना की गई जिस पर 1970-71 में 27.61 लाख रुपये इतने विशाल राष्ट्र में ग्रामीणों की उच्च शिक्षा पर यह ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति न निम्नलिखित पद्धत 'स्टडीट्यूट' में बदलने के लिए चुना है।

(1) श्री निवेदन (पश्चिमी बंगाल) (2) गांधी (3) जामिया नगर (दिल्ली), (4) उदयपुर (राजस्थान) (5) (6) त्रिचपुरी (उत्तर प्रदेश), (7) मीरमर (गुजरात) (तामिलनाडु) (9) गरमोती (महाराष्ट्र) (10) अमरावती राजपुर (पंजाब) (12) वर्धा (महाराष्ट्र) (13) हनु (14) डवनूर (केरल) (15) इन्दौर बन्तूरवा ग्राम (म.प्र.)

इन ग्रामीण शिक्षा संस्थानों में कई प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम चलाये जाते हैं। फिर भी शिक्षा की बुनियादी सामान्य को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने के कारण प्रयास में असफल रही है। शिक्षा के विकास व निरक्षरता निवारण के अर्थ योजनाएँ अन्तिम में आती गई हैं परिणाम स्वरूप गुरिमाया के हैं कार्यो का व्यावहारिक स्वरूप निमग्नता रहा है। इन्हीं को सारदार ने नेहरू युवक केंद्रों की स्थापनाएँ की, जिनमें ग्राम पुस्तकालयों व अध्ययन कक्षों की व्यवस्था की। इनसे नवयुवक-कारण उनसे सांस्कृतिक परिदृश्य का बदलने का प्रयास निरुद्ध तथा राजाराम माहाराय पाठशाला लामबंदी में। को पुस्तक के पिनगुण का साथ सोपा है ताकि ग्रामीण पाठ के अध्ययन को पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जा सकें। ये सभी अधिनियमों के नामों में गवर्नर संदेश के 16 राज्यों में गए हैं। इन की प्रत्येक लागू पद पंचवर्षीय योजनाओं में के बारे में कार्य विशेष प्रगति नहीं हुई। जैसा कि श्री है। 'जारी, 1985 तक 16 राज्यों में 12 में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित हो गए। 9 केन्द्र

(2) निधनता—

जहाँ ग्रशिक्षा का माझाज्य होगा तो कृषि उद्योग एवं व्यापार में वैज्ञानिक-पद्धति का अभाव भी होगा। जब ग्रामीण, कृषि में अर्थोपाजन नहीं कर पायेंगे तो निधनता बनी रहेगी। भारत में फकी ग्रशिक्षा और निधनता का कारण जनता का भी शिक्षा अध्ययन और विकास की उत्पत्ति भी नहीं करती। इन के अभाव में ग्रामीण जन ग्रन्थालय खोलने, ग्रन्थ को पढ़ने की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाते। जो परिवार धनवान है वे निधन परिवार पर ऋण का बोझ लादे रहते हैं। इन ऐसे परिवार शिक्षा ग्रहण करने ज्ञान की महत्त्वपूर्ण जानकारी लेने की इच्छा नहीं रखते। ग्रामीणों की निधनता का परिणाम है कि गाँवों में ग्रन्थालय विकास पर जन सामान्य का स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं देते।

(3) अध्ययन रुचि का अभाव—

ग्रामीणों का जीवन खेती-बाड़ी, श्रम व भाजन जुटाने की प्रक्रिया में व्यतीत होता है। सभ्य समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के न पहुँच पाने के कारण अधिकांश जनता आज भी निरक्षरता के जंगल में अवस्थित जीवन व्यतीत कर रही है। उनका जीवन में कृषि यंत्रों, बला और दुर्घात पशुओं के व्यवस्थापन में ही गुल मिलता रहा रहने का तात्पर्य यह है कि कृषक जीवन के लिए कृषि सुधार प्राथमिक आवश्यकता रही है और शिक्षा गौण। शिक्षित न होने और क्रमशः साक्षर बनने के बाद भी उनमें पढ़ने की रुचि का विकास नहीं हो सका। अध्ययन में रुचि न होने के कारण ही ग्रामीणों ने ग्रन्थालय विकास की दिशा में विचार नहीं किया। अध्ययन रुचि के अभाव का ही परिणाम है कि आज तक गाँव अध्ययन स्थलों की सुविधाओं से वंचित है।

(4) अभिप्रेरणा का अभाव—

प्रारम्भ से ही जब से ग्रामों में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम चलाये गये और शिक्षा की प्राथमिक पाठशालाएँ प्रारम्भ हुईं, तब प्रौढ शिक्षा निदेशक न ही ग्रन्थालयों पर विशेष जोर दिया और न ही शिक्षा-संचालकों अथवा शिक्षा नीति निर्माताओं ने ही शिक्षा नीति में ग्रन्थालयों की अहमियत को महत्व दिया।

आज 41 वर्ष बाद भी हजारों ऐसे गाँव हैं जहाँ पंचायतें हैं अस्पताल हैं बैंक हैं सोसायटीज हैं, विद्यालय हैं, शिक्षक हैं कमचारीयता है परन्तु कोई भी गाँव वाला को अथवा पंचायत का पेरणा नहीं देता कि वे लोक ग्रन्थालयों की स्थापना कर अपनी बौद्धिक भूमि को मिटा सकत हैं। आज गाँव अपनी मूर्खता और सम्यता का भोग का भूत बन रहे हैं। दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे ग्रामीण एकदम अनभिज्ञ हो रहे हैं। इसका कारण है उन्हें अभिप्रेरित करने की कमी। गाँवों में ना तो पुस्तक प्रदर्शनी ही लगती है, ना ही साहित्यिक गतिविधियाँ इन लोगों में पढ़ने का प्रति भी लगाव नहीं होता है।

व चित्तन कम गाँवों में जा 1956 की लहर चली थी। जिन जोन ग्रन्थालया को जिला ग्रन्थालयों में सम्मिलित किया गया था वह प्रक्रिया क्रमशः समाप्त हो गई। अधिनियमों के पारित न हो सकने के बावजूद भी यदि 41 वर्ष तक उक्त परम्परा बनी रहती तो शिक्षा व साक्षरता व साथ ही ग्रन्थालय का कुछ और हो स्वरूप होता।

‘यह लेट की बात है कि अभी तक हमारे देश में पूरे देश के लिए पुस्तकालय कानून नहीं बन पाया है। इसमें पुस्तकालय विकास की कोई राष्ट्रीय प्रणाली (नेशनल लायब्रेरी सिस्टम) अभी तक नहीं है। कुछ प्रदेशों में प्रदेशीय स्तर के कानून बन और लागू हुए हैं। उन प्रान्तों को छोड़कर शेष प्रदेशों में पुस्तकालय विकास की कोई वैज्ञानिक योजना नहीं है।’³⁹

ग्रन्थालय के क्षेत्र में यह पिछड़ापन क्यों है और विकास में क्या बाधाएँ हैं उन पर हम क्रमशः विचार करें तो हमें पता चलेगा कि ग्रामीण पुस्तकालय के बाधक तत्त्व क्या हैं।

(1) निरक्षरता—

हमारे देश के लिए निरक्षरता अभिशाप रही है। इस दिशा में कितनी ही योजनाएँ तैयार की गईं फिर भी 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के 65 करोड़ लोग निरक्षर ही बने हुए हैं। जो साक्षर हैं वे ग्रामीणों का साक्षर बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहे। “साक्षर व निरक्षर नागरिक धन अर्जित करने तथा उसके उपयोग करने के उपायों में लग रहे हैं तथा उनमें अध्ययन प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है।”⁴⁰

परिणाम स्वरूप वे ग्रन्थालय जसी आवश्यक संस्था का लाभ पाने की इच्छा नहीं रखते। कृषि व्यवसाय, व्यापार, आधुनिक खान पान व गहरी संस्कृति के गुणगामक बनकर सिर्फ आराम की जिज्ञासी जीना चाहते हैं। आज का निरक्षर पीढ़े वाला सोचता है कि पढ़े लिखे में तो हम अनपढ़ अधिक बसाते हैं फिर पढ़ने से क्या लाभ। इसी कारणों से देश में बढ़ती निरक्षरता घटन की बजाय बढ़ती गई है और ग्रन्थालयों के प्रति कोई भुकाव ग्रामीणों का नहीं रह गया है। भारत में निरक्षरता का प्रतिशत 1951 में 1981 तक निम्नानुसार रहा है।⁴¹

वर्ष	पुरुष	महिला	योग
1951	24.9%	7.9%	16.6%
1961	34.4%	12.9%	24.0%
1971	39.51%	18.44%	29.45%
1981	46.74%	24.88%	36.00%

(2) निधनता—

जहाँ अधिकांश रा मास्त्राज्य होगा तो कृषि उद्योग एवं व्यापार में वैज्ञानिक-पद्धति का अभाव भी होगा। जहाँ ग्रामीण, कृषि में अर्थोपाजन नहीं कर पायेंगे ता निधनता बनी रहेगी। भारत में पानी अधिकांश और निधनता के कारण जनता कभी शिक्षा अध्ययन और विवास की वसुधता भी नहीं करती। घन र अभाव में ग्रामीण जन ग्रन्थालय खोलने, ग्रन्थ को पढ़ने की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाते। जो परिवार धनवान है वे निधन परिवारों पर श्रुण का बोझ लाद रहते हैं। ग्रन्थ एम परिवार शिक्षा ग्रहण करके पान की महत्त्वपूर्ण जानकारी लेन की इच्छा नहीं रखते। ग्रामीणों की निधनता का परिणाम है कि गावों में ग्रन्थालय विकास पर जन सामान्य व स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं देते।

(3) अध्ययन रुचि का अभाव—

ग्रामीणों का जीवन खेती-बाड़ी, श्रम व भोजन जुटाने की प्रक्रिया में व्यतीत होता है। समय समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के न पहुँच पाने के कारण अधिकांश जनता आज भी निरक्षरता के चंगुल में अविश्वसित जीवन व्यतीत कर रही है। उनकी जीवन में कृषि यन्त्रों, बीजों और दुग्ध पशुओं के व्यवस्थापन में ही सुग मिलता रहा कहन का तात्पर्य यह है कि कृषक जीवन के लिए कृषि सुधार प्राथमिक आवश्यकता रही है और शिक्षा गौण। शिक्षित न होने और क्रमशः साक्षर बनने के बाद भी उनमें पढ़न की रुचि का विकास नहीं हो सका। अध्ययन में रुचि न होने के कारण ही ग्रामीणों ने ग्रन्थालय विकास की दिशा में विचार नहीं किया। अध्ययन रुचि के अभाव का ही परिणाम है कि आज तक गाव अध्ययन स्थलों की सुविधाओं से वंचित है।

(4) अभिप्रेरणा का अभाव—

प्रारम्भ से ही जब से ग्रामों में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम चलाये गये और शिक्षा की प्राथमिक पाठशालायें प्रारम्भ हुईं तो प्रौढ शिक्षा निदेशकों ने ही ग्रन्थालयों पर विशेष जोर दिया और न ही शिक्षा-संचालक अथवा शिक्षा नीति निर्माताओं ने ही शिक्षा-नीति में ग्रन्थालयों की अहमियत को महत्त्व दिया।

आज 41 वर्ष बाद भी हजारों ऐसे गाव हैं जहाँ पचायतें हैं, अस्पताल हैं, बैंक हैं, सोसायटीज हैं, निधालय हैं शिक्षक हैं कमचारीगण हैं परन्तु कोई भी गाव वालों को अथवा पचायतों को प्रेरणा नहीं देत कि वे लोक-ग्रन्थालयों की स्थापना कर अपनी बौद्धिक भूख को मिटा सकते हैं। आज गाव अपनी सस्कृति और सन्धता के गौरव का भूलत जा रहे हैं। दुनिया में नाम के क्षेत्र में जा परिवर्तन हो रहे हैं उनमें ग्रामीण एकदम अनभिज्ञ हो रहे हैं। इसका कारण है उन्हें अभिप्रेरित करने की कमी। गावों में ना तो पुस्तक प्रदर्शनी ही लगती है, ना ही साहित्यिक गतिविधियाँ अतः लोगों में पढ़ने के प्रति भी लगाव नहीं होता है।

(5) ग्रन्थालय चेतना का अभाव—

ग्रामीणा में जहाँ एक ओर पढ़न लिखन में विशेष रुचि नहीं रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूला में ग्रन्थालय सुविधा नहीं है और ताक ग्रन्थालयों का गान गाय जाल नहीं पना है परिणाम स्वरूप ग्रन्थालय के महत्त्व, उद्देश्य एवं लाभों से ग्राम जनना अनभिज्ञ है। चेतना का अभाव है तथा निरक्षरता से उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है।

(6) दोषपूर्ण सरकारी नीति—

शिक्षा में अथवा साक्षरता कार्यक्रम में जब भी सरकारी नीतियाँ बनी हैं, ग्रन्थालय की उपादेयता को गौण माना गया। यद्यपि योजना आयोग, ग्रन्थालय सलाहकार समिति एवं शिक्षा आयोगों ने अपना सकारणिकी में ग्रन्थालयों की शिक्षा का केन्द्र बिन्दु माना और यहाँ तक कहा कि जिस विद्यालय में ग्रन्थालय व खेलकूद जैसी सुविधा न हो उन्हें सरकारी सहायता नहीं दी जानी चाहिए। यही बात प्रौढ शिक्षा में सहयोगी ग्रन्थालयों के लिए बही गई थी किन्तु अब ऐसा जा रहा है कि निरक्षरता निवारण का कार्यक्रम कई दिशाओं में चल रहा है जहाँ ग्रन्थालयों के अभाव में उनके साक्षर बनाने की निरन्तरता को खतरा है। सत्त शिक्षा के लिए साक्षरों के पास कोई साधन नहीं है।

भास्करनाथ तिवारी का मत है कि “अब तक औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में निरन्तर पुस्तकालयों की उपेक्षा की जाती रही है। उससे परिणाम विपरीत होते हुए भी हमने इस तथ्य का कभी स्वीकार नहीं किया। शिक्षा शास्त्रियों व नियाजकों से हमारा अनुरोध है कि अब तक के इतिहास में सन्तुष्टि में पुस्तकालयों की उपादेयता को स्वीकार करें और औपचारिक एवं प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों में इस प्रवृत्ति तथा उपयोगी माध्यम को समृद्ध व समुन्नत कर उपयुक्त स्थान प्रदान करें।”⁴²

“हमारे देश में शासक इस ओर से पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है। यही कारण है कि समस्या ज्यादा बनी हुई है।”⁴³

(7) ग्रन्थालय सघों की निष्पीड्यता—

हमारा देश एक विशाल भौगोलिक सीमाओं सङ्कुनिया, कलाओं व साहित्य साधनाओं का देश है। ज्ञान का अपार भण्डार यहाँ के मनोपियों साधु सन्ना व महापुरुषों ने धरोहर के रूप में हमें दिया है। इस धरोहर को सँवरने व सहेजने के लिए सरकार ने बड़े-बड़े अयोगार, भूचना केन्द्र शोध प्रायोगिकीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करवाये हैं। 1933 में स्थापित भारतीय ग्रन्थालय मध्य व भारत में ग्रन्थालय आदान-प्रदान के प्रणेता पदमयी डा. श्यामली रामामृत रंगनाथन के प्रयास से भारतीय ग्रन्थालय-सेवाओं का नई दिशा प्राप्त हुई। उनके अनुकरणीय प्रयास के उपरान्त भी 50 वर्ष के लम्बे अन्तराल में बीच सिर्फ पाँच राज्यों में ही पुस्तकालय विधान पारित हो सके हैं।

उनकी प्रेरणा से ही देश के ग्रामीण राज्यों में ग्रामीण विकास को व्यापक बनाने व देश में फैली निरक्षरता को मिटाने हेतु राज्या म प्रादेशिक ग्रामालय सघों का निर्माण भी हुआ, किन्तु शासकीय सहायता के बिना राज्यों के ग्रामालय सघ अपने उद्देश्यों में उतने सफल नहीं हो पाये। ग्रामीण सघों ने अपने उद्देश्यों में सफल न हो सकने के बहुतेरे कारण हो सकते हैं किन्तु नव्वे समय से आन्दोलनों की गति प्रदान करने वाले भारतीय ग्रामालय सघ को वह सफलता नहीं मिल सकी है, जिसकी कल्पना स्व० डा० रमनाथन ने की थी। 'यद्यपि भारत में अनेक पुस्तकालय सघ हैं, परन्तु वे प्रायः प्रभावशून्य हैं। भारतीय स्तर पर 1933 में भारतीय पुस्तकालय सघ की स्थापना हुई थी, परन्तु यह सघ आवश्यक नेतृत्व देने में असफल रहा। यह जनता एवं सरकार दोनों में ही पुस्तकालय चेतना उत्पन्न न कर सका।' 44

(8) राष्ट्रीय ग्रामालय नीति का अभाव—स्वाधीनता के बाद देश के विकास हेतु बहुत से आयोजन बनाये गये थे, कृषि, शिक्षा एवं उद्योग व्यापार हेतु कई नीतियाँ निर्मित हुई थी। क्रमशः सभी प्रकार के आयोजन व समिति की नीतियाँ ने भारत की उन्नति में काफी प्रशंसनीय कार्य किया तथा सफलताएँ भी मिली। किन्तु राष्ट्रीय ग्रामालय विधेयक पास होने के बाद जिस ढंग में पूरे राष्ट्र में कार्य सम्पन्न होना था नहीं हो पाया। जो स्थान प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षा में व प्रौढ ग्रामवासी समाज शिक्षा में ग्रामालयों को मिलना चाहिये था वह आज तक नहीं मिल पाया, कुछ राज्यों के अलावा। बच्चों की अध्ययन रुचियों का आज तक हमारे बाल वैज्ञानिक, शिक्षाविद् व नीति नियामक ध्यान नहीं रख सके हैं। 'हमारे देश में बहुतेरे स्कूलों में पुस्तकालय नहीं हैं, सावजनिक पुस्तकालयों का विस्तार नहीं हुआ है। यह सभी सम्भव होगा जब राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति को दश-भर में लागू किया जाएगा'। 45

सन्दर्भ ग्रन्थ

- 1 महात्मा गांधी हरिजन 1937
- 2 गुप्ता (एल एल) तथा शर्मा (डी डी) ग्रामीण समाज शास्त्र, आगरा साहित्य भवन, 1980, पृ 355
- 3 परिहार (मदनमोहन) पुस्तकालयों का इतिहास परिशिष्ट (अ) भोपाल मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, 1974 पृ 270 मूल लेखक अल्फ्रेड हैसल।
- 4 चौवे (सरयू प्रसाद) भारतीय शिक्षा की समस्याएँ आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर 1976, पृ 117
- 5 कुल श्रेष्ठ (अजय) तुलनात्मक पुस्तकालय अध्ययन जयपुर रचना प्रकाशन 1980, पृ 3

- 6 बगरी (एन¹ डी) पुस्तकालय पद्धति, इलाहाबाद, नीलम प्रकाशन 1973, पृ 60
- 7 सक्सेना (एत एस) पुस्तकालय संगठन के सिद्धान्त भोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ 1981, पृ 216
- 8 Ranganathan (SR) Five laws of Library Science Ed 2 1957, P 81
- 9 रंगनाथन (एस आर) पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका दिल्ली, एशिया पब्लिक हाउस, 1963, पृ 322 अनुवाद उमेश दत्त शर्मा ।
- 10 जौहरी (बी पी) तथा पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर, 1981, पृ 244
- 11 Ranganathan (SR) Library Legislation Hand book of Madras Library Act madras Library Association 1935 P 56
- 12 सक्सेना (एल एस) पुस्तकालय संगठन के सिद्धान्त, भोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1981, पृ 219
- 13 जायसवाल (सीताराम) भारतीय शिक्षा का इतिहास लखनऊ प्रकाशन केन्द्रो 1987, पृ 334—35
- 14 जौहरी (बी पी) तथा पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा का इतिहास आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर 1981, पृ 109
- 15 पृ 110,
- 16 पृ 111
- 17 पृ
- 18 तिवारी (भास्करनाथ) सम्पादन प्रीत शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद, वोहरा, 1980 पृ 33
- 19 India Library (Advisory Committee for) A Report 1970 P 32
- 20 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (मुभाषचन्द) पुस्तकालय संगठन एवं संचालन, जयपुर, राज हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1978 पृ 204
- 21 हिन्दी विश्व कोष (पक्षा से प्राम तक) वाराणसी, ना प्र सभा खण्ड 7 पृ 294
- 22 प्राट शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद, वोहरा प्रकाशन 1980 पृ 102 सम्पादन भास्कर नाथ तिवारी ।

- 23 Gokhale (BG) The making of Indian Nation, Barmay, Asia Publishing House, 1960 P 146
- 24 India, Constitution, Article 45 Jan 1950
- 25 India, Publication Division, 1981, P 46
- 26 भारत प्रकाशन विभाग, 1979 पृ 64 एवं 65
- 27 भारत प्रकाशन विभाग, 1967 पृ 60
- 28 तिवारी (भास्कर नाथ) सम्पादक प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद बोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1980 पृ 65
- 29 पाठक (पी डी) तथा त्यागी (जी एस जी) भारत में शिक्षा दशक और शैक्षणिक समस्याएँ, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1984/85, पृ 425
- 30 कुलश्रेष्ठ (अजय) तुलनात्मक पुस्तकालयाध्यक्षता, जयपुर, रचना प्रकाशन 1986, पृ 7
- 31 हैसल (अल्फ्रेड) पुस्तकालयो का इतिहास (परिशिष्ट) भोपाल, हि ग्र अकादमी 1974 पृ 274 अनुवादक मदनसिंह पग्गहार,
- 32 वनर्जी (प्रशांत कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन, भोपाल, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1972 पृ 14
- 33 तिवारी (भास्करनाथ) प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद बोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1980 पृ 67
- 34 Times of India Directory and whos who 1971
- 35 हिन्दुस्तान-वार्पिकी, 1975, पृ 177
- 36 कुलश्रेष्ठ (अजय) तुलनात्मक पुस्तकालयाध्यक्षता जयपुर, रचना प्रकाशन 1986, पृ 9
- 37 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचंद) पुस्तकालय संगठन एवं संचालन जयपुर राजस्थान, हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1972, पृ 3
- 38 ILA Some aspects of Library development in India Indian Library Association, XXXII All India Library Conference Anantpur presidential Address 3 6 Jan 87 P 2
- 39 बगरी (एन डी) भारत में पुस्तकालयो का भविष्य, लेख की पुस्तक पुस्तकालय पद्धति उद्भूत, इलाहाबाद, नीलाम प्रकाशन 1973, पृ 31
- 40 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचंद) पुस्तकालय तथा प्रौढ

शिक्षा लेखकद्वय की पुस्तक पुस्तकालय संगठन एवं संचालन से जयपुर राज हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1972 पृ 96

- 41 Khanna (SD) etc, History of Indian Education and its contemporary problems with special refrence to National development Delhi, Doaba publishers House, 1984 P 284
- 42 तिवारी (भास्कर नाथ) सम्पा प्रौढ शिक्षा भार पुस्तकालय 1980, पृ 39
- 43 वैतर्जी (प्रणात कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन, भोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1972 पृ 3
- 44 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचन्द) पुस्तकालय संगठन एवं संचालन, 1972 पृ 207
- 45 ग्रंथ लेखक द्वारा लिखित, सम्पादक के नाम पर, नवभारत टाइम्स, बम्बई 25/11/87

ग्रामीण विकास के आधार ग्राम पुस्तकालय "

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसमें निहित पुस्तकालयों, शैक्षणिक सम्पत्तियों एवं औद्योगिक इकाइयों से आयी जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश जितना उन्नतिशील होगा उसमें उतने ही शोध संस्थान, औद्योगिक केन्द्र, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य अधिक होंगे और इन सभी कमशालाओं में निश्चित ही बौद्धिक भूख को मिटाने के लिए पुस्तकालयों का प्रबन्ध होगा। किन्तु भारतवर्ष जैसे प्रजातान्त्रिक देश की प्रगति उसका ग्रामीण अवस्था के विकास पर निर्भर करती है। यहाँ वर्तमान में भी 70% जनता गाँवों में वास करती है जिनका जीवन खेती, पशु पालन एवं भजन-पूजन में व्यतीत होता है। पिछले पाँच छ बरसों से अवश्य ग्रामीणों की कृषि-उत्पादन हो रही है। विपुल उत्पादन, आहार पोषण, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन एवं खेल कूद इत्यादि कार्यक्रमों ने गाँवों में एक नई लहर एक नवीन चेतना ला दी है। इन कार्यक्रमों के साथ-साथ पुस्तकालय विकास की कड़ियाँ भी क्रमशः गाँव-गाँव जुटनी चाहिए।

जर्मनी, सोवियत रूस, अमेरिका, फ्रांस स्पेन, ब्रिटन जैसे महान् राष्ट्रों का इन कार्यक्रमों की सफल बनाने में पूर्ण योग रहा है। फिर भी कुछ मामला में ग्रामीण किसान व जनता दूँत पीछे हैं जैसे (1) शिक्षितों की कम संख्या (2) खेती की अपूर्ण जानकारी, (3) पुस्तकालयों का अभाव।

यदि गाँव-गाँव ग्रामीण-पुस्तकालय हो तो कृषक जनता का उनका दृष्ट न हो जितना उँह उठाना पड़ता है। भारत गाँवों का देश है गाँवों से ही सफलता की प्राप्ति की जा सकती है, अतः स्थानीय प्रशासन का यह दायित्व हो जाना चाहिए कि प्रत्येक गाँव पुस्तकालयों में सुसज्जित कर लिये जाय। यह तो सभी अव्यक्ती तरह जान रहे हैं कि सरकार हमारे प्रत्येक कार्य में सहायता देने का तत्पर है, किन्तु जनता का क्या उत्तरदायित्व है यह उन्हें जानना चाहिए। जनता जनता के सहयोग की आकांक्षा भी पुस्तकालय निर्माण के विकास में निहायन करती है।

वर्तमान भारत में पंचायतों का विकास मण्डल एवं सामुदायिक विकास योजनाओं ने जो नग्न महत्वाकांक्षी हैं वह स्तुत्य हैं। फिर भी इनके कार्य में

के लिये ग्राम पुस्तकालया का निर्माण करें शासन से सुविधा जुटाने की अपील करें। जनता पूर्ण सहयोग दे एवं संचालन में मदद पहुँचाय। राजनीतिक दल एवं स्वार्थी ग्रामीण पुस्तकालयो एवं वाचनालयो का दुरुपयोग न करें।

जन-चेतना का देश के निर्माण एवं सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक कल्याण में जो महत्वपूर्ण स्थान है उसे ध्यान में रखात हुए ग्राम-पुस्तकालया के उत्थान के लिये हम भरसक प्रयत्न करना चाहिए ताकि दश का वर्तमान तो सुदृढ़ हो ही और भविष्य का माग भी धुल जाये।

यदि ऐसा होगा तो निसन्देह ही ये पुस्तकालय ग्रामीण चेतना के आधार होंगे शिक्षा एवं स्वाध्याय के साधन होंगे, निरक्षरताहारी होंगे। साथ ही राष्ट्रीय विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। क्याकि कार्लोइन का कहना है कि 'य पुस्तकालय ही देश के सच्चे विश्वविद्यालय है।' इ ही पर देश और देश की उन्नति निर्भर होती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि ग्रामों के समग्र विकास के लिए केवल हल चलाना और फल पैदा करना ही काफी नहीं है। समग्र विकास के लिये गाँवों की विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक प्रवृत्तियों का विकास भी आवश्यक है। हल चलाकर अन्न उपजाना तो शारीरिक श्रम है, किन्तु उन्नत तरीकों के औजारों से कृषि करना, फल का संरक्षण करना वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इस प्रकार के कार्य करने के लिए कृषि विषय का साहित्य कृषकों तक पहुँचना चाहिये। इसका निराकरण एकमात्र ग्राम पुस्तकालया से हो सकता है, ये पुस्तकालय ही उनके पथ प्रदर्शक हो सकेंगे।

—————

एक पक्षीय एव एकामी रहे ह। ग्राम पंचायत एव समाज कल्याण विभाग की सहायता से प्रत्येक पंचायत के द्वा पर पुस्तकालय खोले गये थे, किन्तु आज गावों में विगत 10 वर्षों में विजली, नहर-सड़क निर्माण काय, महिला कल्याण, वासवाड़ी परिवार नियोजन, प्रौढ शिक्षा समाज-कल्याण एव विपुल उत्पादन व खाद प्रयोग के सभी कार्यक्रम हाते रह किन्तु पुस्तक प्रदर्शनी, पुस्तकालय दिवस या पुस्तकालय स्थापना जैसी घटनाएँ नहीं घटती, जिसका लाभ बच्चे बूढ़े, स्त्री पुरुष, मजदूर, किसान सभी उठा सकते थे।

उपरोक्त कार्यक्रमों की सफलता जन-जीवन के साक्षर होने पर ही निर्भर करती है, क्योंकि शिक्षा आदमी का आदमी बनाती है। पुस्तकालय जसी महान सम्पदा जनता में चेतना लाने का काम कर सकती है। अपवाद स्वरूप इक्के-दुक्के पुस्तकालयों का होना अथवा काना राजा होना है, अतः समस्त राष्ट्र में इनकी मांग है।

यह तो हमें मानकर चलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने हम ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की योजनाएँ दी किन्तु स्थानीय प्रशासन ने उन योजनाओं को मटियाभेट कर दिया।

वर्तमान भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बुक बक की योजना अवश्य प्रारम्भ की गई है जो ग्रामीण एव शहरी शिक्षण मन्त्रालयों के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा रही है। आज भी स्थानीय निकायों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे पुस्तकालयों की स्थापना करें और ग्रामीण विकास की बड़ी में राष्ट्र सेवा करें।

ग्रामीण विकास में आभार इन पुस्तकालयों से निश्चित ही हम कुछ महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं जो दस प्रकार से हैं— (1) शैक्षणिक विकास में सहायता (2) कृषि कार्य में उपयोगी, (3) नैतिक एवं चार्ित्रिक विकास, (4) राजनीतिक जागरूकता (5) आर्थिक एवं वाणिज्यिक लाभ (6) मनोवैज्ञानिक विकास, (7) चुस्त प्रशासन (8) राष्ट्रीय विकास एवं जन चेतना में सहयोगी।

इन लाभों के अलावा यदि हम विदेश में चल रहे ग्राम-पुस्तकालयों में एव उनके द्वारा की जा रही सामाजिक कल्याण एव प्रौढ शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं की चर्चा करें तो हम अपनी स्थिति का सहज ही आभास हो जायेगा लेकिन विदेशों की ओर हमारी परिस्थितियाँ एव सी नहीं है। हम अपने आपको तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़ा हुआ या असम्य मानकर होन भावना का अपने मन में स्थान न दें।

आज हम यह निश्चय कर लें कि हम गाँवों से निरक्षरता को मिटाना है, शिक्षा को बम भरना है और आपसी मनमुटाव दूर कर शांति और सहयोग की भावना के साथ जीना है तो तत्कालीन परिस्थितियाँ में ही जनता में जागृति लाने

के लिए ग्राम पुस्तकालयों का निर्माण करें शासन से सुविधा जुटाने की प्रतीति करें। जनता पूर्ण सहयोग दे एवं मंचालन में मदद पहुँचाए। राजनीतिक दल एवं स्वार्थी ग्रामीण पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का दुरुपयोग न करें।

जन चेतना का देश के निर्माण एवं सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक कल्याण में जो महत्वपूर्ण स्थान है उसे ध्यान में रखते हुए ग्राम-पुस्तकालयों के उत्थान के लिये हमें भरमँक प्रयत्न करना चाहिए ताकि देश का वर्तमान तो सुदृढ़ हो ही और भविष्य का मार्ग भी खुल जाय।

यदि ऐसा होगा तो निमग्ने ही ये पुस्तकालय ग्रामीण चेतना के आधार होंगे, शिक्षा एवं स्वाध्याय के साधन होंगे, निरक्षरताहारी होंगे। साथ ही राष्ट्रीय विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। क्योंकि कालाहिन का कहना है कि 'ये पुस्तकालय ही देश के मंचे विश्वविद्यालय हैं।' इन्हीं पर देश और देश की उन्नति निर्भर होती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि ग्रामों के समग्र विकास के लिए केवल हल चलाना और फसल पैदा करना ही काफी नहीं है। समग्र विकास के लिए गाँवों की विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक प्रवृत्तियों का विकास भी आवश्यक है। हल चलाकर अन्न उपजाया तो शारीरिक श्रम है, किन्तु उन्नत तरीकों के अज्ञान से ह्रास करना, फसल का संरक्षण करना वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इस प्रकार के कार्य करने के लिए ह्रास विषय का साहित्य ह्रासकों तक पहुँचना चाहिये। इसका निराकरण एकमात्र ग्राम पुस्तकालयों से हो सकता है, ये पुस्तकालय ही उनके पथ प्रदर्शक हो सकेंगे।

ग्रामीण पुस्तकालयों से लाभ

विश्व में वैज्ञानिक विकास ने साथ-साथ ज्ञान का अद्भुत घमावा हो रहा है। अनेक विषयाएँ एवं लोक जीवन को झरझोर देने वाला। साहित्य अग्रिम रूप में लिखा एवं प्रकाशित किया जा रहा है जिसको पढ़ने वाले पाठक उतनी सरलता में नहीं है और न ही उस साहित्य का समुचित उपयोग हो रहा है। रचनाएँ एवं साहित्य का अधिकाधिक उपयोग हो इसी उद्देश्य से प्रत्येक राष्ट्र शिक्षा सम्वन्धी एवं उनमें निहित पुस्तकालयों पर ज़रूर दे रहे हैं।

भारत गाँवों का देश है इसकी आत्मा गाँवों में वास करती है। इन आत्माओं का साक्षात्कार पुस्तकों, समाचार पत्रों, ज्ञान विज्ञान की विविध पत्रिकाओं में मुद्रित या प्रकाशित विचारों से होना चाहिए। कृषक, मजदूरों, स्त्री-पुरुषों में शिक्षा के प्रति रुझान लाने का प्रयास हमारी सरकार न किया है। बच्चा के लिए प्रत्येक गाँव में माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की है। लेकिन वे लोग जो पढ़े हैं किन्तु लम्बे अरसे से नहीं पढ़ रहे हैं या पुस्तकों के सरसंग में नहीं आये हैं उनके लिए शासन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही पुस्तकालय स्थापना की कोशिश की है। वतमान तक हम सभी गाँवों में पुस्तकालय नहीं खोल पाये हैं फिर भी प्रयास जारी है। आज ग्राम पुस्तकालयों का हाना राष्ट्रीय विकास के हित में है, इनका प्रसार एवं प्रचार देश के कोने-बाने में पहुँचाना है। जो निरक्षर है उन्हें भी इन पुस्तकालयों की ज्ञान गंगा से बौद्धिक पावनता प्रदान की जानी चाहिए। ग्रामों में ये पुस्तकालय प्रत्येक ग्राम निवासियों के लिए ज्ञान के दरवाज़े हैं जिनमें देश विदेश के मानव विकास की भाँवी उन्हें दृष्टिगोचर होनी है। दैनिक जीवन की गतिविधियों से अछूत न रह पायें इसके लिए पुस्तकालयों की साथ ज्ञानवत्ता का लाभ ग्रामवासियों का मिलना चाहिए, क्योंकि इनसे निम्नलिखित लाभ हैं।

(1) जनशक्ति विकास में सहायक — भारत की 70 प्रतिशत जनता ग्रामों में निरक्षर है, शिक्षा में पिछड़ी है। शासन का पूरा प्रयास हो रहा है कि प्रत्येक 6 मील के क्षेत्र में एक पाठशाला खोली जाये जिससे शिक्षा का पूरा लाभ सभी को मिले। इन पाठशालाओं के साथ ही विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय उपलब्ध होना चाहिए। पंचायतों द्वारा खोले गये पुस्तकालयों में ग्रामीण जनता का विभिन्न विषयों का धार्मिक, राजनैतिक कृषि एवं मनोरंजनात्मक पुस्तकों प्रदान की जानी चाहिए। जो निरक्षर है उनके लिए पुस्तकालय में ही प्रौढ़ कक्षाएँ लग जिन्हें

उनकी प्रेरणा से ही देश के अग्र राज्या में ग्रन्थालय विकास को व्यापक बनाने व देश में फैली निरक्षरता को मिटाने हेतु राज्या में प्रादेशिक ग्रन्थालय सघा का निर्माण भी हुआ, किन्तु शासकीय सहायता के बिना राज्यों के ग्रन्थालय सघ अपने उद्देश्यों में उतने सफल नहीं हो पाये। ग्रन्थालय सघों के अपने उद्देश्यों में सफल न हो सकने के बहुतेरे कारण हो सकते हैं किन्तु लम्बे समय से आन्दोलनों की गति प्रदान करने वाले भारतीय ग्रन्थालय सघ का वह सफलता नहीं मिल सकी है, जिसकी कल्पना स्व० डा० रंगनाथन ने की थी। 'यद्यपि भारत में अनेक पुस्तकालय सघ हैं, परन्तु वे प्रायः प्रभाव शून्य हैं। भारतीय स्तर पर 1933 में भारतीय पुस्तकालय सघ की स्थापना हुई थी परन्तु यह सघ आवश्यक नेतृत्व देने में असफल रहा। यह जनता एवं सरकार दोनों में ही पुस्तकालय चेतना उत्पन्न कर सका।' 44

(8) राष्ट्रीय ग्रन्थालय नीति का अभाव—स्वाधीनता के बाद देश के विकास हेतु बहुत से आयोजन किये गये थे, कृषि, शिक्षा एवं उद्योग व्यापार हेतु कई नीतियाँ निर्मित हुई थी। क्रमशः सभी प्रकार के आयोग व समिति की नीतियों ने भारत की उन्नति में काफी प्रशसनीय कार्य किया तथा सफलताएँ भी मिलीं। किन्तु राष्ट्रीय ग्रन्थालय विधेयक पास होने के बाद जिस उम्र से पूरे राष्ट्र में कार्य सम्पन्न होना था नहीं हो पाया। जो स्थान प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षा में व प्रौढ़ अथवा समाज शिक्षा में ग्रन्थालयों को मिलना चाहिये था वह आज तक नहीं मिल पाया कुछ राज्यों के अलावा। ग्रन्थालयों की अध्ययन रुचियों का आज तक हमारे बाल वैज्ञानिक, शिक्षाविद् व नीति नियामक ध्यान नहीं रख सके हैं। 'हमारे देश में बहुतेरे स्कूलों में पुस्तकालय नहीं हैं सावजनिक पुस्तकालयों का विस्तार नहीं हुआ है। यह तभी सम्भव होगा जब राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति को दश भर में लागू किया जाएगा' 45

संदर्भ ग्रन्थ

- 1 महात्मा गांधी, हरिजन 1937
- 2 गुप्ता (एल एल) तथा शर्मा (डी डी) ग्रामीण समाज शास्त्र, आगरा साहित्य भवन, 1980, पृ 355
- 3 परिहार (मदनसिंह) पुस्तकालयों का इतिहास परिशिष्ट (अ) भोपाल मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1974 पृ 270 मूल लेखक अल्फ्रेड हैसल।
- 4 चौबे (सरयू प्रसाद) भारतीय शिक्षा की समस्याएँ आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर 1976, पृ 117
- 5 कुल श्रेष्ठ (अजय) तुलनात्मक पुस्तकालय अध्ययनता जयपुर रचना प्रकाशन 1986, पृ 3

- 6 बगरी (एन डी) पुस्तकालय पद्धति, इलाहाबाद, नीलम प्रकाशन 1973, पृ 60
- 7 सक्सेना (एल एस) पुस्तकालय संगठन के सिद्धांत भोपाल, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ 1981, पृ 216
- 8 Ranganathan (SR) Five laws of Library Science Ed 2 1957, P 81
- 9 ग्गनाथन (एस आर) पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका दिल्ली, एशिया पब्लिक हाउस, 1963, पृ 322 अनुवाद उमेश दत्त शर्मा ।
- 10 जौहरी (बी पी) तथा पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर 1981, पृ 244
- 11 Ranganathan (SR) Library Legislation, Hand book of Madras Library Act madras Library Association 1935 P 56
- 12 सक्सेना (एल एस) पुस्तकालय संगठन के सिद्धांत, भोपाल, मध्यप्रदेश हिं ग्रंथ अकादमी 1981, पृ 219
- 13 जायसवाल (सीताराम) भारतीय शिक्षा का इतिहास लखनऊ प्रकाशन केन्द्रो 1987, पृ 334—35
- 14 जौहरी (बी पी) तथा पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा का इतिहास आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर 1981 पृ 109
- 15 पृ 110
- 16 पृ 111
- 17 पृ
- 18 तिवारी (भास्करनाथ) सम्पादन प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद, बोहरा, 1980 पृ 33
- 19 India Library (Advisory Committee for) A Report 1970 P 32
- 20 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचन्द्र) पुस्तकालय संगठन एवं संचालन, जयपुर राज हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1978 पृ 204
- 21 हिन्दी विश्व कोष (पक्षा से प्राग तक) वाराणसी, ना सभा खण्ड 7 पृ 294
- 22 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद, बोहरा प्रकाशन 1980 पृ 102 सम्पादन भास्कर नाथ तिवारी ।

- 23 Gokhale (BG) The making of Indian Nation, Bombay, Asia Publishing House, 1960 P 146
- 24 India, Constitution, Article 45 Jan 1950
- 25 India, Publication Division, 1981, P 46
- 26 भारत प्रकाशन विभाग, 1979 पृ 64 एवं 65
- 27 भारत प्रकाशन विभाग, 1967 पृ 60
- 28 तिवारी (भास्कर नाथ) सम्पादक प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद बोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1980 पृ 65
- 29 पाठक (पी डी) तथा त्यागी (जी एस जी) भारत में शिक्षा दशक और शैक्षणिक समस्याएँ, भागरा विनोद पुस्तक मन्दिर, 1984/85, पृ 425
- 30 कुलश्रेष्ठ (अजय) तुलनात्मक पुस्तकालयाध्यक्षता, जयपुर, रचना प्रकाशन 1986 पृ 7
- 31 हंसल (मल्होत्रा) पुस्तकालयो का इतिहास (परिशिष्ट) भोपाल, हि प्र प्रकादमी 1974 पृ 274 अनुवादक मदनसिंह परिहार,
- 32 वनर्जी (प्रधानत कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन, भोपाल, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ प्रकादमी 1972 पृ 14
- 33 तिवारी (भास्करनाथ) प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय इलाहाबाद बोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1980 पृ 67
- 34 Times of India Directory and whos who 1971
- 35 हिन्दुस्तान-नापिकी 1975, पृ 177
- 36 कुलश्रेष्ठ (अजय) तुलनात्मक पुस्तकालयाध्यक्षता, जयपुर, रचना प्रकाशन 1986 पृ 9
- 37 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचन्द्र) पुस्तकालय संगठन एवं संचालन जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ प्रकादमी 1972, पृ 3
- 38 ILA Some aspects of Library development in India Indian Library Association XXXII All India Library Conference Anantpur presidential Address 36 Jan 87 P 2
- 39 वगरी (एन डी) भारत में पुस्तकालयो का भविष्य लेख की पुस्तक पुस्तकालय पद्धति उद्भूत, इलाहाबाद नीलाम प्रकाशन 1973, पृ 31
- 40 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचन्द्र) पुस्तकालय तथा प्रौढ

शिक्षा लेखकद्वय की पुस्तक पुस्तकालय संगठन एवं संचालन से जयपुर राज हिंदी ग्रंथ अकादमी 1972 पृ 96

- 41 Khanna (SD) etc, History of Indian Education and its contemporary problems with special reference to National development Delhi, Doaba publishers House, 1984 P 284
 - 42 तिवारी (भास्कर नाथ) सम्पा प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय 1980, पृ 39
 - 43 वैतर्जी (प्रशांत कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन, भोपाल, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1972 पृ 3
 - 44 श्रीवास्तव (श्यामाशय) तथा वर्मा (सुभाषचंद्र) पुस्तकालय संगठन एवं संचालन, 1972 पृ 207
 - 45 ग्रंथ लेखक द्वारा लिखित, सम्पादक के नाम पर, नवभारत टाइम्स, दम्यर्ट 25/11/87
-

3 ग्रामीण विकास के आधार ग्राम पुस्तकालय ...

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसमें निहित पुस्तकालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं औद्योगिक इकाइयों से आती जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश जितना उन्नतिशील होगा उतना उतनी ही शोध संस्थान, औद्योगिक केंद्र, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य अधिक हाथ और इन सभी कमशालाओं में निश्चित ही बौद्धिक भूत्व को मिटाने के लिए पुस्तकालयों का प्रचलन होगा। किंतु भारतवर्ष जस प्रजातान्त्रिक देश की प्रगति उसमें ग्रामीण अंचलों के विकास पर निर्भर करती है। यहाँ वर्तमान में भी 70% जनता गावों में वास करती है जिनका जीवन खेती, पशु पालन एवं भजन पूजन में व्यतीत होता है। पिछले पांच छ बरसों से अवश्य ग्रामों की बाया पलट हो रही है। विपुल उत्पादन, आहार पोषण, मत्स्य पालन, मुरगपालन एवं खेल कूद इत्यादि कार्यक्रमों ने गावों में एक नई लहर एक नवीन चेतना ला दी है। इन कार्यक्रमों के साथ-साथ पुस्तकालय विकास की कड़िया भी प्रमश गाव-गाव जुटनी चाहिए।

जर्मनी, सोवियत रूस, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन ब्रिटन जैसे महान् राष्ट्रों का इन कार्यक्रमों को सफल बनान में पूर्ण योग रहा है। फिर भी कुछ मामला में ग्रामीण किसान व जनता बहुत पीछे है जैसे (1) शिक्षितों की कम संख्या (2) खेती की अपूर्ण जानकारी (3) पुस्तकालयों का अभाव।

यदि गाव-गाव ग्रामीण पुस्तकालय हो तो कृषक जनता को उतना कष्ट न हो जितना उन्हें उठाना पड़ता है। भारत गाँवों का देश है, गाँवों से ही सफलता की आशा की जा सकती है, अतः स्थानीय प्रशासनों का यह दायित्व हो जाना चाहिए कि प्रत्येक गाँव पुस्तकालयों से सुसज्जित कर दिया जाये। यह तो सभी अच्छी तरह जान रहे हैं कि सरकार हमारे प्रत्येक कार्य में सहायता देने की तत्पर है, किन्तु जनता का क्या उत्तरदायित्व है यह उन्हें जानना चाहिए। जनता जनता के सहयोग की आकांक्षा भी पुस्तकालय निर्माण के विकास में निहायत जरूरी है।

वर्तमान भारत में पंचायती राज विकास मण्डल एवं सामुदायिक विकास योजनाओं ने जो सक्रिय सहयोग दिया है, वह स्तुत्य है। फिर भी इनके कार्य सदैव

के लिये ग्राम पुस्तकालयों का निर्माण करें, शासन से सुविधा जुटाने की अपील करें। जनता पूर्ण सहयोग दे एवं संचालन में मदद पहुँचाय। राजनीतिक दल एवं स्वार्थी ग्रामीण पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का दुरुपयोग न करें।

-जन-चेतना का देश के निर्माण एवं सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक कल्याण में जो महत्वपूर्ण स्थान है उसे ध्यान में रखते हुए ग्राम पुस्तकालयों के उद्घाटन के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिए ताकि देश का वर्तमान तौ मुटु ढह ही और भविष्य का भाग भी खुल जाये।

यदि ऐसा होगा तो निस्सन्देह ही ये पुस्तकालय ग्रामीण चेतना के आधार होंगे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साधन होंगे, निरक्षरताहारी होंगे। साथ ही राष्ट्रीय विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। क्योंकि कालिंदिन का कहना है कि 'ये पुस्तकालय ही देश के सच्चे विश्वविद्यालय हैं।' इन्हीं पर दश और देश की उन्नति निर्भर होती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि ग्रामों के समग्र विकास के लिए केवल हल चलायाना और फसल पैदा करना ही काफी नहीं है। समग्र विकास के लिये गावों की विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक प्रवृत्तियों का विकास भी आवश्यक है। हल चलाकर अन्न उपजाना तो शारीरिक श्रम है, किन्तु उन्नत तरीकों के आजारों से कृषि करना, फसल का संरक्षण करना वैज्ञानिक प्रवृत्ति पर आधारित है। इस प्रकार के काम करने के लिए कृषि विषय का साहित्य कृषकों तक पहुँचना चाहिये। इसका निराकरण एकमात्र ग्राम पुस्तकालयों से हो सकता है ये पुस्तकालय ही उनके पथ प्रदर्शक हो सकेंगे।

एक पक्षीय एवं एकांगी रह है। ग्राम पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की सहायता से प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर पुस्तकालय खोले गये थे, किन्तु आज गाँवों में विगत 10 वर्षों में विजली, नहर-मडक निर्माण कार्य, महिला कल्याण, ग़ालपाड़ी परिवार नियोजन, प्रौढ़ शिक्षा, समाज-कल्याण एवं विपुल उत्पादन व खाद प्रयोग के सभी कार्यक्रम होत रह किन्तु पुस्तक-प्रदर्शनी, पुस्तकालय दिवस या पुस्तकालय स्थापना जैसी घटनाएँ नहीं घटती जिसका लाभ बच्चे वृद्धे, स्त्री पुरुष, मजदूर, किसान सभी उठा सकत थे।

उपरोक्त कार्यक्रमों की सफलता जन-जीवन के साक्षर होने पर ही निर्भर करती है, क्योंकि शिक्षा आदमी को आदमी बनाती है। पुस्तकालय जैसी महान समस्या जनता में चेतना लाने का काम कर सकती है। अणुवाद स्वरूप इक्के-दुक्के पुस्तकालयों का होना अच्छा न बाना राजा होना है, अतः समस्त राष्ट्र में इनकी माँग है।

यह तो हमें मानकर चलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने हम ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की योजनाएँ दी किन्तु स्थानीय प्रशासनो ने उन योजनाओं को मटियामेट कर दिया।

वर्तमान भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत बुक-बक की योजना अवश्य प्रारम्भ की गई है जो ग्रामीण एवं शहरी शिक्षण समस्याओं के विद्यार्थियों को लाभ पहुँचा रही है। आज भी स्थानीय निकायों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे पुस्तकालयों की स्थापना करें और ग्रामीण विकास की कड़ी में राष्ट्र सेवा करें।

ग्रामीण विकास के आधार इन पुस्तकालयों से निश्चित ही हम कुछ महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार से हैं— (1) शैक्षणिक विकास में सहायता (2) कृषि कार्य में उपयोगी, (3) नैतिक एवं चारित्रिक विकास, (4) राजनीति-जागरूकता, (5) आर्थिक एवं वाणिज्यिक लाभ, (6) मनोवैज्ञानिक विकास, (7) चुस्त प्रशासन, (8) राष्ट्रीय विकास एवं जन चेतना में सहयोगी।

इन लाभों के अलावा यदि हम विदेश में बस रहे ग्राम-पुस्तकालयों में एवं उनका द्वारा की जा रही सामाजिक कल्याण एवं प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं की चर्चा करें तो हमें अपनी स्थिति का सहज ही आभास हो जायेगा लेकिन विदेशों की ओर हमारी परिस्थितियाँ एक सी नहीं हैं। हम अपने आपको तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़ा हुआ या असम्य मानकर हीन भावना को अपने मन में स्थान न दें।

आज हम यह निश्चय कर लें कि हम गाँवों से निरक्षरता को मिटाना है, प्रशिक्षण को बम करना है और आपसी मनमुटाव दूर कर शान्ति और सहयोग की भावना के साथ जीना है ता तत्कालीन परिस्थितियों में ही जनता में जागृति लाने

के लिये ग्राम पुस्तकालयों का निर्माण करें शासन से सुविधा जुटाने की अपील करें। जनता पूर्ण सहयोग दे एवं संचालन में मदद पहुँचाये। राजनीतिक दल एवं स्वार्थी ग्रामीण पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का दुरुपयोग न करें।

-जन चेतना का देश के निमाण एवं सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक कल्याण में जो महत्वपूर्ण स्थान है उसे ध्यान में रखते हुए ग्राम पुस्तकालयों के उत्थान के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिए ताकि देश का वर्तमान तो सुदृढ़ हो ही और भविष्य का मांग भी खुल जाय।

यदि ऐसा होगा तो निसन्देह ही ये पुस्तकालय ग्रामीण चेतना के आधार होंगे, शिक्षा एवं आध्याय के साधन होंगे निरक्षरताहारी होंगे। साथ ही राष्ट्रीय विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। क्योंकि कार्लोइन का कहना है कि "ये पुस्तकालय ही देश के सच्चे विश्वविद्यालय हैं।" इन्हीं पर देश और देश की उन्नति निर्भर होनी है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि ग्रामों के समग्र विकास के लिए केवल हल चलाना और फसल पैदा करना ही काफी नहीं है। समग्र विकास के लिये गावा की विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक प्रवृत्तियों का विकास भी आवश्यक है। हल चलाकर भ्रष्ट उपजाना तो शारीरिक श्रम है, किन्तु उन्नत तरीकों के औजारों से कृषि करना, फसल का संरक्षण करना वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इस प्रकार के कार्य करने के लिए कृषि विषय का माहिर्य कृषकों तक पहुँचना चाहिये। इसका निराकरण एकमात्र ग्राम पुस्तकालयों से हो सकता है, ये पुस्तकालय ही उनके पथ प्रदर्शक हो सकेंगे।

ग्रामीण पुस्तकालयो से लाभ

विश्व में वनानिक विकास के साथ-साथ पाठ का अद्भुत धमाका हो रहा है। अनेक विषयो एवं लोक जीवन को भ्रमभोर दी जाता। साहित्य अधिातम रूप में लिखा एवं प्रवाशित किया जा रहा है, जिमको पढ़ने वाले पाठक उतनी सख्या में नहीं है और न ही उस साहित्य का समुचित उपयोग हो रहा है। रचना एवं साहित्य का अधिकाधिक उपयोग हो इसी उद्देश्य से प्रत्येक राष्ट्र शिक्षा सन्ध्याओं एवं उनमें निहित पुस्तकालयो पर जोर दे रहे हैं।

भारत गाँवों का देश है, इसकी आत्मा गाँवों में वास करती है। इन आत्माओं का साक्षात्कार पुस्तका, समाचार पत्रा, ज्ञान विज्ञान की विविध पत्रिकाओं में मुद्रित या प्रवाशित विचारों से होना चाहिए। उपरा, मजदूरों, स्त्री-पुरुषों में शिक्षा के प्रति रुचान लाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। बच्चों के लिए प्रत्येक गाँव में माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की है। लेकिन वे लोग जो पढ़े हैं किंतु लम्बे अरसे से नहीं पढ़ रहे हैं या पुस्तका के सत्संग में नहीं आये हैं उनके लिए शासन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही पुस्तकालय स्थापना की कोशिश की है। वर्तमान तक हम सभी गाँवों में पुस्तकालय नहीं खोल पाये हैं फिर भी प्रयास जारी है। आज ग्राम पुस्तकालयों का होना राष्ट्रीय विकास के हित में है इनका प्रसार एवं प्रचार देश के कोने-काने में पहुँचाना है। जो निरक्षर हैं उन्हें भी इन पुस्तकालय रूपी ज्ञान गंगोत्री से बौद्धिक पावनता प्रदान की जानी चाहिए। ग्राम के ये पुस्तकालय प्रत्येक ग्राम निवासियों के लिए ज्ञान के खंदपण हैं जिनमें देश विदेश के मानव विकास की आँकी उद्दे दृष्टिगोचर होती है। दैनिक जीवन की गतिविधियों से अछूते न रह पाये, इसके लिए पुस्तकालय की सावक जानकारी का लाभ ग्रामवासियों को मिलना चाहिए, क्योंकि इनसे निम्नलिखित लाभ हैं।

(1) शैक्षणिक विकास में सहायक — भारत की 70 प्रतिशत जनता आज भी निरक्षर है, शिक्षा में पिछली है। शासन का पूरा प्रयास हो रहा है कि प्रत्येक 6 मील के क्षेत्र में एक पाठशाला खोली जाये जिसमें शिक्षा का पूरा लाभ सभी को मिले। इन पाठशालाओं साथ ही विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय उपलब्ध होना चाहिए। पंचायतों द्वारा खोले गये पुस्तकालयों से ग्रामीण जनता का विभिन्न विषयों की धार्मिक, राजनतिक कृषि एवं मनोरंजनात्मक पुस्तकों प्रदान की जानी चाहिए। जो निरक्षर हैं उनके लिए पुस्तकालय में ही प्रौढ़ कक्षाएँ लग जिहे

पुस्तकालयभारत चलावाये और मंत्री पुरपा को पूर्ण सहयोग दे जिससे उनमें स्वाध्याय की रुचि प्रकटगी और प्रमश बोद्धिक सूत्र तूक का विकास होगा ।

इही पुस्तकालयो से स्कुल, कॉलेज एव नौकरिया में जाने वाले विद्यार्थी एव पुरुष लाभान्वित होंगे और बोद्धिक स्तर बढ़ेगा । इस प्रकार पुस्तकालय से सारे पाठ में एव बोद्धिक वातावरण तैयार होगा । व राजनीति, धर्म, समाज, राष्ट्र एव परराष्ट्र की समस्याओं की आपसी विचार विनिमय से मुलभूत में समर्थ हो सकेंगे ।

(2) कृषि विकास में सहयोगी — ग्रामीण पुस्तकालयो का लाभ किसानों द्वारा कृषि के विकास के लिये भी किया जाता है । चूँकि भारत में विकास खंडों की स्थापना हो चुकी है विकास खंडों के उप क्षेत्रों पर जहाँ पंचायत है, सरकारी समितियाँ हैं वहाँ ग्रामसेवका की नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं । फिर भी ये व्यक्ति किसानों को ठीक समय पर मार्ग दर्शन देने में असमर्थ हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में पुस्तकालयो में मगाई जाने वाली कृषि सम्बन्धी पुस्तकें, पत्रिकाएँ एव पम्पलेट्स का पढ़कर तथा जो किसान नहीं पढ़ सकते हैं वे पढ़वाकर अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोज सकते हैं ।

जब गाँवों में बीमारियाँ का समय हो तब बीमारी के नवीन तरीकों, खाद के महत्वपूर्ण प्रकार एव उनके उपयोगों में पैदावार बढ़ाने के उन्नत साधनों, बीमार फसलों की रोकथाम के लिए उपयोगी दवाइयों का प्रयोग आदि की जानकारी किसानों को यानीय पुस्तकालयो के साहित्य से हो सकता है । कृषि में उन्नति हेतु ग्रामीण पुस्तकालयो में कृषि सम्बन्धी निम्न प्रकार का साहित्य रखा जाना चाहिए ।

(1) विपुल उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धी पम्पलेट्स (2) खाद और उनके प्रयोग पर सामग्री (3) खेती के उन्नत औजार सम्बन्धी पुस्तकें (4) कृषि समाचार-पत्र एव पत्रिकाएँ की उपलब्धता (5) पशु पालन व मुर्गी-पालन पर प्रचुर साहित्य (6) बीटनाशक दवाओं के उपयोग एव विषियों का साहित्य ।

इनके अतिरिक्त समय समय पर कृषि एवं सिंचाई विभागों द्वारा प्रकाशित बुलेटिन उनके द्वारा प्रस्तावित उन्नत कृषि उपकरण एव सिंचाई के विकसित तरीकों की जानकारी देने वाली पत्रिकाएँ ग्रामीण पुस्तकालयो में रखनी चाहिये सम्बन्धित विषयों चले चित्र तथा व्याख्यान आदि की व्यवस्था पुस्तकालय लाभ की उत्कृष्ट कार्यवाही होगी ।

(3) जीवन स्तर एव नैतिक विकास में सहायक — हम सभी भली-भाँति जानते हैं कि कृषक, मजदूर एव ग्रामीण लोग का जीवन स्तर सामान्य होता है । जीवन की कृता का आधुनिक तरीका उन्हें आता नहीं है, यह अज्ञानता का कारण है । उनके पास पैसा तो होता है किन्तु उसे खर्च करने के तरीके उनके पास नहीं होते हैं ।

प्रायः देखा जाता है कि वे पैसे से अच्छे कपड़े साफ सुथरा घर एवं अच्छा भोजन पा सकते हैं, किन्तु फिजूल गच करने की प्रवृत्ति के कारण नहीं पाते हैं। ग्रामीण स्त्रियाँ अधिकशत अशिक्षित होती हैं, उनका बौद्धिक स्तर सामान्य से भी कम होता है। ऐसी स्थिति में उनसे अपने परिवार का सुचारु रूप से चलाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। किन्तु ग्राम पुस्तकालयों के माध्यम से पुस्तक के समय में सिलाई-मढ़ाई, गृह व्यवस्था, स्वास्थ्य शिक्षा, पारिवारिक बजट एवं पाक विद्या सम्बन्धी पुस्तकें पढ़कर मुनाफ़ा जा सकती है। जो शिक्षित हैं उन्हें पुस्तकें दी जाएँ तो अवश्य ही वे उन पुस्तकों को पढ़कर सुनकर अपने परिवार में स्वास्थ्य प्रद भोजन पका कर घर को स्वच्छ एवं बच्चों की परवरिश पर ध्यान रख सकती हैं। उनके आचार-विचार एवं व्यवहार में भी परिवर्तन आ सकता है जब जन-सामान्य में पढ़ने की रुचि जाग्रत होगी तो उनमें सहज स्वाभाविक नैतिक गुणों का विकास होगा उनमें सभ्य नागरिक, के होने के भावों का उद विकास होगा।

(4) चारित्रिक विकास — चारित्रिक विकास से तात्पर्य जीवन में अच्छे गुणों एवं विशेषताओं की अधिकता होना है। मनस बाबा कमला तीनों दृष्टियों से जो पुरुष आचरण करता है वह निसर्गदेह श्रद्धा का पात्र होता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है।

ग्रामीण बच्चों का विकास बुरी आदतों से होता है। उनमें बचपन में ही झूठ बोलना बात न मानना छिपना जैसी प्रवृत्ति घर कर जाती है। युवा वय कुसंगति से जुआ शराब, गुण्डागर्दी एवं अनैतिकता के शिकार होते हैं। पढ़ने में उनका ध्यान कम और उपद्रवों की ओर अधिक रहता है। इसका कारण माता पिता द्वारा बच्चों पर ध्यान न दिया जाना, शिक्षा का खर्च न रखा जाना साथ ही पुस्तकों के सत्संग से वंचित रहना है।

चरित्र के विकास हेतु बाल पुस्तकालय कथ की स्थापना होनी चाहिए जिसमें राम कृष्ण, गौतम गांधी सुभाष भगत आजाद विवेकानन्द, अरविन्द रविन्द्र नाथ ठाकुर शास्त्री, नहरू जैसे महान देश भक्त एवं विद्वान व्यक्तियों की चरित्रावलि दी रखी जाए। सूर तुलसी कबीर, मीरा, दिनकर, प्रसाद पत, महादेवी आदि साहित्यकारों के अथ सबलन एवं जीवनिष्ठा संग्रहित होनी चाहिए। उनके लिए खेलकूद, बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान एवं हास्य व्यंग की पत्रिकाएँ हो तो अवश्य ही बच्चों में अध्ययन की रुचि जागगी स्वाध्याय की प्रवृत्ति तीव्र होगी और चरित्र निर्माण की सलक जम लेगी जो राष्ट्रीय चरित्र का ही एक स्वरूप होगी। समाज शिक्षा के आधार मन्त्र बनकर ये ग्रामीण पुस्तकालय राष्ट्रीय चरित्र के निमाण में भी सहायक हो सकते हैं।

(5) राजनैतिक विकास — ग्रामीण पुस्तकालयों के उपयोग से नागरिकों में राष्ट्रीय विकास के प्रति सद्भाव जाग्रत होता है। प्रतिदिन आने वाला समाचार

पत्रों से राष्ट्र की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, एवं अंतरराष्ट्रीय, उथल-पुथल से जनमानस परिचित होता है। देश के वाणिज्य, कृषि व्यापार में हो रही प्रगति के आकड़े समाचार पत्र पत्रिकाओं में आते हैं जिनके आधार पर देश की अव्यवस्था, वस्तुओं के भाव आदि का पता लगाया जा सकता है।

राजनैतिक दलों की राष्ट्र के प्रति जागरूकता, राज्य सीमा विवाद विजती विवाद, सिंचाई व्यवस्था तथा चुनाव प्रकरण आदि के निणय पत्रों द्वारा जाने जा सकते हैं। पुस्तकालय में राजनीतिक गतिविधियों से परिचित करवाने वाली पुस्तकों से अवश्य नागरिक अपनी स्वतंत्रता, अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सजग हो राष्ट्रीय सेवा से सलग्न हो सकते हैं। इसमें असावा एक सम्य एवं सुरक्षित नागरिक बन सकने का दावा कर सकते हैं।

(6) आर्थिक विकास में सहायक — ग्राम देश के ग्राम लोगों की आर्थिक विपन्नता एवं विपन्नता को दूर करने में शासन सक्षम है किंतु ग्राम निवासियों एवं शहरी लोगों का भी कुछ उत्तरदायित्व हो जाता है, जो वस्तुओं की मांगों से प्राप्त नहीं हो पाती किंतु उनका निर्माण उत्पादन की दृष्टि से किया जा सकता है। जो कम खर्च पर सुगमता से मिल सकती है ऐसी वस्तुओं को छोटे पैमाने पर छोटी छोटी उद्योग-इकाईयों के द्वारा उत्पादित की जानी चाहिये। उत्पादन के तरीके सीखने के लिये लघु उद्योग पुस्तिकाएँ रखनी चाहिये।

इस प्रकार की पुस्तिकाओं से छोटे छोटे खिलौने, मोमबत्ती साबुन, तेल परना, चमड़े के सामान बनाने की विधियाँ सीखी जा सकती हैं। लघु उद्योग के अंतर्गत बीड़ी बनाना चिया सनाइया, अंगूरबत्तियाँ बनाना, लोहे के उद्योग में कुत्सा, पलग टबिल तथा दरवाजे खिड़कियाँ बनाने की कलाओं को सीखा जा सकता है। बड़ाई गिरी के काम एवं आधुनिक भवन निर्माण के कार्य भी इन पुस्तिकाओं से सीखे जा सकेंगे। इस प्रकार लघु उद्योग की तकनीक से अधिक रोजगार मिल सकेगा गरीबी दूर होगी और समाज की आर्थिक दशा भी सुधरेगी।

(7) मनोवैज्ञानिक लाभ — देश के उन गांवों में जहाँ अभी पुस्तकालय नहीं है उनमें यदि पुस्तकालय खोले जावें तो निश्चित ही निरक्षरता का प्रतिशत इस देश में कम होन लगेगा। ग्राम ग्राम पुस्तकालयों से पढ़ने की सुविधा जनता को प्राप्त होती है तो उन लोगों पर जो पढ़ने के आगे नहीं हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और अपने आप वे पढ़ने की ओर प्रवृत्त होंगे। चर्चा की-प्रतिस्पर्धात्मक वृत्ति एवं अध्ययन में रुचि-विशेष का आयोजन होगा और उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप आश्चर्य ग्रंथ भेंट में दिए जायेंगे ताकि वे अधिकाधिक समय पढ़ने में व्यतीत करें।

इस प्रकार नमशः सभी में अध्ययन की मनावृत्ति जन्म लेगी और निमित्त लोगों की वृद्धि होगी। कम पढ़े लिखे व्यक्ति इस पढ़ने में अधिक सक्षम हो जायेंगे।

(8) जनचेतना एवं राष्ट्रीयता का विकास — पुस्तकालयों में मगाये जाने वाले पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर जनता देश की माली हालत से अवगत होगी, जनमानस अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान् होंगे, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग राष्ट्र विकास का्य हेतु करेंगे। समय-समय पर राष्ट्र पर आन वाले सक्टा स के परिचित होंगे व राष्ट्र के प्रति कुछ करन की चेतना उनमें जायेगी।

शिक्षा का एक सहज ढंग होना चाहिये जिसे अपनाते में बच्चे आनाकानी न करें, घबरायें नहीं। स्कूल व बच्चा व शिक्षण व प्रति रुचि पैदा करन के लिये बाल पुस्तकालय वक्ता की व्यवस्था होनी चाहिये जिनमें ग्रामीण बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था हो। बच्चे उनकी इच्छा स पढ़ने या चित्रावली देखने हो चायें तो उनमें पढ़न की लालसा जायेगी महापुरुषों के चित्रों की देख के गव अनुभव करेंगे और पढ़न का प्रमुखता देंगे।

पुस्तकालय के ही माध्यम से ही निरक्षरों के लिये साक्षरता अभियान चलाकर उनको पढ़ाया जा सकता है जिससे राष्ट्र में एक महान समस्या सामाजिक शिक्षा का अन्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सहज गति आयेगी। साक्षरता का प्रतिशत ऊँचा होगा। नागरिक चेतना के द्वारा विकास का मार्ग उ्मुख होगा, जो राष्ट्र हितकारी भी होगा।

ऊपर लिखे सभी लाभों को देखते हुए यदि हम ग्राम पुस्तकालयों का निर्माण करें तो भारत की अधिकांश सामाजिक समस्याएँ जो ग्रामीण विकास से सम्बन्धित हैं आसानी से हल की जा सकती हैं। उक्त लाभों को प्राप्त कर पानाजन एवं वृद्धि विकास पाना है तो जनता एवं सरकार दोनों को चाहिये कि परम्पर उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पुस्तकालयों की स्थापना पर बल दें।



अध्ययन स्थलो की आवश्यकता

अध्ययन स्थलो की आज जरूरत से यहा तात्पर्य ऐसे अध्ययन क द्रा से है जहा विद्यार्थी अपने अवकाश के दिनो मे जाकर रोजगार, प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओ के साथ नव जीवन की नयी आशाओ का माग खोजने म सफलता प्राप्त कर सकें । ज्ञानाजन कर मानसिक विकास कर मके । जिन छात्र छात्राओ को पशासनिक परीक्षाओ म बैठना है वे इन अध्ययन स्थलो मे जाकर अपनी कठिनाइयो को हल कर सकें ।

यह सुविधा मिक दो चार लोगो के लिए न होकर ग्राम लोगो के लिए हो, सबन हो, सभी वग के स्त्री पुरुष, बच्चे इसका लाभ ले मरें । जब कभी ग्राम जनता की बात सोची जाती है, तब हम कोई नियम नहीं ले पाते है, क्वाकि, ग्राम आदमी कौन है और उनकी ग्राम जरूरत क्वा हो सकती है इसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है ।

धूम फिर कर एक प्रश्न सामने बना रह जाता है कि, क्या साधन सम्पन्न बुद्धिमान मध्यम पारिवारिक व्यक्ति ग्राम है या वह है जो पसीने की कमाई खाता है, साधन हीन है किंतु फिर भी साहित्य, विज्ञान, धर्म, दशन से लगाव रखता है ।

कहने का अर्थ हागा ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगो मे दो प्रकार के लोगो का जमाव है, एक साधन सम्पन्न व बुद्धिमान दूबरे आर्थिक दृष्टि से कमजोर लेकिन बलि से तज, कुशाग्र बुद्धि फिर भी अध्ययन स्रोतो स वचित ।

वर्तमान के साथ मानव मस्तिष्क का विकास भी तीव्रतम होता जा रहा है, मस्तिष्क को भूख का पीछटक भोजन साहित्य, विज्ञान मनोरंजन, कला, धर्म, दशन की पुस्तकें है । वकार समय का सदुपयोग पुस्तक पढकर किया जाना चाहिये, ऐसे बहुत से विद्वान मिलेंगे जिहाने पेट की भूख को प्रधानता न देकर अपनी मानसिक क्षुवा को मिटान के लिए ग्रयो को खरीदकर पढा । खाली दिमाग गैतान का घर बन जाता है अतएव अवकाश के क्षण म अपने आपको यदि कोई काम नहीं है तो सुवह शाम पुस्तकालयो के अध्ययन कक्ष म जाकर अध्ययन म लगना चाहिये ।

इस समय अधिकांश छात्र छात्राओ क सिर से परीक्षा का भूत टल गया होगा । काई राजगार की टोह मे इटरव्यू की तयारिया कर रह होंगे, कुछ पी

एम टी पी एम गी आई एफ एम, आई ए एस, एफ सी आई, या सी ए की परीक्षाओं के लिए जूट गया हूँ। कुछ एक बी एड बी टी, ग्राम सेवक, स्वास्थ्य सहायक इत्यादि व प्रशिक्षण हेतु अपने दिमागों को पुस्तकों के साथ घुनवा बीजा बनकर बुराद रहे हूँ।

मसलन सभी विद्यार्थी उपरोक्त नयारी के लिए जान क्या-क्या कर रहे हूँ। उह अपने विषय की समस्त पुस्तकों के साथ साथ सामान्य भाषा, वाक्पीठी, गणित, रीति, करियर डायरेक्ट, एसेज, ग्राफ़्स समाचार-पत्र, दश विदेश की वस्तु-पत्रिकाओं की आवश्यकता होगी लेकिन ये जान पोथीयों को पान योग्य के सभी पुस्तक नहीं हूँ जिन्हें जीवन पथ में कुछ करना है। चूंकि धनी भानी विद्यार्थी उह तरीक़े कर पढ़ सकेंगे। बाकी के छात्र साधजनिक पुस्तकालयों में जो कुछ सामग्री मिलती है, उसे पढ़कर ही मनोप करेंगे। किन्तु मात्र चलाऊ सामग्री एक चलन-फिरत अध्ययन से ऐसे परीक्षाओं का पान नहीं किया जा सकता ऐसे काम के लिये ठोस परातल पर आधार आवश्यक है।

हजारों की संख्या में व युवक विद्यार्थी एक युवतिया जो शहर के ग्राम पास के क्षेत्रों से विद्यालयों महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं, गर्मी की छुट्टियां में परा में बलबुला रहे हूँ। ऐसे अध्ययन स्थानों को वहां व्यवस्था कर वक्ष में आराम सँभलकर अपना समय काट एक पान उद्धि करें।

ग्रामीण भारत की संपदा गांवों में वास कर रही है, किन्तु उसके विकास पर सोचा कम जा रहा है। ग्रामीण अध्ययन स्थलों की मुविधा ग्रामीण पुस्तकालयों में नहीं है। आज गांव का प्रतिभावान छात्र छुट्टियां में जब घर आता है तो उसे गुंडा-नर्दी जुझा, शराब जैसे अनेक झंडा से वाक्प होना पड़ता है वहां एने तल्लण का दम घुटता है। स्वतंत्रता का हनन होने लगता है, बुद्धि दो माह में कुछ ही जाती है, यदि वह अपने अध्ययन व भावन जुटाना भी चाहें तो अपनी अगली वक्षा की पाठ्य पुस्तकें खरीद कर ही पढ़ सकता है, किन्तु उसे नव-जागरण का नये पन्थितनों का जब तक पान न हो वह भाग प्रतिस्पर्धा परीक्षा में नहीं बैठ सकता। यही कारण है कि, मध्यप्रदेश में बहुत कम प्रतिभावान ग्राम अछे पदों पर जा पाये हैं। जो हैं, वे भी अधिकतर मायन सम्पन्न एवं अधिकारी वगैरे हैं। शहरी छात्रों को तो कम से कम साधजनिक एवं शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों से सहायता मिल जाती है, वह भी अत्यंत रूप में किन्तु ग्रामीण छात्र पुस्तकालयों से नोरे वचित रह जाते हैं।

आज तल्लणों के बौद्धिक व शारीरिक विकास के लिए ऐसे अध्ययन स्थलों, त्रीडा संस्थाओं एवं स्वास्थ्य संगठनों की आवश्यकता है, जिसके समग में आकर प्रतिभा खोज पणाली में अधिक से अधिक सफ़लता मिल सकती है। भारत सरकार ने प्रत्येक जिला के दो पर युवक केंद्रों की स्थापना कर एक बहुत अच्छा कदम उठाया है इन केंद्रों में युवकों के लिए बुद्धि विकास खेल भावना, प्रतिस्पर्धात्मक

परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयुक्त अवसर है किंतु यह देखने में आया है कि इन केंद्रों पर सस्ता साहित्य, पाकेट-बुक्स की भरमार है, स्वार्थी तत्वों का समावेश है, व्यक्तिगत स्वाध्याय विषय भूमिका के रूप में दिखाई पड़ता है फिर भी यह अनूठा प्रयोग है। इन केंद्रों के पुस्तकालयों से ही अध्ययनरत ग्रामीण छात्रों को पुस्तकालय सहायता एवं सद्बोध प्राप्त होता रहे तो इसकी साक्ष्यता सिद्ध हो सकती है।

देश भर में ऐसे भी संस्थान हैं जो अपने निजी पुस्तकालय चलाते हैं, फिर भी विद्यार्थियों के लिए इन पुस्तकालयों में विशेष व्यवस्था की जानी है। रामकृष्ण मिशन सामाजिक संस्थाओं की सी.एल., यू.एस.आई.एम. थियोसाफिकल सोसायटी एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थानों के पुस्तकालय कुछ इसी प्रकार के सहयोगी पुस्तकालय हैं। ऐसे प्रयोग सच जनता द्वारा अपने हाथ से किए जाने चाहिये।

सार देश के ग्रामीण व शहरी चाहे व सामाजिक क्षेत्र हो या सरकारी मभी में पुस्तकालयों के अत्यंत विशिष्ट अध्ययन कक्षों की स्थापना की जानी चाहिये। एक उनके लिए अनुसूचित विषयों की पुस्तकों का अध्ययनाथ भेजना चाहिए। युवक युवतियों को इस प्रकार का सहयोग मिलता है तो वे निश्चय ही प्रतिभा प्रकट करने में समर्थ होंगे। अध्ययन स्थलों पर छात्र छात्राओं के माध्यम से दशक हेतु युवक केंद्र शिक्षा विभाग, पंचायत व समाज-कल्याण के प्रचार एवं प्रसार सेवा अधिकारी गए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

अध्ययन स्थलों की अन्य व्यवस्था को बनाये रखने में जिला पुस्तकालयाध्यक्ष, महाविद्यालय एवं विद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष अन्य आदान प्रदान प्रणाली के माध्यम से सहायता पहुंचा सकते हैं। यह कार्य अवश्य ही जिम्मेदारी एवं जोखिम का है, किंतु तत्कालीन युवा भटकाव को रोकने का सुगम माग है तथा शिक्षा में जाति, अनुसंधान में एकाग्रता व श्रम में कुशलता निर्माण करने का अनूठा कार्यक्रम है। विद्यार्थियों व बौद्धिक विकास हेतु इस प्रकार के प्रयोग सफल सिद्ध होंगे बशर्ते कि अध्ययन स्थलों का निर्माण शीघ्र ही जगह जगह कराया जाये। कुछ ऐसे उपाय किए जाने चाहिए ताकि पक्की उम्र के युवकों का ज्ञान उम्र के साथ साथ परिपक्व होता रहे। उक्त निदान सही समय पर रोगी को उचित दवाई देकर स्वस्थ रखने का सफल प्रयास हो सकता है।

ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ने से ढलखड़ान वाले छात्रों के लिए ये अध्ययन स्थल डूबने का तिनके का सहारा होंगे। ज्ञान गभोत्री को पार उतरने में पतवार का काम देंगे। गुरुदेव तो ज्ञान दे ही रहे हैं ये अध्ययन के द्वारा युवक युवतियों का सघन में जीवन का माग देंगे। जिस तरह आज युवक कोचिंग क्लासेस के लिए भटक रहे हैं। बाजारों के नाटसगाईं पर निर्भर हो गए हैं, और शिक्षा के स्तर से व्यथित हो चुके हैं। ऐसी दशा में ग्राम ग्राम खुलने वाले ग्रंथालयों में वाचनालय कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जहां ग्रामीण युवक बैठकर अपनी तमाम समस्याओं का निराकरण ढूँढ सकें।

चू कि भारत के अधिकांश राज्यों में ग्रन्थालय अधिनियम पारित नहीं हो सके हैं अतः स्थानीय पुस्तकालय सघों तथा भारतीय ग्रन्थालय सघ का मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नव-युवकों को अपने ज्ञान की पिपासा को दूर करने के प्रयास हेतु राजनीतिक दलों के सहयोग से ग्रन्थालय अधिनियम पारित करने में अग्रणी होना चाहिए। आज हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अध्ययन स्थलों की आवश्यकता महसूस हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए चिकित्सालयों के बड़े-ठाले मरीजा के लिए, खेत खलिहान से लौटकर आये फुसत में बड़े किसान व मजदूर भाइयों के लिए। इन सबमें अधिक उन लोगों के लिए जो प्रौढ़ पाठशालाओं में अक्षर ज्ञान कर रहे हैं उन्हें निरन्तर अध्ययन की आवश्यकता है अतः उनकी पढ़ाई बीच में ही न छूट जाए उनका अक्षर ज्ञान फिर सपाट न हो जावे इसीलिए इन सबके लिए अध्ययन स्थल की जरूरत है। अपने लिए, समाज के लिए और राष्ट्रीय विकास में सहयोग देने के लिए।

पंचायते और पुस्तकालय विकास

यह विश्व विदित है कि भारत गावों गोशालाओं, पनघटों एवं बाग बगीचों का देश है। अधिकांश निवासी यहाँ के गावों में रहते हैं। जिनकी औसत सख्या लगभग 60 प्रतिशत है। 30 प्रतिशत जनता नगरों में वास करती है। भारतीय ग्रामों के बारे में गांधी जी का कहना था कि 'गाव देश की आत्मा है एवं शहर उसका शरीर', अर्थात् यहाँ उन ही पुराने हैं जितना की यह भारत पुराना है। बाऊपर का कहना है "नगर मनुष्य की दुनिया है परन्तु गाव ईश्वर की" अर्थात् गाव सत्यता है एवं शहर बनावटी। एक किसान की पाठशाला उसकी खेती है घर उसका आसरा और गाव उसकी चहार दीवारी। लेकिन इस चहार दीवारी को फादकर उसमें शहर की जगमगाहट की ओर कदम बढ़ाया है विकास के कदमों ने उसके गाव को भी इस चकाचौंध से अछूता नहीं रखा।

यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कई गाव नगर की सीमाओं में सम्मिलित हो गये और नगर की सख्याओं को बढ़ात गये फिर भी ग्रामीणों की अधिकता कम नहीं हुई। जनसंख्या वृद्धि ग्राम विकास एवं कृषि सम्बन्धी मामलों के लिये पंचायतों का निर्माण हुआ। आज देश भर में कोई 5½ लाख गाव हैं, जिनमें पंचायतें ग्राम का प्रशासन चला रही हैं। इन्हीं पंचायतों के अन्तर्गत पुस्तकालय, वाचनालय, ग्राम्यास मण्डल, नवयुवक मण्डल, महिला मण्डल एवं समाज शिक्षा के विविध कार्य क्रम शासन ने सौंपे हैं ताकि ग्रामीण समाज का शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं नैतिक विकास हो सके।

आज जबकि सम्पूर्ण भारत अधिक प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है किमान अपने कृषि कार्य आधुनिक कृषि यंत्रों से निर्यात रहे हैं, विपुलता उत्पादन कार्यक्रम को अपनाकर अधिक अन्न उपजा रहे हैं। परिवार नियोजन का अपना कर सीमित परिवार में आस्था एवं जीवन स्तर को बढ़ाया देने में तत्पर हैं किन्तु फिर भी ग्रामों के अन्दर में अटक रह है तथा स्वाध्याय में दूर है। देश विदेश की ताजा खबरो व वैज्ञानिक घटनाओं से बेखबर हैं। इसका कारण है पत्र-पत्रिकाओं का दैनिक प्रसार न होना।

ऐसे समय पंचायतों का यह उत्तर दायित्व है कि वे ग्रामों के लोगों के कार्यों व शोध निपटन पर, वृत्ता के अन्तर्गत, में एक कर जो मजदूरों के घर लौटने पर, खाली समय के अन्तर्गत, उनसे दूर रहेंगे

पंचायत भवन में खाली पुस्तकालय में सत्ता साहित्य की व्यवस्था करें, उनके लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराएँ, वाचनालय में दैनिक समाचार एवं पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने हेतु रखें। सप्ताह या माह में एक बार वृषि स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं समाज सुधार व शिक्षा सम्बंधी व्याख्यान आयोजित कराएँ और वृषका का वृषि की नवीन पद्धतियों, स्वास्थ्य सवाया आदि से अवगत कराएँ। पंचायतों का दी गद् शासन की योजनाओं को ग्राम पंचायतों सिर्फ वागज में ही बनाने उन्हें भ्रमली जामा भी पहनाएँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था 'ग्रामीणों की समस्या के हल से ही हमारे देश की प्रगति सम्भव है। उन्होंने समाज के निष्ठावान सेवकों को देहाता में जाकर गरीब जनता की सेवा करने का अनुरोध किया था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही समाज शिक्षा में प्रगति करने हेतु प्रत्येक पंचायत क्षेत्रों में एक एक पुस्तकालय एवं जिना स्तर पर एक जिला पुस्तकालय के मुख्यालय की स्थापना की गई थी। पंचायत के ये पुस्तकाल, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की ओर सौंपे जाय गये। इनकी स्थापना का प्रमुख लक्ष्य किसानों द्वारा अपने खाली समय का सदुपयोग करना था। "भारत जैसे बड़े और बढ़ती हुई आवादी वाले देश में समाज के, खास तौर पर गाँवों में विकास के समय का उपयोग कर लेना परम आवश्यक है। हमारी योजनाओं की सफलता इस पर बहुत अधिक निर्भर करती है।"¹

वर्तमान भारत के किसी गाँव का हम खाली खींचें तो हम उसके अंतर्गत यह दिखाई देगा कि उस गाँव में एक अच्छी पाठशाला (बालक बालिका) है। वह गाँव पक्की सड़क या बच्ची सड़क से जुड़ा हुआ है। वृषि सिंचाई हेतु बिजली पम्प लगे है जात हेतु वृषि के उपकरण भी उपलब्ध है ग्राम सेवक हैं, पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सा सहायक ग्राम मेडिकार्स व शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं। सहकारी-समिति है, समिति मेडिक एवं पंचायत सचिव हैं और इनके साथ ही ग्राम-जीवन के आंतरिक परिवर्तन को बदलने हेतु पंचायत है। युवक केंद्र है महिला कल्याण विभाग है। बच्चों के लिए शिशु मंदिर व आहार पापण की व्यवस्था है लेकिन उन सभी लोगों के लिये जो ग्रामों के सर्वांगीण विकास में सहायता दे रहे हैं उनके लिए आराम के क्षणों में बौद्धिक विकास तथा मानसिक क्षुधा को मिटाने के लिए "सामाजिक सस्था"² "पुस्तकालय" नहीं है जिसका उपयोग कर सभी सरकारी तथा गैर सरकारी कमचारी, मजदूर, किसान, युवक, बच्चे स्त्री पुरुष अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें।

यदि ग्रामीण जनता को उनके खाली समय के सदुपयोग हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं तो वे अपने खाली समय का उपयोग बुरे कामों में करेंगे। ग्रामीण जन जीवन में गलत पहलियों फैलाएँगे भोली-भाली जनता को भ्रान्त कष्ट देकर उनकी सबक में डाल देंगे।

अतः ऐसे सबडों, सामाजिक व्यवस्था में होने वाले गलत कार्यों से मुक्ति दिलाने के लिये ग्राम पंचायतों को चाहिये कि वे आदर्श ग्राम के निर्माण स्वरूप पुस्तकालयों को सत्रीय रूप से संचालित करें। ये पुस्तकालय ही ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों, युवकों बच्चों व स्त्रियों के मानसिक भटकाव को दूर करने में प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं।

भौतिक और शारीरिक सुख सुविधाओं का मुहैया कराने में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि जनता के चरित्र और नीतिमत्ता की रक्षा करने और सुधारन की बात पर हम आवश्यक जोर देना भूल ही जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अपनी योजनाओं में हम इस शैक्षणिक और सांस्कृतिक पहलू पर विशेष रूप से ध्यान दें। हमारे देश में अधिकांश धन औद्योगिक या अन्य संगठित क्षेत्रों में खर्च कर दिया जाता है और इस बाप के लिये प्रायः बहुत कम खर्च पाता है, ऐसा नहीं होना चाहिये। देश के नागरिक जब तक सच्चे चरित्रवान और बाप कुशल नहीं होंगे, इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं में सफल नहीं हो सकते। लोक-शिक्षण स्वाध्याय एवं स्वशिक्षा में प्रगति कर मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना है।

पंचवर्षीय योजनाओं ने पंचायतों को बहुत जिम्मेदारी के बाप हाथ में दिये थे किन्तु पंचायतों को इनमें सफलता कम मिली। इसका प्रमुख कारण शिक्षा, अज्ञानता एवं आपसी फूट प्रमुख थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में गाँव गाँव पुस्तकालयों की स्थापना पंचायत भवनों में की गई थी, जिनकी देख रेख का बाप ग्राम पंचायतों को ही सौंपा गया था, किन्तु कृषि विकास, पशुपालन, रोजगार, यातायात, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि कार्यों में ही इनकी दिलचस्पी अधिक रही। स्थापना के कुछ दिनों बाद तक ये पुस्तकालय अवश्य चले फिर बाद में बंद हो पड़े रहे। आज भी जिन गाँवों में युवा सरपंच तथा शिक्षित समाज का शासन है वहाँ कुछ हद तक जनता को पुस्तकें पढ़ने व देश विदेश के समाचार जानने हेतु पुस्तकालय का प्रयत्न जैसे-तैसे ही है।

इन पंचायतों का कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं है जिसके आधार पर पुस्तकालयों के द्वारा ये ग्रामीण निरक्षरता की मुहिम को धीरे धीरे बढ़ा सके और राष्ट्र व शैक्षणिक विकास में 1% भी हाथ बटा सके। पाँचवीं एवं छठी पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा को पूर्ण विकसित करने हेतु एवं निरक्षरता को समाप्त करने के लिये गाँव-गाँव पुस्तकालयों के विस्तार की आशा है। वैसे तो आज भी कई गाँवों में पंचायत के अथवा सावजनिक पुस्तकालय विद्यमान हैं लेकिन दैनिक जीवन में उनका उपयोग बहुत कम हो रहा है। इसके पीछे ग्रामीण समाज व्यवस्था, दलगत पुराई, आपसी मनमुटाव एवं निरक्षरता आड़े आ रही है।

सर्वोदय मन्त्र बाबा विनायक भाव का कहना है “आज सभी ग्राम पंचायत (परशानी) बन गई हैं। इसका कारण यही है कि हम लोग गाँव में रहकर ग्राम पंचायत बनाते हैं फलतः जिनके पास अधिक शिक्षा व अधिकांश”

है उही के पास अधिक सुविधायें व अधिक जमीन रहती है। व ही पचायत के मुखिया बनते हैं और सारी सत्ता उही में केन्द्रित रहती है।”³

उपरोक्त सामिया का कारण पचायत की स्वायत्तता, आपरवाही, गाँव में वास एक विरादरी, या आयोग्य व्यक्ति का चुनाव हो सकता है। यह अनुभव किया गया है कि गाँवों में दो चार घर ऐसे होते हैं जिनका जन्मसिद्ध अधिकार भगड़े फसाद व अच्छे कार्यों में रोड़े अटकाना होता है, ऐसे लोगों से गाँव बदनाम हो जाता है तथा प्रशासन ठप्प हो जाता है।

आदश पचायतें व हैं जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण, पयजल व्यवस्था, विजली, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की व्यवस्था की है, बेकार युवकों का काम दिताया है, मजदूरों को सहूलियतें दी हैं, पिछड़े एवं आन्ध्रवासी जनता के आवास का प्रबंध स्वयं के कोष से किया है। ऐसी पचायतें निश्चित ही प्रशंसा की पात्र हैं।

ऐसे उदाहरण भारत में केवल कुछ ही राज्यों में देखे जा सकते हैं, जहाँ ऐसा कोई गाँव नहीं है जो पक्की सड़क से न जुड़ा हो, बिजली, ठीक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था न हो। ऐसे राज्यों में हरियाणा, पंजाब उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास एवं बंगाल आदि प्रदेशों को अग्रणी माना जा सकता है। इसका श्रेय वहाँ के शासन तथा जनता को जाता है जिन्होंने सहयोग एवं सहकार की भावना से ग्रामोत्थान में सहयोग दिया। इसका कारण शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक जागरण भी हो सकता है।

आज हमारा ग्रामों में आपसी टकराव, ईर्ष्या द्वेष, एवं फूट का-साम्राज्य छाया हुआ है। छोटी छोटी बातों को लेकर भगड़े फसाद खड़ा हो जाता है जून खराबा हो जाता है। रातों रात घर भरे खेत बटवा दिये जाते हैं या फसलें जला दी जाती हैं और भूठी प्रतिष्ठा के मोह में एक दूसरे पर काट बचहरी के चक्कर चल पड़ते हैं। इन सबका मूल कारण अज्ञानता व निरक्षरता है। उनमें वह शालीनता हमें लाना है जो सड़कों का टालने में सहायता करे। एक दूसरे को समझने का मौका पाने के लिए बौद्धिक समझ व आत्मीय भावना लाना जरूरी होगा। यह कार्य पुस्तकों के सत्संग स्वाध्याय के अच्छे अवसर व अध्ययन स्थलों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

इतना कुछ होने पर भी आज में आधुनिक जीवन जीने के प्रति जन आप्रति एवं शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। यह कार्य उनके लिये न सही आने वाली पीढ़ी के लिये नितांत जरूरी है अतः उनके द्वारा चलाये जाने वाले पचायत पुस्तकालयों का क्या स्वरूप हो इस पर भी हमें विचार करना है। अभी तक अवस्था में चल रही पचायतों में अब भी अपने-अपने ग्राम एवं राष्ट्र की उन्नति में सहायक बनना चाहिये और जागना चाहिये। उन्हें चाहिये कि वे आभीण विकास कार्यक्रम तैयार करें जिसके अन्तर्गत विपुल उत्पादन, पीने के पानी की व्यवस्था, बांध पुस्तकें, कलब,

साक्षरता पाठशाला, लघु उद्योग बालवाडी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ-साथ एक विशाल पुस्तकालय के निमाण का काय भी हाथ में ले। इसके लिये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव व उपाय सुझाये जा सकते हैं जिन्हें ग्राम में लाकर पचायत पुस्तकालय के निमाण तथा विकास में सफलता हासिल कर सकती है।

- (1) सबसे प्रथम पचायत पुस्तकालय विकास समिति का निर्माण करें जिसमें सरपंच, उपसरपंच पचायत सचिव पधानाध्यापक ग्राम सेवक, नव-युवक मण्डल तथा महिला मण्डल के अध्यक्षों को समिति का सदस्य बनावें।
- (2) उस पचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम गाँव के पचायत सदस्यों द्वारा ग्रामीणों को पचायत सचिव की सहायता से पुस्तकालयों के महत्व एवं उपयोग को समझाना तथा निश्चित राशि चढ़ाने के रूप में प्राप्त करना।
- (3) शिक्षित अशिक्षित स्त्री पुरुष एवं बच्चों को गणना कर उनकी सदस्यता निवारित करना।
- (4) पचायत कायानय के व्यवस्थित कमरे के सामने "ग्राम पचायत पुस्तकालय" अथवा "वाचनालय" का बोर्ड लगाये ताकि ग्राम जानने वाले ग्रामीण आसानी से देख पायें एवं पुस्तकालय में जानें की उत्सुक हो।
- (5) अशिक्षित व प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को पुस्तकालय का अनिवार्य सदस्य बनाया जावे।
- (6) बच्चों के लिये अलग ही अध्ययन कक्ष की व्यवस्था हो, इस बात का ध्यान पुस्तकालय विकास समिति रखें।
- (7) ग्रामीण नागरिकों के लिए सरल, सुबोध एवं सचित्र पुस्तकें जो देश विदेश की जानकारी के साथ साथ कृषि उद्योग, व्यापार, धर्म दर्शन, इतिहास, लोक साहित्य एवं संस्कृति, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्रस्तुत करें, पुस्तकालय में तुरंत की जाये।
- (8) समय समय पर पुस्तकालय विकास-समिति की बैठक हो जिसमें पुस्तकालय की चलने वाली गतिविधियाँ पर प्रकाश डाला जाये और गतिविधियों का सुधारने का प्रयास किया जाय।
- (9) पुस्तकालय के प्रचार प्रसार हेतु धार्मिक त्यौहार मela, बाजार या राष्ट्रीय पर्वों पर विद्वान वक्ताओं को बुलाकर पुस्तकालयों की उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डाला जावे ताकि जनता में अधिक पढ़ने की रुचि जाग्रत हो।
- (10) ग्राम पाठशाला में पुस्तकालय की व्यवस्था यदि नहीं है तो उन विद्यालयों को भी शाला विकास समिति एवं पुस्तकालय विकास समिति द्वारा पाठ्य पुस्तकें देकर प्रदान की जानी चाहिये। बालकों में अध्ययन वृत्ति का प्रोत्साहन देने हेतु सहयोग आवश्यक है। किसी ने सब ही कहा है आज

के वच्चे बल के भावी नागरिक एवं नवीन भारत के निर्माता है। इनके सम्पूर्ण विकास पर हमें ध्यान देना चाहिए।”

- (11) ग्राम सरपंच अथवा ग्राम प्रमुख के द्वारा निरक्षर प्रोढ-स्त्री पुरषों का साक्षरता पाठशाला में आने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये।
- (12) महिने में एक बार पाठका को चलचित्र के माध्यम से यह दिखाया जाय कि पठने में क्या लाभ होता है। इस कार्यक्रम में, पशुपालन, भुर्गी तथा मत्स्य पालन मुधरी खेती व उद्योगों के साधना का भी प्रदर्शित किया जा सकता है।
- (13) सप्ताह में एक बार जिला ग्रन्थपाल को बुलाकर ग्रामीण जनता के मध्य उनका उद्बोधन कराया जाये ताकि जनता में अध्ययन प्रेरणा जगेगी एवं ग्रन्थशिक्षा के प्रति हाने वाली हीनवृत्ति का अन्त होगा।
- (14) जिला ग्रन्थपाल के द्वारा पढ़ने में लाभ, निरक्षरता से मुक्ति, उपयुक्त पुस्तकों के नाम एवं निरक्षरता के परिणामों से समाज के पतन इत्यादि पर वक्तव्य दिये जावे। यह काम समाज सेवा अधिकारी भी कर सकते हैं।
- (15) पचायत-पुस्तकालय के ग्रन्थपान एवं जिला ग्रन्थालय के प्रमुख का माह में एक बार जन सम्पर्क हो। शिक्षित एवं अशिक्षित की दूरियाँ कम होगी तो नागरिकों में सहज रूप से शिक्षित बनने तथा उनसे बताने माग को अपनाने की उत्कण्ठा जाग्रत होगी।
- (16) पचायत सरपंच जनता के दिला की जीतने का एव उनमें प्रेरणा जाग्रत करने का कार्य करने तक जाकर हम यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि ग्रामों में पचायतों, पुस्तकालयों का विकास कर सकती हैं। इस मामले में सरपंच को बहुत लगनशील उत्सुक, नेक एवं ईमानदार होना चाहिये उस पर ग्रामीण जनता की पूर्ण श्रद्धा हो तथा ग्रामवासी भी उसके कहे की टालने वाले न हों, तभी पुस्तकालय एवं ग्राम विकास का सपना पूरा हो सकता है।
- (17) पुस्तकालय संचालन का कार्य ग्रन्थपाल की नियुक्ति, वेतन भत्ता, निवास एवं पुस्तकों का खर्च शासन द्वारा दिया जाना चाहिये। ये ग्रन्थ पचायत भी है। यदि पचायत अधिक रूप से असमर्थ है तो शासन से अनुदान माग सकती है, बाकी वह स्वयं करे।
- (18) गाँव की जनता को चाहिये कि वह ग्रन्थपाल को प्रतिष्ठा प्रदान करें। किसी भी प्रकार की ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिये वह तत्पर होगा।
- (19) पचायत अपने पुस्तकालय की प्रगति-सूचना प्रत्येक 3 माह में जिला ग्रन्थालय को भेजे। यदि ये ग्रन्थालय पचायत विभाग के अन्तर्गत है तो पचायत अधिकारी को भी दी जा सकती हैं।

(20) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष का बजट एवं पुस्तकालय-सेवा की विस्तार योजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्त मुद्दों को यदि पचायत गम्भीरता से ग्राम में लाकर अपने गाँवों में पुस्तकालय की स्थापना करना चाहती हैं तो सर्वप्रथम उन्हें जिला ग्रामपाल, नेहरू युवक केन्द्र के सम्बन्धक अथवा पचायत एवं समाज-कल्याण विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। जिला-प्रमुख से मिलकर भी इस पवित्र कार्य को सम्पन्न कर सकते हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि आपस के मतभेदों को मिटाकर राजनीतिक दलों के घगुल से दूर रहकर ग्राम पचायतों का उज्ज्वलीकरण हो। ग्रामों में पुस्तकालयों की स्थापना कर समाज में फैले अशिक्षा जैसे कलक को जड़ से मिटाया जा सकता है। गाँव वाले यह स्वरूप करें कि गाँव के सभी लोगों की चिन्ता के विषय गाँव वाले ही देख ले ता उन्हें पुस्तकालय मितकर स्थापित करना चाहिए तब उन सबकी सवानुमति से जा पचायत सहमति बनेगा वह सदैव जनता के हित बनिए होगी ना कि अहित के लिये।

जहाँ ऐसी जन सवानुमति है उन्हें आज ही पुस्तकालयों की स्थापना कर देनी चाहिए और शासन को आर्थिक मदद हेतु लिखना चाहिये। जिनके पास श्रद्धा सम्पत्ति, धन दौलत है खुश है साथ ही दूसरों की चिन्ता भी है, उन्हें जन हित के लिये पुस्तकालय खुलवाने में आर्थिक सहयोग देना चाहिए। यह भी समाज के धनी-मानी लोगों का उत्तरदायित्व है जो भले काम में योगदान देकर ऐसे पुनीत कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। जनता का सहयोग भी वाञ्छनीय होगा।

जनता यह बात अच्छी तरह याद रखे कि आज खोला पुस्तकालय आनवाली कई पुस्तकें तक उनकी पीढ़ियों को नानार्जन कराता रहेगा, मानव सम्पत्ता एवं संस्कृति के विकास क्रम की याद दिलाता रहेगा। देश-भर की पचायतों को एक-जुट होकर पुस्तकालयों के विकास एवं स्थापना का बीड़ा उठाना चाहिये। राज्य सरकारें अपने प्रदेशों में साबजनिक ग्रामालय कानून शक्ति कर दें ता ग्राम-पचायतों के ग्रामालयों की दुनिया ही बदल सकती है।

सन्दर्भ —

- 1 श्रीमन्नारायण भारतीय संयोजन में नई दिशाएँ। पृ 41
- 2 रगनाथन (एस चार) पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका।
- 3 नई दुनिया, (३) दीपावली विशेषांक, इंदौर म प्र 1975 पृ 97

7

ग्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम मे पुस्तालयो की भूमिका

लोक पुस्तकालय साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं नैतिक दृष्टिया से व्यक्ति विकास तथा लोक रूचि के केन्द्र होते हैं। यह एक ऐसा सामुदायिक केन्द्र है जहाँ किसी भी वर्ग का व्यक्ति बिना भेद-भाय के जाकर अपनी बौद्धिक अभिगम प्राप्त कर सकता है। सम्पूर्ण जगत् की जानकारी हम लेना चाहें तो एक समृद्ध लोक-पुस्तकालय हमें दे सकता है, वस्तुतः की यह सभी दृष्टिया से परिपूर्ण और वैज्ञानिक साधना एवं अपनी वितरण सेवाओं में सक्षम है। देश की साहित्यिक सम्पदा की सुरक्षा एवं पाठकों के लिये अध्ययन के साधन जुटाना ही इनका काम नहीं है बल्कि देश की निरक्षर पीढ़ी को साक्षर बनाना व उन्हें अध्ययन में प्रियाशील बनाना भी इनका प्रमुख लक्ष्य है।

जिन राष्ट्रीय में निरक्षर जनता को साक्षर बनाने हेतु साक्षरता अभियान चलाये गये उनके लिये लोक पुस्तकालय बहुत उपयोगी मिट्टी हुये हैं। निरक्षरों को पुस्तक से कहानी, व्यंग्य, नाटक, कविता आदि पढ़कर सुनाना, चलचित्र दिखाना, व्याख्यान एवं गोष्ठीया आयोजित करना साथ ही उन्हें बर्णमाला का ज्ञान देकर लिखना पढ़ना सिखाना सावजनिक व पुस्तकालयों का कार्य क्षेत्र रहे हैं। यूनस्को जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन न पढ़ना मानव का अधिकार मानें उनकी शिक्षा पर बड़े बड़े कार्यक्रम बनाये हैं, निरक्षरों के लिये सावजनिक पुस्तक सभायें दी हैं। कार्लाइल ने 'लोक शिक्षण हेतु लोक पुस्तकालयों को जनता के विश्व विद्यालय माना था। हम मानते हैं कि जो अक्षर साक्षर हैं उनका ज्ञान एवं बौद्धिक कार्यक्रम सम्पूर्ण जीवन विकास के साथ अध्ययन सुविधा न मिलने पर छूट जाता है, अतः उस ज्ञान का वापस रखना, स्थायित्व प्रदान करने, उनमें अध्ययन रूचि जगाने के लिये सावजनिक पुस्तकालयों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारतवर्ष में लोक पुस्तकालयों का विकास बहुत धीमा रहा है। देशवासियों की ग्रामीण स्थिति एवं बढ़ते हुये प्रतिक्षा के कारणों का देगने हुये इनका विस्तार होना चाहिये। प्रजातन्त्र शासन के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपनी महत्ता को समझे और यह तभी संभव है जब वह पूर्ण साक्षर हो। ज्ञानन के स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त बहुततर साक्षरता कार्यक्रम राष्ट्र में प्रारम्भ नियमित

उनका क्रियान्वयन सिर्फ महानगरी, नगर एवं शहरी परिसीमाओं में बंधकर रह गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अवश्य कुछ आशा की जा सकती है।

यदि देश में निरक्षरता के अभिशाप को समाप्त करना है तो सर्वप्रथम हम ग्राम ग्राम शहर शहर लोक पुस्तकालयों के निर्माण पर सोचना होगा। तत्पश्चात् उनका द्वारा दी जान वाली सेवाओं के वितरण पर भी विचार करना लाजिमी होगा। जैसा कि केन्द्रीय समाज कल्याण एवं शिक्षा राज्य मंत्री ने फरवरी 1978 के विश्व पुस्तक मेले में आयोजित अखिल भारतीय पुस्तकालय समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'देश में पुस्तकालयों का अव्यवस्थित ढंग से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समय 80 प्रतिशत बड़े पुस्तकालय महानगरों में हैं। माव-जनिक कोष से पूरा या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त सभी प्रकार के पुस्तकालयों को सावजनिक पुस्तकालय घोषित कर दिया जाना चाहिये। एक केन्द्र पर नाम लिखवाने वाले प्रमाण कर्ता को देश के सभी अन्य पुस्तकालयों का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।'

वर्तमान में देश में जितने भी लोक पुस्तकालय कार्यरत हैं, उनमें महानगरीय स्तर के पुस्तकालय जन शिक्षण अथवा प्रौढ शिक्षा विकास ताल में अपना सहयोग कुछ हद तक दे रहे हैं। साक्षरता के नाम पर उक्त पुस्तकालयों में भी शायद कोई परिपुष्ट कार्यक्रम नहीं चलाय जात। नियोजित कार्यक्रम नहीं होने के बावजूद भी देश भर के समस्त लोक-पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को चाहिये कि वे अपनी पुस्तकालय-सेवाओं का वितरण करें। और अधिकाधिक लोगों को पुस्तक पढ़ने, पढ़ाने, पढ़कर सुनाने, शोध एवं अनुसंधान करने की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था कर लोक पुस्तकालयों निम्नलिखित कार्यों को अपनी विस्तारण सेवाओं के अंतर्गत कामावित करें, तो निश्चित ही देश हित में अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

(क) लोक पुस्तकालयों में परस्पर सहयोग—देश के जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो गया है उन राज्यों के पुस्तकालयों में अवश्य सहकारिता एवं मगठन से काम हो रहा है। समाज शिक्षा मुहिम भी इन राज्यों में प्रगति पर है। जहाँ पुस्तकालय अधिनियम नहीं है वहाँ सावजनिक पुस्तकालय अपनी हथेली अपना राग अलाप रहे हैं। कुछ राजनीतिक शिकंजे में जकड़े हैं और कुछ अर्ध-भाव से विपन्न हैं। उनमें आपसी सहयोग एवं सामंजस्य नहीं दिखाई देता। लोक पुस्तकालयों ने सुनियोजित याचना बनाकर एक दूसरे को सहयोग देना चाहिये। आपस से ग्रंथों का अन्तर्-प्रदान केन्द्रीय सूचीकरण पुस्तकालय समारोह प्रदर्शनी साक्षरता कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करना चाहिये। केन्द्रीय पुस्तकालय से सम्बद्ध आस पास के क्षेत्रों में शाखा पुस्तकालयों की स्थापना करना चाहिये।

(ख) साक्षरता कार्यक्रम चयन—एक प्रजातन्त्र देश के समान अधिकार एवं समान जीवन यापन करने तथा शिक्षा की

प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार का है। राष्ट्र की लगभग सभी सामाजिक मस्थायें जस राष्ट्रीय समाज कल्याण केन्द्र समाज शिक्षा सघ, नेशनल बुक ट्रस्ट, अखिल भारतीय पुस्तक प्रकाशक सघ, समाज सेवी संगठन रोटरो क्लब, लियो क्लब लायस इंटरनेशनल राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाइया पचायतें एवं सामुदायिक विकास केन्द्र इत्यादि इस प्रयास में जुट है कि देश में अशिक्षा का कायाकल्प हो, नामानिधान न रहे। स्वाध्याय को महत्व देने वाले कुछ ग्रामीण पुस्तकालय एवं प्रतिष्ठा प्राप्त सावजनिक पुस्तकालय भी अपने क्षेत्र की निरक्षर जोवनिया का मानसिक चेतना, प्रदान करने में सक्षम है। इतने से शैक्षणिक विकास में गति मिलता नहीं आयेगी, इसमें और विस्तार की जरूरत है,

साक्षरता अभियान का कार्य सावजनिक पुस्तकालयों के जरिये सहा जाता इसका लिय उपयुक्त स्थल पुस्तकालय भवन हो सकते हैं। शहर एवं गांव के जा प्रौढ़ एवं युवा निरक्षर है, साथ ही जो अल्प साक्षर या अल्पज्ञान प्राप्त कर्ता है उह लोक पुस्तकालयों का अनिवार्य सदस्य बना लिया जाय और यदि जन प्रस्थालय में धार्मिक सामाजिक ऐतिहासिक, प्राधुनिक अनुसंधान से सम्बन्धित तथा कथा, कहानिया की पुस्तकों का वाचन निरक्षर लोगों के समक्ष किया जावे तो वे भी ज्ञान की ज्यादा से प्रकाशित होग।

पुस्तकालयाध्यक्ष या अन्य दूसरे कर्मचारी द्वारा उनकी एक घण्टा प्रतिदिन पढ़ान की व्यवस्था हो। तीन माह में एक बार जाच परीक्षा एवं अंतिम वार्षिक इस्तहान हो। उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र भी प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जाय। यह क्रम तब तक चालू रखा जाय तब तक कि उन क्षेत्र के सम्पूर्ण निरक्षर व्यक्ति पूर्ण लिखना, पढ़ना न सीख लें। उपकरण एवं पाठ्य सामग्री के निय केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड या समाज कल्याण विभाग से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती हैं। शासन इसमें सहायता देने की पूर्णतः मदद करें किन्तु जनता से इसमें मुख्य भूमिका निर्वाह की अपेक्षा की जाती है, और वह मुख्य भूमिकाओं की पुण्य स्थली लोक पुस्तकालय है।

(ग) अंतर ग्रामीणीन आदान प्रदान सेवा—बहुधा यह दखने में आता है कि शासन में चलने वाले सावजनिक पुस्तकालयों के अलावा बहुत कम लोक पुस्तकालय ऐसे हैं जो एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय को कुछ समयावधि के लिये ग्रंथ आदान प्रदान करते हैं। ग्रंथ आदान प्रदान प्रणाली बौद्धिक सीमाओं के विस्तार में सहायक होती है साथ ही सहकारिता की भावना को जन्म देती है हम जानते हैं कि विश्व में प्रकाशित होने वाली सभी पुस्तकें, एक पुस्तकालय किसी भी दशा में नहीं खरीद सकता अतः ग्रंथों का आपसी आदान प्रदान करना साहित्य जनता को पहुँचाया जाना चाहिए। ऐसा करने से एक क्षेत्र की रुचि का साहित्य दूसरे क्षेत्र में पहुँच कर नवीनता प्रदान करता है। लोक-साहित्य एवं

संस्कृतियों का समन्वय अच्छी तरह हो सक्ता है। नया नया साहित्य पढ़ने की ललक पाठकों में जगती है। इसका विस्तार भी लोक पुस्तकालयों की शाखा जिला, प्रदेश क्षेत्र या राष्ट्र स्तर पर करना चाहिये। यहाँ तक कि यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्भव है।

(घ) चलित ग्रन्थालयों का विस्तार—इस बात को सभी भारतीय जन जानते हैं कि शिक्षा के विकास पर ही जीवन विकास का बौद्धिक पक्ष सुदृढ़ होगा। वक्कन ने ठीक ही कहा है “अध्ययन मनुष्य को पूण बनाता है, समोष्ठी व्यक्ति को अनुभवशील बनाती है और लेखन व्यक्ति को मुक्तियुक्त बनाता है।” अतः लोक पुस्तकालयों का दायित्व हो जाना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छित पुस्तक मिले ताकि वह उसका चिंतन मनन करे और समय पर चल ग्रन्थालय सेवा को पाकर धन्य हो। यह सेवा ऐसे पाठकों को दी जाती है जिन्हें फुसत नहीं मिलती जा पुस्तकालय तक नहीं आ सकते जो अपग ह इत्यादि। मान लो ‘अ’ शहर के पुस्तकालय में 50,000 ग्रन्थों का भण्डार है जो औसतन 10,000 आवादी को बौद्धिक साहित्य प्रदान करता है, शेष 30,000 जनसंख्या ग्रन्थ अध्ययन से वंचित रहती है। इसके विपरीत उभी शहर के आस पास पन्द्रह गांव ऐसे हैं जो दस मील की सीमा में बसे हैं जहाँ एक भी पुस्तकालय नहीं है। 15 गांव के 50,000 लोग अध्ययन से वंचित रहते हैं। उन्हें सिर्फ व्यापार बेनी-बाड़ी, घर गृहस्थी में ही अपना समय खपाना पड़ता है। पढ़ लिखे हैं किंतु ग्रन्थ उपलब्ध न होने से अपनी उसी बौद्धिक सीमा रेखा पर हैं जहाँ उन्होंने उसे आराम दिया था।

उन पन्द्रह गांवों के लोगों के विराम लग मस्तिष्का में नया साहित्य नये विचार, नई राजनीति, नया विज्ञान एवं उद्योग अनुमधान साहित्य सामग्री पहचाने का कार्य उस ‘अ’ शहर को अपने शाखा पुस्तकालय खोलकर करना चाहिये जिस प्रकार बैक ने अपने शाखा कार्यालय खोल रखे हैं। इसके लिये पुस्तक गाड़ी रिकशा या विशेष वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिये। ग्रन्थ एक सप्ताह या 15 दिन के लिये एक बार में एक गांव में दिये जायें। पन्द्रह दिन बाद जब दूसरा बक्कर होता तो पूर्व के निगमित ग्रन्थ वापस कर नये ग्रन्थ पढ़ने हेतु दिये जायें। इस प्रकार नित नवीन साहित्य का वितरण होता रहें। यह कार्य उसी कार्य पद्धति से सम्भव होगा। जिसे लाय स क्लब, रोटरी क्लब, लियो क्लब, इनरव्हील क्लब एवं बैंक संध आदि करते आ रहे हैं। इन संस्थाओं को भी अब इस ओर ध्यान देना चाहिये। सावजनिक पुस्तकालयों के सम्थापकों व प्रशासकों को इस ढंग के कार्यक्रम क्रियावित करन चाहिये तभी देश को व्यापक निरक्षर जनता का उद्धार होगा।

(ङ) गोष्ठी एवं प्रदर्शनियों का आयोजन—यदि लोक पुस्तकालयों की प्रशासकीय कड़ी गांव जिला, क्षेत्र राज्य तथा केन्द्र के पुस्तकालयों से जुड़ी ह तो विस्तृत पुस्तकालय सेवा का लाभ मिलेगा। जिने सम्पूर्ण क्षेत्र में लगने वाले भन्ने उत्सव तीर्थ व त्यौहारों पर जिला पुस्तकालय द्वारा पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन

हो। यह कार्य संगठन के रूप में ग्राम पुस्तकालय ही करें। महापुरुषों व शक्ति कारियों की पुण्यतिथियों, राष्ट्रीय व धार्मिक पर्वों पर गोष्ठीयों व पुस्तकालय वातावरणों का आयोजन हो। इसमें निरक्षर एवं अल्पसाक्षर युवक युवतियाँ को भी भाग लेना दिया जावे। प्रत्येक माह में लोक पुस्तकालयों में ही शोध कक्षा का निर्माण करना चाहिये तथा शोध कर्त्ताओं में अपना सम्बन्ध बनाय रखने चाहिये। सावजनिक जीवन में कोई व्यक्ति अव्यक्त करना चाहता हो तो उसमें सावजनिक पुस्तकालय वाचनालयों का यह प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये कि वे सामान्य पाठकों से कहीं अधिकतर सेवा इस विशिष्ट पाठकों को दें।

(घ) पुस्तकालय का वैज्ञानिक व्यवस्थापन स्वरित सेवा की भावना ही पुस्तकालय सेवा की सफलता का मूल है। स्वरित सेवा प्रदान करने हेतु पुस्तकालयों को तकनीकी एवं वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। तकनीकी एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन करने के लिए भारत के 33 विश्व विद्यालयों पुस्तकालयों में विज्ञान विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें पुस्तक वर्गीकरण, सूचीकरण, व्यवस्थापन, संगठन प्रलेखन एवं सन्दर्भ सेवा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ाया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण देने का अर्थ है कुशल प्रशासक एवं पुस्तकालय की वैज्ञानिक प्रणालियों का अधिकाधिक उपयोग। ज्ञान साहित्य एवं अध्ययनकर्त्ताओं के विकास के साथ पुस्तकालयों का भी वैज्ञानिक विकास होना चाहिये, तभी मूल भूत धारणा 'पुस्तक सबके लिये है' का हम सार्वभौमिक कर सकते हैं।

अपना पाठकों की शीघ्र सेवा देने के लिये पुस्तक पत्र पत्रिकाओं का विषयवार, लेखकवार या वगैरह वर्गीकरण कर व्यवस्थापन करना चाहिये। ग्रन्थालय सग्रह की सूची पत्रों के आकार में बनाना चाहिये। लेखन-लेखक के आधुनिक तरीका को अपनाकर प्रशिक्षित विद्वान पुस्तकालयध्यक्षों की नियुक्ति पुस्तकालय में करनी चाहिये। प्रायः यह कहा गया है कि लोक पुस्तकालयों में न कोई वैज्ञानिक पद्धतियाँ का नियाचयन होता है और न ही प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति। भारत में ऐसे पुस्तकालय राजनीतिक सरक्षणता कर कठपुतली का खेल दिखा रहे हैं। पुस्तकालय अधिनियम पारित कर इस पुस्तकालयों की व्यवस्था बदली जा सकती है। राजनीतिक दलदल में फँस य पुस्तकालय निस्वार्थ भाव से जनहित एवं राष्ट्रीय विकास का कार्य नहीं कर पाते हैं। य चाह तो अपने प्रदेश के लोक साहित्य सस्कृतिकला एवं संगीत पर रचे जाने वाले साहित्य की प्रादेशिक ग्रन्थ वचनाओं का निर्माण कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं। कुर्सी एवं सत्ता की राजनीति लोक पुस्तकालयों के विकास एवं प्रगति में बाधक है इसका उपाय सोचा जाना चाहिये।

पुस्तकालय प्रचार एवं प्रसार कार्य—एटमी युग के बढ़ते हुए कार्यों, साहित्य प्रकाशना, मुद्रित पत्र पत्रिकाओं, श्रोतपूर्ण सामयिकों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों को

देखते हुए जन-जन तक युगानुरूप साहित्य पहुँचाने में पुस्तकालयों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है। ग्रामीण विकास व कार्यक्रमों में प्रगति लाने का प्रशिक्षितों का शिक्षित बनाना तथा जीवन पथ पर अधिकारिक रूप से अध्ययन व स्वाध्याय की सुविधा जुटाने का कार्य लोक पुस्तकालयों को करना चाहिए। इस जैसे देश में गांव गांव तक पुस्तकें पहुँचाने का कार्य पुस्तकालयों व बसें करती है यहाँ तक कि दूरदराजों में बसे लोग भी इनकी सेवाओं का लाभ पाते हैं। हमारे देश में यह कार्य अभी सुप्तावस्था में है। दूर-दूर व गाँवों दहातों में पुस्तकालय प्रचार अनेक माध्यमों से कर उनका विस्तार किया जाना चाहिये। प्रसार तथा विस्तार सेवाओं का उद्देश्य अपाठकों को पाठकों में परिवर्तित करना है और जनसाधारण में पठन पाठन की अभिरुचि जाग्रत करना है। लोक शिक्षा के विकास में यह कार्य प्रशंसनीय होगा।

यदि हम चाहते हैं कि देश सभी दृष्टियों से सबल हो, सभी साक्षर हो, स्वतन्त्र विचारा की अभिव्यक्ति का हौसला रखने वाले हो, प्रयास का डटकर मुकाबला करने में समर्थ हो तो हमें चाहिये कि बुद्धि के विकास की बुनियादी कड़ी जन शिक्षा को सबल सबके लिए उपलब्ध कराया जाय। देश की ऐसी समृद्धि जिसे सराहा जा सकता है, ता इसके लिए सामाजिक पुस्तकालय जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं को अपनी विस्तारण सेवाओं का व्यवहारिकता में परिणत करना होगा। लोक पुस्तकालयों का विकास कर सूक्ष्म ग्रंथों में जनमत को प्रजातन्त्र के योग्य बनाना होगा।

विश्वविद्यालयीन प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम एवं प्रणाली—अनेक प्रयासों के बावजूद जब सरकार ने दखा कि राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम समाज-कल्याण विभाग, समाज सेवी संगठनों एवं स्वायत्त शासन मन्त्रालयों से भी निबटाया नहीं जा सकता साथ ही निरक्षरता में प्रतिशत भी बढ़ता ही जा रहा है तब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्व-विद्यालयों के माध्यम से इस शैक्षणिक कार्यक्रम को बड़ पैमाने पर प्रारम्भ किया। प्रत्येक विश्व विद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों को अपने केन्द्रों से सम्बन्धित प्रौढ शिक्षा केन्द्र इकाई मोहल्लेवार अधिकाधिक खोलने का प्रावधान रखा गया जिसमें प्राध्यापकों व छात्र छात्राया का पूरा सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

जसा कि कोठारी कमीशन (शिक्षा आयोग) ने अपनी रिपोर्ट में प्रौढ शिक्षा के लिए भारतीय परिवेश में निम्न बातों की अनुमति दी—

- 1 निरक्षरता का उन्मूलन
- 2 निरक्षर शिक्षा
- 3 पत्राचार पाठ्यक्रम
- 4 पुस्तकालय

5 प्रौढ शिक्षा में विश्वविद्यालयों का योगदान

6 प्रौढ शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन¹

उक्त छ मुद्दों को ध्यान में रखकर निरक्षरता उन्मूलन हेतु सारा राष्ट्र एकजुट होकर लग पड़ा है। निरंतर शिक्षा की सुविधा हेतु खुले विश्वविद्यालय अथवा सतत शिक्षा के द्रव्य पत्राचार पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किया है साथ ही पुस्तकालयों के माध्यम से सतत शिक्षा में सहयोग की अपेक्षा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1970 के अपने सतत शिक्षा कार्यक्रम में, 1977 में विश्वविद्यालयों के योगदान में जोष एवं अध्ययन के अतिरिक्त एक नये कार्यक्रम प्रसार को स्वीकृत किया। इनके सहयोग से यह अपेक्षा की गई कि सतत शिक्षा और प्रौढ कार्यक्रम में प्रसार के माध्यम से मदद ली जा सकती है अतः विश्वविद्यालयों को शिक्षा प्रसार हेतु प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम सौंपे गये। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने मन्त्रों में कहा—'मुझे खुशी है कि हम राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक बृहद साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इसी साल गणितों की छुट्टियाँ में तीन लाख कॉलेज छात्र भाग लेंगे।'²

इस दृष्टि से शिक्षित युवक किसी भी देश का भाग्य विधान बन सकता है। देश भर में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर 35 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिसमें से दस लाख रास्यों छात्र छात्राओं की सहभागिता इस अभियान में रेखांकित की गई है। इतना करना के बाद भी एक अक्षर जान कर लेने वाले साक्षर के पास यह समस्या है कि उसने जो कुछ सीखा है पढ़ा है उसे बनाये रखने के लिए सतत अध्ययन की सुविधा (अथवा पत्रिकाओं की) उसके पास उपलब्ध नहीं है कि वे अपने पढ़े को म्याथी रख सकें। इसके लिए उच्च वाचनालय केन्द्रों अथवा ग्रन्थालयों की नितान्त आवश्यकता होगी। अब तक महाविद्यालयों को जिन प्रौढों को साक्षर बनाने का कार्य सौंपा गया है वे केन्द्र उन्हें साक्षर बनाकर छोड़ रहे हैं, पर भविष्य में ज्ञान को अर्जित करते रहने जैसी मामूली प्रदान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम में प्रौढ साक्षरों को प्रश्नोत्तरों से जोड़ जाने का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित नहीं है। फिर भी 'योजनाबद्ध' तरीके से यह कार्यक्रम चलाया जाता है तो 1986-87 में अनुमानित 10-15 लाख प्रौढ ज्ञान एवं साक्षरता पाने में सफल होंगे।'

प्रौढों के लिए सतत शिक्षा के खुले विश्वविद्यालयों की सुविधा में ग्रन्थालयों का योगदान—

यह तो एक बड़ा सत्य है कि एक बार किसी महिला अथवा पुरुष को अक्षर जान करा दिया गया हो, पढ़ना सिखा दिया गया हो और अब वह बहुत कुछ पढ़ने की लालसा रखता हो, किन्तु पठन-सामग्री की अनुपलब्धता के कारण उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो, एक लम्बे अरसे के बाद उसका पढ़ा लिखा मपाट हो

जावगा। अतः यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि सतत् शिक्षा के लिये उनसे अध्ययन की भूल को शांत करने के उपाय के रूप में उसका क्षेत्र में माहल्ले में या शहर के प्रौढ शिक्षा केन्द्र ईकाई में साक्षरों के लिए प्रारम्भिक-साहित्य के ग्रन्थ व प्रौढों की पत्रिकाओं के वाचनालय केन्द्र हो। यह कार्यक्रम है जो ग्राम पंचायत करें, नगर है तो नगर पालिकाये करें, शहर हो तो नगर परिषद करे और महानगर है तो महानगरपरिषदें करें। यदि ये संस्थाएँ यह कार्य नहीं करती हैं तो पंचायत विभाग समाज कल्याण विभाग, नहरू युवक केन्द्र अथवा समाज सभी संस्थाएँ करें। अभी तक देखने में आया है कि प्रौढ शिक्षा केन्द्रों पर ग्रन्थालयों से ग्रन्थ प्रदान करने अथवा पढ़ने के लिए दिये जाने का कोई उपाय नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में निरक्षरता अथवा सतत् शिक्षा की बात उन लोगों के लिये अधूरी छूट जाती है जो आगे कोई परीक्षा नहीं देना चाहते व्यस्त होकर भी पढ़ने के इच्छुक हैं या आर्थिक कमजोरी के कारण ग्रन्थ अथवा पत्रिकाएँ खरीद कर नहीं पढ़ सकते पर पढ़ने का लाभ से वंचित भी नहीं रहना चाहते ऐसे साक्षरों की शिक्षा को निरंतरता प्रदान करने हेतु ग्रन्थालयों की उपयोगी भूमिका हो सकेगी।

दूसरी ओर वे प्रौढ साक्षर हैं जो परीक्षा देकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिन बच्चों में बीच में ही शिक्षा बन्द कर दी है वह आगे की शिक्षा को चालू रखने के लिए भी सरकार ने सतत् शिक्षा केन्द्र व खुले विश्वविद्यालयों की व्यवस्था कर रखी है।

इन खुले विश्वविद्यालयों से सीधे प्रौढों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से पाठों का प्रसारण भी प्रारम्भ हो गया है। पत्राचार पाठक्रमों के द्वारा प्रौढों साक्षरों की शिक्षा के अवसर प्रदान कर जन शिक्षा के ये सुलभ विद्यालय निश्चित ही बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं।

परंतु यहां प्रश्न यह उठता है कि टी वी के पाठ क्या भारतीय ग्रामीण प्रौढों तक साक्षरों की पहुँच तक उपलब्ध है। क्या पत्राचार में सहायक सामग्री के रूप में उपयोगी ज्ञान सामग्री को क्रय कर पढ़ने की क्षमता उनमें है या कि दश विट्ठल में घटित होने वाले तत्कालीन घटनाक्रमों की जानकारी के प्राथमिक सूचना स्रोत (ग्रन्थ अथवा पत्र पत्रिकाएँ) उनसे प्राप्तपास अध्ययन हेतु उपलब्ध है जिनसे वे अपना खाली दिमाग भर सके।

इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिये राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम की ही तरह राष्ट्रीय ग्रन्थालय नेटवर्क कार्यक्रम को हाथ में लेना होगा ऐसा करने पर जब प्रत्येक गाँव, नगर, शहर, जिला, राज्य व सम्पूर्ण देश में ग्रन्थालयों का जाल फैल जाय तो गाँव के ग्रन्थालयों से गाँव के युवा बच्चे, प्रौढ एवं विद्यालय

रत सभी लड़के लड़कियाँ पानाजन करेंगे । साथ ही सतत् शिक्षा के लिये मानव के रूप में एक अध्ययन केन्द्र मिल जायेगा । खुले विश्वविद्यालयों में प्रदान की गई सुविधाओं में ग्रंथालयों के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम की पुस्तकों को पढ़ाने का अवसर दिया जावे तो गण्डू के सारे नागरिक जो अर्द्ध साक्षर हैं व अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा कम पढ़ी लिखी योग्यता वाले पढ़कर परीक्षा देकर अधिक योग्य होंगे इस प्रकार देश में छपने वाली पुस्तकों का पान प्रदत्त करने की दृष्टि से उपयोग नही हो जावेगा और लोगों की जन शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी निकल आयेगा ।

माना कि हमारे देश में उक्त कार्यक्रमों, टी वी कार्यक्रमों, दूर संचार साधना व कम्प्यूटर के डाटा स सीधा जोड़कर एक विराट समस्या का अनायास उत्तरशील समाधान करने हेतु वनानिक साधनों का सहारा लिया जा रहा है, जो राष्ट्र के लिये जरूरी है । परंतु यह बात निश्चित है कि ग्रंथों पत्र-पत्रिकाओं में एक साथ डेर सारी जानकारी पायी जा सकती है जबकि टी वी और कम्प्यूटर एक साथ विभिन्न पाठकों की अनेक रुचियाँ को एक ही समय में अनेक जानकारीयों देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं । तभी तो एक शोधार्थी ने प्रौढ शिक्षा साधना की व्यावहारिक कमियों का बताते हुये लिखा है कि— सम्पन्न पाठ्यक्रम मुख्यतः शहरों में और कुछ स्थानों पर जिला के द्रो पर ही संचालित होते हैं । ग्रंथालय सुविधायें तब अपर्याप्त हैं । वहाँ न कोई बुक बक है और ना ही मदद सामग्री न कोई अध्ययन केन्द्र है और ना ही प्रयोगशालाओं की सुविधायें । प्रौढ शिक्षा का भागत में क्या स्तर है उक्त पत्तियाँ इसकी वास्तविक छवि प्रस्तुत करती हैं और यह भी स्पष्ट है कि हमारा देश में प्रौढ शिक्षा का भविष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं से अपूरण है तब हमारे लम्बे चौड़े तबनीकी व वनानिक कार्यक्रम कहा तक इनकी पूर्णता में सहयोगी हो सकते हैं यह विचारणीय प्रश्न है ।

हालांकि जन शिक्षा का यह उत्तरदायित्व सिर्फ सरकार का ही नहीं है । इस विकसित करने, जन प्रचारित और प्रसारित करने का दायित्व जनता का, जनसेवी सम्यक्ता व कलकाम व संगठनों का भी है जिन्होंने जन सेवा का बीड़ा उठा रखा है । सरकार ने जहाँ दूरदर्शन, उपग्रह प्रणाली कम्प्यूटर मिस्टम की सुविधा शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रदान करें वहीं दूसरी ओर मावजनिक-ग्रंथालय, ग्रंथालय विभाग, ग्रंथालय सच व संगठना व ग्रंथालय मवाओं में लग व्यक्तियों ने प्रौढ शिक्षा आन्दोलन के यत्न में जनता के साथ मिलकर प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम में जिन साधना (ग्रंथ, पत्र पत्रिका) का अभाव है उनकी पूर्ति की व्यवस्था करें अथवा इन साधनों के नियम व्यापक आन्दोलन चलाकर लोगों में अध्ययन के प्रति रुचि को जगाने ताकि सतत् शिक्षा की शृंखला में पानाजन की सतत् प्रक्रिया निरंतर चलती रहे ।

सदर्भ —

- 1 शिक्षा आयाग (1964 66) प्रौढ शिक्षा पृ 485 रिपोर्ट
 - 2 प्रौढ सतत् शिक्षा एव विस्तार कार्यक्रम मासिक परिपत्र, सागर, डा हरीसिंह गौर विश्व विद्यालय, 2 जून 1986 अंक 6
 - 3 प्रौढ सतत् शिक्षा एव विस्तार कार्यक्रम मासिक परिपत्र, सागर, डा हरीसिंह गौर विश्व विद्यालय, 2 जून 1986 अंक 6
 - 4 जैन (हुकुमचन्द) कार्यात्मक साक्षरता के लिये जन आन्दोलन, प्रौढ सतत् शिक्षा एव विस्तार कार्यक्रम केन्द्र के मासिक परिपत्र से सागर, डा हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय वप, 2 अंक 6 जून 1986
 - 5 Bal Subramaniam (Saraswati) special issues on National Conference on distance Education in University News, Delhi, Vol XXIV, No 42 Nov 8 1986 P 14
-

कृषको के लिए पुस्तकालयों का उपयोग

कृषि पध्दान भारत का नया परिवेश का काय स्वाधीनता के बाद प्रारम्भ हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक ग्रामीण भारत का जन-जीवन बड़ी अनिश्चितता, अभाव, शोषण व गरीबी में चल रहा था। सम्पूर्ण देश में अशिक्षा निधनता व पिछड़ेपन का साम्राज्य था। अज्ञेजाने देश की काफी क्षति पहुँचाई थी अतः नये भारत का नय रूप में सवारने का बीड़ा हमारे भारती पुनो न उठाया।

देश की जनता को सवप्रथम साक्षर बनाने के लिए याजना काल में शैक्षणिक विकास कार्यक्रम गाव गाव सहृ शह- चलवाय, सामुदायिक विकास कार्यक्रम व कृषि उत्तति के अभियान सम्पन्न किए। इन सभी कार्यक्रमों के पीछे राजनेताओं का एक ही उद्देश्य था कि देश के विकास के लिए जनता को शिक्षित जागरूक व प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल बनाया जावे। 'स्वतंत्र भारत में कए धार इस बात की भली भाँति समझ लुके थे कि देश की उत्तति, विकास, कल्याण तथा सुरक्षा के लिए देशवासियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है अतएव अपने अविश्वपूर्ण कार्यों में वे देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे।' अतः समाज शिक्षा के रूप में गावों की प्रौढ शिक्षा पाठशालाओं से जोड़ा गया। समाज शिक्षा में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रौढ साहित्य और जनसाहित्य की रचना की गई समाज के द्रो, पुस्तकालयों, वाचनालयों और जनता कालेजी की बड़ी सरया में स्थापना की गई।

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय याजनाकालों में ग्रामीणों की साक्षरता के काफी अच्छे प्रयास किये गये। "इस समय तक सावजनिक पुस्तकालय का सामान्य शिक्षा के एव सजीव माध्यम तथा एशियाई देशों की सांस्कृतिक भुक्ति अपरिहाय विशिष्टता के रूप में मायता प्राप्त हो चुकी थी।"

प्रौढ शिक्षा में पुस्तकालयों की उपयोगिता का देखते हुए भारत सरकार ने 1954 में सावजनिक ग्रंथालयों के विस्तार हेतु पुस्तकानय सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति ने 1958 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में ग्रंथालय सम्बन्धी व्यापक सिफारिशें प्रस्तुत की गईं जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं।

1. देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पुस्तकानय सेवा नि शुल्क होना चाहिए।

2 सावजनिक पुस्तकालय संरचना का देश में इस प्रकार का स्वरूप होना चाहिए—राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, प्रखण्ड पुस्तकालय और पंचायत पुस्तकालय ।

3 राज्य सरकारों का चाहिए कि वे सावजनिक पुस्तकालय सेवा के प्रति अपने दायित्वों को स्वीकारें ।

4 देश में पुस्तकालय प्रणाली के निर्माण एवं इसकी पूर्ण व्यवस्था के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों का एक 25 वर्षीय पुस्तकालय विकास योजना चलाना चाहिए ।

5 राज्य सरकार एवं भारत सरकार को क्रमशः एक व्यापक राज्य पुस्तकालय कानून तथा केन्द्रीय पुस्तकालय कानून पारित करना चाहिए ।

इस तरह सावजनिक ग्रंथालय सेवा के विकास कार्यों का निरन्तर पंचवर्षीय योजनाओं में तीव्रतर विकास होना चाहिए था ताकि पुस्तकालय सुनियोजित और सुसंगठित शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग बन सकें । भारत सरकार ने इसी उद्देश्य से पुस्तकालय सलाहकार समिति की स्थापना की । इस समिति ने जो सर्वेक्षण किया उसमें सावजनिक ग्रंथालयों की दशा यह स्थिति पायी । 'जहाँ तक सावजनिक पुस्तकालयों पर व्यय की बात है। 1963-64 में राज्यों ने केवल 3 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से खर्च किया जो उस वर्ष राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर व्यय किये गये धनराशि यानि प्रति व्यक्ति 6 40 रुपये के 1/213 भाग के बराबर पड़ता है । देश में 1 जनवरी, 1965 को सावजनिक पुस्तकालयों की स्थिति निम्न प्रकार थी ।'⁴

क्र.सं.	सावजनिक पुस्तकालय प्रणाली	संख्या वष	कितने	प्रतिशत
1	राष्ट्रीय पुस्तकालय	1	पूरे देश के लिए	
2	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	12 राज्य	16 राज्य	75%
3	केन्द्रीय पुस्तकालय	5 केन्द्रशासित	9 केन्द्र	55%
4	जिला पुस्तकालय	205 जिला	327 जिला	63%
5	प्रखण्ड विकास पुस्तकालय	1394 प्रखण्ड	5223 प्रखण्ड	27%
6	ग्राम पुस्तकालय	28317 ग्राम	566878 ग्राम	5%

समिति द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आंकड़ों को देखते हुए 5 लाख 66 हजार 878 ग्रामों में सिर्फ 5% यानि 28 हजार 317 गांवों में ग्रंथालय का होना 70% ग्रामीण भारत की जनता के लिए सतोषप्रद व्यवस्था का प्रतीक नहीं है । फिर भी अशिक्षा, निधनता और बेकारी के विरुद्ध निरन्तर सघन जारी है । किमाना

को (ग्रामीणों) पारिवारिक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परिस्थितियाँ म बदलाव लाने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाएँ, समग्र-ग्राम विकास प्राधिकरण, 20 मूनीय कार्यक्रम, कृषि विकास कार्यक्रम इत्यादि को लागू कर ग्रामों की वाया को नया रूप देने का सफल प्रयास किया गया है। इन सब कार्यक्रमों व योजनाओं के लागू होने ग्रामीणों के बीच जो वैचारिक समानता धार्मिक उच्चता व ममता का वातावरण दृष्टिगोचर होना चाहिए वह नहीं हा पाया है।

आज विज्ञान एवं तकनीकी आविष्कारों ने कृषि उद्योग, स्वास्थ्य पशुपालन एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी में इतनी उन्नति कर ली है कि, विज्ञान की करामाती में खेती व गृहस्थी के कार्यों को अधिक उन्नतिशील व समृद्ध कर दिया है। आज गाँव शहरों की सृष्टि सम्यता व रहन सहन के सम्पर्क में आकर निश्चित ही आधुनिकता की गिरफ्त में आ चुका है, फिर भी ग्रामीण प्रगति में हुई आशातीत वृद्धि के कारणों से वह आज भी अनभिज्ञ बना हुआ है। गाँवों का खेतिहर किसान व मजदूर वैज्ञानिक उपलब्धियों का अपने जीवन में उपयोग कर सुखी तो है, परन्तु इसके ज्ञान में अज्ञानता होकर रह रहा है। भारत के ग्रामीण किसानों के पास आज जहाँ विज्ञान का दो हुई धडियाँ, रडियाँ, टी वी प्रीज ट्रेक्टर, स्कुटर, दाब, रसायन, आज स्वास्थ्य सुविधायें व पशु प्रजनन व पशु पालन की नवीन विधियाँ उपलब्ध करा दी गई हैं वहीं उनमें अध्ययन, चिन्तन सांस्कृतिक व साहित्यिक चेतना की कमी दृष्टिगोचर हो रही है। आज का किसान कृषि स्वास्थ्य, उद्योग व्यापार व तकनीकी साहित्य के अभाव में पूरे समय गाँव के सरकारी अधिकारियों के सुझावों पर निर्भर रहते हैं। कृषि क्षेत्र में जो भी नई-नई तकनीकी होती है उनसे ग्रामीण जन तभी परिचित हो सकते हैं जबकि उन्हें कृषि साहित्य के ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने का सौभाग्य मिले। दुर्भाग्य से यह अवसर अभी देश के शेष (उपरोक्त सारणी के अनुसार) ग्रामों को नहीं मिल पाया है जहाँ एक छोटी विकसित पद्धतियों द्वारा आधुनिक जीवन शैलियाँ न ग्रामों में प्रवेश पा लिया है वहीं यदि ग्राम की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण-पुस्तकालयों की व्यवस्था हो जावे तो कृषक अपनी वैचारिक-प्रगति में भी पीछे नहीं रह सकेंगे। ग्रामीण पुस्तकालयों से होने वाले लाभों से ग्राम के गुया शिक्षित यदि अशिक्षित लोगों को परिचित करवा दें तो हम यह महसूस होगा कि ग्रामालय विहीन ग्राम आज किस तरह अपनी मानसिक-मुसामी का भोग रहे हैं और यदि उन्हें ग्रामालयों की सुविधा प्राप्त हो जाये तो वे किस प्रकार अपने व्यक्तित्व की अपनी कृषि सम्बन्धी, अपने जीवन-स्तर, स्वास्थ्य एवं भोजन सम्बन्धी तथा राष्ट्रीय विकास की गतिविधियों में अपनी मूल्यवान सहयोग देकर और भी अधिक तरक्की कर सकत हैं कृषक का पुस्तकालयों के उपयोग की आवश्यकता क्या है और इनके हानि से उन्हें क्या-क्या लाभ हो सकत हैं उनका हम त्रिवचन निम्नानुसार करेंगे।

(1) भारतीय सृष्टि सन्तोष का परिचय—आज का ग्रामीण जो मूलतः कृषक जीवन व्यतीत कर रहा है अपने ही देश के अथ समाजों, सभ्यताओं में

रीतिरिवाजों व लोक साहित्य सम्पदाओं से अपरिचित है। ग्रामीण को यह वाव नहीं है कि जम्मू कश्मीर, वंगाल, बिहार, केरल व मद्रास की संस्कृति धर्म कैसा है लोग कैसे ह क्या भाषा बोलते हैं और कैसे रहते हैं, उनका व्यवसाय व शिक्षा दीक्षा क्या है। उन साम्प्रतिक अवचेतना का ग्रामीणों में हाने का मूल कारण है, इन पर प्रकाशित होने वाले ग्रन्थों का ग्राम पुस्तकालयों तक न पहुँचना। ग्राम पंचायतों के ग्रन्थालयों में यदि ग्रामीण जनता को देश में प्रकाशित हान वाले विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों व प्रादेशिक प्रगतियों से परिचित कराने वाले ग्रन्थ व पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध हों तो किसान, भारत में फल-फूल रही विभिन्न संस्कृतियों के बारे में, उनके धर्म, खान पान व उनकी उन्नति से परिचित हो सकते हैं। और संस्कृति सर्वोपेय हो सकती है। डॉ. श्रीनाथ सहाय ने सावजनिक ग्रन्थालयों के पास हमारे नागरिकों को पढ़ने के लिए ग्रन्थों की उपलब्ध सरया के बारे में लिखा है कि "पुस्तकों के भण्डार की दृष्टि से भारत में सावजनिक पुस्तकालयों के पास 00 ग्रन्थों पर एक पुस्तक हाती है।" यह सरया संस्कृति सर्वोपेय का ज्ञान कराने की दृष्टि से अत्यल्प है। पुस्तकें संस्कृतियों की सहायक हाती हैं मानव इतिहास का स्पष्ट होती हैं अतः विभिन्न विषयों की पुस्तकों से युक्त ग्रामों के ग्रन्थालयों के लिए साम्प्रतिक आदान प्रदान के केन्द्र व बौद्धिक उत्पादकता के उपादान हो सकते हैं। संस्कृति-समय के रूप में ग्रामों के ग्रन्थालयों को विकसित करना राष्ट्र की समृद्धि के लिए आवश्यक होगा अतः इनकी उपयोगिता का समझा जाना अत्यावश्यक है।

(2) खाली समय का सदुपयोग—ग्रामीणों के एक कुपक परिवारों के पास अपने कुपक काय व लेखी गृहस्थी के कामों के बाद काफी समय बर्बाद व्यतीत हो जाता है। प्रमुख रूप से धीम्म, वषा व ठण्ड की ऋतुओं में कुपकों व लेखीहर मजदूरों को काम से लौटने के बाद काफी समय मिलता है जिसका उपयोग ग्रन्थालयों में जाकर अच्छे-अच्छे ग्रन्थों को पढ़ने व ज्ञान बढ़ाने में किया जा सकता है। एक समय था जब फुसंत के समय ग्राम-वासी अपने आपको मजन कीतन, रामायण वाचन व कथा कहानी सुनने सुनाने में व्यस्त रखा करते थे। आध्यात्मिक व धार्मिक प्रवृत्तियों में लग ग्रामीणों को भी अब आधुनिकता से अपनी शहरी चकाचौंध व वैज्ञानिक प्रगति ने अपने पूर्व कृत्यों से विमुक्त कर दिया है। आज कल ऐसे काम कलाप में लोग ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। किसान अपने काम यंत्रों की सहायता से तथा आधुनिक उपकरणों के द्वारा जल्दी पूरा कर लेते हैं। अतः आराम का समय पहले से काफी अधिक मिलता है। उनका समय के सदुपयोग के लिए उचित मागदशक की आवश्यकता आज और भी ज्यादा है। नहीं तो खाली समय को लोग उपयोगी तौर पर गुजारने के बदले उस बुरे काम में नष्ट करते हैं। जनता खासकर ग्रामीण जनता का इस प्रकार गलत माग अपनाने से बचाने के लिए पुस्तकालय प्रभावशाली काय कर सकते हैं।

(3) दैनिक जीवन में उपयोगी साहित्य का अध्ययन—कृषक जितना कृषि (अनुभव) होता है उतना पढ़ा नहीं होता फिर भी अनुभव के साथ-साथ उसे उपयोगी विषयों के साहित्य का अध्ययन करने को मिल जाये तो शायद उसके जीवन और उसके कार्यों में चार चांद लग जाये, वह धन हो उठे। धन ने यदि उसे अनुभव में अड़थका बनाया है तो शायद उसे अध्ययन व ज्ञान में परिपक्व बना सकते हैं। अभी तक स्वास्थ्य की दृष्टि से वह जड़ी-बूटियों, पड़-पौधों का दवाइयों के रूप में उपयोग करता आया है तो अब अनेक विमारियाँ के प्रारम्भिक प्रकोपों से ही भयभीत है ऐसी स्थिति में यदि घरेलू उपचार प्राथमिक चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा अथवा फल-पूल व सब्जियों द्वारा चिकित्सा की जानकारी उस स्थानीय पुस्तकालयों के रखे चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थों से मिल जाती है तो वह विमारी के प्रारम्भिक लक्षणों को जान प्रारम्भिक चिकित्सा का उपाय कर सकता है।

रोगों के फैलने के कारणों व उनसे बचने के उपायों का अध्ययन कर वह अपने परिवार को बचा सकता है। पशु विमार हो गये हों या गाय भैंस दूध कम देते हों। फसलों में कोई रोग हो गया हो या बाढ़ व रासायनिक उर्वरकों को खेत में डालने की सही विधि ज्ञात करना हो तो वह ग्रामालय में उपलब्ध कृषि-साहित्य पशुओं की बीमारी और घरेलू उपचार सम्बन्धी ग्रन्थों को पढ़कर स्वयं उनका निदान कर सकता है।

घर व खेती में उपयोग में लाये जाने वाले कृषि यन्त्र, मोटर, वाहन व बिजली उपकरणों को ठीक करने के लिए भी ग्रामालय में संग्रहित ग्रन्थों से सुधारन की कला सीख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण पुस्तकालयों में वह सभी साहित्य उपलब्ध हो जो दैनिक जीवन को सवारने सजाने में मदद करें, साथ ही कृषक जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करें। ऐसे साहित्य से भर भण्डार का सदुपयोग कर कृषक स्वयं सिद्ध हो सकने में सफल हो सकते हैं।

(4) धर्म, राजनीति व राष्ट्र से रूबरू होना—ग्रामीण जीवन आज भी धार्मिक आस्थाओं में जी रहा है, परन्तु अपने ही धर्म की परिधि का उसे पूरा ज्ञान नहीं है। अपने धर्म के साथ दूसरे धर्मों से तालमेल बिठाने का अवसर उसे ग्रामालय में संग्रहित अनेक धर्म ग्रन्थ पुस्तकों के अध्ययन से मिल सकता है। धर्मों की वास्तविकता से स्वरूप हानि का अवसर ग्रामालय दे सकते हैं। धर्म से राजनीति का क्या सम्बन्ध है और देश की ताजा राजनीति में देश हित में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं इसकी जानकारी के लिए देश विदेश के प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन से लाभ होता है। प्रजातंत्र प्रणाली में जागरूक नागरिक के क्या अधिकार तथा कर्तव्य है, राष्ट्रीय विकास में उनकी क्या भूमिका है, चुनाव प्रक्रिया की वास्तविकता क्या है, ग्राम प्रणाली, वायुपालिका व प्रशासनिक व्यवस्थापिका क्या है आदि बातों की जानकारी भी ग्रामालयों में जाकर मिल सकती है। राष्ट्र में चर्चा

रही सभी प्रकार की गतिविधियाँ से परिचित होने के लिए ग्रन्थालय वाचनालय में आने वाली, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक धार्मिक व शैक्षणिक-विश्व की पत्रिकाओं से व्यवस्थित जानकारी प्राप्त हो सकती है। उद्योग व्यापार, कृषि व घर-बार की हलचल का भी पता पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन से लग सकता है। उपर्युक्त सभी सुविधायें दिलाने में ग्राम पंचायतों को जिला ग्रन्थालयों व प्रखण्ड पुस्तकालयों की मदद करनी चाहिए।

(5) स्वाध्याय व सतत-अध्ययन से ज्ञान अभिवृद्धि—शिक्षा एक जीवन पथ प्रश्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और औपचारिक रूप से ली जाने वाली शिक्षा की पूर्ति में मदद करती है। इस प्रकार की सतत शिक्षा के अवसर सावजनिक ग्रन्थालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। आज देश के प्रत्येक गाँव में शिक्षा की व्यवस्था हो गई है। जो लोग पहले से साक्षर हैं, जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है और जो नव साक्षर बनकर अपनी शैक्षणिक प्रक्रिया का जारी रखना चाहते हैं वे ग्रामीण ग्रन्थालयों में जाकर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में भर्ती होकर अपने शैक्षणिक पिछड़ेपन का दूर कर सकते हैं। विना स्कूली शिक्षा के भी स्वाध्याय द्वारा अपनी शैक्षणिक प्रगति को बढ़ा सकते हैं। लोक ग्रन्थालय से वे ग्रंथों में जनता के खुले विश्वविद्यालय हैं जहाँ जाकर ग्रामीण स्त्री पुरुष व बच्चे सभी पढ़ाई कर सकते हैं। "प्रौढ़ व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं का पान पाना चाहता है और वह ऐसी सरल भाषा के ग्रंथ भी उपलब्ध कराये जान चाहिए जिन्हें पढ़कर वे अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकें। यह काम सिर्फ ग्रन्थालयों द्वारा ही संभव हो सकता है।" गाँव में ऐसे ग्रन्थालय पंचायतों व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों से सम्बद्ध होकर ग्रामीण जनता का ज्ञान अभिवृद्धि में सहायक होते हैं व हानि चाहिए।

(6) सामुदायिक व सांस्कृतिक हलचल का केन्द्र—ग्राम पुस्तकालयों में जब गाँव की ही अनेक विराट्गी व मनुष्य के लोग पहुँचते हैं, तो उनका एक सामुदायिक संगठन कायम हो जाता है। उनमें एकता सदभाव व सहयोग की भावना जन्म लेती है। ग्रन्थालय में बैठकर विभिन्न मसलों पर चर्चा करते हैं तो वह एक नया माँग मितता है। नया माँग को प्रशस्त वर्गों में ग्रन्थपाल ग्राम जनता को मदद करते हैं। जब कभी मले उत्सव अथवा पुस्तक प्रदर्शनी या भाषण गोष्ठी, खनकूद के समारोह आयोजित किये जाते हैं और उनमें ग्रामवासी अपने अपने धर्म समुदाय व जाति के सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो वह अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। जब एक ही स्थान पर अनेक संस्कृतियों का जमघट होता है तब सांस्कृतिक एकता के बीज प्रस्फूर्ति हो जाते हैं। ये ही सांस्कृतिक एकता व बीज राष्ट्रीय एकता की शक्तिशाली जनता में मदद पहुँचाते हैं। ग्रामीणों का भी गर्व होता है जब वे विना किसी भेदभाव के ग्रन्थालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में एकजुट होकर भाग लेते हैं और उसे सम्पूर्ण मनोयोग से सफल बनाते हैं।

उपरोक्त सभी प्रकारों से ग्रामीण कृषक और उनके परिवारों सेतीहर मजदूरों, युवकों व बच्चा के बौद्धिक विकास में ग्रंथालय अपनी उपयोगी भूमिका निभाने हैं। ग्राम पुस्तकालयों के उपयोग से गाँवों में फैलने वाली सामाजिक बाधियों में बचा जा सकता है। बुरी आदतों अपराधवृत्तियों व लड़ाई झगड़ों में दूर रखा जा सकता है। इन कुसंस्कारों से भविष्य की पीढ़ी को बचाकर उन्हें सुसंस्कारित करने में ग्रंथालयों का साहचर्य भी लाभप्रद सिद्ध होगा।

संदर्भ सामग्री—

- 1 चौबे (सरयूप्रसाद) भारतीय शिक्षा की समस्याएँ, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर पृष्ठ 120।
- 2 चौबे (सरयूप्रसाद) भारतीय शिक्षा की समस्याएँ, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर पृष्ठ 125।
- 3 सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एवं समुदाय, पटना, बिहार हि भ अका पृष्ठ 58।
- 4 सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एवं समुदाय, पटना, बिहार हि भ अका पृष्ठ 58।
- 5 सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एवं समुदाय, पटना, बिहार, हि प्र अका 1980, पृष्ठ 69।
- 6 बगरी (एन डी) भारतीय ग्रामों में पुस्तकालय लेखक की पुस्तक, पुस्तकालय पद्धति इलाहाबाद, नीलम प्रकाशन, 1973, पृष्ठ 5।
- 7 कालमोर (गोपीनाथ) सतत शिक्षा के लिए ग्रंथालय, साहित्य परिचय (भा) आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर पृष्ठ 5।

युवा कृषक मन और पुस्तकालय प्रसार

सामुदायिक विकास एवं पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत को पिछले बीस वर्षों में कृषि, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, विज्ञान एवं टेक्नालाजी में बहुत कुछ आत्म-निर्भर बनाया है। शिक्षा जिसे राष्ट्रीय विकास की आधारशिला माना जाता है, देश में विशाल पैमाने पर फैली, लेकिन जनसंख्या की बढ़ती हुई दर के कारण साक्षरता का औसत स्तर बढ़ने की बजाय गिरता गया, बेरोजगारी फैलती गयी। शासन ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए अप्रेंटिसशिप योजना, उद्योग नृण व कृषि नृण की सुविधा प्रदान की किन्तु ममम्याओं का हल नहीं निकल सका। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।

ग्रामीण शिक्षित युवा वर्ग पिछले दस वर्षों से शहर की ओर दौड़ रहा है। खेती भाग्य भरोसे जो उत्पादन कर रही है वही बहुत है। किसान के दृष्टि को पांच आठ कक्षा तक की पढ़ाई न बौद्धिक स्थिरता प्रदान नहीं की और न ही सुखी खेती के तरीकों से वे अवगत हो पाये। शहरी जिन्दगी के सम्पर्क ने उनके रहन-सहन, खान पान एवं मनोरंजन के दृष्टिकोण को बदल दिया है। मगठित परिवारों में विघटन हो रहा है, पुरानी प्रथाएँ टूट रही हैं जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों का भी बँटवारा हो रहा है।

वर्तमान वैज्ञानिक प्राद्योगिकी, सघन कृषि कार्यक्रम के युग में जब उसने अपनी कृषि को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कार्य एवं सुखी जीवन का आधार बनाया है तो उसे अच्छे कृषि साहित्य, उद्योग समाचार साहित्य ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन-आत्मिक साहित्य की निरन्तर आवश्यकता है। कृषक युवकों का ध्यान शहरी स्कूलों के साथ-साथ देश की राजनीति में भी बढ़ता जा रहा है। उनके पढ़ने की मनावृत्ति ने समाचार-पत्रों कृषि एवं मनोरंजन सम्बन्धी पत्रिकाओं के स्थान पर समासूची एवं अश्लील साहित्य की पुस्तकों की अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाने का साधन बना लिया है। युवकों के चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के साथ ही आधुनिक व कृषि विकास से सम्बन्धित साहित्य सामग्री उपलब्ध न होने से उनका मानसिक स्तर रुका होता है एवं वे अपनी परम्परागत कृषि को ही महत्त्व देकर तसल्ली करते हैं।

हम जानते हैं कि देश में अभी भी पूरी जनसंख्या का चात्नीस प्रतिशत भाग ही साक्षर है। साठ प्रतिशत लोग गाँव में पूणत शिक्षित नहीं हैं। ग्रामीण भारत में नूतन योजनाओं का विकास प्रथमाव में दशाव की गति स गीत नार,

शहर, जिला सभाग प्रवेश एवं दश के क्रम में होना चाहिये था वह सबसे प्रथम शहरी से प्रारम्भ हुई और गावा तक पहुँची भी नहीं थी कि मानवीय दुर्गुणा की झुर चपट में आती गयी। गांधीजी का कहना था “हम गावों से शहर की आर बढ़ना है गावा में ही सबप्रथम, शिक्षा, कृषि विज्ञान एवं उद्योगों की प्रयोगशालाओं का निमाण करना है।” किन्तु यह नहीं हुआ। आज तक जा भी योजनाएँ, परियोजनाएँ श्रियावित की गईं उनका केन्द्र शहरों को बनाया गया और उनके आसपास के दस-बीस गावा का ही अपन वायस्त्र के अन्तर्गत लिया गया और वहाँ तक इनमें प्रयोग चलते रहे। इसलिए विकास योजनाएँ गावा की तकदीर व तस्वीर नहीं बन सकी। प्रौढ शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम काफी समय पहले शुरू हुए थे किन्तु सार्वजनिक आसन्न स्तर चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सका। जो कुछ सुविधाएँ जुटायी गयीं व अस्सी प्रतिशत ग्रामवासियों के हित में न होकर बीस प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में ही बँटा रहे गईं।

गांधीजी तो भारत की आत्मा गावा की मान चुके थे। अतः उन्होंने सहकारिता की भावना गावा में काय करने को बताया था। इसी के अनुरूप देश में सहकारिता आन्दोलन, प्रशिक्षण समितियाँ एवं सहकारी शिक्षा परियोजनाओं का निमाण हुआ था। साम्य समितियों से ग्रामीणों को लाभ पहुँचाना था। 1952 में पुस्तकालय वितरण अधिनियम एवं ग्रामीण पुस्तकालय विकास कार्यक्रम में ग्रामीण जनता में अध्ययन को प्रोत्साहन देना एवं उनके बौद्धिक स्तर को विकसित करने का प्रयत्न हुआ था लेकिन यह शिक्षा प्रसार कार्य भी सिर्फ जिला ग्रन्थालयों तक सीमित रह गया। नेहरूजी का कहना था कि ग्राम पुस्तकालयों का जाल बिछा दिया जाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न रहे और पढ़ने से वंचित न हो सक। ग्राम पंचायतों ने पुस्तकालय व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही शासन ने।

वर्तमान भारत का शिथिल युवा कृषक अब अज्ञान के अधकार में निकल रहा है शहरी नवाचार को अपने चारों तरफ देखना चाहता है, ग्रामीण औद्योगिकरण, कृषि विकास कार्य, तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य की ललक उसके मस्तिष्क में कौंध रही है। सहकारी शिक्षा परियोजनाएँ जो विभिन्न प्रान्ता में प्रारम्भ की गयी हैं, युवा कृषक विकास का सराहनीय कार्य है। इसका द्वारा युवा कृषकों को भूमि परीक्षण, खाद का सही उपयोग - पोषक व फसल संरक्षण कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, पशु रोगों की जानकारी मुर्गी, भेड़-बकरी पालन सूअर-पालन उद्योग, कूटीर उद्योग एवं सुघर हुए कृषि औजारों एवं उन्नत बीजों के चुनाव का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका ही ग्राम विकास योजना बका की कृषि विकास सहायता वषि एवं अनुसंधान आयोग की सर्वेक्षण एवं अनुसंधान प्रक्रिया सभी ग्रामीण विकास में आर्थिक रूप से सहायक हो सकती है लेकिन किसानों की मानसिक आत्मा करल पम में ही नहीं होगी और

न ही लम्बे चौड़े प्रशिक्षण मात्र से। आज का युवा कृषक अद्यावत तक का आदी नहीं है, वह किसी भी कार्य को करने या अमल में लाने में पहले उसके बारे में जानना, अध्ययन करना एवं मनन करना चाहता है, तदोपरान्त वह उसका नियामन चाहता है।

सैद्धान्तिक रूप से थोप गये कार्यों से कृषि क्षेत्र में तरक्की के आसार कम नजर आते हैं। युवा कृषको को दिये जाने वाले प्रशिक्षणों के व्यावहारिक पक्ष का जहां तक प्रश्न है वह कृषि विकास में निश्चित ही सहायक है किन्तु सैद्धान्तिक दृष्टि से कृषि साहित्य की कमी उनके सफल कृषि प्रयोग में विघ्न पैदा करती है। अतः जिस विषय में युवको को प्रशिक्षण दिया जाना है उस विषय में विस्तृत वायस्त्र, शोध एवं अनुसंधान सुविधा, खोज व परिवर्तन सम्बन्धी साहित्य पढ़ने की सुविधा युवा कृषको के लिए हो तो वे उक्त योजनाओं, विकास कार्यक्रमों का सही लाभ लेकर व्यावहारिकता में उपयोगी बना सकते हैं। कुछ वर्ष पूर्व सारे देश में नव युवकों का मण्डली का गठन किया गया था। जिसमें नव युवकों एवं कृषको की खेलकूद, संगीत नाटक, कला एवं अध्ययन सुविधाएँ प्रदान की गयी थी। पचासवीं की निष्क्रियता की निष्क्रियता से न खेल के मैदान बने, ना नाट्य मण्डलियां जीवित रही और न ही युवको को पुस्तकालयों का लाभ मिल सका। इसका प्रमुख कारण भावों में दलगत राजनीति का होना रहा। कुछ प्रयोग व्यावहारिक रूप से अपूर्ण रहे और कुछ सैद्धान्तिक रूप से असफल रहे। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सिर्फ कक्षा में पढ़ा ही सकते हैं लेकिन अगर वह पुस्तकों की पहुँच से दूर रहे या पुस्तकों को पढ़ाने की सुविधा उसे नहीं मिले तो वह कैसे अपने गुरुओं का परिचय देपायेगा उसे अध्ययन के दौरान पुस्तकों का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक यही हाल उन युवा कृषकों का है जिन्हें उन्नत कृषि करना है, मशीनों का उपयोग करना है उद्यान घरों को चलाना है किन्तु उचित माग दर्शन एवं विषय साहित्य के अभाव में असमर्थ है। उद्यान एवं कृषि अनुसंधान कार्य की जिज्ञासा अपूर्ण रह गयी तब युवा मन कहीं भटकना क्या करेगा।

आज मजदूर, किसान युवा विद्यार्थी-सभी को किसी कार्य को करने के पूर्व उसकी अधिकाधिक जानकारी हासिल करना आवश्यक हो जाता है। तकनीकी ज्ञान की कमी एवं यथोचित साहित्य की अनुपलब्धि में युवा कृषक यह नहीं जानना कि क्या करना है। जिसमें पढ़ा ता है लेकिन आत्ममात नहीं किया दुविधा में फँस जाता है। गाँव में पुस्तकालय सुविधा भी नहीं होती कि वे हज़ारों डॉलर सके। कृषि कार्य छोड़कर शहर जाकर कृषि विशेषज्ञों या जानकार अधिकारियों से भी वह मिल नहीं पाता है। ऐसे अवसर पर युवकों को अपनी अच्युती गिना, अपूर्ण व्यवस्था एवं अविकसित क्षेत्र पर माना जाता है। यद्यपि अभिजात ही है कि वे इस तरह शिक्षित होकर भी अभिजात हो रहे हैं अविकसित रहें और फिर भी सपना होने की कोशिश में मेहनत करें और भ्रम में रहें।

शिक्षा का ले तो दसोंगे कि नेशन के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर करने का भरोसा प्रयास चल रहा है यह निहायत जरूरी है। गांव-गांव में सहकारी समितियाँ कृषि सेवा केन्द्र, कृषि अनुसंधान एवं विकास केन्द्र लघु एवं कुटीर उद्योगों के निमाण की याजनाएँ हैं। कहीं ऐसा न हो कि फिर वही पुराना इतिहास दोहराया जाये गांव जहाँ है वही रह सिर्फ शहरी क्षेत्रों को ही लाभ मिलता रहे। एमो कम सम्भावनाएँ हैं, बदलत भारती परिवेश में ग्रामीण पुनर्निमाण को कल्पना शायद गांवों की बाया पलट कर दे। शिक्षा के गुणात्मक विकास में तो वृद्धि नहीं हुई है किन्तु प्रौढ शिक्षा एवं माक्षरता अभियान के द्वारा ग्रामीण जनता में अध्ययन की रुचि अग्रथ्य बढ़ेगी। देश का प्राथिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए एक राष्ट्र को अपने परो पर खड़ा करने के लिए, चाहे वह युवा कृषक हो, चाहे विद्यार्थी या बुजुर्ग, उसके अध्ययन की अभिरुचिया का ध्यान रखा जाना आधुनिक सदन में नितान्त आवश्यक है। ग्रामीण युवकों पर योजनाएँ धोपन से अधिक अच्छा है उन्हें स्वच्छिदक बाय का चयन करने दिया जाय क्योंकि युवा कृषक आदि अधिक पर सिले नहीं ह और न ही पठन जाना चाहत ता उनको दैनिक अध्ययन की सुविधा पुस्तकालया से दी जानी चाहिए ताकि उनका बाहिक सन्तुलन कायम रखा जा सके। समग्र ग्राम विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण पुस्तकालया के निमाण पर भी कुछ साचा जाय तो बुरा नहीं है।

जिन प्रदेशों में शिक्षा का प्रबन्ध अच्छा है उनमें शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन की व्यवस्था पर नजर दोड़ायें तो पता चलता है कि जहाँ भी पाठशालाओं में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय खोले गये हैं उन संस्थाओं ने शिक्षा सत्रों के दौरान कभी भी पुस्तकालयों के द्वार नहीं खोले। जैसा कि 'अग्निमान' में प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पुस्तकालय बहुत कम हैं और जहाँ भी हैं उन स्कूल पुस्तकालयों के ताले सबब ही बंद रहते हैं। कहीं नहीं पुस्तकालय सड़क में बंद हैं तो कहीं कहीं रद्दी के ढेर के रूप में सीजन भरे कमरों में।

जब शिक्षा के मंदिरों की यह दशा है तो गांव-गांव पुस्तकालय निर्माण की योजना कितनी सफल हो सकती है इसका अनुमान हम भलीभांति लगा सकते हैं। फिर भी युवा कृषकों, बच्चा एवं महिलाओं के मानसिक हित को ध्यान में रखते हुए एवं याजनाओं के क्रियाचयन को दैनिक जीवन में आत्मसात करने के लिए पुस्तकालय प्रसार को महत्व देना होगा। उन अस्सी प्रतिशत क्षेत्रों में लोगों को पढ़ने की सुविधा सत्याहित्य से दी जाना चाहिए। योजनाओं की सफलता स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण में फले फूले इसके लिए आवश्यक है ग्रामीण विकास साहित्य का निमाण हो एवं उनके समीप तक पहुँचने में सुगमता हो।

भारत के प्रमुख प्रकाशक एवं अग्रिम भारतीय पुस्तक प्रकाशक महासंघ के निदेशक श्री कृष्णचन्द बेरी ने ग्रामीण विकास हेतु साहित्य निमाण पर बल दे

हए लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे कृषि विकास, उद्योग, कुटीर उद्योग आदि व्यवसायों पर उपयुक्त साहित्य लिखा एवं प्रकाशित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से जनता अध्ययन को महत्व देगी साथ ही अपने व्यवसाय की कठिनाइयों को दूर करने में भी सामर्थ्यमान बनेगी।

इस प्रकार का साहित्य निमाण हान पर उसे गांव गांव पहुँचाना निहायन जरूरी हो जायेगा जिसके लिए पुन पुस्तकालयों के प्रसार एवं विस्तार पर सोचना पड़ेगा। यदि यह सम्भव होगा तो ग्रामीण जनता का अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी, युवा कृषकों को कृषि कार्यों में एवं राष्ट्रीय गतिविधियों को जानने में सहायता मिलेगी। युवा मन को उस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वह अपने व्यवसाय के प्रति सहृदय आत्मापित हो जाय, सारी सुविधाओं को प्राप्त कर उसका हृदय कमल सदैव खिलता रहे योजनाएँ उसके पदचिह्नों पर चले न कि उसे योजनाओं के क्रियान्वयन में खपना न पड़े। पुस्तकालय प्रसार के माध्यम से गांव गांव वह समाचार व साहित्य पहुँचाना जरूरी है जिससे वैचारिक शक्ति जन्म ले और सम्पूर्ण शक्ति का नारा घर-घर द्वार द्वार गूँजने लग। ऐसा मौका युवा जनो को न आय कि छोट छोट कामों के लिए उन्हें सदैव अधिकारियों के पास दौड़ दौड़ कर जाना पड़े। सहकारी संस्थाओं के साथ ऐसे न हों कि किमान उनकी शरण में जा जाकर अपने भांये रगड़, व अधिकारियों के शिकंशों में जकड़े न जाय। युवा कृषकों की समस्याओं का समाधान उसके शिक्षित होने में है, अध्ययनशील और कार्य के प्रति निष्ठावान होने में है। युवा कृषकों को अध्ययन और अनुसंधान की सुविधा पुस्तकालयों के द्वारा दी जानी चाहिए। ग्रामीण आधुनिकीकरण, कृषि एवं तकनीकी अनुसंधान की बात आज बहुत जोर पकड़ रही है। इसने पीछे भारत के समग्र गांवों के विकास की कल्पना है। उद्योग खुल जाये, बराजगारी समाप्त हो जाय और अनुसंधान परियोजनाओं में सफलता मिल जाये तो देश के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक आवश्यक जनक शक्ति होगी। किन्तु मानसिक शक्ति नहीं मिलती, स्वाध्याय की सहूलियत प्राप्त न हुई तो युवा मन पर शायद सबकुछ का नया होगा, वह नहीं सकते। सभी का चहुँमुखी ध्यान ग्रामीणोकरण, तकनीकी कृषि विकास, सहकारी शिक्षा विकास एवं बेरोजगारी समस्या समाप्त करने के साथ ही ग्राम ग्राम पुस्तकालयों एवं अध्ययन स्थलों की स्थापना की शक्ति भी हो तो गांवों पर फैलत अज्ञानता के बादल हटते जायेंगे एवं विकास के पथ में नया मूल उदित होगा जिसके प्रकाश में शहर एवं ग्राम एक में घमकेँगे त्रिविधता की दूरियाँ समाप्त होंगी।

युवा कृषकों का कृषि कार्य में आने वाली बाधाएँ कृषि साहित्य एवं समाचार व अध्ययन से दूर हो सकती है, बशर्ते उनकी समस्याओं का मानसिक दृष्टि से समाधान निकल जाय। पुस्तकालय प्रसार सुविधाओं के लिए युवा जनो के सेवा का भी प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना के कमरों

चाहिए कि ये गावों में वाचन कथा की स्थापना पर बल दे, निरक्षरता को समाप्त करने में ये कक्ष भी सहायक होंगे। अमिल भारतीय विद्यार्थी संघ ने ग्रामोत्थान का जो बीड़ा उठाया है वह बहुत प्रशंसनीय है। गावों की सभी समस्याओं का समाधान तो क्रमशः निकाला जा सकता है, परन्तु जनता को पहले समझदार बनाकर योजनाओं की कार्यविधियाँ में रुचि लेने के लिए भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। देश की ताजी राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक दशा सभी की सम्यक जानकारी उसे मिलती रहे तो निश्चित ही युवा कृषक एवं नागरिक देश के विकास में रुचि लेंगे। इसके लिए पुस्तकालयों में ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय गतिविधियों से युक्त साहित्य पहुँचाया जाना आवश्यक होगा। पुस्तकालय प्रसार सुविधा से ग्रामीण युवा कृषकों एवं अन्य लोगों को निम्न प्रकार से लाभ पहुँचाया जा सकता है।

- 1 निरक्षरता को साक्षर बनाने में
- 2 देश में होने वाले कृषि अनुसंधान, उद्योग व्यापार की खबरें हासिल करने में
- 3 प्रशिक्षित युवकों मजदूरों व किसानों एवं शासकीय सेवकों को अध्ययन के सुअवसर उपलब्ध कराने में।
- 4 अध्ययन गोष्ठियों से समस्याओं का समाधान निकालने में।
- 5 जनता की अध्ययन प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने में।
- 6 बौद्धिक क्षेत्रों का विकास करने में।
- 7 शोध एवं अनुसंधान की प्रेरणा को प्रोत्साहन दिलाने में।
- 8 नारी जागरण एवं राष्ट्रीय निर्माण में सहायता पहुँचाने में।
- 9 समग्र ग्राम विकास को आधार दिलाने में।
- 10 पुस्तकालय उपयोग के महत्त्व को सामान्य जन भी जान सकेंगे।

उपरांत ग्रुहों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि घर घर ज्ञानि-लान में जानागार ग्रन्थालय बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। यद्यपि पुस्तकालय प्रसार की आवश्यकता को आज तक अनुभव नहीं किया गया है जबकि यह ग्राम की ऐसी इकाई सिद्ध हो सकती है जहाँ समग्र ग्राम की भावनाओं को पैदा पनपा एवं अनुभव किया जा सकता है।

शासन एवं जनता दोनों को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना चाहिए ताकि भावी भारत के पुनर्निर्माण की कल्पना को साकार रूप प्रदान किया जा सके।

पुस्तकालय प्रचार की आवश्यकता

विषय की विधिवत् व्याख्या करने के पूर्व पाठका से आग्रह करेगा कि व द्य नये प्रचार पर आश्चय न करें। जन सामा य यह न सोच कि जीवन की अनियाय वस्तुमा क प्रचार से तो हमारी आत्मसंतुष्टी नहीं हो रही है तब यह पुस्तकालय प्रचार हमारी किम आवश्यकता का सन्तुष्ट करेगा। लिखना, यह भी एक प्रकार का पुस्तकातय प्रचार ही है। जब जिनासु पाठक पुस्तकें व पत्र पत्रिकायें प्रतिनिधिया पुस्तक विज्ञेतामा, पान ठलो सामाय पुस्तक स्टालो से प्राप्त नहीं कर पाता है तब उसक मस्तिष्क का एक तार भ्रूत हाता है और उसक पग सावजनिक पुस्तकालय विद्यालयीन पुस्तकालय महा विद्यालयी पुस्तकालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय के द्वार की ओर बढ जात है। यह प्राय जिनासु पाठक व शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है कि वह किस पुस्तकालय से प्रभावित है, और किस पुस्तकालय का नाम या सेवा काया के गुण उसने सुन रख हैं तथा वह किस सत्स्य व पुस्तकालय का सदस्य है या बनना चाहता है।

यह इतना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति पुस्तकालय के सदस्य बन ही जावें और उन्हें पूरा सन्तोष प्राप्त हा। कारण स्पष्ट है कि मानव क समक्ष उसकी आधिक सामाजिक सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं एतिहासिक स्थितिया का पहाड खडा होता है जिसका सामना करने क उपरांत वह इस योग्य नहीं रह पाता कि वह पुस्तकालय जैसे पान गृह तक पहुचकर अपना मानसिक तनाव कम कर सके। तात्पर्य यह कि पुस्तकालय-सेवा उनके लिए उनकी सुगम और सुलभ नहीं है कि व आसानी से उस जीवन निर्वाह म उपयोगी बना सक।

विकास र युग म मानवीय ज्ञान ने जितनी सुग सुविधाओं क उपागान साज है उनम बौद्धि-स्तर का सक्षम बनान क लिए पुस्तक का निमाण, विविध विषयो की ग्राज एवं पुस्तकालय का विकास एवं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिन प्रकार मानव शरीर का शक्तिशाली बनाने क लिए ग्राज पदार्थ की प्रतिबायता मानी गई है तदनुसृ ही पानश्रम को शक्तिशाली बनान क लिए पुस्तक एक ऐसा उपकरण है जिसक अध्ययन से मानव मस्तिष्क की बौद्धिक श्रुत शान हो सकती है। चटनी प्रचार का मानव विविध विषयो के ज्ञया का पगपण है।

मानव द्य बौद्धि-श्रुता का मिटान हुनु जाने क्या-क्या उपाय मात्रा है और चाहे अंत भी हा पुस्तक प्राप्त करन पढ़न का प्रयत्न करना है। जब तक

वह ग्रन्थ का पारायण नहीं कर नेता बन नहीं पाता है। पट की भूम मनुष्य को मिटाने का कारण है नो मन्त्रिण की भूम भी मनुष्य की उत्तेजना का कारण बन सकती है।

अतः पुस्तकालय में जाकर पुस्तक में याग आज की महत् आवश्यकता बन गई है। निम्न परिवार में लेकर उच्च परिवार के लोग के लिए बिना किसी भेद भाव के ऐसे अध्ययन के आधुनिकतम साधन जुटाये कि सहज भाषा से सुगमता पूर्वक, समीर-मरीच, दून-अच्छे, बूढ़े-बच्चे, अंधे-बहर, लूले लगभग सभी प्रकार के व्यक्ति पुस्तकालयों का लाभ प्राप्त कर नानाजन कर सके।

वर्तमान में विपश्चि पुस्तकालयों की संख्या अल्प है। सावजनिक एवं व्यावसायिक पुस्तकालयों का देश भर में जाल बिछा हुआ है, फिर भी वे पुस्तकालय अपने लक्ष्य का पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सावजनिक पुस्तकालयों की मर्यादें पाठकों के शैक्षणिक स्तर के मान से ठीक हैं किन्तु उनमें वैज्ञानिक तकनीक का अभाव पुस्तकालय व्यवस्थापना की बर्बादी का दशाता है। ग्राम पाठक इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि ग्रामीर वास्तविक वस्तु स्थिति का ज्ञान उन्हें नहीं होता है। अतः यह अनिवार्य रूप से मान लेना चाहिये कि सावजनिक पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण ऐसे स्थान पर हो जहाँ जनसमूह अत्यधिक मात्रा में अपना समय व्यतीत करता हो, जहाँ बड़-बड़ ऊपर-उसकी पढ़ने की तीव्र अभिलाषा हो।

ऐसे स्थल बाजार मण्डि, चौराहा, मोटर स्टण्ड या पब्लिक मिटिंग स्थल हो सकते हैं। यह तो हुई भवनों के निर्माण स्थल की बात, द्वितीय भवन के कक्षों में अध्ययन की आराम देह सुविधा हो, अच्छे-बुरे ग्रन्थ हो, और विशिष्ट बात यह हो कि वाचनालय बस के स्टण्ड के किनारे वाला भाग से जीव की लिडकियां ले बने हो जिसमें अध्ययनार्थ पाठक चलने-फिरने वाले व्यक्तियों का दिवाई दे और महज ही उनका मन भी पुस्तकालयों को देखने के लिये आकर्षित हो पाये।

जिस प्रकार विज्ञान अपनी बहुमूल्य वस्तुओं व उपकरणों को बचन हेतु अपनी दुकान की प्रति आकर्षण बनाता है, जिसे देखकर स्वाभाविक रूप से क्रेता उन दुकानों की ओर देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं तत्सम ही पुस्तकालयों की बनावट ऐसी हो कि जन सामान्य उसे दगबर आकर्षित हो, 'आकर पढ़ने का दो मिनट के लिये अवसर दे। इस प्रकार की पुस्तकालय सेवा निःशुल्क हो ताकि पुस्तक का उपयोग अधिक से अधिक हो। ताजा राजनीति देश विदेश की हलचलों से सामान्य लोग भी पढ़कर अवगत होते रहें और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यवहार में रुचि ले और अपने अस्तित्व को देश के निमित्त जानने में समर्थ हो सकें।

लेकिन आज व्यवसायिक पुस्तकालयों का लक्ष्य अधिक से अधिक घटिया किस्म के उप-पाठों की विक्री मात्र है, यह एक प्रवृत्ति हो गई है कि उप-पाठों को पढ़कर ही हम अपना बौद्धिक स्तर ऊँचा उठा सकते हैं किन्तु अच्छे अध्ययन के लिये यह कोई

अच्छे साधन नहीं है न सक्षम । शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए गाव-गाव, शहर शहर पुस्तकालयों की आवश्यकता है ।

हमारे देश में इन पुस्तकालयों के इतिहास का भविष्य अभी तक बहुत अ-कार में रहा है । अभी तक ऐसे कोई साधन नहीं आनाये जा रहे हैं कि पाठकों में सहज भावना की जाग्रति हो सके और न ही सहज रूप से पुस्तकालयों की उपलब्धि हो रही है जिनका पूरा लाभ उठा मिल सके ।

भारत में स्थित विदेशी पुस्तकालय जैसे ब्रिटिश कॉंसिडर लायब्रेरी, यू एस आई एम पुस्तकालय आदि देश के महत्वपूर्ण पुस्तकालयों के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं जिनके सामने भारतीय पुस्तकालयों की स्थिति, कार्यक्षमता एवं सेवा क्षेत्र फीके होते जान पड़ते हैं । दूतावासा के पुस्तकालयों का अपना अभिन्न स्थान बन गया है जिन्हें जासूसी अड्डों का रूप माना जाता है । ये पुस्तकालय अधिक से अधिक सेवा देकर हमारा लाभ पहुँचाते हैं तो देश में जासूसों का जाल फैलाकर हमें दुख भी पहुँचाते हैं । विगत कुछ वर्षों से इस प्रकार की घटनाएँ सामने आई हैं जो भारत के लिये एक कष्टप्रद बात है । इनके विरुद्ध कदम उठाये जाने चाहिये ।

हमें चाहिये कि साक्षरता के विकास में पुस्तकालयों का उपयोग अधिक व अधिक करें । सुधरे हुए वैज्ञानिक तरीकों से निर्मित पुस्तकालय-उपकरणों एवं पद्धतियों को अपनाये ताकि पुस्तकालय सेवार्थ जन सुलभ होकर अधिक प्रबल हो ।

उपरोक्त बातों को पूरा करने हेतु हमें जन साधनों का प्रयोग करना चाहिये जिससे पुस्तकालयों के प्रचार में सुविधा हो और उक्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकें । पुस्तकालय प्रचार के लिये हम निम्नांकित बातों पर विचार करना आवश्यक माना ।

शैक्षणिक संस्थाओं के लिए वर्तमान में प्रायः 8 वीं से 11 वीं तक पढ़ने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे स्तर एवं सर्वोत्कृष्ट साक्षरता के प्रतिशत का दृढ़ सुझाव मिले । सामान्य उपरोक्त कुछ बातों के लिए सतत् प्रयत्नशील रहना आवश्यक है, जो कि मनुष्य को मददगार रखत हुए भर्त्ता बन सकें । समय का इसका इन्तजार है ।

पुस्तकालय वार्ता—जहाँ पुस्तकालयों की संख्या कम है, वहाँ जहाँ पुस्तकालयों की गतिविधियों में सम्बन्धित कार्य कम है, वहाँ जहाँ पुस्तकालयों के होने वाले परिवर्तनों, उसकी पद्धतियों, विधियों, विचार-मार्गों को मिले । पुस्तकालय के विकास के लिए हमें सतत् प्रयत्न करना चाहिए । हमें इस प्रकार की योजनाएँ बनानी चाहिए, जो कि हमें सतत् प्रयत्न करने में मदद कर सकें । हमें सतत् प्रयत्न करना चाहिए, जो कि हमें सतत् प्रयत्न करने में मदद कर सकें । हमें सतत् प्रयत्न करना चाहिए, जो कि हमें सतत् प्रयत्न करने में मदद कर सकें ।

वार्ता, विषय से सम्बन्धित विद्वानों द्वारा सम्पन्न होनी चाहिये, ताकि उपयुक्त विषय की गहन पैठ में उतरकर विद्वान वक्ता पाठकों का मन सम्मोहित कर ले और बार बार विषय की अच्छाइयों को सुनने में आग-तुक पाठक का मन लालायित हो। यह विशेषता भी पुस्तकालय प्रचार का महत्वपूर्ण सहयोगी भूँग है।

रेडियो वार्ता— भारत वष में रेडियो के आने से प्रचार साधनों की बाढ़ सो आ गई है सभी प्रकार के औद्योगिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक, राजनैतिक ऐतिहासिक गतिविधियों के प्रचार रेडियो के माध्यम से होने लग है शिक्षा के क्षेत्र में भी केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न विषयों पर शैक्षणिक-वार्ता रेडियो द्वारा प्रसारित होती है, जिससे देश विदेश में होने वाले अनुसंधान, नये विषयों के आगमन की जानकारी के साथ ही उन पर शिक्षाप्रद लेख की प्राप्ति हमें होती है। किंतु हमें यह है कि कोई शिक्षक या वक्ता विद्वान अपने भाषणों व वार्ता में कभी इस प्रकार से नहीं कहते हैं कि इस प्रकार के अध्ययन हेतु पुस्तकालयों की शरण जाकर उन विषयों पर खोज करना चाहिये। कुछ अनुमार्गित्सु विद्वान पाठक एस होत है जिन्हें प्रथमपण, इण्टेक्स, एबस्ट्रेक्ट की जानकारी ही नहीं होती और व पी एच डी भी प्राप्त कर लेत हैं जबकि पुस्तकालयों में इन्हें बिना देखे निर्धारित विषय पर पूर्ण सामग्री की जानकारी हो ही नहीं हो सकती है। अतः यह वक्तमान में अत्यंत आवश्यक है कि रेडियो के माध्यम से पुस्तकालय सेवाओं की वार्ताओं का आयोजन किया जावे तभी अनुसंधान के विविध नवीन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। रेडियो वार्ता में पुस्तकालयों से होने वाले लाभ, उनकी सेवाओं के क्षेत्र, उनकी विशेषताएँ एवं वैज्ञानिक युग में उनकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला जाना आवश्यक है, आज यह साधन खर्चीला अवश्य है किन्तु प्रचार के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।

फिल्म प्रदर्शन—फिल्म स्ट्राइल के माध्यम से 'पुस्तकालयों की सेवा, सम्बन्धी प्रचार किया जा सकता है शासन का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि जिस प्रकार धूम्रपान, नशाबन्दी, छुआछूत के स्लाइड्स छविगृहों में दिखाने की व्यवस्था रखते हैं उसी प्रकार से एक पक्ष यह भी दिखाने का आदेश होना चाहिये कि "पुस्तकालयों से लाभ उठाइये" या "पुस्तकों की जीवन का भग बनाइये" "पुस्तकालय चलो" इत्यादि। इस प्रकार के प्रदर्शन से दशकों में पुस्तकालय के प्रति मोह होगा और वे जाने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि विद्वान पुरुषों ने जो समय पुस्तकालयों में व्यतीत किया है उसका चल चित्र प्रदर्शित करना चाहिये। पुस्तकालयों में अध्ययनरत शोधकर्त्ताओं के चित्रों को एक पूरे पलक पर प्रदर्शित करना चाहिए और पढ़ने में मिलने वाली योग्यता का परिणाम सहित उसके चित्र का प्रदर्शन आवश्यक है। इन्हीं प्रदर्शनों के माध्यम से युवा वर्ग में प्रतिस्पर्धा की भावना जाग्रत होगी और पढ़ने में अधिक रुचि लेने लगेंगे। यह कार्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा अधिक सुविधाजनक हो सकता है।

विज्ञापन—समाचार पत्रों पत्रिकाओं में यह आवश्यक सक्त दिया जाना चाहिये कि पुस्तकालयों से दश की सस्कृति और सभ्यता का पता लगता है। माक्षरता का माप उस दश में निहित पुस्तकालयों से होता है। विभिन्न प्रकार के कोटेशन लिखे जा सकते हैं जैसे—

पुस्तकालय ही सच्चे विश्वविद्यालय है। पुस्तकालय ज्ञान का कल्पतरू है इससे जो मागोग वही मिलेगा। महान बनने की प्रयोगशाला पुस्तकालय है आदि आदि। इस प्रकार के विज्ञापन अवश्य ही पुस्तकालय प्रचार में सहायक हाग और उसकी आवश्यकताओं को समाज के सामने प्रतिबिम्बित करेंग। बड़े-बड़े लिखे पोस्टर एवं पम्पलेट दिवाला पर चिपका कर भी विज्ञापन किया जा सकता है।

पुस्तकालय सघों की स्थापना—यह सत्त्व पुस्तकालय प्रचार का अनिवार्य साधन है। राष्ट्र सेवा, सघों के माध्यम से अधिक होती रही है। कहते हैं सघ शासन की राह में बाधक भी होत है किन्तु यह एक शका भाग है सघ तो होने वाले विकास के लिए शासन से माग करता है, यदि शासन भाग भजूर नहीं करता तो सघ की एकता उन भागों को मनवान का पूरा प्रयत्न करती है और तभी विकास का पथ अग्रसर होता है।

भारत में पुस्तकालय सघाओं से सम्बन्धित राष्ट्रव्यापी सघ नहीं है जो कि पुस्तकालयों के प्रचार को बढ़ाने में महयाग दे। छोटे छोटे राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय सघ अवश्य है किन्तु वे उतने क्रियाशील नहीं हैं जितना की सघा को होना चाहिये। केन्द्रीय सगठनों से उनका कोई तालमेल नहीं बैठा है। पुस्तकालयीन सेवाओं की अवन्ति का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि अभी तक पुस्तकालय सघा न मिलकर ऐसा कोई कठोर कदम नहीं उठाया है जो सबहित में रहा हो। सघा को चाहिये कि वे एक हाकर इस आ दोलन को बड़ाये और भारत में निहित निरक्षरता को समाप्त करने में अपना बहुमूल्य यागदान दे।

अन्तर पुस्तकालयीन आदान प्रदान—हमारे देश में पुस्तकालयों के विकास की गति अति मन्द रही है, साथ ही साथ विस्तृत रूप में फले राष्ट्र के पुस्तकालयों में आपसी लेन-देन की प्रक्रिया को प्रास्ताहन नहीं दिया गया, आज भी हम दावते हैं कि अल्प मात्रा में विश्वविद्यालयीन स्तर पर पुस्तकालयों से पुस्तकों का आदान प्रदान होता है जबकि इसका रूप व्यापक होना चाहिये। ग्रामीण पुस्तकालयों से लेकर राष्ट्रीय पुस्तकालय तक श्रृंखलित व्यवहार होना चाहिये ताकि जिज्ञासु पाठकों को वाञ्छित पुस्तक की प्राप्ति में विलम्ब न हो। इस प्रकार के आदान-प्रदान से किसी भी स्तर का व्यक्ति अपनी वाञ्छित पुस्तक की माग कर सकता है इसने लिए उस ग्रन्थालय को जहाँ का वह सदस्य है पूरा सहयोग प्रदान करना चाहिये।

इस प्रकार अन्त पुस्तकालयीन आदान प्रदान की जानकारी जन सामान्य में होगी ता मदक प्रवृत्तिवत्त मनुष्य ऐसे सहयोग का लाभ प्राप्त करत रहेंग एवं

पुस्तकालय प्रचार अधिकाधिक होकर पुस्तकालयीन सेवाया में वृद्धि को प्रोत्साहन देगा।

छोटे से छोट पुस्तकालय को बड़े से बड़े पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों का लेन देन बंटाना चाहिये और बड़े पुस्तकालयों का यह वक्तव्य हो जाना चाहिए कि वे पुस्तकों तथा समय पहुँचाने में डाक द्वारा मदद करें। इसी प्रचार के कारणों से पाठकों की अभिगम पूर्ण होगी एवं पढ़ने की अभिरुचि अधिक जाग्रत होगी। सभी घर बैठ अपने पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों मगवाकर पढ़ सकेंगे।

सदभ सेवा केन्द्र—यह पुस्तकालय की विशेष सेवा होती है। राज्या में जहाँ-जहाँ केन्द्रीय एवं राज्य पुस्तकालय स्थापित हैं, साथ ही विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के बड़े पुस्तकालय हैं उन पुस्तकालय भवनों में एक सदभ सेवा कक्ष भी होना अति आवश्यक है। सामान्य रूप से इस प्रकार के केन्द्र सभी पुस्तकालयों के अनिवार्य अंग हैं, इन विभागों के बिना पुस्तकालयों की विशिष्टता नजर नहीं आती अतः इन केन्द्रों का निर्माण पुस्तकालयों के लिये जरूरी है।

पुस्तकालयों में जहाँ सेवाएँ दी जाती हैं न जाने कौन किस समय क्या प्रश्न लेकर उपस्थित हो जाये और आप आश्चर्यचकित होकर उसका मुँह ताकत रहा, अतः सदभ सेवा केन्द्र ऐसे प्रश्नों का उत्तर शीघ्र देकर उनकी अभिगम को पूर्ण करेगा। सदभ सेवा केन्द्र में चलचित्र, अणु चित्र, आडोविजबब एडस सीटीयल पक्की एवं सरकारी प्रकाशना का होना आवश्यक है। यदि ये उपकरण आपके पुस्तकालय में हैं तो सदैव ही कोई न कोई समस्या मूलक पाठक आप तक पहुँचेगा और हल की प्राप्ति पर जन-साधारण में प्रकट करेगा तभी आपके पुस्तकालय का सही उपयोग हुआ माना जावेगा। शीघ्र सदभ सेवा एवं दीघ सदभ-सेवा के माध्यम से प्रत्येक प्रकार के पाठकों को सेवाएँ दी जा सकती हैं पुस्तकालयों में टेलीफोन की व्यवस्था दीघ सेवा का एक उपकरण है जो आवश्यक सन्दर्भ विभाग में वर्णों का सामग्री क्या न हो एक वष में यदि हजारों में से एक ग्रंथ भी काम आ गया तो समझना चाहिये कि एक पुस्तकालय का निर्माण हुआ। इस प्रकार का पुस्तकालय प्रचार आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के लिये आवश्यक है जस जनसंख्या के आंकड़े, जन्म मृत्यु दर, मुद्रा स्थिति इत्यादि।

पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन—ज्ञान विज्ञान की अनेक पुस्तकें देश विदेश में प्रकाशित होती हैं, देश विदेश में टूटने वाले विभिन्न अंग्रेपण एवं अनुसंधान कार्य सम्बन्धी पुस्तकों की जानकारी अनुसंधान पाठकों को नहीं हो पाती है, इस प्रकार की प्रकाशित एवं पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों को मस्यागत-पुस्तकालयों में प्रदर्शित करना चाहिये, यदि ऐसा नहीं होगा तो एक विषय में होने वाले अनुसंधान सम्बन्धी पुस्तक यदि 2 वष प्रायः पुस्तकालय में आती है या प्रदर्शित होती है तब तक विश्व में उस विषय पर न जाने कितनी खोज हो चुकी होती है, ऐसी अवस्था में पुस्तकालय सेवा अपने आप में अक्षम हो जाती है।

पुस्तकालया म या आयत्र वही पुस्तक प्रदर्शनीया आयोजित की जाय वहां देसन वान दसव पुस्तकालय क गुण-दोषा स परिचित हो सक तथा उसस सम्प्रचित माहित्य की पडवर सा उठा सक । पुस्तकालया की मयात्रा की अधिक सक्षम बनान हेतु उन पुस्तका की प्रदर्शना रनी जावे जिनकी प्राप्ती प्राप्त-पास क प्र या लया म नही हो सकनी, इस प्रकार का उद्यम सभी पुस्तकालयाध्यक्ष क तो प्रत्येक प्रयानय म विशिष्ट एव दुनम प्रया का संग्रह हो जावेगा जिह पढ़ने दूर-दूर स प्रामुखित्सु पाठक आयेंग इस प्रकार स उक्त प्रयालया का प्रचार तीव्र गति स होगा । प्रति पुस्तक प्रति पाठक की अभिगम भी पूर्ण होगी । मनचाहा पाठक पुस्तक का धीर चहेती पुस्तक पाठन की मिलगी पुस्तकालयो के उद्देश्य भी पूर्ण होग एव पुस्तकालय प्रचार म वृद्धि होगी पाठका म वृद्धि हागी ।

गो रम (खिडकी प्रदर्शन)—प्राचीन समय म पुस्तका की सजाकर रखने म मतनय सुरक्षित रखन से था, बहुत आकषक जिल् साजा और बडाइ हुआ करत थी किन्तु जजौरा स वधी रहने क कारण ग्राम व्यक्तियों क काम नही आनी थी उनका एक मात्र कारण पढ़ने की प्रवृत्ति एव साक्षरता की कमी का था किन्तु जन्म बागजा का बनना प्रारम्भ हुआ और प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था हुई, शिक्षा क क्षेत्र म भी विकास हुआ तभी म पुस्तका का उपयोग बढ गया । वतमान म पुस्तक मनुष्य क मन बहलाव का साधन-स्वरूप मित्र हो गई है । मित्र होने पर पाठको का विद्याह ग्रन्थ नहीं लगता बह चाहता है कि जसे ही पुस्तको का कम हो (रचना के प्रकार क रता रहे मित्रता का हाथ बढाकर पुस्तको से स्नेह पाता रहे । अत जस ही नवीन उत्तम इतिया प्रकाशित हो उह पुस्तकालय क एक कमर म जो पूर्णत शीश प्यार करता रहे मित्रता का हाथ बढाकर पुस्तको से स्नेह पाता रहे । अत जस ही पुस्तक पढ़ने क लिए मिला करें । यह कमरा सामा म कमरा म अलग एक सिर से बना हो सजाकर अच्छी तरह रख दना चाहिये नाकि पाठको की प्रत्येक नई दृष्टि मिरे तक सडक क बिनारे स लगा हुआ होना चाहिय जिस देगकर यात्री आकर्षित हो और पुस्तकालय म प्रवेश हेतु ललक उठे । यही कमरा वाचनालय क बन होना चाहिये ।

सहकारिता—वतमान युग म सहयोग अनिवार्य आवश्यकता के रूप म सामने आता है । देश जहा विदेशा का सहयोग लेकर अपने व्यापार व्यवसाय, आर्थिक राजनतिक एव प्र तरापीय सम्बन्धों को मजबूत बनाता है और आय विकासशील देशों की तुलना म अपन की मक्षम एव योग्य समझता है वहा दूसरी और राष्ट्र मे शिक्षा वृत्ति मानव कल्याण सचार एव प्रशासनिक व्यवस्था का कायम रखने के लिए भी अपने पडोसी राष्ट्रों स सहयोग लेना पडता है जिसम राज्या का बहुमूल्य योगदान सराहनीय है ।

इसी प्रकार से शिक्षा में गायरत इकाई पुस्तकालय, सावजनिक एवं निजी पुस्तकालयों को आपस में सहयोग देना चाहिये। सहकारिता की भावना से ही इन पुस्तकालयों का विकास सम्भव है। जनता के द्वारा पुस्तकालयों के भण्डार सामग्री को बढ़ाने हेतु अपने ग्रन्थ भण्डारों का दान करना चाहिये, आर्थिक दृष्टि से सहयोग प्रदान कर जनता में जाग्रति एवं अध्ययन की रुचि को द्विगुणीत करना चाहिये।

सहकारिता से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को शाखा के द्वारा विश्व भर के पुस्तकालयों को आर्थिक एवं ग्रन्थ सम्बन्धी सहयोग प्रदान किया जाता है ताकि विश्व बहुत्व की भावना बड़े मानव परमाणु हो, जिसे म मानवजनक मापदण्ड निर्मित हो। मानव की जिजिया दिन प्रति दिन इस ओर गहरी हो तो शिक्षा का मानव स्तर निर्मित होगा। इस ओर शासन की रुचि होना अनिवार्य है, राष्ट्रीय पुस्तकालय योजना का निर्माण, पुस्तकालय अधिनियमों की म्योदृति सहकारिता का सुंदर उदाहरण है।

अतः यह कहा जाना उचित ही होगा कि उपक्षित पुस्तकालयों के लिये शासन की जागरूक होना चाहिये, साथ ही साथ जनता को भी सरकार का साथ देकर इस सेवा का स्वाध्याय के प्रति आकृष्ट बन रुचि का क्षेत्र बनाना चाहिये और सारे देश में इस प्रकार के प्रचार माध्यम से पुस्तकालयों का विकास कर निरक्षरता में कमी एवं शिक्षा में वृद्धि कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहिए।

जिस प्रकार किसी देश विशेष की उन्नति शिक्षा से मापी जाती है तत्सम हमें भी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाकर अपना चारित्रिक मनोबल, नतिक विकास एवं शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाना है। ऊँचे उठे रहने के लिये जिस प्रकार ताड़ के पत्र की जड़ शक्तिशाली होती है उसी प्रकार शक्षणिक संस्थाओं के स्तर का बढ़ाने के लिये हमें पुस्तकालय रूपी जड़ों का जाल सारे देश में फैला देना चाहिये यही पुस्तकालय प्रचार देश के सर्वांगीण विकास में महामुक्त हो सकता है। सर्वांगीण विकास से मेरा तात्पर्य चतुर्मुखी उन्नति से है। राष्ट्र का हर नागरिक जब शिक्षित होगा तो उसे प्रत्येक क्षेत्र में काम करने की गहरी रुचि जाग्रत होगी। देश विदेश की नवीन राजनीति को समझने में वह समय हागा तथा अपना भला बुरा समझेगा। व्यापार व्यवसाय में कुशल होगा, और सबसे बड़ी बात होगी, अपने परिवार की भली-भाँति परवरिश, जिस हम महगाई के युग में नहीं कर पाते हैं। अधिशा से नाना विकारों, व्यसनो में फँसा व्यक्ति अपना नतिक पतन कर रहा है उसके सामने स्वयं के अस्तित्व तथा इज्जत का प्रश्न तो है ही नहीं और राष्ट्र के गौरव का भी उसे ख्याल नहीं है। तब वह किस अपने आपका राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान अर्थात् नहीं। देश-विदेश, राज्य-राष्ट्र समाज परिवार, धर्म संस्कृति बना विज्ञान राजनीति इतिहास इन सभी बातों को जानने में व्यक्ति तभी समर्थ होगा जब वह शिक्षित होगा, चरित्रवान और निष्ठावान होगा।

उपरोक्त बातों से निष्पत्ति रूप में यह कहा जा सकता है कि पुस्तकालयों का प्रचार अधिकाधिक माध्यमों से किया जावे, जनता एवं शासन दोनों ही इसके प्रचार में सहभाग दें एवं निज की उन्नति का साधन मानकर बहुजन हिताय इसके प्रचार में जुट जाय। देश पर महरा रहता सकट अशिक्षा से उत्पन्न भीड़ कान्ति है। कुछ शक्तिशाली और शिक्षित हैं उनकी मुट्ठी में देश की 80% ग्रामीण अशिक्षित जनता बन्द है, जिधर बुद्धिमान का इशारा होता है उसी ओर अशिक्षितों की भीड़ टूट पड़ती है। शिक्षित भीड़ होती तो एक बारगी सोचती किन्तु यहाँ ऐसा नहीं है। इनमें हम शिक्षा का मत फूँकना है ताकि इनमें नैतिक चरित्र का निर्माण हो जो राष्ट्र को शक्ति भक्ति और एकता देगा। इन सब बातों के लिये प्राथमिक उपचार पुस्तकालयों का प्रचार है जिनकी आज गाँव गाँव शहर शहर, गली गली मोहल्ला-मोहल्ला आवश्यकता है, यही मनुष्य के विकास का सस्ता और सुलभ उपाय है तथा निरक्षरता समाप्त करने का यत्न है। इन यत्नों के निर्माण में शक्ति की वृद्धि रही है अवश्यमेव उन्नति के परम स्थल ये सरस्वती के ज्ञान भवन संस्कृति कला विज्ञान एवं मानव इतिहास के साक्षी हैं। इनका निर्माण सच्चे पथ का निर्माण होगा शीघ्र आइये सहकार सह समस्या का समाधान होगा।

ग्रामीण पुस्तकालय भवन व फर्नीचर

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में पुस्तकालयों का जाल बिछा देने के पीछे ग्रामीण भारत की अनपढ़ जनता को शिक्षा एवं स्वाध्याय के सुअवसर प्रदान करना था। प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली में प्रत्येक नागरिक को जाम्बूक होकर अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होता है। इसी मौलिक अधिकारों की महत्ता एवं व्यक्ति जीवन के समग्र विकास को समझने के लिए भारतीय जनता का साक्षर बनाना नितांत आवश्यक है। चूँकि शिक्षा मानव विकास का उपयोगी अंग है तदनु रूप ही अध्ययन भी मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। राष्ट्र की जनता का अध्ययन अध्यापन एवं स्वाध्याय के साधन उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना की जाती है। यह नया राष्ट्र का नागरिक भी 'साधजनिक पुस्तकालय' की स्थापना कर पूरा कर सकत है।

भारत ग्रामीण देश है। इसकी भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से 70% प्रतिशत भारतीय ग्रामों में वास करते हैं तथा कृषि, उद्योग एवं पशुपालन से अपनी जीविका चलाते हैं। प्रारम्भ से ही इन गाँवों में शिक्षा काफी देर से पहुँची। पञ्चवर्षीय योजनाओं में समाज शिक्षा का विस्तार सम्पूर्ण भारत में हुआ साथ ही देश भर में प्रमुख जिला राज्य एवं केन्द्रीय पुस्तकालय खोले गये।

ग्रामों में भी पचासतों के भवनों में पुस्तकालय एवं वाचनालय चल रहे हैं। फिर भी ग्रामों में वह स्वस्थ अध्ययनशील वातावरण नहीं बन पाया है जिससे यह अपेक्षा की जा सके कि, इन ग्रामीण-पुस्तकालयों को केन्द्रीय, राज्य एवं जिला पुस्तकालय इकाईयाँ से जोड़ा जा सके।

आज वैज्ञानिक अनुसंधान, आविष्कार एवं नवीन शोध के युग में कृषि प्रधान भारत का कृषि कार्य भी बेहतर उन्नति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। कृषि में वैज्ञानिक तकनीक के समावेश से कृषकों के समक्ष यह समस्या आ गई है जिसे वे अल्प साक्षर या निरक्षर हो सकने के कारण समझ नहीं पाते हैं। इनके अभाव में उन्हें कृषि अधिकारियों का उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है ऐसी स्थिति में यदि साक्षर कृषक स्थानीय पुस्तकालय में उपलब्ध साहित्य का पट्टर कोई हल निकाल सकता है तो उसकी समस्या का निराकरण पूरा हो की ओर अग्रसर हो जाता है।

भारतीय कृषक जीवन के लिए अन्धे बीज, खान, उर्वरक, सयन एवं उद्योग सम्बन्धी जानकारी का उचित साहित्य ग्रामीण-पुस्तकालय में उपलब्ध हो जाता है

तो विज्ञान की बहुत बड़ी समस्या का हल निकल आता है। बनानिक ग्रामीण श्रीयोगीश्वर एव समग्र ग्रामीण विकास की बात यदि हम चरितार्थ करनी है तो सवप्रथम हम प्रत्येक ग्राम पंचायत एव विकास-खण्ड में अच्छे कृषि एव ग्रामीण साहित्य से युक्त सुन्दर ग्राम-पुस्तकालय भवन की आवश्यकता होगी।

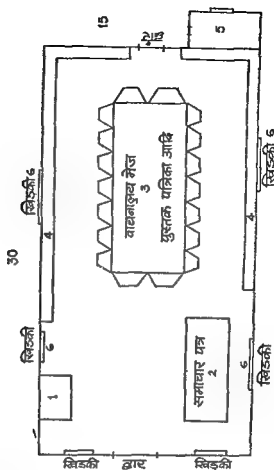
आज ग्रामीण पुस्तकालय भवन या तो पंचायत भवन के कमरे में है या फिर बड़े बड़े सन्दूक। यह स्थिति वर्तमान युग के विवर्धित ग्रामों जसी नहा हा सकती। इसमें हम परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार हमने सड़करी बैंक खोलने एव चलाने में शिक्षण मर्यादा को बढ़ाने में, सबके एव गृह निर्माण के कार्यों में रुचि लेकर ग्रामों की कार्यों को धिजली सिंचाई स्वास्थ्य पशुपालन एव कुटीर उद्योगों द्वारा बदलना है, उसी प्रकार ग्रामीण विचारधारा को बौद्धिक स्तर प्रदान करने के लिए हम एक अच्छे पुस्तकालय भवन के निर्माण में रुचि लेना है ताकि हमारा मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक एव आर्थिक सभी प्रकार से विकास हो।

ग्रामीण-पुस्तकालय भवन की रूपरेखा—यह हम भलीभांति जानते हैं कि ग्रामों में जहाँ भी पुस्तकालय अथवा वाचनालय हैं वे सभी या तो पंचायत भवनों में स्थित हैं अथवा किसी गाँव प्रमुख के घर में। दूसरी ओर यह बात भी हम जान लेना चाहिए कि भारत में ग्राम-पंचायतों की स्थिति राजनीतिक प्रभावों के कारण बदलती जा रही है। दलगत भावना के कारण ग्राम विकास रुके पड़े हैं, जहाँ हो रहे हैं वहाँ सत्ताखण्ड पाटों की सहायता का कारण है। ऐसा न करके सभी ग्रामीणों को मिलकर एक-एक प्रसिद्ध स्थल को पुस्तकालय भवन हेतु चुन लेना चाहिये वह या तो एक स्थान हो, बाजार नगरी हो स्कूल पास में हो या फिर जहाँ लोग अधिक उठन बैठते हैं ऐसे स्थान पर पुस्तकालय स्थापित किया जा सकता है।

पुस्तकालय-भवन निर्माण पंचायत की आर्थिक सुदृढता अथवा ग्राम की सम्पन्नता पर भी निर्भर रहता है। जहाँ पंचायतों को आर्थिक मदद अच्छी मिलती है एव जिनकी ग्राम के श्रेष्ठ अधिक अच्छे हैं वे पुस्तकालय भवन उपरान्तनुसार किसी भी स्थान पर बनवा सकते हैं। शासकीय स्तर पर भी शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु इन लोक पुस्तकालयों का आर्थिक मदद देना चाहिए।

जहाँ पंचायत भवन बने हैं उनमें स्थान की सुविधानुसार पुस्तकालय स्थापित किये जा सकते हैं। जहाँ ग्राम पंचायतों के भवन नहीं हैं वहाँ हम निम्नानुसार पुस्तकालय भवन का निर्माण कर सकते हैं।

1. लेन-देन विभाग
2. समाचार पत्र स्टण्ड अथवा मज
3. वाचनालय मज (कृतियों सहित)
4. अलमारियाँ के लिए स्थान (दीवार के सहारे)



5 प्रसाधन (पशाव घर)

6 खिड़किया—जालीदार

पचायत भवन युक्त पुस्तकालय—भारत में कुल 5½ लाख ग्राम हैं और इनमें लगभग 5 लाख ग्राम पचायतों अपना अस्तित्व में हैं। 1954 के 'डिलिवरी ऑफ बुक्स एक्ट' के अंतर्गत सम्पूर्ण भारत में लोक पुस्तकालयों का जाल बिछाया जाना निश्चित हुआ और देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की तीन प्रतियाँ राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, सेट्रल पब्लिक लायब्ररी बम्बई एवं वानमारा सावननिक पुस्तकालय भद्राम को भेजा जाना निश्चित हुआ था जिसके माध्यम से ग्राम पुस्तकालयों में भी उन पुस्तकों को अन्तः पुस्तकालयीन आदान प्रदान के तहत मंगा सके। यह सच वर्तमान में नहीं हो रहा है और न ही निकट वर्षों में सम्भव है अतः हमें हमारे पचायत भवनों के एक कमरे में ही पुस्तकालय की स्थापना कर दनी चाहिये और किसी शिक्षित बराजगार युवक को उसके संचालन हेतु नियुक्त

कर देना चाहिये। यदि शासन भवन-निर्माण के प्रति उत्सुक नहीं है तो भी यह कार्य हमें अविलम्ब करना चाहिये।

एल डी बगरी का ग्रामीण पुस्तकालय भवना के बारे में विचार पढ़ें। 'ग्रामों में पुस्तकालयों के लिए खास अच्छी आधुनिक ढंग की इमारतों की आवश्यकता नहीं है। किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वार में मुफ्त या किराये के कमरे काफी हैं। ऐसी जगहों में विविध प्रकार की पुस्तकें रखकर ग्रामों को आकर्षक बना सकते हैं।'¹

आज जब राष्ट्र का प्रत्येक ग्राम आधुनिकता की चपट में है, विद्यालय भवन पोस्ट ऑफिस, बैंक, अस्पताल एवं पंचायतों के सुंदर सुंदर भवन भवन गांवों में निर्मित हो रहे हैं तब ग्राम पुस्तकालयों के लिए भी अच्छे भवनों का निर्माण किया जाना अनुकूल होगा। जब भी नवीन पंचायतों के भवन बनें तो भविष्य की ग्रामालय सुविधाओं का दखते हुए पंचायत भवन का निमाण करना चाहिए। वृहत्तर यह होगा कि भवन की दीवारों में ही आलमारियों का निमाण किया जाय ताकि ये आलमारियां ही गंध रखने के काम आ सकें।

यह व्यवस्था संभव न हो सके तो लकड़ी की आलमारियां से काम चलाया जा सकता है। जैसे बहुत पहले जब 1956 में पंचायतों का अंतर्गत ग्रामालय प्रारम्भ किए गये थे तब लोहे की बड़ी बड़ी पेटियां, जिनमें लगभग 100 पुस्तकें रखी जा सकती थीं, पंचायतों को पंचायत एवं समाज कल्याण विभागों द्वारा प्रदान की गई थी। अब इस प्रकार की व्यवस्था भी समाप्त प्रायः हो चुकी है। फिर भी ग्रामीण विकास की परम्पराओं में हमें ग्रामालय निर्माण की बात को भुलाना नहीं है।

देश, नवनिर्माण के सवर्णा को लेकर विकास के प्रत्येक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, तब हमें अपनी सतत शिक्षा की निरंतर बढ़ती भूख के लिए ग्रामालयों के निर्माण को नहीं भूलना चाहिए। पंचायत-भवनों में व्यवस्था चाहे न हो तब भी कुछ ऐसी व्यवस्था ग्रामवासियों को मिलजुल कर करनी चाहिए कि वे सभी अपने खाली समय में किसी एक स्थान पर अध्ययन, गोष्ठी, वाता, चर्चा अथवा कथा कहानी सुनने के लिए बैठें। यह कार्य ग्राम के युवक-मण्डलों व महिला मण्डलों को समुक्त रूप से मिलकर करना चाहिए।

गांवों के ग्रामालयों में बैठने के लिए बहुत अधिक फर्नीचर की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रामालय की मेज एवं कुर्सी, ग्रामों के निगमन हस्त लिखने-पढ़ने के कार्य में उपयोगी रहे बहुत हैं। पाठकों को जिनमें बच्चे, महिलाएं युवा व वृद्ध शामिल हैं, इनके बैठने की व्यवस्था, क्या भी ही दरिया बिछाकर की जा सकती है। आजकल पंचायतों के पास भी टक्स वसूली से आदिक साधन बढ़ते जा रहे हैं अतः इन खाता से प्राप्त राशि का कुछ प्रतिशत ग्रामालय फर्नीचर के लिये खर्च किया जा सकता है।

पढ़ना चूँकि एक बौद्धिक प्रक्रिया है अतः इस रोकना मस्तिष्क के लिए घातक भी हो सकता है। अतः प्रयास यह होना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम ग्रन्थालय भवनो से युक्त हो। इन पुस्तकालय भवनो के निर्माण एवं उपकरणों के अर्थ हेतु, विकास खण्ड, अधिकारी तथा ग्राम अधिकारी अथवा जिन अध्यापकों को भी आर्थिक सहयोग करना चाहिए। यदि प्रदश ग्राम ग्रन्थालय विधान की व्यवस्था हो तो ग्रन्थालय संचालनालय अथवा ग्रन्थालय-परामर्श मण्डल की मदद से ग्रन्थालय-समस्या सम्बन्धी सार काय सम्पन्न किया जा सकता है। भारत सरकार के शिक्षा एवं युवा सेवायें मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ग्रन्थालय परामर्श समिति के प्रतिवेदन¹ में "सावजनिक ग्रन्थालय के संगठन सम्बन्धी विस्तृत अनुशसार्थ पड़ने का मिल सकती है। समिति की अनुशसार्थों पर दशक बहुतेरे राज्यों ने आज तक कोई गौर नहीं किया है। इसका कारण भी ग्रन्थालय विधान का पारित न होना बताया जाता है। सत्यता कहा गायब हो गई है अनुमान लगाना कठिन है।

वास्तव में इसके ग्रन्थालय-विकास का कार्य गैर सरकारी संगठन समाज सेवा संस्थायें एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा छुट्टी-छुट्टी रूप में सारे देश में चल रहा है। जहाँ तक ग्राम पुस्तकालयों अथवा सावजनिक ग्रन्थालयों के संचालन का प्रश्न है, श्री विश्वनाथन महोदय का सुझाव है कि "जन-पुस्तकालय का प्रबंध स्थानीय प्रशासन द्वारा पूर्णतः व अधिकारित अपने ही व्यय से हो, उसका शासन व संगठन प्राधिकारी एवं समिति द्वारा हो और उसकी सेवा अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों का बिना रंग, जाति व अन्य किसी भेद-भाव के निःशुल्क प्राप्त हो।"²

संदर्भ —

- 1 बगरी (एन डी) पुस्तकालय पद्धति, इलाहाबाद, नीलम प्रकाशन 1973 पृ 56
- 2 भारत, ग्रन्थालय (सलाहकार समिति) प्रतिवेदन, 1959
- 3 विश्वनाथन (सी जी) सावजनिक पुस्तकालय संगठन की रूपरेखा 1965, पृ 1

पुस्तकालय प्रसार सेवा में पुस्तकालयाध्यक्ष का योगदान

पुस्तकालय प्रसार काय व सहायक तत्त्वों में पुस्तकालयाध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। डा थोनाथ सहाय का कहना है कि "हम लोग सामाजिक काय करता बनने की अपेक्षा शिक्षा शास्त्री बनने का कठिन प्रयास करते रहे हैं।" सम्भवतः पुस्तकालयाध्यक्ष का, शिक्षक भूमिका से हटकर सामाजिक भूमिका की ओर ध्यान देने में उन्हें समाज में अपना पद और प्रतिष्ठा खो बैठने का डर है? व्यापक संदर्भ में यह अर्थ देशों की अपेक्षाकृत जो बहुत आगे बढ़ गये हैं, आधुनिक भारत में पुस्तकालय सेवा की धीमी प्रगति और "गुनलोकप्रियता का अक्षमाली कारण है।" इस कारण को समाप्त करने तथा देश की जनता को प्रजातन्त्रीय विकास की ओर अग्रसर करने में "पुस्तकालयाध्यक्ष का एक समाज वैज्ञानिक और सृष्टि वैज्ञानिक बनना चाहिए।"

पुस्तकालयाध्यक्ष को किन्हीं पुस्तकालय प्रसार संगठन का काय करता है इस निमित्त समाज एवं समुदाय के लिए उसकी स्थिति नियामक जैसी हो जाती है। आज चाहे सम्पूर्ण भारत के गांव पुस्तकालय से सुसज्जित व सुनवद्व नहीं है। फिर भी पुस्तकालयाध्यक्ष के सहयोग एवं सहभाव से गांव गांव पुस्तकालय खोले जा सकते हैं और उनके माध्यम से शिक्षा विकास में सहायता पहुँचाई जा सकती है। वैसे तो बहुत से माध्यम पुस्तकालय प्रसार हेतु अपनाये जाते हैं लेकिन उन्मत्त उतनी मर्यादा हाथ नहीं लगती है जितनी पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा प्रयुक्त होने में प्राप्त होती है। ग्रामों में गोष्ठियाँ स्थापित कर बालक जवान व बुढ़ा का एकत्रित कर पढ़ने पढ़ाने से जहाँ पुस्तकालयाध्यक्ष प्रौढ शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं वही बच्चा की जिज्ञासु प्रवृत्ति का लाभ उठाकर उनमें शिक्षा का प्रसार भी कर सकते हैं।¹²

पुस्तकालय प्रसार शैक्षणिक विकास की मौलिक आवश्यकता है जिस पुस्तकालयाध्यक्ष को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्रीय हित को सामने रखकर करना चाहिए। वह केवल ग्रंथालय में आने वाले पाठकों का ही समुचित ग्रंथालय सेवा प्रदान करके सन्तुष्ट नहीं होता। अपितु वह तो अपने क्षेत्र के प्रत्येक स्त्री पुरुष, युवा-बुढ़ा को ग्रंथालय का सक्रीय सदस्य बनाने के लिए कृत मत्स्य है।¹³ ऐसे सकली व्यक्ति द्वारा ही पुस्तकालय प्रसार सेवा का

पढ़ना चू कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है अतः इसे रोकना मस्तिष्क के लिए घातक भी हो सकता है । अतः प्रयास यह होना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम ग्रन्थालय-भवना से युक्त हो । इन पुस्तकालय भवनो के निर्माण एवं उपकरणों के क्रय हेतु, विकास खण्ड, अधिकारी तथा ग्राम अधिकारी अथवा जिनाध्यक्ष महोदयों को भी आर्थिक सहयोग करना चाहिए । यन्त्रि प्रदेश में ग्रन्थालय विधान की व्यवस्था हो ता ग्रन्थालय सचालनालय अथवा ग्रन्थालय परामर्श मण्डल की मदद से ग्रन्थालय-समस्या सम्बन्धी सारे कार्य सम्पन्न किए जा सकें हैं । भारत सरकार के शिक्षा एवं युवा सवायें मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित ग्रन्थालय परामर्श समिति के प्रतिवेदन¹ में "सावजनिक ग्रन्थालय के संगठन सम्बन्धी विस्तृत अनुशसयें पत्रों को मिल सकती है । समिति की अनुशसामा पर देश के बहुतेरे राज्यों ने आज तक कोई गौर नहीं किया है । इसका कारण भी ग्रन्थालय विधान का पारित न होना बताया जाता है । सत्यता कहा गायब हा गई है अनुमान लगाना कठिन है ।

वावजूद इसके ग्रन्थालय-विकास का कार्य गर सरकारी संगठन समाज सेवा सवयों एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा छुट पुट रूप में सारे देश में चल रहा है । जहा तक ग्राम पुस्तकालय अथवा सावजनिक ग्रन्थालयों के सचालन का प्रश्न है, श्री विश्वनाथन महोदय का सुझाव है कि "जन पुस्तकालय का प्रबंध स्थानीय प्रशासन द्वारा पूरात व अधिकारत अपन ही व्यय स हो, उसका शासन व संगठन प्राधिकारी एवं समिति द्वारा हो और उसकी सेवा अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों को बिना रग, जाति व अन्य किसी भेद-भाव के नि शुल्क प्राप्त हो ।"³

सन्दर्भ —

- 1 वगरी (एन डी) पुस्तकालय पद्धति, इलाहाबाद, नीलम प्रकाशन 1973, पृ 56
- 2 भारत, ग्रन्थालय (सलाहकार समिति) प्रतिवेदन, 1959
- 3 विश्वनाथन (सी जी) सावजनिक पुस्तकालय संगठन की रूपरेखा 1965, पृ 1

पुस्तकालय प्रसार सेवा में पुस्तकालयाध्यक्ष का योगदान

पुस्तकालय प्रसार काय के सहायक तत्त्वों में पुस्तकालयाध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। डा श्रीनाथ सहाय का कहना है कि “हम लोग सामाजिक काय कर्ता बनने की अपेक्षा शिक्षा शास्त्री बनने का कठिन प्रयास करते रहे हैं।” सम्भवतः पुस्तकालयाध्यक्ष का, शैक्षिक भूमिका से हटकर सामाजिक भूमिका की ओर ध्यान देने में उन्हें समाज में अपना पद और प्रतिष्ठा खो बैठने का डर है? व्यापक संदर्भ में यह अर्थ देश की अपेक्षाकृत जो बहुत आगे बढ़ गये हैं, आधुनिक भारत में पुस्तकालय सेवा की धीमी प्रगति और जनलोकप्रियता का शक्तिशाली कारण है।¹ इस कारण का समाप्त करने तथा देश की जनता को प्रजातन्त्रीय विकास की ओर अग्रसर करने में “पुस्तकालयाध्यक्ष का एक समाज वैज्ञानिक और संस्कृति वैज्ञानिक बनना चाहिए।”

पुस्तकालयाध्यक्ष चूँकि स्वयं पुस्तकालय प्रसार संगठन का काय करता है इस निमित्त समाज एवं मनुष्य के लिए उसकी स्थिति नियामक जैसी हो जाती है। आज चाहे सम्पूर्ण भारत के गांव पुस्तकालयों से सुसज्जित व सूत्रबद्ध नहीं है। फिर भी पुस्तकालयाध्यक्ष के सहयोग एवं सहभाव से गाँव गाँव पुस्तकालय खोले जा सकते हैं और उनके माध्यम से शिक्षा विकास में सहायता पहुँचाई जा सकती है। वैसे तो बहुत से माध्यम पुस्तकालय प्रसार हेतु अपनाय जाते हैं लेकिन उनमें उतनी सफलता हाथ नहीं लगती है जितनी पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा प्रयुक्त होने में प्राप्त होती है। ‘ग्रामों में गीठिया स्थापित कर बालक जवान व बूढ़ा को एकत्रित कर पढ़ने पढ़ाने से जहाँ पुस्तकालयाध्यक्ष प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं वही बच्चा की जिज्ञासु प्रवृत्ति का लाभ उठाकर उत्तम शिक्षा का प्रसार भी कर सकते हैं।’²

पुस्तकालय प्रसार शैक्षणिक विकास की मौलिक कायवाही है जिसे पुस्तकालयाध्यक्ष को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्रीय हित को सामने रखकर करना चाहिए। वह केवल ग्रंथालय में आने वाले पाठकों को ही समुचित ग्रंथालय सेवा प्रदान करके सन्तुष्ट नहीं होता। अपितु वह तो अपने क्षेत्र के प्रत्येक स्त्री पुरुष, युवा वृद्ध का ग्रंथालय का सजीव सदस्य बनाने के लिए कृतमत्क है।³ ऐसे सकलपी व्यक्तित्व द्वारा ही पुस्तकालय प्रसार सेवा का

काय सम्भव हो सकता है। इस प्रकार के विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिस पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति इस कार्य निमित्त से की जाती है, उसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित बुनियादी विशेषताएँ आवश्यक हैं।

- 1 कुशल प्रशासन
- 2 विषय विशेषज्ञ
- 3 समाज-सेवी दृष्टिकोण

पुस्तकालय प्रसार कार्य की सफलता में समाचार पत्र, विडियो टेलीविजन, रेडियो चलचित्र, व्याख्यान साथ ही जिनासु पाठक एवं जनता के कार्यक्षमता का अपना स्थान तो है ही, इन सभी में भी पुस्तकालयाध्यक्ष का अपना विशिष्ट स्थान एवं उपयोगिता होती है। वह एक विशेष योग्यता एवं गुणों से सम्पन्न व्यक्ति बनता है जो पुस्तकालय का योजनाबद्ध प्रसार-कार्य अपना कर लोगों में अध्ययन के प्रति रुचि जाग्रत कर सकता है। ऐसे विशिष्ट गुणों एवं योग्यताओं के आधार पर ही पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय प्रसार की सफलता पूर्वक आगे बढ़ा सकता है।

“पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशासन होने के साथ-साथ वैज्ञानिक भी कम नहीं होना है। वह प्रविधिज्ञ होता है साथ ही सिद्धांतवादी भी कम नहीं होता उस पुस्तक से प्रेम होता है साथ ही मानवता में भी उसकी रुचि रहती है।⁴ अतः वह सेवा कार्य वह भली भाँति कर सकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का देखते हुए समुदाय का जो रुख है, वह विरागी हो जाता है। अतः जन जीवन में शिक्षा के विकास की एक अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में पुस्तकालय प्रसार के द्वारा समाज में व्याप्त दूषित विचारधारा का बदला जा सकता है। पुस्तकालयाध्यक्ष समाज के सामने एक पथ प्रदर्शक है। दार्शनिक शिक्षक नायक एवं सहपाठी है वह अनेक रूप में हमारे सामने आता है। विभिन्न आचार विचार के पुरस्कर्तियों से साक्षात्कार करता है इस स्थिति में उस सभी को सात्वना देने पड़ती है यही उसकी सफलता का राज हो सकता है। इस कार्य कर्ता के बारे में साहित्य महर्षि महादेवी वर्मा का कहना है “मैं मानती हूँ कि किसी राष्ट्र के हीरो मोती और सोना इसका जो कोश है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं। उससे जो वह अध्यक्ष ब्रह्मा है। जो उसके चिन्तन विचार का अध्ययन होता है अर्थात् पुस्तकालय का अध्यक्ष होना है। जो पुस्तकालय का अध्यक्ष है वह वास्तव में हमारी के बीच में रहने वाला व्यक्ति है।”⁵ ऐसे व्यक्तित्व का निम्नलिखित गुणों से युक्त होना आवश्यक है।

- 1 विषय का पूर्ण व यथायथ ज्ञान। 2 ज्ञानाजन की उत्कण्ठ इच्छा। 3 स्पष्टता। 4 विवेकी। 5 कार्यकुशल। 6 साधन सम्पन्नता। 7 दूर दक्षिता। 8 सहोदर पूर्ण व्यक्तित्व। 9 सेवा की भावना।

इसने अतिरिक्त पुस्तकालय प्रसार सेवा व आवश्यक गुणों को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं।

अ व्यक्तित्व-सम्बन्धी गुण

ब स्वभाव-सम्बन्धी गुण

स व्यवहार-सम्बन्धी गुण

द तननीय गुण

अ व्यक्तित्व-सम्बन्धी गुण—

1 आकषक व्यक्तित्व—पुस्तकालय के प्रसार हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि सटज ही में नागा का खिचाव उनकी ओर हो जाय। उमम नम्रता, सरलता, हसमुख एवं विनीत जैसे गुणों का समावेश होना आवश्यक है। इन विशेषताओं से कभीभूत हा पाठक निश्चयच पुस्तकालय में आया और प्रसन्नता का अनुभव करता।

"The good librarian should therefore be something of a psychologist able quickly to assess readers' individual responsibilities and requirements and possessing all the necessary tact and bibliographical knowledge to deal with each user according to his or her special needs."

2 पुस्तकालय प्रसार सेवा में आस्था—जिस कार्य को करने का बीड़ा निररता है एवं लोग में प्रतिष्ठा बढ़ती है। विश्वास ऐसा सम्पन्न है जिसका आधार पर जगत् की सत असत् सत्तियाँ तुलती हैं। जब विश्वास में आकर छात्र जगत, समुदाय के स्त्री-पुरुष सभी पुस्तकालय में जाकर पढ़ेंगे तो पुस्तकालय प्रसार को बल मिलेगा। जनता के विश्वास प्राप्त होने के साथ ही साथ पुस्तकालयाध्यक्ष को अपने पुस्तकालय प्रसार सेवा में प्रतिपूण निष्ठावान होना चाहिए तभी जनता इन कार्यक्रम के प्रति सजग होगी।

3 कार्य में उत्साह—मनुष्य में उत्साह का होना महत्वपूर्ण गुण है। पुस्तकालय प्रसार कार्य को सम्पन्न करने में पुस्तकालयाध्यक्ष में जाश उत्साह एवं लगन होना चाहिए, उत्साह के बिना जनता में चेतना एवं विश्वास नहीं लाया जा सकता है। अतः पुस्तकालयाध्यक्ष को अपने कार्य के प्रति सजग व उत्साही होना आवश्यक है। उत्साह सफलता का वह उम्मुक्त द्वार है जिसे अपनाकर प्रत्येक कार्य मलीभाति निपटारा जा सकते हैं। अधिक उत्साह भी कभी कभी जायिम बन जाता है। अतः पुस्तकालयाध्यक्ष को वही कार्य उत्साह से करना चाहिये जिसमें उसका अग्रिष्ट न हो।

4 साहस—पुस्तकालयों में भिन्न भिन्न प्रकार के पाठक आते हैं पुस्तकालय की स्थापना एवं उसका चलान में कई विषय कठिनाइयाँ सामने आती हैं, इन

परिस्थितियों से मुकाबला करने का साहस पुस्तकालयाध्यक्ष में होना चाहिए। साहस काय की सफलता का श्रेष्ठ गुण है। पग पग पर आने वाली बठिनाइयाँ, विरोध एवं असफलताओं के लिए पूर्ण से ही पुस्तकालयाध्यक्ष का सतक होना चाहिए। साहस का न होना अपने प्रसार काय से असफलता पाना होगा।

जनता के मागदर्शन के लिए साहसी व्यक्तित्व ही ठीक सकते हैं।

5 स्वस्थ सुगठित शरीर - पुस्तकालय ज्ञान का भण्डार हाता है। ज्ञान में मानसिक शक्ति प्रबल होती है। पुस्तकालयाध्यक्ष बुद्धि बल से पूर्ण है और उसमें शारीरिक दुबलता है तो वह प्रसार काय में कम सफलता प्राप्त करेगा। पुस्तकालयों में आने वाले कई प्रकार के पाठकों से पुस्तकालयाध्यक्ष को साक्षात्कार करना पड़ता है ऐसे समय जनता की प्रभावित करने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष को मानसिक के साथ-साथ शारीरिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। दुबल व क्षीण काय लोगों से पुस्तकालय प्रसार समाज के गलत तत्त्वा के रहते नहीं हो सकता अतः पुस्तकालयाध्यक्ष को शारीरिक दृष्टि से हट्ट पुष्ट होना चाहिए ताकि पाठक गलत तरीका का अपनाकर पुस्तकों से ज्ञान का दुसाहस न करे।

ब स्वाभाविक गुण—

बुद्धि एवं गुण शरीर में विद्यमान होते हैं, जो जन्म जात सभी स्त्री पुरुष में होते हैं। प्रकृति के नियमों के पालनाथ ये गुण मानव को प्रेरणा देते हैं। समाज में रहने, परिवार में खाने पीने, उठने बैठने का ढंग सिखाते हैं। इनमें से प्रमुख गुण निम्नलिखित इस प्रकार हैं।

1 सहनशीलता— पुस्तकालय प्रसार काय के माध्यम से समाज में व्याप्त निरक्षरता एवं अज्ञानता को दूर करने के साथ-साथ उसके आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को भी बदलता है। ग्रामीण जनता अपने आचरण रीति-रिवाज धार्मिक आस्था से लब्ध होती है, ये निडर तो होते ही हैं साथ ही धर्म भीरु भी होते हैं, ऐसे समय स्थिति वश ये पुस्तकालय प्रसार काय में बाधक बन सकते हैं। अतः पुस्तकालयाध्यक्ष को जनता की खरी खोटी, बेतुकी बातें सुनकर सहनशीलता के साथ उनका निवारण करना चाहिए ताकि उनका भ्रम दूर हो, अध्ययन के प्रति रुझान पैदा हो विरोध में उत्पन्न परिस्थितियों से पुस्तकालयाध्यक्ष को विचलित नहीं होना चाहिए। वेदना नहीं होना चाहिए। सकट से उत्पन्न क्रोध को शकल सा विषधारी बनकर हजम कर लेना चाहिए। सहनशीलता उसके स्वाभाविक गुणों का महत्वपूर्ण अंग है।

2 ईमानदारी—पुस्तकालय प्रसार के काय को पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा ईमानदारी से किया जाना चाहिए। जनता के मध्य नीति निर्धारण एवं व्यवहारिकता में सदैव सत्यता एवं ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। पुस्तकालय की स्थापना से लेकर उसके काय रूप में परिणित होने तक जनता का सहयोग पाने के लिए सदैव ईमानदारी का व्यवहार हो, कोई तथ्य अधर में न

रखे जाये। जनता पुस्तकालय का लाभो से वंचित न हो उमरे उपयोग क तरीका को जुलो पुस्तक के सदृश्य पुस्तकालयाध्यक्ष को रखना चाहिए तभी जनता का विश्वास कायकर्ता के प्रति होगा और पुस्तकालय प्रसार काय म कभी बाधा उत्पन्न नही होगी।

3 मित्रवत् व्यवहार—पुस्तकालय प्रसार की आवश्यकता को डमलिये प्राथमिकता देना है कि देश म व्याप्त अशिक्षा दूर हो, ग्रामीण जनता के मस्तिष्क मे बैठा भीरुपन दूर हो, आपसी वैमनस्यता एवं ईर्ष्या का अन्त हो। अध्ययन मे रुचि जागृत करने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष का व्यवहार सदभाव एवं समभाव पूर्ण होना चाहिए। पुस्तक लेन एवं वापस करने वाले सभी पाठको से समानता का वर्ताव हो, उनसे मित्रतापूर्ण बातें की एवं समझाई जावे पक्षपात न हो। पुस्तकालय का उपयोग सभी स्तर के, उम्र के स्त्री पुरुषो बच्चो के लिए समान रूप से किया जाना चाहिए तभी पुस्तकालय प्रसार सेवा का काय सफल हो सकता है। मित्रवत् व्यवहार पुस्तकालय प्रसार सेवा को सफलतम कुंजी है जिसे जनता एवं अधिकारियो सभी को समभाव म अपनाना चाहिए।

4 काय के प्रति दृढ सकल्प—सामान्यत यह दखा गया है कि ग्रामीण जनता अध्ययन के प्रति रुचि नही लेती है। इसके पीछे मनावनानिक कारण काय करते है। या तो पुस्तकालयाध्यक्ष अपने काय मे शिथिलता रात है, या अपने जिज्ञासु पाठका पर ध्यान नही देत। सिर्फ नौकरी करना ही उसका ध्येय नही होना चाहिए। वर्तमान भारत के निमाण मे पुस्तकालयाध्यक्ष का महत्वपूर्ण योगदान है उसे चाहिए कि पुस्तकालय प्रसार क काय को दृढ सकल्प होकर करें। यदि वह अपने काय क प्रति दृढ सकल्प नही है तो वह पुस्तकालय प्रसार क काय को जनता तक नही पहुंचा सकता है। पुस्तकालयाध्यक्ष का अटूट दृढ मकल्प ही पुस्तकालय सेवाओ के विकास की रूपरेखा है राष्ट्र मे व्याप्त निरक्षरता का निराकरण है।

5 निःस्वाथ सेवा भावना—आज सरकार पुस्तकालय प्रसार एवं प्रचार पर इसलिए जोर दे रही है कि जनता मे व्याप्त सकुल धारणाओ का अन्त हो, निरक्षरता समाप्त हो, कृषि उद्योग एवं व्यापार मे देश प्रगति करने ज्ञान विज्ञान म हो रहे नये आविष्कारो की सूचना प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, अर्थात् मानव-विकास के लिए पुस्तकालय एवं अनिवार्य विद्या है, जिसके सत्सय से आदमी-आदमी बनता है। स्वस्थ परम्परा का निर्वाह होता है जीवन स्तर म विस्तार के प्रयास का आधार वैदिक विकास ही होता है।

जहा भी पुस्तकालय अधिकारी है उह जाति-पाती ऊच-नीच तथा सामाजिक अनैतिक विचारा को त्यागकर स्वस्थ निःस्वाथ सेवा भावना मे जनता क हित म व्यवहार करना चाहिए। वे भी हरीसन के मतानुसार 'एक अच्छे अध्यक्ष को चाहिए कि वह नितान्त आवश्यक है कि वह एक उत्तम पत्रकार की भांति हर चीज

की कम से कम अशत जानकारी रखे और किसी भी अशत घटित घटना को पूरी पूरी जानकारी रखे ।

पुस्तकान्वय प्रसार काय का अभीष्ट लक्ष्य समाज कल्याण तथा समाज का पुनरोत्थान ही होना चाहिए, इसे निस्वाथ सेवा भावना से किया जाना चाहिए । पुस्तक के क्रय करन, बेचने सम्बन्धी कार्यों से आर्थिक लाभ की विचारधारा का त्याग कर तन मन धन से इसके प्रसार में सहयोग देना चाहिए तभी पुस्तकालयाध्यक्ष अपने गुणों से पुस्तकालय प्रसार के लक्ष्य का पूर्ण करने में सफल हो सकेगा ।

॥ दूरदर्शिता—दूरदर्शिता पुस्तकालयाध्यक्ष का आवश्यक गुण होना चाहिए । पुस्तकालय प्रसार काय का भूत-भविष्य में किस दशा में कितना किस और विकसित किया जा सकता है, इसकी जानकारी पुस्तकालयाध्यक्ष को होनी चाहिए । पुस्तकालया में आने वाले पाठकों के हिसाब से समुचित अध्ययन सामग्री जुटाना, एवं अध्ययन सामग्री की अधिकता पर उनके रखरखाव व संरक्षण की व्यवस्था करना पुस्तकालयाध्यक्ष का काय है । पुस्तकालयाध्यक्ष को इतना विवेकी होना चाहिए कि वह पुस्तकालय भवन निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखें कि भ्रगत 15-20 वर्ष में ग्रन्थों का संग्रह अधिक हो जाये तो भी उनकी व्यवस्था भवन में कर सके । यदि उसने इस बात को भदे नजर रखत हुय किसी पुस्तकालय भवन का निर्माण करवाया है तो निश्चित ही वह दूरदर्शिता का परिणाम है ।

(स) व्यावहारिक गुण—समाज में मानव के दैनिक व्यवहार का असर उनकी अच्छाई एवं बुराई का परिचय देता है । व्यवहारिक गुणों के आधार पर ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज व समुदाय में होती है । इही गुणों में से कुछ प्रमुख गुण पुस्तकालयाध्यक्ष में होने चाहिए जो निम्नांकित हैं ।

1 लोक व्यवहार में कुशल—ग्रामीण भारत की निधन जनता में कूट-कूट कर भरे हुय अंध विश्वास रुढ़िवाद प्रथा एवं अनानसता को दूर करना उतना आसान नहीं है जितना एक सुशिक्षित व्यक्ति का समझना । यहाँ की जनता के बीच पुस्तकालय प्रसार के काय का सफल बनाना एक जटिलतम काय है । पुस्तकालयाध्यक्ष को विपम से विपम परिस्थितियाँ से विरोधी बातावरण से एवं गांव की दूषित राजनीति से निवटना एवं दूर रहना है तो उसे अपने व्यवहार में नम्रता, अनुशासनशीलता एवं मृदुता लाना होगा । पुस्तकालया के माध्यम से उसे लोक कल्याण के काय करना है ता चाहिये कि अपने सद्व्यवहार से जनता के दिलों को जीते उनमें अटल विश्वास जगायें एवं सभी का ध्यान अध्ययन की ओर आकृष्ट करे । यही बातें पुस्तकालय प्रसार सना को बढावा देने में पुस्तकालयाध्यक्ष को ध्यान रखनी चाहिए यह उसका चरित्र व गुणा में से एक गुण हो जाय तो समझा की जनता का दिल उसने जीत लिया वह अपने गुणा से कतय के प्रति सतक व सजग होगा तभी पुस्तकालय प्रसार सवा का काय पूर्ण होने की सम्भावना होगा ।

शहरी, वृद्धिमत्ता एवं आधुनिकता में मुखानुभूति करती है ऐसी स्थिति में दोनों स्थानों पर प्रचलित परम्पराओं सस्कारों का निवाह पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा किया जाना चाहिये ताकि उन सस्कारों से अभ्यस्त हो जाये और जनता उसे अपना सके।

ग्राम की जनता यदि गीता, रामायण, महाभारत की प्रेमी है तो पुस्तकालयों के कार्यक्रमों में इन्हें स्थान मिले, ग्रन्थों रामायण पाठ हो, धार्मिक व्याख्यान हो तो लोगों की इस प्रकार के कार्य के प्रति झूठ थड़ा हागी और वे पढ़ने के अभ्यस्त होने के लिये पुस्तकालय के द्वार खटखटायेगे।

(ब) व्यवसाय सम्बन्धी तकनीकी गुण—पुस्तकालय व्यवसाय हमारे देश के लिये एक नया विषय है इस विषय के विस्तार हेतु देश के 50 विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं—
 (1) दिल्ली विश्वविद्यालय (2) मद्रास विश्वविद्यालय (3) नागपुर विश्वविद्यालय (4) चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय (5) पंजाब विश्वविद्यालय (6) सागर विश्वविद्यालय (7) बम्बई विश्वविद्यालय (8) नागपुर विश्वविद्यालय (9) विश्व विश्वविद्यालय (10) ग्वालियर विश्वविद्यालय (11) जबलपुर विश्वविद्यालय (12) अलीगढ़ विश्वविद्यालय आदि। पहले इन प्रशिक्षण संस्थाओं का मुख्य ध्येय पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षित कर समाज सेवा संस्थाओं व सावजनिक पुस्तकालयों में प्रौढ शिक्षा कार्य प्रमोद करना हेतु भेजा जाता था किन्तु कुछ समय बाद विज्ञान शिक्षा व सामाजिक अनुसंधान की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए शोध व अनुसंधान के क्षेत्र में भेजा जाने लगा और आज ये प्रलेखक व सूचना केन्द्रों के उत्तरदायित्व पूर्ण पदों को सफलता पूर्वक सुशासित कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें पुस्तकालय वर्गीकरण, सूचीकरण, व्यवहार व सिद्धान्त, सन्दर्भ व प्रलेखन सेवा प्रशासन के सिद्धान्त संगठन एवं ग्राम परक संस्थाओं का अध्ययन कराया जाता है। चूंकि यह विज्ञान एवं सूचना सेवाओं में जुड़ गया है अतः कम्प्यूटरीकरण सूचना पुनः प्राप्ति, साव-भौम विषयों का ज्ञान, पुनः उत्पादन सेवा अनुवाद कार्य जैसे तकनीकी विषयों की पढाई कराई जाती है। पुस्तकालय व सूचना विज्ञान में दिल्ली, जयपुर चण्डीगढ़, मद्रास, बंगलौर आदि स्थानों पर शोध व अनुसंधान का भी कार्य होता है।

इन प्रशिक्षण संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय प्रसार सेवा को सारे देश में पूर्ण विकसित करना व राष्ट्रीय विकास में सहयोग देना है। पुस्तकालय विज्ञान विषय में पूर्ण पारंगत होकर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पुस्तकालय प्रसार सेवा में आता है और अपने दायित्व को निभाता है।

आज पुस्तकालयाध्यक्षों का दायित्व पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है। दायित्व के दृष्टिकोण से उसमें निम्न गुणों का होना आवश्यक है नहीं वरन् अनिवार्य है।

- 1 विषय का पूर्ण ज्ञान ।
- 2 नये ज्ञानाजक की प्रबल इच्छा ।
- 3 शीघ्र निगम्य की क्षमता ।
- 4 किसी बात को समझने एवं व्यक्त करने की क्षमता ।
- 5 स्थानीय साधनों का उचित उपयोग ।

पुस्तकालयाध्यक्ष अपने विषय का ज्ञाता हो ताकि पुस्तकालय के संचालन एवं संगठन में कोई अपरोध उत्पन्न न हो । ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों में प्रवाशित पुस्तकालय को पढ़ने की उमे प्रबल इच्छा हो ताकि स्वयं पढ़कर दूसरों का मार्गदर्शन व सके "जा पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय से प्रेम नहीं करता वह पुस्तकालयों में प्रवेश करने का भी अधिकारी नहीं है ।" पुस्तकों के विषय में उसे पूर्ण जानकारी होना चाहिए और उसे यह भी जानना चाहिए कि कौन सी पुस्तक किसके लिए उपयोगी है ।¹⁷

किसी कार्य की तत्परता से करने या न करने की क्षमता उसमें होनी चाहिये नहीं तो पुस्तकालय में वायु बहुत पिछड़ जायेगा । पुस्तकालय की बात या व्यावहारिकता की बातों को समझने एवं पढ़कर मुक्तकर समझाने की मागध पुस्तकालयाध्यक्ष में होना चाहिये जिससे कि नव जिज्ञासुओं को कठिनाइयाँ का निराकरण किया जा सके पुस्तकालय प्रसार के लिये जितने भी स्थानीय साधन उपलब्ध होते हैं उनका यथोचित उपयोग करने की कला का समावेश पुस्तकालयाध्यक्ष में अवश्य होना चाहिये । "किसी पुस्तकालयाध्यक्ष को केवल पुस्तक पाठक नियोजन की कला का विशेषण मानना ही पर्याप्त नहीं होगा प्रत्युत उसे एक आदर्शवादी सेवक भी मानना पड़ेगा जो पुस्तकों का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के लिए अहर्निश श्रमक परिश्रम करना रहता है ।¹⁸

उपरोक्त सभी गुण पुस्तकालय प्रसार के लिए एक पुस्तकालयाध्यक्ष में होने चाहिये । इसके अलावा प्रशासन की दृष्टि से कुछ विशेष गुणों व तत्वों का होना पुस्तकालयाध्यक्ष के लिये अनिवार्य है जिनका उल्लेख पुस्तकालय जैसे सामुदायिक केन्द्र व विकास एवं प्रसार सेवाओं हेतु आवश्यक है । इन तत्वों के अभाव में जिन्हें प्रशासक के सिद्धान्त माना जाता है श्रमालय सेवा का काम जटिल हो सकता है । एल डी व्हाइट ने ठीक ही कहा है कि "प्रशासक की कला किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निश्चयन सहयोग तथा नियंत्रण है ।"

इस विभिन्न प्रसार सेवाओं में बहतर परिणाम लाने हेतु निम्न तत्त्वों पर विचार करना जरूरी है प्रशासन के सात तत्व ये हैं—

- 1 नियोजन
- 2 संगठन
- 3 कमचारियाँ की व्यवस्था
- 5 निर्देशन करना

- 4 सम रय करना
- 6 रिपोर्टिंग
- 7 बजट बनाना

1 **नियोजन (Planning)**—जिस प्रकार उद्योग, व्यापार व व्यवसाय के लिए किये जाने वाले कार्य बहुत नियोजन स्वरूप में तैयार की जाती हैं उसी प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष को भी विशेषतः इन ग्रंथालयों में जो लोक शिक्षण व सामुदायिक केंद्र हैं प्रशासन के इस पृथक सिद्धांत का अपनावर योजनाबद्ध प्रणाली से काम करना चाहिये। पुस्तकालय प्रसार सेवा ही अथवा पुस्तकालय व द्वारा सामाजिक सेवा ही क्या न हो प्रदान करने के पूर्व पाठकों की समस्या, उनकी रुचि व उनकी शिक्षा-सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन पुस्तकालयाध्यक्ष का करना चाहिए। प्रो० अग्रवाल का मत है कि "जन ग्रंथालय के क्षेत्र में योजना निमाण का अर्थ है ग्रंथालय सेवा प्रदान करने से पूर्व उस वस्ती (Locality) का पूर्ण अध्ययन अर्थात् जनते, नियासियों की भाषाओं, परम्पराओं, व्यवसाय व शैक्षणिक स्तर आदि का अध्ययन व आधारों पर ग्रंथालय सेवा प्रदान करने की योजना निर्मित की जाती है।" ¹⁰ यह नौ योजना का बाह्य पक्ष हुआ इसके साथ ही ग्रंथालय के आंतरिक पक्ष के प्रशासन में भी भवन निर्माण, ग्रंथ चयन वर्गीकरण व्यवस्थापन एवं वाचनालय का नियोजन भी प्रसार सेवा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है।

2 **संगठन (organization)**—योजना निर्मित के उपरान्त पुस्तकालय सेवाओं के संगठित स्वरूप का संचालन करना बाह्य स्वरूप के संगठन का देखें तो इसके अन्तर्गत, पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन, पुस्तकालय प्रसार कार्यक्रमों पर चलचित्र प्रदर्शन एवं पुस्तकालय सभों की बैठक, सेमिनार इत्यादि का संगठन करना आंतरिक संगठन की दृष्टि से पुस्तक पाप्ति विभाग, आदेश विभाग, तकनीकी विभाग, पुस्तक संग्रह का व्यवस्थापन तथा सामयिक विभाग के संगठन पर ध्यान देना श्रेष्ठ पुस्तकालय सुविधाओं का प्रतीक होगा। "पुस्तकालय के विभिन्न विभागों का पूर्ण रूप से विकास तभी संभव है जब हम उन्हें अपने उद्देश्यों के विषय में अवगत कराये और हम बात का भी ध्यान दिलायें कि ये अपने कार्यों का ठीक ढंग से कर रहे हैं।" ¹¹

3 **कर्मचारियों की व्यवस्था**—गिनो दिन पुस्तकालय सेवाओं के प्रति पाठकों वगैरह में प्रशासन में के प्रति असन्तोष बढ़ रहा है। उसका प्रमुख कारण है पुस्तकालयों में कर्मचारियों की व्यवस्था का न होना पाना। एक ओर शासन यह चाहता है कि समुचित पाठकों को कोई असुविधा न हो और दूसरी ओर कर्मचारियों की नियुक्ति भी नहीं कर पा रहा है तब ऐसी स्थिति में पुस्तकालय सेवाओं का आचित्य खतरे में लगता है, उज्ज्वल भविष्य व पुस्तकालय सेवाओं में उत्तम निष्ठा के लिए योग्य, परिश्रमी तथा समुचित मर्याद कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। ¹²

पुस्तकालयाध्यक्ष की आवश्यकतानुसंग व्यवसाय निपुण, पुस्तक प्रेमी एवं पाठकों के प्रति सवाभाव गुणों से युक्त व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अपने पुस्तकालय में व्यवस्था करना चाहिए तभी प्रसार सेवा की योजना का मूल रूप प्राप्त हो सकेगा ।

4 निर्देशन (Directing) — निर्देशन नेतृत्व का एक ऐसा गुण है जो काम करवाने की योग्यता व नियंत्रण लेने की क्षमता का संकेतक है । इस गुण के प्रयोगात्मक पक्ष पर निर्देश को हम यहाँ पुस्तकालय कार्य के भली भाँति सम्पन्न कराने में सामयिकता नहीं है, तो काम सुचारु रूप से नहीं हो सकता । पुस्तकालयाध्यक्ष यदि उचित निर्देश नहीं दे पाय तो कमचारियों में अच्छे काम के प्रतिफल की आकांक्षा कम रहती है अतः प्रचालकों में यह योग्यता भी हो कि किसी विभाग का कार्य किसी कमचारी से नहीं हो रहा है तो वह उचित मित्रवत मार्ग दर्शन दें समझाव और अपने अधीनस्थ कमचारियों में अपनी व्यावहारिकता का आदेश प्रस्तुत कर सकें । कमचारियों में अपने प्रशासक के प्रति पूर्ण निष्ठा सद्भाव व सहयोग की भावना का होना ही इस बात का संकेतक कि प्रशासक की कार्यप्रणाली से सभी प्रसन्न हैं । यही एक प्रशासक के निर्देशन की निर्यात है ।

5 समन्वय करना (Co ordination)—समन्वय एक ऐसा शब्द है जहाँ पानी और दूध के मिलने पर भी वह दूध ही बढ़ जाता है, जबकि दानों को सत्ता अलग-अलग है । वही स्थिति पुस्तकालय एवं उनसे सम्बद्ध विभागों की हानी चाहिए तभी वह सच्चे मायने में समन्वय है । वहन का तात्पर्य यह है कि पुस्तकालय प्रशासक या पुस्तकालयाध्यक्ष के साथ कमचारियों का सहयोग तथा अन्य विभागों से सम्बन्धित तालमेल ही समन्वयभाव की परिणति है । यहाँ अन्य विभागों से मेरा तात्पर्य, शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्षों, लोक पुस्तकालय के सचालकों व ईकाई पुस्तकालयों व अन्य विभागीय पुस्तकालय के विभागाध्यक्षों से है जिनका आपसी सान्मन्य प्रशासकीय नीतियों के कारण ठीक नहीं बैठ पाता जिससे समन्वय भावना का ठेक पैदा नहीं है । फिर भी ग्रन्थालय के अध्ययन की भावना के साथ साथ अन्य विभागों के लोगों को भी अपने कार्य के प्रति उत्तम निष्ठा होना चाहिए । समन्वय से विकास का दुःख मार्ग भी सुलभ जाता है अतः मिलजुलकर आत्मनिष्ठा से कार्य करना ही इस क्षेत्र में सफल बड़ी उपलब्धि होगी ।

6 रिपोर्टिंग (Reporting)—तथ्या व आँकों का प्रतिवेदन विभिन्न विभागों से प्राप्त कर उसका सामूहिक प्रतिवेदन तैयार कर अपने विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना ही रिपोर्टिंग है । इसके अन्तर्गत विभागों की प्रगति तथा आने वाले वर्ष में आवश्यक साधन सामग्री की जानकारी उच्चाधिकारियों तक पहुँच जाती है । इस प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष अपने कार्यों व कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है और पुस्तकालय की प्रगति भी स्पष्ट हो जाती है । पुस्तकालय सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु ऐसी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए

सभी दृष्टि में लाभप्रद सिद्ध होते हैं। वर्ष भर की गई बाह्य एवं आन्तरिक गति-विधियाँ का लेखा जोखा भी इसमें सम्मिलित है। पुस्तकालय प्रचार एवं प्रसार हेतु किये गये सारे कार्यक्रमों का प्रतिवेदन के महत्त्वपूर्ण अंग है।

7 बजट बनाना (Budgeting)—आर्थिक संसाधन योजना विकास के प्रमुख स्रोत हैं बाई भी संगठन बिना आर्थिक सहायता के अयोग्य है और बिना कुशल प्रशासनिक अधूरा। पुस्तकालय संगठन समाज शिक्षा, शोध व विकासशील राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहता है अतः पुस्तकालयाध्यक्ष को पूरे वर्ष का योजना कार्यक्रम का आय व्यय तैयार कर अपनी माँग का लिखना चाहिए साथ ही उपयुक्त अधिकारियों को माँग का युक्ति संगत कारण भी स्पष्ट करना चाहिए। "माध्यमता हमारा देश में ग्रन्थालयों के विकास के लिए समुचित धन की व्यवस्था नहीं की जाती फलतः ग्रन्थालयों का समुचित विकास नहीं हो पाता।" ¹⁷ जन सामान्य की धारणाओं को अनुभव करते हुए प्रशासन कुमार बैंजर्जी लिखते हैं कि 'प्रायः यह समझा जाता है कि पुस्तकालय में धन का केवल व्यय ही होता है और उसमें देश को आर्थिक दृष्टि में बाई लाभ नहीं होता इसलिए शासन इसकी उपयोगिता को मंजूर नहीं करता भी इन्हें पर्याप्त रूप से आर्थिक सहायता देने में आनाजानी कठिनाई है और इससे पुस्तकालयों का समुचित विकास नहीं हो पाता।' ¹⁸ यही कारण है कि देश के अधिकांश पुस्तकालय आर्थिक जटिलता में जूझ रहे हैं और जिससे पुस्तकालय व्यवसाय की छवि धूमिल होती जा रही है। इस क्षेत्र में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। अनुदान आयोग की आवंटित राशि का समय पर उपयोग कर पुस्तकालयाध्यक्ष को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज देना चाहिए ताकि शीघ्र दूसरा आवंटन स्वीकृत होकर आ जाय इसी प्रकार का सहयोग यदि सरकारें भी करें तो पुस्तकालय सेवाओं के भविष्य में सुधार निश्चित होगा इन सब बातों के अतिरिक्त पुस्तकालय अधिकारी का यह कर्तव्य ही होता है कि जो कुछ भी धन जितनी भी मदों के लिए प्राप्त होता है उसका यथा सम्भव उपयोग कर उसकी रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें एवं भविष्य की योजनाओं की मूल्यात्मक व गुणात्मक प्रगति की रूपरेखा भी आवंटन के साथ भेज दें ताकि आवश्यकताओं पर पुनर्विचार हेतु अधिकारी का ध्यान दें।

इस प्रकार ऐसा करने से प्रशासन के उपयुक्त सात सहत्वपूर्ण सिद्धान्तों की व्यवहारिक अवधारणों को सफलता मिलेगी व ग्रन्थालय में एक कुशल नेतृत्व का भाव प्रकट होगा। परन्तु प्रायः यह देखने में आता है कि ग्रन्थालय में ग्रन्थालय के नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है विभागा के अध्यक्ष अपने अलग आदेश दिया करते हैं संस्था प्रमुख को उन पर विचार करना होता है और बहुत बड़े बार यह होता है कि ग्रन्थालयों के सुभाव की अवभावना हो जाती है। वही-वही प्रभागी ग्रन्थालय बनाये जाते हैं जो अपने पद का दुरुपयोग कर ग्रन्थालयों की वाता से सहमत नहीं हो पाते और पुस्तकालय प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं। इन सब बातों

से बचने के लिए 'आदेश की एकता' व नेतृत्व का अधिकार किसी एक व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। प्रा एस एस अग्रवाल का कहना है 'यदि नेतृत्व का अधिकार एक ही व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा तो कमचारिया की कार्यक्षमता का ह्रास होकर काम में देरी और गड़बड़ी हो जाना अवश्यम्भावी है।'¹⁵ आज पुस्तकालय जगत् में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि सद्वाचिक रूप से हम मानते हैं कि ग्रन्थालयी स्वनिर्णय नेने में सक्षम हैं किन्तु व्यवहार में इसका बिलकुल उलटा है, जब तक पुस्तकालय विज्ञान की व्यवस्था न हो नेतृत्व बँटा हुआ रहेगा।

अतः प्रशासन की उपरोक्त दशाम्रा का अध्ययन शासक व शासन दानों व द्वारा किया जाना चाहिए। प्रशासन में आ रही कठिनाइयाँ का जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक पुस्तकालय सेवाओं को वैज्ञानिक आधार प्रदान नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक आधार के बिना पुस्तकालय जैसी जटिल संस्था के कार्यों को आसानी से हल नहीं किया जा सकता इसके उपचार हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रसार विधियों का प्रयोग — भारत में यद्यपि पुस्तकालय सेवाओं के प्रति कोई "राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति" नहीं अपनाई गई है अतः पुस्तकालय प्रसार सेवा का स्वरूप उतना समुन्नत नहीं हो पाया है जितना अमेरिका, ब्रिटेन एवं सोवियत मध्य में है। विदेशों में पुस्तकालय प्रसार की अनेक विधियों का प्रयोग जन शिक्षा के विकास हेतु किया जाता है। ब्रिटेन के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार के लोगों को पुस्तकालय सुविधा प्रदान करने हेतु शाखा पुस्तकालय भवना की स्थापना का गई ताकि पुस्तकालय प्रसार कार्य को बढ़ावा मिले और लाग पुस्तकालयों की सुविधा का पूर्ण लाभ ले सके।

पुस्तकालय से सम्बद्ध केन्द्रों के नियमित पाठकों तथा साक्षरता आन्दोलन से जुड़े पाठकों तक उनकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य प्रसार सेवा का मुख्य अंग है। ऐसे पाठकों जिनका शैक्षणिक विकास रुक गया है तथा जिन्हें पढ़ने की इच्छा है लेकिन अध्ययन सामग्री के अभाव में विवश हैं, और वे लोग जो अनपढ़ होकर भी कुछ सीखना चाहते हैं एम. ए. तकियों को प्रसार की विभिन्न विधियों द्वारा पुस्तकालय सेवा की और आकर्षित किया जाता है।

भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रसार सेवा की विधियों को डॉ. रगनाथन ने अपने ग्रन्थ 'पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र' में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया है।

1. प्रशिक्षित के समक्ष पढ़ना।
2. जनता की भाषा में पुस्तक का अनुवाद करना।
3. अध्ययन-माष्ठीयों का आयोजन।

- 4 बौद्धिक क्षेत्र गोनना ।
- 5 पुस्तकालय वार्ता ।
- 6 मंगीत ।
- 7 पुस्तकानय प्रदर्शनी ।
- 8 कहानी-पाठ ।
- 9 उत्सव व मेले ।

उपरोक्त विधियाँ को अपनाकर पुस्तकालयाध्यक्ष निरक्षर भारतीयों के लिए श्रियाचित प्रोट-आधारता वायधम म सहयोग दवर शिक्षा का प्रसार कर सका है इन विधियाँ पर हम प्रमश विचार करेंगे।

1 अनिशितो के समक्ष पढ़ना —भारत मे जहाँ भी प्रोट शिक्षा वायधम चल रहे ह उन स्थाना पर पुस्तकालयाध्यक्ष निरक्षरों के समक्ष जावर उनके रुचि की प्रेरक कथा, कहानी जीवनियाँ, कृषि माहिर्य, पशु-पालन रोग निदान व रीटनाशक दवाईयाँ के उपयोग आदि के बाग मे पढ़कर सुनावें तो निश्चित ही अनिशिता के मन म पढ़ने की उत्सुकता जगगी और वे अक्षर पान सीखने व शिक्षा ग्रहण करने म रुचि दिखायेंगे ।

2 जनता की भाषा मे पुस्तक का अनुवाद कर पढ़ना —विभिन्नता म एकता के देश भारत म अनक भाषा व बोलिया का प्रयाग हाता है । प्रत्येक प्रात की भाषा व बोलीयाँ अलग-अलग है और उसी-के अनुरूप प्रदेशा मे प्रयो का मृजन भी हाता है । ऐसी स्थिति मे अय प्रदेश की भाषा म लिखी पुस्तको का स्थानीय भाषा व बोली म अनुवाद कर पढ़कर सुनाने स निरक्षरों म अन्य प्रदेशों की प्रगति व नवीन तकनीको की जानकारी हा सकेगी यह कार्य (अनुवाद व पढ़ना) पुस्तकालयाध्यक्ष को करना चाहिए । जिससे ग्रामीण निरक्षरों म नई नई जानकारीयाँ को जानने की जिनासा प्रबल होगी तथा प्रसार सेवा का उद्देश्य भी पूरा होगा ।

3 अध्ययन गोष्ठी —जो पाठक साक्षर ह साथ ही पुस्तकालय सवाआ का लाभ लेत हैं उनमे अधिक जिनासा व अध्ययन की प्रेरणा देने के लिए अध्ययन गोष्ठीयाँ का आयोजन प्रसार सेवा का महत्त्वपूर्ण कार्य है । भती भाति पढ़ने वाले पाठको न एक माह म जो कुछ पढ़ा है उसका गोष्ठी के माध्यम से विचार विनिमय अथवा आदान प्रदान माह मे एक बार पुस्तकालय म अथवा शाखा केन्द्रो पर हो तो साक्षरों व विचारा मे परिपक्वता आयेगी और वे और अधिक पुस्तकालय सुविधाआ का लाभ लेना चाहेंगे । उनके लाभ की पठन-सामग्री जुटान म पुस्तकालयाध्यक्ष सहयोग करेंगे तो गोष्ठियाँ क आयोजन म विस्तार होगा ।

4 बौद्धिक क्षेत्र —पुस्तकानय की सुविधाआ का लाभ लेने वाले पाठको म कुछ ऐसे पाठक भी होते ह जिनकी मोच समझ अध्ययन मनन, बातचीत व व्यक्तित्व विवेक इतना प्रभावशाली व आकर्षक होता है कि उह हम सामान्य

पाठकों की श्रेणी में न रखकर विशेष बौद्धिक-स्तर के वर्ग में रखते हैं। उनके साथ वही व्यवहार हम करना चाहिए जैसा उनका स्वयं का है। एम वर्ग के लिए उनकी रचि के अनुसार बौद्धिक केन्द्र चलाने चाहिए जिनमें धर्म, दर्शन, राजनीति, समाज इतिहास, व सम्प्रति जैसे विशेष विषयों पर ही विचार विमर्श तथा गम्भीर अध्ययन व चर्चा हो। इनके अनुकरण से अन्य पाठक प्रभावित होंगे और पुस्तकालय में एक सुखद पारिवारिक वातावरण बनेगा।

5 पुस्तकालय धार्ता —पुस्तकालय धार्ता भी पुस्तकालय प्रसारण अथवा प्रसार सेवा की उत्तम विधि है इस विधि द्वारा पुस्तकालय कमचारी तथा जन समूहों की उपस्थिति में प्रतिष्ठित लोगों द्वारा वाताभाषण व बाद विवाद तत्त्व हा साथ ही पाठकमण भी इनमें भाग लें तो प्रसार सेवा का उद्देश्य पूर्ण होगा तथा पाठकों का पुस्तकालय में आना व पुस्तकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों हेतु अपने को तैयार करना लाभप्रद सिद्ध होगा।

प्रसिद्ध लोगों के भाषण, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बातियाँ विशिष्ट लोगों के लिए उपयोगी होगी व पुस्तकालय का नाम भी प्रसिद्ध होगा जिससे भविष्य में कई लाभ हो सकते हैं। म प्र के ब्यण्डवा जिले की बुरहानपुर तहसील के बुरहानपुर शहर में होने वाली "व्याख्यान माला" जो कि लोक पुस्तकालय द्वारा आयोजित की जाती है वही कारणों से सम्पूर्ण भारत वष में प्रसिद्ध है।

6 संगीत या मनोरंजन के कार्यक्रम —पुस्तकालय की सेवामें प्रसारित करने की यह सर्वोत्तम विधि है। पुस्तकालय के सभाकक्ष अथवा वाचनालय कक्ष में चलचित्र, संगीत समारोह, मुशायरा नाटक, कवि सम्मेलन, गीत गजल अथवा लोकसंगीत का आयोजन होता रहे तो श्रोताओं का मन पुस्तकालय की ओर आकर्षित होगा। पाठकों की संख्या में वृद्धि होगी ता पुस्तकालय का उपयोग भी स्वाभाविक ही बढ़ेगा।

7 पुस्तकालय प्रदर्शनी —आज हमारा देश जिन परिस्थितियों में गुजर रहा है और विश्व में आधुनिक आणविक शस्त्रों की जिस तीव्रता से होड़ बढ़ती जा रहा है वही हमारे ग्रामीण भारत की जनजीवन बातों से बेखबर हमारा ग्रामीण कृषि पत्र व धर्म में जुड़ा अपने उदर पापण में लगा हुआ है देश के आर्थिक विकास में 20 सूनीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा विश्व में शान्ति स्थापना हेतु गुट निरपेक्ष सम्मेलन की ग्रहम भूमिकाओं में सम्बन्धित साहित्य व चित्रों की प्रदर्शनी लोक पुस्तकालयों में ग्रामीण जनता हेतु व शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए लगायी जावे तो राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय घटना-क्रम व कार्यक्रमों की जानकारी सुविधा पाठकों को होगी।

वैज्ञानिक अनुसंधान व अन्तरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में भारत द्वारा किये गये परीक्षणों की जानकारी भी प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम में दिखायी जा सकती

है इनके ऊपर प्रकाशित साहित्य को पढ़ने में पाठक अपनी रुचि दिखायेंगे तो अध्ययन प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आयेगा नये-नये पाठक भी पुस्तकालय की सदस्यता हेतु प्रेरित होंगे। इस प्रकार प्रसार-सेवा का लक्ष्य पूर्ण होता नजर आयेगा।

8 कहानी पाठ — साहसी, वीरता-पूर्ण चरित्रों से युक्त कहानी, हास्य व्यंग से भरपूर सस्मरणा व विनोद-पूर्ण साहित्य का पाठ बच्चों व वृद्ध जनों का प्रमत्त करने के लिये सुनाय व सुने जावे ताकि उनका मनोरंजन भी हो व पुस्तकालय की प्रसार सेवा का उद्देश्य भी पूर्ण होता रहे।

9 उत्सव व मेले — अनेक धर्म व संस्कृतियों से भरपूर हमारा देश उत्सव, मेले, त्यौहार व महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए प्रसिद्ध है। हो भी क्यों न? यहाँ की विजाल, परम्पराएँ, विराट जीवन दश तथा सब धर्म के समन्वय की एवता ने विराट-भारत का स्वरूप प्रदान किया है। प्रत्येक धर्म के अपने त्यौहार, हर धर्म के अपने देवी-देवता व हर जाति का अपना महा मानव यहाँ पैदा हुआ है जिनकी याद में प्रतिवर्ष उत्सव मनाये जाते हैं। मेले लगते हैं और भारत व ग्रामीणों की सांस्कृतिक परम्पराओं को फलने फूलने का अवसर मिलता है।

इन अवसरों पर पुस्तकालयों के अधिकारियों द्वारा हर धर्म, जाति, संस्कार व इतिहास-पुरुष व्यक्तियों की जीवनी के साहित्य चित्रों को प्रदर्शित कर उनमें पढ़ने की प्रेरणा जगावे तो जनता में फले भ्रम व अज्ञानता का अंत होगा, भाई-भार की भावना बढ़ेगी। एक अनुभवी पुस्तकालयाध्यक्ष श्री एन डी बगरी ने तो यही तक लिखा है कि "इनकी एक स्मारिका जन-समुदाय में बांटना चाहिए जिसको पढ़ने से लोगों की अंधों के बारे में अनुभव प्राप्त होता है"।¹⁷

अनुभव के साथ ही यह अग्र्य धर्मों का समझने की दिना-दिवाज, परम्पराओं व सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अपनाने में भी ग्रामीण अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर सकते हैं। यह विधि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में भी बहुत सहायक होगी।

इस प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष अपने बुद्धि विकास, कला कौशल एवं व्यवसायिक योग्यता का उपयोग कर पुस्तकालय प्रशासन में सुस्ती व पुस्तकालय प्रसार सेवा में तीव्रता ला सकता है। देश में बढ़ती हुई निरक्षरता की समस्या का समाधान भी प्रसार सेवा की उपरोक्त विधियाँ द्वारा किया जा सकता है। बशर्ते कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पुस्तकालय सेवाओं को महत्त्व दिया जावे, पुस्तकालय कानून-पास किये जावे और राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का निर्माण भी हो। आश्चर्य तो यह है कि दश में कीडिया, टेलीविजन का प्रचलन गायों तक में पहुँच रहा है किन्तु पुस्तकालय स्थापित करने के प्रति न जनता जागरूक है और न ही सरकार। प्रगति फिर भी प्रगति है चाहे व अगूठा निशानी तक ही सिमटी क्यों न हो वैज्ञानिक विकास में हमने प्रगति कर ली है।

- 1 सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एवं समुदाय, पटना, बिहार हिन्दी ग्रंथ
अकादमी 1975 पृ 322
- 2 वर्मा (सुभाष चन्द्र) पुस्तकालय संगठन एवं संचालन, जयपुर राजस्थान
हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1978 पृष्ठ 160
- 3 अग्रवाल (एस एस) ग्रंथालय संचालन तथा प्रशासन, आगरा
श्रीराम मेहरा एण्ड प्रमाक 1976, पृष्ठ 64
- 4 Rao (K Ramkrishna) Philosophy of Librarianship
in Development of Libraries in New India Edited
by N B Sen New Delhi New book Society of
India 1965 p 297
- 5 वर्मा (महादेवी) प्रौढशिक्षा में पुस्तकालयों का योगदान, विचार
गोष्ठी में दिया गया भाषण ।
- 6 स भास्करनाथ तिवारी इलाहाबाद बोहरा पब्लिशर्स, 1990 पृ 11
- 7 Harrison (K C) First step in Librarianship, London
Andre Deatsch, Ltd, 1980, p 86
- 8 बैनर्जी (प्रशान्त कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन, भोपाल मध्य प्रदेश
हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1972, पृ 7
- 9 दत्त (विमल कुमार) पुस्तकालय कार्य पद्धति का व्यवहारिक ज्ञान,
नयी दिल्ली एशिया पब्लिशिंग हाऊस, 1958 पृ 2-3
- 10 White (L D) Public Administration p 4
- 11 अग्रवाल (एस एस) ग्रंथालय संचालन तथा प्रशासन, आगरा, श्रीराम
मेहरा एण्ड प्रमाक 1976 पृ 9
- 12 बनेर्जी (प्रशान्त कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन, पृ 9
- 13 अग्रवाल (एस एस) ग्रंथालय संचालन तथा प्रशासन, पृ 10
- 14 अग्रवाल (एस एस) ग्रंथालय संचालन व प्रकाशन, पृ 11
- 15 बैनर्जी (प्रशान्त कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन पृ 10
- 16 अग्रवाल (एस एस) ग्रंथालय संचालन तथा प्रशासन पृ 11
- 17 Ranganathan (S R) Five Laws of Library Science
Bombay, Asia publishing House 1957 p 280-84
- 18 वगरी (नागप्पा दासप्पा) पुस्तकालय पद्धति इलाहाबाद नीलम
प्रकाशन, 1973, पृ 112

मध्य-प्रदेश मे पुस्तकालय व्यवसाय : सीमायें एवं संभावनाएं

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो भारतीय पुस्तकालयों का इतिहास अनि प्राचीन एवं वैभवशाली रहा है। व्यावसायिकता की नजर से भारत में पुस्तकालय व्यवसाय यूरोपीय देशों से 25 वर्ष बाद का है। इसका सुरुआती प्रारम्भ प्रारम्भ 1910 से बड़ौदा स्टेट से माना जाता है। वैसे इसके पूर्व भी अनेक प्राचीन मत्स्यालय होने पर पुस्तकालयों की स्थापना पर जोर दिया गया। सन् 1850 तक पुस्तकालयों की स्थापना देश के प्रमुख शहरी कल्याण बम्बई एवं मद्रास में हो चुकी थी किन्तु इनका उपयोग जन साधारण के लिए न होकर सीमित था।

स्वाधीनता के बाद देश में शिक्षा की आवश्यकता ने राष्ट्र निर्माताओं, बुद्धिजीवियों समाजसेवियों तथा सृष्टारकों की प्रवृत्ति को राष्ट्रीय विकास की ओर मोड़ा। उस समय व्याप्त निरक्षरता ने जगह-जगह शिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ सामाजिक पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना में मदद पहुँचाई। देश में शिक्षा का प्रचार करने एवं निरक्षरता दूर करने हेतु 1948 में ग्रन्थालय योजना क्रियान्वित की गई। "योजना का मुख्य ध्येय प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना कर सम्पूर्ण राज्य में निक्षेपालय एवं चल पुस्तकालयों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में भ्रमणशील पुस्तकालयों का जाल बिछाना था।" इस योजना का पूर्ण लाभ मध्यप्रदेश राज्य को भी मिला।

मध्यप्रदेश में "ग्रन्थालय एवं वाचनालयों का काम 1948 में प्रारम्भ किया गया। इस वर्ष 263 ग्रन्थालय और 200 नवीन वाचनालय स्थापित किये गये। ग्रन्थालयों की पटिया के लिए 258 पुस्तकों का चयन किया गया तथा 21 हजार रुपये की पुस्तकें खरीदी गईं अथवा तब गाँवा में 9,263 परिवारों को पुस्तकालय स्थापित किये गये हैं।"

भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक कल्याण मन्त्रालय द्वारा स्थापित 195 की पुस्तकालय सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 4 केन्द्रीय पुस्तकालय इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में स्थापित थे तथा जिला केंद्रों पर भी जिला ग्रन्थालयों की स्थापना की गई थी। वर्तमान में विशाल मध्य प्रदेश राज्य में पांच रोजनल सफ़ल लायब्रेरी एवं 44 जिला पुस्तकालय हैं। सभी ग्रन्थालयों में प्रशिक्षित ग्रन्थपालों की नियुक्ति की गई है।

मध्य प्रदेश राज्य जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4 43,452 वर्ग किलोमीटर है। देश में पहले नम्बर का सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 22.14 है जो कि अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी कम है। शिक्षा की सुविधा हमें हमें राज्य की तुलना करें तो हमें विदित होगा कि हमारे राज्य में सबसे अधिक 1। विश्वविद्यालय हैं जिनमें 8 (आठ) सामान्य विश्वविद्यालय हैं जिनमें 318 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। इन 318 महाविद्यालयों में 1979-80 तक 2,02,585 छात्र अध्ययन कर रहे थे।

उपरोक्त शिक्षा-संस्थान उच्च अध्ययन के मुख्य केन्द्र हैं जिनमें मल्लिकार्जुन विश्वविद्यालय का नाम शोधार्थी, प्राध्यापक एवं अनुसंधानकर्ता के लिए है। विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

लोक-शिक्षण संचालनालय एवं जिना शिक्षा अधिकारियों के अधीनस्थ 2,145 उच्चतर माध्यमिक शालाओं 9 646 माध्यमिक तथा 55 378 प्राथमिक शालाओं शिक्षा के एक गुरुत्तर भार का निर्वाहन कर रही हैं। उपरोक्त 67 169 पाठशालाओं में कुल अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या 69 लाख 91 हजार 45 थी। इन सभी विद्यार्थियों को उचित शिक्षा में भाग देना प्रदान करने, उनमें अध्ययन रुचि जाग्रत करने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं, वैज्ञानिक आविष्कारों का विकास करने हेतु ग्रंथों पत्र-पत्रिकाओं से युक्त साहित्य भण्डारों का व्यवस्थापन संगठन संचालन एवं क्रिया-व्ययन करने हेतु पुस्तकालयों का भी निर्माण किया गया है। इन पुस्तकालयों को पुष्कारूप से चलाने ग्रंथ सामग्री को व्यवस्थित रूप से रखने तथा वैज्ञानिक पद्धतियों से उनका उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियां भी प्रदेश भर में की गई हैं।

ग्रंथालय-व्यवसाय में लग्न अध्यापकों की पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रदेश में 6 विश्वविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। भोपाल तथा ग्वालियर के क्षेत्रीय-पुस्तकालय, पुस्तकालय विज्ञान का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र पंचमढी में पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। उज्जैन विश्वविद्यालय, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा एवं रायपुर विश्व-विद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम तथा विक्रम विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन की सुविधा है। सम्पूर्ण भारत में मध्यप्रदेश राज्य ही ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे अधिक पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के प्रशिक्षण संस्थान हैं। इन सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रशिक्षण हेतु लगभग 80 छात्र-छात्राओं का एक पूरा सत्र में प्रवेश दिया जाता है। विक्रम विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 1981 तक सिर्फ 8 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता था जबकि 1981-83 में यह संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है। डा. हरीसिंह गौर विश्वविज्ञान सागर में सन 1983 से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था की गई है जिसमें 10 विद्यार्थी प्रवेश

ले सकेंगे। इस प्रकार एक वर्ष में मध्यप्रदेश में करीब 200 छात्र-छात्राएँ पुस्तकालय विज्ञान स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रदेश की विभिन्न शैक्षणिक निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के पुस्तकालयों में नियुक्ति पान अथवा व्यवसाय में लगने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं।



पुस्तकालय व्यवसाय में लगे ग्रंथालय अथवा कमचारियों को प्रशिक्षित करने में विश्व विश्वविद्यालय का योगदान बहुत पुराना है। यहाँ 1957 से पुस्तकालय विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुआ था, जिसके प्रथम संस्थापक, भारत के प्रथम पुस्तकालय विज्ञान वेत्ता स्व डा एस आर रंगनायन थे। सन् 1963 से यहाँ स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुआ एवं 1972 से स्नातकोत्तर। 25 वर्ष में इस एक विश्वविद्यालय से लगभग 850 छात्र-छात्राएँ ग्रंथालय व्यवसाय में प्रशिक्षित हुए हैं। इसी प्रकार अन्य पाँच विश्वविद्यालयों एवं दो क्षेत्रीय पुस्तकालयों द्वारा संचालित केंद्रों पर यह पाठ्यक्रम यथावत् प्रारम्भ है।

इतना सब कुछ हाते हुए भी यदि हम पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में प्रवीण एवं व्यवसायियों की संख्या राज्य में फले विस्मृत शिक्षा-क्षेत्र में देखें तो हमें यह जानकर दुःख होगा कि-जितना निर्माण हो रहा है उसके बदले में उसकी खपत विन्दुल मन्द है। राज्य के सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों में बहुत-बहुत ग्रंथपालों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। यदि पद है भी तो नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। जिन विश्वविद्यालयों में ग्रंथपाल है उनकी व्यावसायिक स्थिति, वेतन पदोन्नति स्टेटस एवं प्रशासनिक दृष्टि से कोई बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है। जबकि ये विश्व विद्यालय ही हमारी प्रगति के सबसे बड़े ज्ञान गृह हैं, इन पर हमारी प्रगति निर्भर है क्योंकि इनसे ही जीवन में वैज्ञानिक, डाक्टर, इंजीनियर, गणितज्ञ, राजनीतिज्ञ, साहित्यकार एवं दार्शनिक बाने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है।

महाविद्यालयीन स्तर पर तकनीकी, अभियांत्रिकी, चिकित्सा कृषि एवं प्राइवेट फ़ैलिया को छोड़ दें तो हम देखेंगे कि म प्र के 317 महाविद्यालयों के लिए लगभग 170 ग्रंथपालों की नियुक्ति की गई है। प्रतिवर्ष पुस्तकालय व्यवसाय में लगने हेतु दो स्थान बँटते हैं। ग्रंथपालों को लोक सेवा आयोग से भाषास्कार के उपरांत सेवा श्रेणी दो में नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति अथवा व्यवसाय में नम्बी प्रक्रिया के कारण बेरोजगार प्रशिक्षार्थी जल्दी जल्दी अपनी नौकरी नहीं ढूँढ़ पाते अतः अपनी विशेषता को मुलावर किसी अन्य व्यवसाय में लग जाते पड़ते हैं। महाविद्यालयीन ग्रंथालयों में लग ग्रंथालय व्यवसायियों में लगे ग्रंथपालों को 1968 से 300 600 रु का वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा पर दिया गया जो महाविद्यालयों के ध्यायाताओं के समक्ष था। 1973 से अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान रु 700 40 1600 महा विद्यालय ध्यायाताओं को देने की अनुशंसा आयोग ने की किन्तु ग्रंथपालों को

उक्त वेतनमान से बचित रखा गया जबकि अनुदान आयोग को पुस्तकालय सलाहकार समिति ने 1959 की रिपोर्ट में लिखा "हम महसूस करते हैं कि प्रत्येक राज्य में पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान शैक्षणिक व्यक्तियों के तुलनात्मक आधार पर समान होना चाहिये। समिति ने यह भी अनुशंसा की थी कि जिस प्रकार प्राध्यापकों को उच्च अध्ययन हेतु शासन विशेष अवकाश एवं अनुदान देती है उसी को अनुरूप ग्रंथपालों को सामान्यतः ग्रंथवा उच्च व्यवसायिक प्रशिक्षण मजाने हेतु राज्य सरकारों को अध्ययन अवकाश प्रदान करना चाहिये। इस दिशा में मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ स्नातक स्तर पर पांच व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु प्रतिवर्ष भेजा जाता है। स्नातकोत्तर स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है।

ग्रंथालय व्यवसाय में तीव्रता लाने तथा प्राध्यापकों के समकक्ष पद एवं प्रतिष्ठा देने हेतु मध्य प्रदेश शासन ने 1-4 81 से महाविद्यालयों के ग्रंथपालों को 700 40-1100 रु का वेतनमान देकर इस व्यवसाय के प्रति उदारता दर्शायी है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस वेतनमान का राज्य शासन ने सर्वप्रथम प्राध्यापकों के लिए निम्नानुसार लागू किया—

महाविद्यालय यात्राया—300 600 1972 दिसम्बर तक

यू जी सी 620-1300—1973 से

700 1600—1976 से

महाविद्यालय ग्रंथपाल—300 600 के बाद 1-4 80 से 700-1600

यू जी सी

राष्ट्रीय-वेतन नीति के निर्वाहन हेतु शासन को चाहिए कि ग्रंथपालों को भी उपरोक्तानुसार वेतन देकर ग्रंथालयों के विकास एवं बेहतर ग्रंथालय सेवा को प्रोत्साहित करें।

व्यवसाय में आने के इच्छुक सकड़ों वरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षणार्थी भटक रह रहे हैं। उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए ग्रंथ राज्या के समान स्टाफ पटन बनायें ताकि महाविद्यालयों में कार्यरत अकले अकेले ग्रंथपालों को राहत मिल सके। अभी तक राज्य के अधिकांश महाविद्यालयों में सिर्फ ग्रंथपाल ग्रंथवा सहायक ग्रंथपाल के पद हैं और जवाबदारी लाखों रुपयों की। महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में जिस प्रकार प्रयोगशाला सहायक एवं परिचायक दिए जाते हैं उसी प्रकार पुस्तकालय विभाग के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि पुस्तकालय कोई एक विभाग तक सीमित नहीं है और न ही कुछ प्राध्यापकों एवं कुछ विद्यापियों तक। यह तो समस्त विभागों का सम्पत्क सूत्र, समस्त छात्र प्राध्यापकों का सेवा केन्द्र एवं अध्ययन रूपी प्रयोगशालाओं की प्रयोगशाला है। इनके

विकास पर नहीं सोचा गया तो शिक्षा के गुणात्मक विकास की कल्पना अपने समग्र परिपक्व में मफल नहीं हो सकेगी।

दूसरी ओर शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पुस्तकालय व्यवसाय का परख तो हमें महसूस होगा कि म प्र में उक्त शिक्षण संस्थाओं में ग्रंथालय व्यवसाय का कोई तरदीबवार स्वरूप नहीं है और न ही ग्रंथालयों के अस्तित्व का निश्चय। पूरे प्रदेश में 1979-80 तक 55, 378 प्राथमिक शालाओं 9,646 माध्यमिक शालाओं एवं 2,145 उच्चतर माध्यमिक शालाओं थी। इन शालाओं में उच्चतर माध्यमिक शालाओं को छोड़कर शेष शालाओं में ग्रंथालय सुविधा है ही नहीं जबकि होना चाहिये। किंतु इन पाठ शालाओं को जिना ग्रंथालय के माध्यम से पुस्तकों का अस्थायी निगमन किया जाता है जिसका लाभ विद्यार्थी उठाते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 2,145 सरया में म प्र की कुछेक पाठशालाओं में ग्रंथपाल का पद है और कुछ में नहीं। जिन पाठशालाओं में ग्रंथपाल हैं वे अपने व्यवसाय के साथ उचित वेतन नहीं कर रहे हैं। पढानाचार्यों के दबाव में अक्सर अपना व्यक्तिगत स्वार्थों के लालच में अक्सर अपने मूलभूत व्यवसाय से हटकर पाठशालाओं की विभिन्न गतिविधियों में निगमन रहते हैं। पाठशालाओं के इन पुस्तकालय कक्षों में पूरे वर्ष ताल लग रहते हैं और विद्यार्थियों को यह पता ही नहीं रहता कि उनकी पाठशाला में पुस्तकालय की भी कोई व्यवस्था है। लोक शिक्षण मन्त्रालय के नवीन आदेशों से माध्यम पुस्तकालय व्यवसाय पर कुछ प्रभाव पड़गा तथा ग्रंथपाल अपनी पूर्ण कालिक सेवाओं छात्र-छात्राओं को द सकेंगे।

इस प्रकार हम मध्य प्रदेश की पाठशालाओं में पुस्तकालयों की स्थिति को बेहतर तो नहीं, बल्कि मजबूत किन्तु विचारणीय अवस्था है, कह सकते हैं। प्रदेश में अभी तो शिक्षण की व्यवस्था पर अधिक ध्यान देने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में आज भी 72 हजार गाँवों में से 24 हजार ग्राम ऐसे हैं जहाँ प्राथमिक स्कूल भी नहीं है। इन 24 हजार में से 3 हजार ग्राम ऐसे हैं जिनकी आबादी 200 ॥ अधिक है। इन गाँवों में केवल प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था का मतलब है कराडों का खर्च। 1984 तक इस प्रदेश में प्राथमिक शिक्षण की समुचित व्यवस्था हो सके, अभी तो हमारा यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के अनिवार्य राज्य शासन ने शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए प्रत्येक महाविद्यालय व राज्य स्तरीय पुस्तकालयों में 40,000 हजार रुपये की पुस्तकों राज्य ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए 15 लाख रुपये तथा क्षेत्रीय व जिला पुस्तकालयों में पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं खरीदने के लिए 4 लाख रुपये की व्यवस्था वर्ष 1979 से की।

यह स्थिति आर्थिक सहयोग तथा सम्पन्नता की दृष्टि से सराहनीय है किन्तु पुस्तकालय-व्यवसाय से जुड़े उन तमाम व्यक्तियों कमचारियों व अधिकारियों के हित में नहीं है जब तक कि उनके अधिकारी, उनकी आवश्यकताओं एवं उनकी तरक्की के लिये आयामा का पथ न निर्मित किया जाए। जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा आयोग तथा पुस्तकालय सलाहकार समिति ने यह स्पष्ट किया है कि ग्रन्थपालों का स्तर अथ शिक्षण सस्थाओं के व्याख्याताओं प्राध्यापकों एवं अधिकारियों के समकक्ष होना चाहिए। तब त्रमश ग्रन्थपालों को भी पदानुति के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

यही बात लोक पुस्तकालयों के मामले में भी कही जा सकती है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला पुस्तकालय है। उनमें प्रशिक्षित ग्रन्थपाल भी नियुक्त किये गये हैं किन्तु इनमें भी ग्रन्थपाल के सहायक के रूप में शिक्षा विभाग के विशेष रूप से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से एक उच्च श्रेणी लिपिक दिया जाता है जबकि होना यह चाहिए कि जिला-ग्रन्थालया में सहायक ग्रन्थपाल तथा बुक लिप्टर के पद निर्मित करके नियुक्तियाँ की जानी चाहिए तो ग्रन्थालय सेवा में और अधिक सजगता आयेगी, ग्रन्थालय के कार्यकलाप ग्रन्थालय के उद्देश्यों के अनुरूप हो सकेंगे।

1955 की ग्रन्थालय सुधार योजना के उद्देश्यों के अनुसार अधिक से अधिक लोगों का शिक्षित करने तथा शिक्षित लोगों को निरन्तर अध्ययन की सुविधा यथो, पत्रिकाओं के माध्यम से प्रदान करना था। इस योजना से प्रारम्भ में आशा-तीत सफलताएँ मिलीं। उस समय इन सावजनिक पुस्तकालयों की स्थापना साक्षरता निवारण के विशेष लक्ष्य का लेकर हुई थी। कुछ समय बाद इन पुस्तकालयों की शिक्षा अधिकारी के अधीन कर दिया गया अतः इनके प्रारम्भिक उद्देश्यों का पूर्ण नहीं किया जा सका। यदि पुस्तकालय अविनिमय पारित हो गया होता तो लोक पुस्तकालयों के विकास की दिशा कुछ और ही होती, साक्षरता अभियान में वर्षों पापड़ न फैलने पड़ते।

आज इन जिला ग्रन्थालयों की दशा कुछ और ही है। जिला स्तर पर बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती शिक्षा एवं तकनीकी व वैज्ञानिक ज्ञान के विकास से पाठकों का बढ़ने की व्यवस्था, फर्नीचर की कमी पर्याप्त ग्रन्थ की अनुपलब्धता से जन-सामान्य में कोमल फल रहा है। वहीं-कहीं यह स्थिति है कि जनता को यह पता ही नहीं है कि जिला ग्रन्थालय में भी अध्ययन की सुविधा होती है। इसका कारण है ग्रन्थालयों के प्रचार-प्रसार की कमी। ग्रन्थ भण्डारा के विकास में राजा राम मोहनराय फाउण्डेशन लायब्रेरी का योगदान सराहनीय है। इस फाउण्डेशन द्वारा देश के सभी सावजनिक पुस्तकालयों का प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण ग्रन्थों का मुफ्त प्रदायन किया जाता है। लोक-पुस्तकालयों के विकास में यह एक अच्छा कदम है। जिला ग्रन्थालयों का ग्रामीण-पुस्तकालयों से जुड़े न रहने से इनके विकास की गति रुक

गई है। जिला पचायत एवं समाज कल्याण विभाग ग्रामीण पुस्तकालयों के प्रशासन, संगठन एवं संचालन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिसका कारण है ग्रन्थालय विज्ञान में प्रशिक्षित ग्रन्थपालों की नियुक्तियों का न होना। ग्रामों में पचायत द्वारा अथवा जनता द्वारा खोले गये वाचनालय ग्रामीण जनता को अध्ययन के अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु बिना प्रशिक्षित ग्रन्थपाल ऐसे पुस्तकालयों का प्रशासन, संगठन एवं समुचित व्यवस्थापन नहीं कर पा रहा है। जिस प्रकार लोक पुस्तकालयों को जनता के विश्वविद्यालय कहा जाता है तदनु रूप इनकी सेवाएँ भी होनी चाहिए। वर्तमान में निजी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे बड़े बड़े पुस्तकालय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्रों में हैं परन्तु ग्रन्थालय संस्थाओं के क्षेत्र में उनके प्रचार-प्रसार एवं विकास पर कम ध्यान दिया जा रहा है। इन पुस्तकालयों को राजनीतिक दाव-पच के झड़े बनाकर इनके अधिष्ठान को पूर्ण न कर मात्र दलगत-वैभवं को बढ़ाया जा रहा है। वैसे मध्य प्रदेश के सावजनिक पुस्तकालय सघ ने मध्य प्रदेश सावजनिक पुस्तकालय अधिनियम का विधान-सभा तक प्रस्तुत करने में जो अद्वितीय कदम उठाया वह पुस्तकालय व्यवसाय के विकास में अनुकरणीय माना जावेगा। यद्यपि प्रारम्भ में इस अधिनियम का प्रारूप में कुछ कमियाँ थी जिसे बाद में विषय विशेषज्ञों के सह-योग से दूर किया जा चुका है। कोई भी अधिनियम सब-जन हिताय होता है और जन-जन में साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए ऐसे पुस्तकालय अधिनियम की अरसे की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो शीघ्र ही पूर्ण होगी।

निजी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे सावजनिक पुस्तकालयों अथवा वाचनालयों की स्थिति मध्य प्रदेश में 31-12-77 की बुरहानपुर में हुए सावजनिक पुस्तकालय सम्मेलन की रिपोर्टिंग के अनुसार इस प्रकार थी। 'मध्य प्रदेश में 45 जिले हैं 190 तहसीलें (अब अधिक) हैं। इसमें 12 जिलों के वाचनालयों की अनुदान नहीं मिलता, शेष 33 जिलों के 150 वाचनालयों को कुल मिलाकर रुपये 2,10,000 का अनुदान मिलता है। इसमें रुपये 500 तक पाने वाले 67 वाचनालय हैं। 501 से 1500 तक पाने वाले 43 हैं 1501 से 3000 तक पाने वाले 25 वाचनालय हैं। 15,000 तक पाने वाला एक वाचनालय है। जिनको अनुदान नहीं मिलता ऐसे सैकड़ों वाचनालय हैं जिनमें कुछ सौ सान से अधिक आयु वाले हैं, ज्यादातर मरणासन्न अवस्था में हैं।'

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सावजनिक वाचनालयों को शासन से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। किन्तु जिन्हें सहायता पहुँचाई जा रही है क्या वे पुस्तकालय इस अनुदान राशि का सत्प्रयोग उपयुक्त मद्दा में कर रहे हैं। सावजनिक पुस्तकालय सघ (ग्राहक) एवं वाचनालयों के सचिव अथवा अध्यक्ष

यह प्रयास क्यों नहीं करते हैं कि इन ग्रंथालयों में प्रशिक्षित एवं काय कुशल ग्रंथालय विज्ञान के बेरोजगार भटक रहे लोगों को लगाया जा सके ताकि एक साथ अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः हाता रह।

अनुदान और अधिक मिले सिर्फ इसी गरज से शासन का विश्वास में लेकर अधिनियम को प्रदेश में लाया किया जाय यह पुस्तकालयों के विश्वास हेतु एक तरफ बात है, इसका स्वरूप तो समग्र राज्य की पुस्तकालय सेवाओं को एक सूत्र में पिरो कर संगठित करता है चाहे वे शासकीय ग्रंथालय हों चाहे अशासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय।

मध्य प्रदेश के प्रायः सभी अशासकीय लोक-पुस्तकालय ऐसे हैं जहाँ न ग्रंथालय विज्ञान में प्रशिक्षित ग्रंथपाल सेवारत हैं और न कोई व्यवसाय निपुण कर्मचारी। परिस्थितियों के मागे लोगों को अल्प वेतन पर नियुक्त कर भतमाने ढंग से उनसे काम लिया जाता है। क्योंकि ग्रंथालय प्रशासन के नाम पर समिति या इनकी सर्वेसर्वा होती है जिनके प्रमुख अध्यक्ष एवं सचिव होते हैं। इनकी ही इशारों पर ग्रंथालय का संचालन होता है। ये सभी आधुनिक पुस्तकालय के कायकलापो एवं तकनीकी जानकारी से अनभिज्ञ होते हैं। माना कि ये ग्रंथालय जन सेवा का काम करते हैं, शहर व कस्बे की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गति विधियाँ के केन्द्र होते हैं। किन्तु इनका मालुम होना चाहिए कि ग्रंथालय विज्ञान इतना विकसित विषय हो गया है कि इनके जानकारी व्यक्ति ग्रंथालय को जिस वैज्ञानिक तरीके से चला सकत है वैसे अनभिज्ञ व्यक्ति नहीं। ग्रंथालय व्यवसाय में लगे इन व्यवसायियों की सीमाओं को समाप्त किया जाना चाहिये। यह काय प्रश्न में पारित होने वाले अधिनियम से ही सम्भव होगा।

वर्तमान में राज्य में लगभग 400 अशासकीय लोक पुस्तकालय एवं पचासता के अधीन 12,185 अर्द्ध शासकीय 110 जनपदान्तर्गत पुस्तकालय हैं जिनमें पचासत एवं जनपद के पुस्तकालयों को शासन सहायक अनुदान 2 लाख रुपये देता है। अनुदान के बावजूद इनकी सेवाएँ कोई सतोपजनक परिणाम नहीं दे रही हैं। पचासत एवं जनपद के अथवा नगरपालिका-परिषद के जितने भी ग्रंथालय हैं उनमें विषय के जानकारी एवं ग्रंथालय-विज्ञान में प्रशिक्षित व्यवसायिक कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की जानी चाहिये ऐसा करने से ग्रंथालय व्यवसाय की सीमाएँ समाप्त होगी एवं विकास की सम्भावनाओं का माग खुलेंगे।

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण व कन्वार्ड प्रतिभागों को उभारने एवं जन-जीवन में अध्ययन के प्रति रूझान पैदा करने हेतु प्रत्येक राज्य में नहुरू-युवक केन्द्र की स्थापनायें की हैं। ये युवक केन्द्र ग्रामीण पुस्तकालय भी चलाते हैं। इनके समन्वयक प्रथम श्रेणी अधिकारी होन हैं और बाकी सभी काय युवा प्रतिभागों के माध्यम से होता है। इन युवक केन्द्रों के पुस्तकालयों के प्रशासन में भी प्रशिक्षित ग्रंथपालों को लगाया जावे

तो सभी प्रकार के वग की बेहतर सेवाएँ प्रदत्त की जा सकती हैं शासन को इस पर विचारना चाहिए।

उपरोक्त सभी प्रकार के पुस्तकालया एव उनमें लगे व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है और न ही मध्य प्रदेश के पुस्तकालय संघ इतने सक्षम हैं कि अपने व्यवसाय की दशा को सुधारने तथा व्यवसायियों की विगटती आर्थिक एव सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने में सफल हो सकें।

व्यवसाय में लगे ग्रंथालय-कर्मचारियों की कार्यक्षमता, उनके काम के घंटे, उनकी जवाबदारियाँ एव अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन, समाज में उनकी प्रतिष्ठा एव उनकी जवाबदारियों की तुलना करें तो ग्रंथालय कर्मचारियों का ही पलड़ा हल्का दिखाई देता। ग्रंथपालों अथवा कर्मचारियों के साथ एव उनके उत्तरदायित्वों को भट्टे नजर रखते हुए उनके साथ निष्पक्षतापूर्ण विचार किया जाना चाहिए।

विद्यार्थी और पुस्तकालय उपयोग

शिक्षा, राष्ट्र की भगव एव युवा पीढ़ी के शैक्षणिक, सामाजिक एव चारित्रिक विकास की अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्रों का अध्ययन रुचि, मनोज्ञता को विवसित करने एव पाठ्येतर गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु संस्थाओं में ग्रंथालयों की व्यवस्था की जाती है। ग्रंथालयों को मोलने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं का समाधान बिना किसी कठिनाई के हो जाय, साथ ही उनके विविध विषय (क्षेत्र) में होन वाले शोध व अनुसंधान की अद्यतन सूचना उन्हें मिलती रहें।

हमारे देश में हजारों विद्यालय हैं, माध्यमिक पाठशालाएँ व महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय हैं, किन्तु प्राथमिक स्तर पर कोई भी ग्रंथालय जैसी गति विधियाँ देखने में नहीं आती हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में ग्रंथालय तो है यह जानकारी मिलती है परन्तु उन ग्रंथालयों में विद्यार्थियों को कोई लाभ हो रहा हो यह अभी तक सन्देहस्पद है। उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में ग्रंथालयों की स्थिति कुछ उन्नत कही जा सकती है बहुत अच्छी कदाधि नहीं। विश्वविद्यालयीन स्तर पर ग्रंथालयों का व्यवस्थापन संगठन एव संचालन अपेक्षा से अच्छा है। कुल मिलाकर शैक्षणिक-सुविधाओं का अतन्त्र जहाँ भी ग्रंथालय है वहाँ इन ग्रंथालयों का उद्देश्य शैक्षणिक वातावरण को गति प्रदान करना तथा अधिकतम विद्यार्थियों को अधिकतम पुस्तकें प्रदान करने का होता है।

वक्ता अध्ययन के अतिरिक्त पाठ्य सहयोगी श्रियाओं के रूप में ग्रंथालय संचालन विज्ञान के विभिन्न विषयों की नवीन सामग्री छात्रों को अध्ययन हेतु देना तथा वाचनालय में रुचि अनुकूल पत्रिकाओं व पत्रों का प्रदर्शन करना ग्रंथालय की जिम्मेदारी होती है। समस्याओं में जबकभी भी सामान्य ज्ञान सम्बन्धी परीक्षा, प्रतिस्पर्धाएँ, लेखन व साहित्य गतिविधियाँ होती हैं। तब विद्यार्थी अपनी तैयारी हेतु ग्रंथालयों का सहयोग लेते हैं और ग्रंथालय कर्मचारी अपनी पाठकों के लिए उचित सामग्री व सार्वभौम सेवाएँ प्रदान करते हैं। साथ ही विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, कुशल नैतिक, अनुशासन व शैक्षणिक विकास हेतु साहित्य को ग्रंथालय में संप्रतिष्ठित करने व सूचना के माध्यम से उसका वितरण करने का कार्य करते हैं। प्रमुख रूप में ग्रंथालयों के उद्देश्य निम्नानुसार माने गये हैं।

1 छात्रों में अध्ययन रुचि को जगाने में सहायता करना।

2 स्वशिक्षा प्राप्त हेतु प्रशिक्षित करना।

- 3 विद्यार्थियों व पान में पूरक वनकर मदद करना ।
- 4 विद्यार्थियों का सूचना तथा मनोरंजन प्रदान करना ।
- 5 शैक्षणिक कार्य और ग्रन्थालय उपयोग में समय स्यापित करना ।
- 6 सहयोग एवं समन्वय भावना से काम करने की शिक्षा देना ।
- 7 शोध अनुसंधान व सूचना स्रोतों के प्रवाशन में मदद करना ।
- 8 अपनी सेवाओं का प्रचार प्रसार करना ।

उपरिलिखित उद्देश्य ग्रन्थालयों के आचार प्रचारानुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं किन्तु पाठक जब पान पाने की इच्छा रखता है तो उसे उसकी इच्छित पुस्तक मिल जावे और जो पुस्तक ग्रन्थालय में रखी है उसे उसका पाठक मिल जावे तो ग्रन्थालय का उद्देश्य पूर्ण हुआ मानना चाहिए ।

उक्त उद्देश्यों से वचित आज का बालक, किशोर व युवा विद्यार्थी-मानस अमनुष्य है । पुस्तकालय-सेवाओं के प्रति भीतरन विद्यार्थी अमनुष्य परेशान व शिकायती हो गया है । इन कारणों के मूल में विद्यार्थियों पाठकों, प्राध्यापकों एवं ग्रन्थालय-कर्मचारियों को क्या करना चाहिए कि ग्रन्थालय सेवाओं की शिकायतें दूर हों । इन पर क्रमशः हमें विचार करना चाहिए ।

विद्यार्थी क्या कर—ऐसी बहुत सी शिक्षण समस्याएँ हैं जहाँ ग्रन्थालयों का अस्तित्व है ही नहीं । ग्रन्थालय विहीन समस्याओं जैसे प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के अध्ययन कार्य करने की व्यवस्था होनी चाहिए । हालाँकि भारत की ग्रन्थालय संघ 1971 की सूचनानुसार भारत में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ग्रन्थालयों के होने की जानकारी मिलती है, फिर भी यह सन् 70 करोड़ की आबादी तथा 5 लाख गांव वाले देश भारत के लिए पर्याप्त नहीं लगती ।

फिर भी जहाँ पुस्तकालय सुविधा का लाभ छात्र-छात्राओं को मिलता है मिन रहा है ग्रन्थों के आदान प्रदान की सुविधा प्राप्त है वहाँ उन्हें ग्रन्थों का लाभ पान में कदापि संकोच अथवा विलम्ब नहीं करना चाहिए । निःसंकोच अपने अधिकार के लिए ग्रन्थपाल या पुस्तकालयाध्यक्ष से मिलना चाहिए । अपनी समस्याओं (अध्ययन सम्बन्धी) के निराकरण के लिए अपनी शिकायत उनके समक्ष रखनी चाहिए । शिक्षा मंत्रालय एवं बाद में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा लगायी जान वाली समस्त सूचनाओं को प्रतिदिन ग्रन्थालय सूचना फलक अथवा छात्र सूचना पटल पर दर्जते रहना चाहिए ।

ग्रन्थालय सदस्य बनने से लेकर ग्रन्थ निगमन कराने तक जितनी भी प्रक्रियाएँ अपनायी जाती हैं उन्हें भली भाँति पूरा करना आवश्यक है । समय पर माग पत्र (Requisition slip) अथवा अग्रनापणी भरना नहीं भूलना चाहिए । ऐसा करने

से विद्यार्थियों को पुस्तक पाने की पात्रता मिल जाती है और निर्धारित तिथि यी दिनांक को उह पुस्तकें प्राप्त हो सकती है ।

यहा हम एक बात का मुलासा कर दें कि ग्रंथालयों के आकार प्रकार, मग्नह, लेन देन पद्धति व नियमावली के अनुसार ग्रंथालयों की भिन्न भिन्न प्रणालिया हो सकती ह अत इन प्रणालियों से भी विद्यार्थी पाठकों को परिचित हाना चाहिए । आजकल ग्रंथालय पद्धति की जानकारी हेतु भारत के विश्व विद्यालयीन ग्रंथालयों मे सूचना एव अनुदेशन का काय पाठकों को लाभ पहुंचान की दृष्टि से किया जा रहा है । एक मायने में अनुदेशन काय (Instruction work) का उपयोग कर्त्ताओं की शिक्षा (Users Education) का नाम भी दिया जा रहा है ।

महाविद्यालया मे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मे अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के निमित्त देश भर के विश्व विद्यालयों स सम्बद्ध महाविद्यालया मे ग्रंथालया की व्यवस्था की गई है । ग्रंथालय चूँकि अध्ययन को विकसित करने व यत्न अध्ययन मे सहयोगी भूमिका निभाते है अत शिक्षालयों मे इनका होना शरीर मे रीड की हड्डी के होने जैसा है । अत विद्यार्थियों को पूव धारणाओं का त्याग मव-प्रथम प्रवश लेते समय पुस्तकालय सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए । पुस्तकालय नियमावलियों का भली-भाति अवलोकन करें साथ ही पुस्तकालय व्यवस्था से पूणत परिचित हो जायें ।

पुस्तकालयाध्यक्ष को चाहिए कि छात्रों को आवश्यक निर्देश, अनुदेशन एव मागदर्शन द्वारा सहायता करे । सूचीकरण व्यवस्था आदान प्रदान पद्धति, सदस्य तथा सूचना सेवा अतिदेय एव ग्रंथों के नवीनीकरण आदि बातों से अवगत कराए । आम तौर पर प्रत्येक पुस्तकालय एक सप्ताह या पंद्रह दिन के लिए पुस्तकें अध्ययनाय देत है । पुस्तकें प्रदान करते समय पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकों के अग्रिम प्रथवा अन्तिम पृष्ठ पर चिपके देय तिथि पत्रक (Due date slip) पर वापसी तिथि अंकित करते है इस तिथि का प्रत्येक पाठक को ध्यान रखना चाहिए । यदि पाठक देय तिथी मे पुस्तकें वापस नहीं करते है ता उन पर यथा नियमानुसार विलम्ब शुल्क के रूप मे अग्रदण्ड लगाया जाता है ।

विद्यार्थी जब पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने की ले जाते है तो उनका यह कर्त्तव्य होता कि न ग्रंथों का क्षति न पहुँचाएँ ग्रंथों के पृष्ठों को न फाटे, चित्रों का न निकाले, या ग्रंथों पर स्याही अथवा पन्सिल के निशान न लगाये तथा ग्रंथों के पृष्ठों को अपने लिए आवश्यक जानकारी न बाट । उनका यह धम हो जाता है कि पुस्तक जिस दशा मे ग्रंथालय से प्राप्त की है उसी दशा मे पढ़न के बाद वापस करें । विद्यार्थी यदि निगमित पुस्तकों के साथ धमपरायणता व अर्च्छे पाठक हान का परिचय देकर जजर पुस्तकों की देखभाल कर पुस्तकों को जिल्द बांधकर द दत हैं ता यह काय उनका चान के प्रति जगाव व उसकी उपयोगिता का स्पष्ट करता है । अने विद्यार्थी अवश्य अभिवादन व अभिनन्दन के पात्र होते है ।

जिस प्रकार शरीर की सुन्दरता के लिए प्रसाधन सामग्री की खरीद एवं सुरक्षा हम अनिवार्य समझते हैं तदनु रूप ही जीवन की सुन्दरता पुस्तक के अध्ययन, मनन, चिंतन तथा उनके रस-रखाव में निहित है। हमारे शरीर पर मुशोभित होने वाले अच्छे कपड़े हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं वैसे ही ग्रंथों की संगति तथा हमारी बौद्धिक-ऊँचाई बढ़ती है और हम बुद्धि-विवेक के तत्काल वित्त के योग्य बनते हैं अतः ग्रंथों के अध्ययन में उनकी सुरक्षा का ध्यान भी पाठकों को रखना चाहिए। पुस्तक के साथ धोखा करना जीवन के किसी विशिष्ट समय के साथ धोखा करना है।

शिक्षक विद्यार्थी सहयोग—21वीं सदी की ओर बढ़ रहा प्रत्येक छात्र चतुर व विवेकी है, वह अनुशासन, सदैव-व्यवहार सन्तुष्टि एवं आदर्श जैसे शब्दों की मूल अर्थ-चेतना से अच्छी तरह परिचित है, फिर भी वह इनके अनुपालन में जीवन में इतने व्यवहारिक बनाने से बहुत दूर है। जहाँ तक गान-गायन में लक्ष्य का प्रश्न है प्रत्येक विद्यार्थी जिज्ञासु है, औसतन विद्यार्थी चतुर है किन्तु इनके बावजूद वे अपनी बुद्धि का उपयोग शिक्षकों की अनिच्छा उपद्रव, तोड़फोड़ एवं मादक वस्तुओं के प्रयोग में करने लगा है। यहाँ मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं वे पढ़ते हैं, पास भी होते हैं और उनमें बड़े-से-बड़े व्यक्ति बनने की महत्वाकांक्षा भी होती है। किन्तु शिक्षा के मानक-स्तर के प्रतिगत से उन्हें प्रतिष्ठात्मक अर्थ प्राप्त नहीं हो पाता है। पढ़ने के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध होने पर भी वे उसका उपयोग नहीं कर पाते जो करते हैं उनकी बुद्धि उतनी तीव्र व कुशाग्र नहीं होती है जितनी चतुर और शरारती विद्यार्थी की होती है। ऐसे शरारती विद्यार्थी पुस्तकालय से पुस्तकें तब लेते हैं जब परीक्षा का मात्र दायें एक माह बचे रहते हैं। शीघ्रता में पढ़ी गई विषय सामग्री एक दम ही पहल में नहीं उतरती सिर्फ उतनी ही विषय सामग्री विद्यार्थी प्राप्त कर पाता है, जितनी उस पुस्तक में है। चूँकि शिक्षक भी ऐसे अन्तिम समय में छात्रों को उचित सलाह देने में असमर्थ होते हैं। तब सिर्फ सीमित प्रश्न-सामग्री बाजारू नोट्स गाइड्स के आधार पर वे अच्छे अर्थ प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। नक्षाओं में भी वह नियमित नहीं रहता होता है और शिक्षकों का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता है। अतः वह हताश, उदास और पढ़ने से तय आकर फेल हो जाता है। कभी-कभी आत्म-हत्या करने तक को तैयार हो जाता है। ऐसी स्थितियाँ न आने अतः कक्षा अध्यापकों व ग्रन्थालय प्रभारियों को चाहिए कि ग्रन्थालय उपकरणों का वातावरण का शैक्षणिक सुविधाओं के अनुकूल बनाए तथा विद्यार्थियों को प्रेरित करें।

विद्यार्थी द्वारा अनुचित कदम उठाने के पूर्व वित्त का अच्छा होता यदि उनमें प्रत्येक विषय पर सख्तराम ही प्रत्येक व्याख्यान के लिए माह में दो पुस्तकें प्रति अध्याय हस्त-ग्रन्थालय से प्राप्त की जाती। इस तरह मान लो एक प्रश्न पर

की एक पुस्तक में 10 अध्याय हैं तो विद्यार्थी को 20 पुस्तकें एक प्रश्न पत्र के लिए निगमित (Issued) करानी चाहिए। इस प्रकार यदि आठ प्रश्न-पत्र के लिए 16 पुस्तकें ह तो पूरा सत्र में उनके द्वारा 160 ग्रन्थों का अध्ययन किया जाना चाहिए तभी माना जायेगा कि विद्यार्थी न अपनी शिक्षा में अध्ययन को सही रूप में स्थान दिया है और ग्रन्थों के उपयोग को महत्त्व देकर ग्रन्थों की विषय सामग्री से ज्ञानाजन किया है।

ऐसे उद्यमी कार्य हेतु शिक्षकों को वृत्ता अध्यापन के दौरान विद्यार्थी-वर्ग को उचित मार्ग-दर्शना देना चाहिए साथ ही पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा उपयोग कर्त्ताओं के लिए अनुदेशन कार्य (Instruction Work) कर उनकी मांगों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षकों एवं ग्रन्थालयों के कार्य को विभाजित करते हुए एक अनुमोदित तथा वे के तनेजा ने भी स्पष्ट किया है कि वृत्ता-अध्यापन में पूरा के रूप में ग्रन्थालयों को किस प्रकार अपने सहायकों की मदद से छात्रों व प्राध्यापकों को सहायता पहुँचानी चाहिए।

कहा जा तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ग्रन्थों का चयन करने, ग्रन्थों के विशिष्ट विषयों को पढ़ने में शिक्षकों व छात्रों को मार्गदर्शन तो देना ही रहना चाहिए। ग्रन्थपाल व उसके सहायकों का भी विद्यार्थियों की समस्याओं से मुक्त कर उनकी इच्छित पुस्तकों की उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। इस तरह उन्हें बंधन नियमित रूप से ग्रन्थों का आदान-प्रदान व उनकी मार्गदर्शन किया जाना चाहिए तभी उनके शैक्षणिक जीवन में आशा की विररण विकसित हो सकती है।

विद्यार्थी पुस्तकालयाध्यक्ष सम्बन्ध —ग्रन्थों की पर्याप्त उपलब्धता होने पर विद्यार्थियों का ग्रन्थों की विशेषताओं के आधार पर, उनकी अधिकाधिक उपयोग कराना पुस्तकालयाध्यक्ष पर शत-प्रतिशत निर्भर करता है। पुस्तकालय-सूची की पूर्णता, वर्गीकरण प्रणाली को अपनाया जाना तथा स-संवा-सेवा प्रथम अनुदेशन कार्य पर्याप्त ग्रन्थालय सहयोगिता के अभाव में संभव नहीं होता। ऐसे समय में सिर्फ अकेले ग्रन्थपाल को या सहायक ग्रन्थपाल को ग्रन्थों का आदान-प्रदान का कार्य करना पड़ता है। वास्तविक ग्रन्थालय सेवा देने के लिए उपरोक्त सेवाओं का अद्ययन होना आवश्यक है। यदि इनमें से कोई एक भी विभाग का कार्य अपूर्ण रहता है तो स्वयं ग्रन्थपाल छात्रों को उचित सेवा देने में असमर्थ हो जाता है।

ऐसे समय विद्यार्थी-समुदाय को शांतिपूर्ण ढंग से सहानुभूति पूर्वक, सहयोग कर ग्रन्थालय की सेवाएँ व ग्रन्थों का लाभ प्राप्त करना चाहिए। उद्वेगता, उच्छ्वेखलता, तोड़ फोड़, नाग-बाजी या हिंसात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। समझौते व सुनह से काम करना चाहिए। पुस्तकों का प्रदायन कार्य सच पूछा

जावे तो ग्रन्थालय-वर्गीकरण एवं फलक-व्यवस्थापन पर पूरकत निभर करता है। छात्रों को माँग पत्र भरने अथवा ग्रन्थों की जानकारी के लिए ग्रन्थालय सूची का अध्ययन (Uptoditeness of Catalogue) होना भी अत्यन्त आवश्यक है। ग्रन्थालय-सूची की अद्यतनता पर ही पाठकों को ग्रन्थों की वास्तविक जानकारी विदित होगी अतः यदि पर्याप्त कमचारियों का अभाव है तो उनकी पदस्थापनाएँ की जानी चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष को सम्भवतः यह प्रयास करते रहना चाहिए कि समय-समय पर विद्यार्थी-पाठकों को पुस्तकालय में होने वाले रोचक-परिवर्तनों जैसे ग्रन्थों का अद्ययन (विद्यार्थी सहयोग में) नवीन ग्रन्थों का अग्र्य (प्रवेशन द्वारा) सन्दर्भ तथा सूचना विधि लेन-देन का तरीका, नियम-उपनियम सूची व्यवस्थापन फलक व्यवस्थापन एवं सूची का उपयोग आदि कठिनाईयों से अवगत कराते रहना चाहिए। ये सभी जानकारीयाँ प्राप्त करने में छात्रों को सहयोग करना जरूरी है।

विद्यार्थियों को पान-ग्रन्थों को पाने व अपने बौद्धिक होन का परिचय देने में सदैव पुस्तकालयाध्यक्ष के साथ तथा अन्य ग्रन्थालय कमचारियों के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार व आचरण होना चाहिए। गसत हस्तों व अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई ग्रन्थ एक बार दो बार या बार-बार मागन पर नहीं मिलता है तो ग्रन्थालय प्रमुख (Chief Librarian) से व्यक्तिगत सम्पर्क कर पूर्व में पुस्तक को आरक्षित (Reserved) करवा लेना चाहिए।

विद्यालयाँ एवं महाविद्यालयों में होने वाले साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा परीक्षात्मक प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों पर यदि किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार के सन्दर्भ की या सूचना पाने की आवश्यकता होती है और ग्रन्थालय के अन्य ग्रन्थालय-सेवी टालमटोल करते हैं तो विद्यार्थियों को अपनी कठिनाईयों सबसे प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष को बतानी चाहिए तथा अपने अध्यापकों व व्याख्याताओं के सहयोग से समुचित ग्रन्थ पाने का प्रयास करना चाहिए। आज का छात्र जिस तरह शिक्षा-परिसर में भटका हुआ है, वक्षा वक्ष में उबला हुआ है और ग्रन्थालय व खेल के मैदान पर टूटा हुआ है, उसका कारण यह है कि आज न तो उसे शिक्षका द्वारा उचित मार्गदर्शन मिल रहा है और न सही ढंग की वक्षा में पढ़ाई हो रही है। जो कुछ हो रहा है वह स्थानीय-राजनीति (Local Politics) रह गई है। इसी राजनीति के मोहरे ग्रन्थालय व खेलकूद विभाग बन जाते हैं, और पूरे वर्ष विद्यार्थी शिक्षक राजनीति का शिकार होकर अपनी यथाचित सेवायें नहीं दे पाते। परिणाम विद्यार्थियों को भोगना पड़ता है। फिर भी ग्रन्थालयों से जो सेवायें पाना हैं उनके लिए विद्यार्थियों को अपनी मानसिकता (Mentality) को बदलना चाहिए। किसी के बहकाने में न आकर विद्यार्थियों को स्वविवेक से काम लेना चाहिए।

पुस्तकालयाध्यक्ष को भी अपने ग्रन्थालयीन सेवा काय के दौरान नम्र, मृदुभाषी, दूरदृष्टा, शिष्ट, सदाचारी, व्यवहार कुशल, कुशाग्रबुद्धि एवं हँसमुख होना चाहिए। उसमें ऐसे गुण होने चाहिए कि पाठक-विद्यार्थी के ग्रन्थालय द्वार पर हर बार आने पर भी कोई उसका काय से असंतुष्ट न हो उसमें प्रभावित ही हो। यद्यपि यह असम्भव है फिर भी उसे ग्रन्थालय व्यवस्था व विद्यार्थियों के सम्बन्धों में मधुरता लाने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए।

‘योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष वह है जिसे पुस्तक, ज्ञान एवं मानवता से प्रेम है।’³ इसके अलावा उसमें व्यक्तिगत योग्यताएँ आकषक व्यक्तित्व व अपने व्यवसाय का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपने ग्रन्थालय की प्रगतिशील सस्था के रूप में सर्वाधिकार कर सके। उसे विद्यार्थियों से मित्रवत् व शांतिप्रिय ढंग से व्यवहार करना चाहिए और पाठकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे भी पुस्तकालयाध्यक्ष को उतना ही सम्मान दें जहाँ ज्ञान दाता को दिया जाता है। यदि यह गलत धारणा शिक्षकों अथवा विद्यार्थियों के मन में बैठ गई हो कि ग्रन्थपाल अब एक साधारण व्यक्ति है तो ऐसा साचना गलत है। यूँ जी सी ने इस आशंका के समाधान के लिए अपनी अनुशमाओं में साफ लिख दिया है।⁴ फिर भी कुछ परम्परा में बंधे रहे लबादों को छोड़े शिक्षक श्रेष्ठ ग्रन्थपाल व उनके व्यवसाय के साथ सही माप नहीं कर पाते हैं।

इतना होने के बावजूद भी पुस्तकालयाध्यक्ष को पाठकों की कठिनाईयाँ को अपनी कठिनाई समझकर दूर करने का सदैव प्रयास करना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष के कार्यों की सफ़लता अधिकराधिक पाठकों द्वारा अधिकतम पुस्तकों के उपयोग पर निर्भर करती है। उसका लक्ष्य विद्यार्थियों की मांग व पूँति पर केंद्रित होना चाहिए। सन्धा-प्रमुखों का भी इस और ध्यान देना चाहिए। प्रशासकीय स्तर पर ग्रन्थालय सेवा व ग्रन्थपालों के कार्यों को प्राप्ताहित करना ही शार्णिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना होगा तभी विद्यार्थीगण पुस्तकालय का पूरा उपयोग कर शिक्षा में तात्त्विक विकास लाने में समर्थ हो सकेंगे।

उपरोक्त विवचन के अनुसार पुस्तकालय अपनी उपयोगी सेवाएँ बिना किसी भेद भाव के सभी तरह के पाठकों को दे रहे हैं। पाठक एवं अधिकारीगण अपने उत्तरदायित्वा का सफलता पूर्वक निवाह कर रहे हैं, तो यह निश्चित माना जाना चाहिए कि आदकार क्षेत्र में हम प्रकाशमान क्षेत्र की आर वृद्धि रहे हैं। एक सस्था के पुस्तकालय में अपने उद्देश्यों में यदि अत्यल्प भी सफ़लता पा ली है तो यह मानना चाहिए कि वह भविष्य में शिक्षा सस्थान का मवने-व्यस्त और लाभकारी केंद्र साबित होगा। ऐसा पुस्तकालय निश्चित ही प्रशंसा पाने योग्य है, राष्ट्र के लिए गोस्वशास्त्री परम्परा का निर्माण करने में अग्रणी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ —

- 1 I L A, *Bulletin*, Vol XIX, 1—3 April—Dec 1983 P 5
Proceedings
 - 2 I L A *Bulletin*, Role of Professional Assistants in
Academic Libraries, Delhi, Indian Library Association,
Vol XX No 1—2 April—Sep 1984 P 65
 - 3 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचन्द्र) पुस्तकालय संगठन एवं
संचालन, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1978 पृ 31
 - 4 U G C Letter No F 1-6/83 (MP) 28 January
1984 by S K Khanna Secretary, University Grant
Commission New Delhi regarding, Merit promotion
Scheme of University and College, Librarians
-

“पठन-रुचि—पुस्तक मेले एवं पुस्तकालय”

अब क्या / और कस / जैसे प्रश्न चिह्नो के इस देश में किसी समस्या के समाधान के पहले ही पूरा-विराम लग गया महसूस होता है। क्या राजनीति क्या धर्म और क्या नैतिकता सभी प्रगति की चरम सीमा पर पहुँच गये हैं बिना साचे की प्रगतिशीलता के।

पठन पाठन, प्रकाशन तथा पुस्तकालयों के मामले में भी कुछ इसी प्रकार की चर्चाएँ प्रकाशक-जगत पाठक वगैरह बुद्धिजीवियों के माध्यम से चल पड़ी हैं। प्रकाशक इसलिए परेशान हैं कि पुस्तक प्रकाशन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है फिर भी पुस्तकें छप नहीं रही हैं। पुस्तक व्यवसाय चौपट हो रहा है। ग्राम लोगों में पढ़ने की रुचि कम हो रही है, जिसके कारण पुस्तकें खरीदी नहीं जा रही हैं। इसके पर्याय में मैं यह कहना चाहूँगा कि पाठकों में पठन रुचि कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। गम्भीर अध्ययन अथवा सत्साहित्य की पुस्तकें खरीदकर नहीं पढ़ी जा रही हैं बल्कि मत्तलब वदापि यह नहीं है कि पठन रुचि कम हो रही है वरन् कारण तो यह है कि पाठक जिन पुस्तकों को सन्त दामों में खरीदकर पढ़ना चाहते हैं वे पुस्तकें जाने माने प्रकाशकों की सन्त दामों की न होकर बहुत महंगी होती हैं। पुस्तकों के भाव जब आसमान छूने लगे तो पैसे कमाने वाले व्यावसायिक प्रकाशकों ने ऐसी-ऐसी पुस्तकों का, पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया जो कम मूल्य व आसान किशोरावस्था पर भी उपलब्ध होना लगी हैं ऐसी पुस्तकों के बार में सारिका के माध्यम से सुरेश कुमार लिखत हैं “रत्न में सफर करते हुए वस्तु कान्ते के लिए सन्त किस्म की जासूसी व रहस्यमयी पुस्तकें काफी उपयोगी होती हैं पर इन पुस्तकों को पढ़ते देव वर कोई नहीं कहता कि आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं।” पुस्तक अच्छी हो या न हो परन्तु पढ़ी गई हो तो यह कहा जाना कि पठन रुचि कम हो रही है पुक्ति सगत नहीं लगता। हा एक बात जरूर हुई है कि 90 पैसे की पुस्तकें उक्त किस्म की घर-घर में पढ़ी जा रही हैं, बिक रही हैं। ऐसी पुस्तकें जिनका धूम-धाम में न प्रचार होता है न विज्ञापन और न ही जिनके मेले लगते हैं, परन्तु हर ऐसी पुस्तक जो पाठकों का माहित कर रही है छुप छुप कर चन्दे से पढ़ी जाती है। इस दशा में प्रकाशकों का यह सावना कि पठन रुचि कम हो रही है बेमानी लगना है। ये पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ भी प्रकाशकों के ही भाई-बन्धु-रिश्तेदार प्रवाहित कर रहे हैं। तब एक ओर सत्साहित्य की कम बिक्री का, दूसरी ओर पठन रुचि के कम होना तो रोना क्यों रोया जा रहा है। क्यों नहीं ऐसी पुस्तकों पर प्रकाशक सघ

वर्दिश लगाता जिनसे प्रवाशन बदनाम हो रहा है, पाठना की अध्ययन रुचि भी त्रिगड रही है, उनके अध्ययन से नैतिक व चारित्रिक पतन घा रहा है और राष्ट्र की बहुत बड़ी जनसंख्या घटिया विस्मय व ग्रंथ अध्ययन का शिवार होकर गुमराह हो रही है।

यदि पुस्तक मूलों में व शासन से प्रकाशक अपनी बर्बादी का डोल पीट रहा है तो उमरे पहले उन्हें उन प्रकाशकों का तथा उन लेखकों को पुस्तक छापन में रोक्ना चाहिए जिनका पढ़न से हर परिवार में जहर फैलता जा रहा है। यही कारण है कि महाविद्यालय एवं विश्व विद्यालय पुस्तकालयों में भी बहुत प्रतिष्ठित युवा विद्यार्थी सबसे पहले बिनाद, बिश्रान्त, मनाज की उपयोग सौरीज व फिल्म पथर, माधुरी चित्रपट सिनेस्कोप जमी पत्रिकायें पढ़ने में अधिक रुचि रखते हैं। ऐसा साहित्य पुस्तकालय से नहीं मिलता है तो विद्यार्थी निजी लायब्रेरी से किराये से लेकर महाविद्यालय बम्पस में पढ़ते हैं। पुस्तक सत्कृति का यह स्तर है।

बढ़ने का तात्पर्य यह कि प्रत्येक शहर में पठन रुचि की प्रगति देखनी है ना हमका बर्माई के उद्देश्य से खोले गये छोटे छोटे निजी पॉकेट-बुकस पुस्तकालय जो हर गली मोहल्ले में आपका मिलेंगे, वहां महसूस कर पायेंगे। इनकी संख्या सिर्फ दो-चार तक हो तो भी मान लें, लेकिन इनकी संख्या संकटों में होती है। इनसे प्रतिदिन पढ़ी जाने वाली पुस्तकें व पत्रिकाया की संख्या भी हजारों में होता है। यह स्थिति है शहरों की। गांवों में भी इनका चलन बढ़ रहा है यदि गांवों में ऐसे फूहड़ प्रकाशनों की भीड़ व्यवसायिकता बनकर ग्रामालयों की धरोहर बन गई तो, गांव-गांव नहीं रहे पायेंगे और फिर प्रकाशन जगत का गम्भीर साहित्य के प्रचार प्रसार का सपना टूट जायेगा। बेहतर यह हो कि इन पर राक लगे, साथ ही गम्भीर साहित्य के प्रचलन हेतु उनकी कीमतें इतनी हो कि सामान्य पाठक अपनी रुचि के ग्रंथों को नियमित रूप से प्रकाशक से या ग्रंथ ग्रंथ विक्रय केन्द्रों से खप धरन में सामयिकान हो सके।

पुस्तक मेंले ग्रंथया बुक-बाजार निस-दह पाठकों में अध्ययन रुचि को बढ़ाने की ओर एक अच्छा प्रयास है परन्तु इनकी साधकता फलीभूत तभी मानी जा सकती है जब इन मेंलों में पाठना की भीड़ मधुमक्खियों का उमड़ पड़े प्रदूषित पुस्तकों हाथा हाथ बिके। लेकिन यह होता नहीं है उसका एक ही कारण है पुस्तकों का अधिक कीमतों में होना। पुस्तक की कीमतें बढ़ने व सम्बंध में भी प्रकाशकों को कई दलीलें हैं।

पुस्तक प्रकाशक बागज की महगाई को भी बीच में ले घाते हैं। मैं पूछना है क्या महगाई हमानी तिलस्मी, जासूसी, सेक्स, फिल्मी व युवा भटकाव को गलत दिशा देने वाली पुस्तक व पत्रिकाया के छापन वाला के लिए नहीं होती है। हाती है, फिर भी नावा के सम्करण के लिए इनके पास कहा से बागज पैदा हो जाना है। इसलिए बागज महगाई की बात करना बमानी है, इसके अतिरिक्त कोई बात

जबर है जिसके कारण अच्छी पुस्तकें महंगी हैं, और महंगी होने से पाठक की खरीद शक्ति से दूर है। अभी तक हमने लोगों में पठन रचि कम होने के कारणों की व्याख्या की, पुस्तकों की बिजली न होने की बात की तथा उनकी कीमतों के अधिक होने की चर्चा की। यथा शक्ति मैं निदान के तक भी प्रस्तुत किया। अब ग्रन्थालय व्यवसायी होने के नाते पुस्तकालयों के माध्यम से पठन रचि में इजाफा, बिजली में तरक्की एवं पुस्तक-व्यवसाय में पुस्तकालयों के योगदान पर भी चर्चा कर ली जाय।

स्पष्ट रूप में यह बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि उच्च स्तरीय-साहित्य, गम्भीर साहित्य अथवा ज्ञान-धाराओं के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विविध प्रकार का विषयगत साहित्य जब रोजमर्रा के जीवन में पढ़े जाने वाले तथाकथित साहित्य के प्रभाव के कारण बाजार में नहीं बिक पाता है तब ऐसी पुस्तकों का एकमात्र खरीददार पुस्तकालय होता है। यदि ये सस्ती रहें तो निश्चित ही पाठक इनको खरीद सकते हैं परन्तु महंगी होने के कारण शासकीय खरीद में आ जाती है।

ग्रन्थालयों में आने के बाद खरीदी गई पुस्तक पाठकों के अध्ययनाथ कब तक पहुँच पाती है यह ग्रन्थालय सेवा की तत्परता पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह कि भारत के ग्रन्थालय आज उतने समृद्ध एवं विशाल नहीं हैं जितने अमेरिका के स्टडियम। यदि इतने बड़े ग्रन्थालय हो जायें तो मास्को, लंदन एवं अमेरिका की लायब्रेरी ऑफ कांग्रेस से बड़ी बड़े ग्रन्थालय हमारे देश के हो जायें। उनसे कहीं बँकर पढ़ने वालों की तादाद हमारे देश में है और प्रकाशन के क्षेत्र में पहला स्थान भारत का ही हो।

कहने का मतलब यह कि प्रकाशन में जो बढ़ोतरी छपन में दिखाई है वह हमारे ग्रन्थालयों के विकास में नहीं दिखाई। परिणाम यह हो रहा है कि वे सभी पुस्तकें जिनके पाठक हैं, अनुदान के अभाव में, स्थान के अभाव में, सुरक्षा के अभाव में खरीदी नहीं जा सकती। फिर हर छपी पुस्तक को ग्रन्थालय खरीदने में समय भी नहीं होता।

इसके आगे ग्रन्थालयों की अपनी कुछ सीमाएँ हैं। शिक्षण-संस्थाओं के ग्रन्थालयों में सिर्फ पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पुस्तकें ही अधिक रुच की जाती हैं। इसमें भी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक वे ही पुस्तकें मकलित करते हैं जिनकी नमूने की प्रति उनके पास पहुँचती है और दूसरी जो उनके विषय की होती है।

पुस्तकालय की गरिमा में चार चाद लगाने की तमन्ना व अच्छे सग्रह की कल्पना ग्रन्थपाल करता भी है और नव प्रकाशित ग्रन्थों की सूची बनाकर प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत भी करता है ता बीच में विषय शिक्षक से पूछो वाला प्रश्न उठ खड़ा होता है। मतलब यह कि ग्रन्थपाल की अधिकार ही नहीं होता कि वह अपनी इच्छा से कोई खरीद कर सके। कुछ अपवादों का छोड़कर सभी जगह यह स्थिति है।

ग्रंथालय भी मगह मे घनगन नम बने । सावजनिक ग्रंथालयों में केनेय तरीक होनी ह । वहाँ ग जा आ गया उही रखना पाना है भले हो ग्रंथालय में पहुँच स य ग्रंथ उपस्थित ह । दूसरे प्रकार क सावजनिक पुस्तकालय य हैं जिन पर न शासन का अकुण है न जनता की जवदस्ती । गमाज सवा के नाम पर जितनी सम्पत्ती में सम्पत्ती अधिकतम रमीशन पर पुस्तकें मिलती ह उह मनीद लिया जाता है ।

पाठकों की पठन रुचि की आर तीनों ही प्रकार क (शिक्षा सम्बन्धी, साव जनिक निजी पुस्तकालय) ग्रंथालय स्थान नहीं देते हैं । य ग्रंथालय कोई ऐसा कायस्थ ग्रंथालय सवा काय नहीं करने जिनमे ग्राम लोगो में पढ़ने की रुचि का जाग्रत किया जा सक । इस दृष्टि में पुस्तक, मेल हो बहुत अच्छे माध्यम है वगैर पुस्तकें सस्त दामों में ग्रहण को प्राप्त हो सके ।

पठन रुचि में पिछड़ेपन का एक और बहुत बड़ा कारण स्वाधीनता के बाद ग्रंथालयों का विकास बिस्तार एक उनकी उपयोगिता पर ध्यान नहीं दिया जाता रहा है । परिणाम यह हुआ है कि देश की जनता सही समय पर ग्रंथालयों का लाभ न बचिन रही और जब ज्ञान-मामग्री बाजार में खुले रूप में मिलने लगी तब तक वह महगी हो गई । अर्थात् दाना ही स्थितियों में य ता चाह तर भी पाठक पुस्तकें पढ़ नहीं पाया । इस बीच सिनेमा के प्रसार, फिल्मों पत्रिकाओं का प्रकाशन एक जामूनी उपयासों का प्रेम का रोमान की कथा पुस्तकों ने पाठकों का मन अपनी ओर लीक लिया । विज्ञान का भौतिकता की प्रगति न पाठकों का भी प्रगतिशील बना लिया साथ ही चान विरम के साहित्य न अच्छा खासा मनोरंजन बँट-ठाले द दिया । सरकार की विकास योजनाएँ चलती रही और तब तक ग्रंथालयों का ग्रामीण बाव न लयो पर ध्यान नहीं दिया गया, जब तक कुटित साहित्य जन जन की रुचि का विषय बन गया जा अच्छी पुस्तकें थी व सिफ ग्रंथालयों तक सोमित रह गई । पिछले एक दशक में जो प्रकाशन में वृद्धि हुई है उसका अनुरूप में आज भी ग्रंथालयों का बिस्तार नहीं हो पाया है ।

जिला ग्रंथालयों की गाव गाव डिपोजिटरी केन्द्र गोलने का उहे सत्साहित्य पहुँचाने की यात्राएँ विचाराधीन है परन्तु आर्थिक मदद का अभाव में यह काम भी नहीं हो रहा है । महाविद्यालयों के ग्रंथालयों में विद्यार्थियों की संख्या का माग निमा निन प्रगती जा रही है किन्तु अच्छा मगह होने पर भी यथोचित कमचारियों का अभाव में उह पयाप्त पुस्तकें का अध्ययन के सुअवसर नहीं मिल पा रहे हैं । ग्रंथालयों का पाठ्य रीटिंग रूम का अभाव प्रदर्शन कक्ष का अभाव अनभारियों की कमी का स्थान की अनुपयुक्तता के कारण ग्रंथों के उपयोग का उनके पढ़े जाने का अनुपात कम होता जा रहा है । परिणाम स्वरूप विद्यार्थी, ग्रंथालय सेवाओं की कोसत हुए बगैर सटा करत जुत्स निवालत ह, और अन्त में नोटस का ग्राइड बुक्स में पढ़कर परीक्षा पास कर लेत ह । यह है आज की शिक्षा का चित्र । जब नोटस ग्राइडस का

गम पत्रम के अध्ययन में 60 से 70% तक परीक्षा उत्तीर्ण की जा रही है तो विषयो पर निखी जान वाली, प्रकाशित होने वाली और उनकी भी सहायक पुस्तको के रूप में अपने वाली पुस्तको का बौन खरीदकर पढेगा। जब छात्रों की जानाजन की उम्र में यह स्थिति है तब ग्राम जनता क्यों इन सब चक्करों में पड़ें। ऐसी स्थिति में किसी समस्या का हल ढूँढना रत में पानी निकालना जैसा है।

किसी की चिन्ता तथा पठन रात्र का अभाव ये ही प्रकाशन जगत के चिन्तनीय विषय हैं जिनका हल हम तीन तरह से योजन में सफ़्त हा सकते हैं।

(1) बाजार साहित्य के प्रकाशन पर सेंसरशिप हो।

(2) अच्छे साहित्य का रियायत पर कागज उपलब्ध कराकर सस्ते नामों में छपा जाव।

(3) ग्रामवासियों का जाल गावा से राष्ट्रीय पुस्तकालय तक पहुँचाया जावे जिनका संचालन प्रशिक्षित विषय के ज्ञाता ही करें।

उपरोक्त तीनों समाधानों में मध्य में अनेक और समस्याएँ उठ सकती हैं जैसे नेलक की रायल्टी प्रकाशक को घाटा तथा नये ग्रंथालयों की खोलन पर हान बाला खर्च इनमें से देश के हित में कुछ अक्ष कुतानी करनी होगी। यदि हम सिर्फ खेनकूद के नाम पर अरबों रूपया खर्च कर स्वास्थ्य लाभ करने की बात कर सकते हैं तो बड़े का अप्रावृत्तिक व अमानवीय साहित्य जो मानसिक भटकाव, तनाव एवं दुवतता का कारण है। क्या हम इन समाज के दीमकों को सदा के लिए नमाम्त नहीं कर सकते। कर सकते हैं। इसमें हमें थोड़ी कठिनाई जरूर आयेगी किन्तु उन कठिनाइयों के दूर हान पर हमारी सम्पूर्ण मनोकामनायें हमारे पश्चानाप हमारी कुठायें सामा य रूप में फलत फलत दृष्टिगोचर होगी।

इस बात की हमारे देश की गज सग्न आवश्यकता है। गलत जा नी हा रहा है, वह होता चला जा रहा है उस पर न कोई अकुश है और न ही इस आर कोई माच रहा है। नही माचन आर साचकर भी अकुश न लगा पाने का परिणाम है समस्या दर समस्या राष्ट्रीयता में उलझाव जीवन में अनिश्चितता, वत्त ध्या के प्रति अकम्प्यता।

भारत के जो पाच सात लाख गाव हैं उनमें राष्ट्रीय ग्रंथालय नीति के माध्यम में सस्ता और अच्छा साहित्य खप जाये तो पठन रात्रि स्वतः स्फूर्त होगी। ग्रंथालयों में खरीद होगी, सस्ते नामों की पुस्तकें पढ़ने वाला पाठक खरीदगा भी, तब प्रकाशकों की शिकायत भी दूर होगी, और समस्या का निदान भी सुगमता से होगा।

वैचारिक क्रान्ति बनाम बुक माइण्डेडनेस

पुरतका को गाँवों तक पहुँचाना वैचारिक क्रान्ति की महत्वपूर्ण गत है—

भारत में आज भी 30 प्रतिशत लोग ही साक्षर हैं शेष 70 प्रतिशत निरक्षर हैं, कम पढ़े लिखे हूँ जो अधिकतर ग्रामों में वास करते हैं किन्तु पढ़न में अत्यंत रुचि रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों तक राष्ट्र में प्रकाशित साहित्य की जानकारी पहुँचाने, उनमें अध्ययन की रुचि उत्पन्न करने का एक प्रयास विगत पाँच वर्षों में किया जा रहा है इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिलेगा, पुस्तक प्रकाशन एवं साहित्य के प्रचार-प्रसार में प्रतिष्ठात्मक मूल्य कायम होगा इहाँ कुछ मूलभूत तथ्यों को लेकर भारतीय पुस्तक प्रकाशन महासंघ एवं पुस्तक विक्रेता महासंघ, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक वास के सहयोग से प्रतिवर्ष देश के बाने-बाने में (महानगरों) पुस्तक प्रदर्शनीयाँ 'गल पुस्तक' मेले आयोजित करत आ रह ह ।

भारतीय परिप्रेक्ष्य इन योजना, प्रदर्शनियों का महत्व तभी है जब प्रत्येक पाठक को अपनी इच्छित पुस्तक पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके पर स्थिति यह है कि आधी से अधिक आबादी प्रकाशित साहित्य से अछूती और अनदखी रह जाती है ।

यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय विचार मंच का यह नारा कि "पुस्तकें सबके लिए हैं" व्यक्ति-विकास का अनिवार्य सूत्र है इस सूत्र के प्रथम उद्घोषक स्व डा एस आर रंगनाथन थे पिन्का सपना या कि इस सूत्र के माध्यम से पुस्तकें घर घर पहुँचायी जाना चाहिए ताकि उसको सही पाठक मिले, सही उपयोग हो ।

पुस्तक प्रकाशन पिछले दस वर्षों में बहुत बढ़ गया है फिर भी ग्रामों का खपत एवं प्रयोग उम सादास्य में नहीं हो रहा है जितनी मात्रा में एक विचारवान व अध्ययनशील पाठक को उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है । भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण एवं 20 प्रतिशत शहरी जनता का सामयिक विषय की तुला में तौल तो परिणाम यह निकलेगा कि केवल 20 प्रतिशत लोग ही पुरतकों का वास्तविक उपयोग करने वाले सिद्ध होंगे । ग्रामीण क्षेत्रों के पाठक तो ध्यास ही रह जात हैं । इसका प्रमुख कारण गाँवों में पुस्तकालयों एवं अध्ययन स्थलों का न होना है, यह वास्तविकता है कि जब 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के जन सामान्य के लिए पुस्तकालय नहीं है तब वहाँ पुस्तकें कैसे पहुँचेंगी और उनका अध्ययन कैसे हो पायगा ऐसे समय निश्चित ही ग्राम लोगों के लिए प्रकाशित की गयी सामान्य पुस्तकें प्रकाशकों व पुस्तक विक्रेताओं के लिए एक व्यापारिक अडचन बनकर रह जाती होगी । इस तथ्य से बचने व अधिकाधिक पुस्तकों का प्रचार प्रसार एवं व्यापार करने,

प्रवाशन श्रमता वद्वान क साध-माथ राष्ट्र की जनता म वैचारिक क्रांति लान तथा उह "बुक माइण्ड" बनान क लिए आवश्यक हागा दश म पुस्तकालयो का विस्तार प्रचार एव प्रसार । यद्यपि पुस्तक-व्यवसानिया द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी प्रादि निश्चित ही पुस्तक प्रचार प्रसार के अछुद माध्यम है किन्तु सभी क द्वारा सभी पुस्तकें नही पारीदी जा सकती । अत एम पाठको को पुस्तकालय सुविधा दी गयी है । इसकी साधकता इसी म है कि पुस्तका की पूर्ति सभी प्रकार क पुस्तकालया म की जायें ।

नवविचारधारा है कि ग्रामीण भारत को आधार बनाकर गाव-गांव मे पुस्तकालया को इस प्रकार का साहित्य पहुँचाया जायें तो प्रत्येक पुस्तक ग्रामी पाठक का पुस्तक मिलेगी । मजदूर कृषक बच्चे य म्मियाँ सभी इह पढ़ेंग तथा जो निरक्षर है उह पठकर सुनायेंग ता निश्चित रूप स एव शैक्षणिक प्रगति तैयार होगी । आज एम साहित्य की महती आवश्यकता है जो डाइग रूम स निकलकर धान धोर गन्ना के खेतो क साथ सहलहाता हुआ चले । गावो म मेल उत्सव एव राष्ट्रीय पर्वो पर पुस्तक प्रदर्शनिया का आयोजन होगा तो ग्रामीण पाठका म सहज ही पठन की रुचि जगगी । ऐस उपयोग गी जाने वाली पुस्तकें ग्रामीण विकास कायद्रमा पर कृपि एव उद्योगो के तौर तरीको पर प्रकाशित की जानी चाहिये ।

गावो म चल रह शिक्षा के द्रा की दशा भी कोई खास अच्छी नही है । 'दिनमान' म प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार 60 प्रतिशत ग्रामीण स्कूलो म पुस्तकालय है ही नही और जो हैं भी, वे या तो भालमारी एव सन्तूक म बद हैं या फिर सीनन भरे कमरो म पुस्तकें सड़ रही है । एसी दशा म न तो विद्यार्थियो म पुस्तक पठन के प्रति उम्रता होनी है और न ही पुस्तका का उपयोग हो पाता है ।

ग्रामीणा की पठन की स्थिति को हम बुद्धिमान कहलाने वाले लोग हास्यास्पद कहत हैं । सिफ यह कहना कि ग्रामीण क्या पढ़ेंगे और क्या करेंगे से काम नही चलता । आज बल्लत सन्धो म हम उनकी अध्ययन रुचि को उनक कृपि एव उद्योग विकास को, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकताओ को ध्यान म रखत हुए पुस्तकें न तब पहुँचानी होगी ।

देश के एक प्रसिद्ध प्रकाशक का कहना है हम सिफ 20 प्रतिशत शहरी लोगो का ध्यान ही नही रखना है वरन् उन 25 करोड लोगो को भी समना है जा अशिक्षित है, साथ ही व 80 प्रतिशत ग्रामीण जन जो यथाचिन साहित्य क प्रकाशित होन पर भी पुस्तक पढ़ने से वचित रह जात है । एम म समग्र ग्राम विकास योजना कृपि म प्राधुनिकता, उद्योगो म ग्रामीणीकरण, विज्ञान एव तकनीकी म जोर अनुसंधान को राष्ट्रीय कायद्रमा क रूप म अग्रत मयाथा जा रहा है । सभी वृत्त वक ग्रामीण विनाम कायद्रमा क रूप म मार्ग ज्ञान का ऋण दे रहे है ।

समय में आर्थिक सामाजिक सम्पन्नता के साथ ही वैचारिक क्षमता का होना युवाओं के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य जान पड़ता है। इसके लिए उन्हें 'बुक मण्डल' बनाया जाना चाहिए तभी उस सत अमृत का निगम करने में समय हो सकेगा। यह सुविधा पुस्तकालयों व माध्यम से उन्हें प्राप्त होगी।

1972 एवं 1976 में प्रथम एवं द्वितीय विश्व-पुस्तक मेल का आयोजन कर अखिल भारतीय पुस्तक सघ पुस्तक विक्रेता सघ एवं पुस्तक व्यास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है फिर भी उपराक्त मना से सतापजनक प्रगति नहीं दिखाई गी। राष्ट्र भाषा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को जन-जीवन तक पहुँचाने का अभी तक पुस्तक मेल सर्वोत्तम माध्यम रहे है, लेकिन इससे कहीं बेहतर तरीका ग्राम-ग्राम, नगर-नगर में पुस्तकालयों के निर्माण में निवाला जा सकता है।

वैचारिक आति फैलाने व लोगो को पढ़ने के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय-पुस्तक व्यास ने जो विचारगोष्ठी आयोजित की, इसकी कुछ सस्तुतिया इस प्रकार हैं —

- 1 ऐसे प्रभावी पुस्तक समाज के विकास की महती आवश्यकता है, जिसमें लेखक प्रकाशक, बुद्धिजीवी और सरकारी एजेंसियों पठन रुचि को बढ़ावा देने में परस्पर सहयोग कर सकें।
- 2 महाराष्ट्र का अनुसरण करते हुए पदयात्राएँ आयोजित की जानी चाहिये और पुस्तकों की जनता के घरो तक पहुँचाया जाना चाहिये। इन यात्राओं में ग्राम-ग्रामों में पद यात्राओं का आयोजन सरकारी एजेंसियाँ करें और लेखक प्रकाशक और बुद्धिजीवी उनमें भाग लें।
- 3 सरकार पुस्तक मेलों और पुस्तक समारोहों के लिये पर्याप्त समय रहते हुए पुस्तकालयों का अनुदान स्वीकृत कर ताकि वे अपनी आवश्यकतानुसार पुस्तकें खरीदने में उन अवसरों का लाभ उठा सकें।
- 4 सामान्यतः समाचार-पत्रों में विशेषी पुस्तक की समीक्षा की जाती है। भारतीय पुस्तक की समीक्षा भी होनी चाहिये। इसी प्रकार नाटक एकांकी एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम यद्यपि हिन्दी एवं अन्य भाषाओं में होते हैं, फिर भी कदल अंग्रेजी पत्रों में ही उनकी समीक्षा छपती है। भाषा पत्रों को भी ऐसी समीक्षाएँ छापनी चाहिए। दूरदर्शन और आकाशवाणी को भी नई पुस्तकों के प्रकाशनों की ओर ध्यान देना चाहिए।
- 5 शिक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय पुस्तक मण्डल को पुनर्जीवित करने के अविलम्ब कदम उठाने चाहिये। सरकार का एक सुरपट्ट और निश्चित पुस्तक नीति पुस्तकों के मूल्य का नियंत्रित करन के लिए बनानी चाहिये और प्रकाशन उद्योग के लिए ढाक सुविधायें, रियायती कागज एक्साइज एवं करा आदि के विषय में विशेष उदारता दिखाने जानी चाहिए।

- 6 पुस्तकमनस्कता, पठन रुचि एवं अथ य सम्बद्ध पहलुया के लिए सर्वेक्षण किय जान चाहिये । इन सर्वे रणा के परिणामो को भी सावजनिक र्ग दना चाहिये ।
- 7 पुस्तको के मूल्य कमलिए ऊँचे ह कि वे केवल पुस्तकालयो और शहरी पाठका को देखकर ही प्रफाजित की जाती है । पुस्तकें ग्राम पाठका तक ग्रामीण क्षेत्र म पहुँचे ।

उपराक्त सभी सस्तुतियो के असावा विचारगोष्ठी म भाग लेने वाले सदस्या न अलग से ग्रन्थालया की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया होता तो ग्रन्था की ग्राम जनता तक पहुँच आसान होती । भविष्य मे इस विषय पर भी प्रकाशक, लेखक, बुद्धिजीवी एवं राष्ट्रीय पुस्तक आस सावग, यह अपेक्षा है ।

“ नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित विचारगोष्ठा की सस्तुतिया हिंदी प्रकाशक सघ के मुख्य पत्र हिन्दी प्रकाशक” से अवतरित, 20 (4) जून 1983 पृ 23

दूषित होता पुस्तकीय पर्यावरण

हिन्दी साहित्य के भारतीय मनीषी व महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि 'साहित्य समाज का दर्पण होता है' बहुत हद तक ठीक है। ठीक इस तरह कि प्रस्तुत लेख पुस्तकालय में वही ध्यान पायेगा और लोग इसे पढ़ेंगे तो पायेंगे कि एक समय ग्रन्थों की दुर्गवस्था इतनी गिर गई कि आश्लील ग्रन्थों, पत्र पत्रिकाओं में जन जीवन के विचारों को भी दूषित कर दिया। अच्छे ग्रन्थों की खरीद, उनका अध्ययन एवं उनका संग्रह बन्द सा हो गया। कारण खोजने पर पता चला कि प्रदूषित साहित्य ने श्रेष्ठ साहित्य का चलन से बाहर निकाल फेंका।

अथशास्त्र में मुद्रा का एक सिद्धांत है कि अच्छी मुद्रा, खराब मुद्रा को चलने में बाहर कर देती है या जब सिक्का घिसघिसकर चलने के बाहर हो जाता है तो उसका मूल्य खत्म हो जाता है परन्तु ग्रन्थों के मामले में एकदम विपरीत हो रहा है। घटिया साहित्य रोजमर्रा की जिंदगी का भ्रम बन गया है और अच्छा साहित्य कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। ऐसा क्या हो रहा है यह विचारणीय प्रश्न है और समाज के पतन का ज्वलंत कारण।

पढ़ने वाले भी यह भलीभांति जानते हैं कि सस्ते साहित्य और काम चलाऊ मनोरंजक ग्रन्थों से बौद्धिक विकास या नानाजन के नाम पर कोई उपलब्धि नहीं होगी फिर भी फैशन के रूप में आज का आम आदमी चलनाऊ साहित्य का ही प्राथमिकता दे रहा है।

भारत के परिवारों में प्रातः व शाम को आरती पूजन बंदन की परम्परा ने यक्ति को धार्मिकता प्रदान की थी, परिणामस्वरूप परिवार के प्रत्येक सदस्य को धार्मिक ग्रन्था, पौराणिक कथाओं एवं महान् चरित्रों को पढ़ने का अवसर मिलता था।

आज के आधुनिक भारत के परिवारों में पूजा वस्त्रों में सीधे टपेरिकाइस, चनत हैं और कुछ पढ़ना ही तो सबसे पहले फिल्मी पत्रिकाएँ निकलती हैं, फिर उपवास, फिर कुछ चटपटा-साहित्य और बच्चों के लिये कामिक्स एवं जामूनी ग्रन्थ व पत्रिकाएँ।

आप किसी बच्चे को कोई गाना गाने को कहिए तो वह फटाफट किन्मी गाना सुना देगा परन्तु उस उम्रकी बच्चा में चलने वाली पुस्तक में से कोई गीत अथवा कविता सुनाने को कहिए तो वह नहीं बता पायेगा। आप बिशोर एवं युवा विद्या यियों में दिखें व किन्हा महान् हस्तिया व बारे में पूछें तो वे आश्चर्य की आरंभ करने लग पायेंगे, परन्तु किन्मी फिल्मी हारो अथवा हीरोइन के बारे में पूछियें तो पता

फट उनकी नाम, उनकी उम्र तथा उनकी फिल्मों के नाम बता दग । उपरोक्त दोनों प्रकार के लक्षणों से यह बात हा जायगा कि व्यक्ति की रुचि और उसका बौद्धिक भुकाव किस ओर है ।

कई बार इस प्रकार के इंटरव्यू एव रिपोर्ट्स पत्र एव पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं जिनमें अश्लील साहित्य के प्रति खेद प्रकट किया जाता रहा है । सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि फिल्मी पत्रिकाओं अपराध कथाओं, जासूसी कहानी व रहस्य कथा विशेषांका व अध्ययन से कई लोगों ने अपना जीवन बरबाद कर लिया । सबसे एव गन्दे साहित्य के प्रचार-प्रसार ने व्यक्तियों की मानसिकता को कुठाप्रमत्त बनाया है, कुत्सित विचारों एव अपराधिक वृत्तियों से ग्रसित किया है ।

अमेरिका में अश्लील साहित्य व फनते जहर के खिलाफ जनमोर्चा बनाकर जनता कुत्सित व भ्रमज का पतनो मुख करने वाले प्रकाशित साहित्य, वीडियो टैप कैसेट व लघु फिल्मों के खिलाफ आंदोलन करने लड़का पर निराल पड़े हैं । हमारे देश में भी नारी मुक्ति आंदोलन, नारी स्वातंत्र्य मोर्चा एव नारी शोषण के खिलाफ महिला संगठन न क्रान्तिकारी कदम उठाए हैं । विनापना में नारियों के शरीर का नग्न प्रदर्शन व पत्रिकाओं में देह व्यष्टि का मोहक चित्रांकन पर आपत्ति उठान में भारतीय नारियाँ भी अब पीछे नहीं हैं । यहाँ तक नारी अंग पतन के सम्बन्ध में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित चित्रा पर समद में भी कई बार सम्भोर बहस चली है । परंतु फिर भी यह नग्नता सही गई है । विनापना में नारी देह की नग्नता पर प्रहार करनी हुई नीलम लूथरा लिखती है 'साडिया ॥ विनापन में एक से एक सुंदर लड़की दिखाई दमी मगर बिना ब्लाऊज के केवल साडी लपेटे भद्र नग्न अवस्था में । साडी के साथ अगर ब्लाऊज भी पहना दिया जावे तो क्या साडी के विनापन में कोई कमी आ जाती है किंतु उह ता (उत्पादकों का) केवल नारीदेह को ही प्रदर्शित करता है वस्तु चाह किसी भी हो ।

यही हाल उन प्रकाशित चर्चित उपन्यासों के बारे में कहा जा सकता है जिनमें मुख पृष्ठ पर नग्न नारी की भासन देह को स्पष्ट करता उपन्यास नायक का बलिष्ठ शरीर खुला दिखाया जाता है । ऐसे चित्रों का देखकर ही सदैव मन स्थिति से गुजर रहा पाठक सोचता है कि ऊपर इतना दिलकश चित्र दिया हुआ है तो भ्रंश और भी बहुत कुछ सेक्स युक्त प्रसंग होंगे । इस विचार का आचरण पाठक को ऐसे चित्रों से युक्त पुस्तकों व पत्रिकाओं को खरीद हनु विवश करता है ।

यदि हम कह कि नारियाँ अपनी देह को क्या इस तरह से व्यावसायिकता के लाभ में फनकर अपना अंग प्रदर्शन करती हैं और उह यदि अंग प्रदर्शन में ही आनन्द मिलता है तो फिर वे नारी-मुक्ति की बात क्या करनी है । उन पर होने वाले भावात्मक अपराध के प्रति क्या आंदोलन पर आमादा हा जाती है । महिनार्यें क्या नहीं इन नग, नई व नैतिक पतन के प्रेरक मॉर्निंग, चित्र व

पोस्टरा व उप-यास व कहानी व वृत्तान्त को बन्द करने के सिवाफ लड़ती है। नाम, धन, प्रतिष्ठा और प्रशंसा का लाभ सवरण न कर सकने के कारण शायद यदि अपने शरीर को कमर की परिधि में दबकर विनाशना के माध्यम से समाज में अपने यह सोच को उजागर करती है तो दूसरी ओर गम्भीर साहित्य के अध्ययन और प्रकाशन की हालत इतनी खराब है कि अच्छा साहित्य बाजार में सस्ते मूल्य में उपलब्ध नहीं है, कारण है उनकी माँग कम होना। तभी पिछले दो दशकों में साहित्यिक लेखन की धारा ही पाठकों की रुचि के अनुसार बदल गई है।

व्यंग, हास्य-परिहास, जीवन चरित्र, व्यक्तित्व विश्लेषण, यात्रा सस्मरण एवं रिपोर्टेज से निरन्तर पत्र-पत्रिकाओं के कालम भरत जा रहे हैं। पाठकों की रुचि में आए अनायास परिवर्तन ने जामूसी उप-यास उपराध कथा, सच्ची कहानियाँ एवं यौन साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया। इसी के समानांतर बच्चों के लिए जहाँ राष्ट्रीय धारा एवं वीर चरित्र व प्रकाशनों की भीड़ थी, वही अब कामिक्स, रहस्य-रोमांच व कात्पनिक जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला प्रकाशन शुरू हुआ। इस प्रकार के चटपट साहित्य से गली-गली, नगर-नगर के घरेलू ग्रन्थालय आबाद हो गए। इनकी प्रगति और प्रकाशन जगत पर मण्डरात सबके के कारण प्रकाशकों ने हिन्दी साहित्य के स्थापित प्राप्त साहित्यिक, उप-यासकारों, कथाकारों की रचनाओं को सस्ते कागज व सस्ते मूल्यों के सम्मेलन के रूप में प्रकाशित करना प्रारम्भ किया फिर भी प्रकाशन की विसंगतियों एवं अधकचरे साहित्य को बाजार में बटन से ये रोक नहीं सके। कई प्रकाशकों ने घरेलू साइबरी योजना का लालच देकर गम्भीर साहित्य के प्रचार-प्रसार का प्रयत्न किया। यह प्रयास निरन्तर चल रहा है फिर भी माँग अधिक न होने और गम्भीर साहित्य के दाम अधिक होने में आम आदमी इस सुविधा को नहीं भोग पा रहा है।

ऐसा भी बहुत कम हुआ कि पूरे देश में पुस्तक जाति के नाम पर ग्रन्थालयों के विकास पर विचार किया गया हो। ग्रन्थालय नहीं खुले अतः उनमें पुस्तकें नहीं आ सकी जब पुस्तकें नहीं आयी तो विशाल पाठक मोहल्ले के ग्रन्थालयों से प्राप्त धन की पुस्तक से ही खुश हुए। चलताऊ पठन सामग्री के अत्यधिक प्रचार-प्रसार का परिणाम यह हो रहा है कि लोग सार्वजनिक ग्रन्थालय व शासकीय ग्रन्थालयों के अस्तित्व का क्रमशः भूलते जा रहे हैं। जनता उन्हें ग्रन्थालयों को ग्रन्थालय समझ रही है जहाँ से उन्हें जामूसी, रहस्य, रोमांच, उपराध व सेक्स से सम्बन्धित ग्रन्थ किराये पर पढ़ने को मिलते हैं। मौलिक ग्रन्थ व गम्भीर साहित्य के प्रकाशन में आज का आम पाठक पा रहा है क्योंकि नुक़्कड़ों पर मुली स्टार लायब्रेरियाँ को पुस्तक को स्थान नहीं दे रही हैं। कारण पर ध्यान न दिया जाना है।

मौलिक व गंभीर साहित्य की दशा—आज यह चिन्ता है कि मौलिक साहित्य पढ़ा नहीं जा रहा है न सिर्फ प्रकाशकों की चिन्ता का विषय है अपितु मौलिक लेखन और विशुद्ध चिन्तन से जुड़े रचनाकारों, मृज्जनधर्मिया एवं बौद्धिक लोगों को भी इस बात में बड़ा खोम है कि आज की पीढ़ी मौलिक साहित्य, नहीं पढ़ रही है सिर्फ पका पकाया माल पाकर ही अपने उद्देश्य में सफल हो रही है।

साहित्य प्रकाशन और माहित्य-उपाजन का सबसे अधिक काय शिक्षा जगत से सम्बन्धित है। इस दृष्टि से जो भी ज्ञान पाठ्यक्रम में पनाया जाता है और जिस शिक्षालयों में वक्षा अध्यापन के माध्यम से सिखाया जाता है उसे विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए और समस्याओं के निदान हेतु कक्षा शिक्षक अथवा ग्रंथपाल से सम्पर्क करना चाहिए यह एक बुनियादी बात है। इसी बुनियादी बात को ज्ञान के रूप में प्रदान करने के अवसर देने के निमित्त प्रत्येक शिक्षण सस्थानों में पाठ्यक्रमों, सहायक ग्रंथों एवं ज्ञान विज्ञान की जानकारी से युक्त सद्म ग्रंथों से सुसज्जित ग्रंथालय निमित्त किये जाते हैं। इन ग्रंथालयों का काय विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों को शिक्षण में आवश्यक ग्रंथों को निगमित कर मदद पहुँचाना होना है साथ ही ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तनों की जानकारी आवश्यक सूचना स्रोतों के माध्यम से देना होता है। इतना ही नहीं छात्रों को अनुशासन, चरित्र व नैतिकता के गुणों की शिक्षा देने वाले सत् साहित्य से साक्षात्कार करना भी है। शैक्षणिक संस्कारों से परिपुष्ट करने के उद्देश्य से शिक्षा विभागों में पाठ्यग्रंथों की अहम् भूमिका होती है, लेकिन बौद्धिक सद्भूति को बनाये रखने के लिए पाठ्यग्रंथों के अतिरिक्त अध्ययन की सहायक ग्रंथ-सामग्री का ग्रंथालयों में बाजार में होना आवश्यक होता है। सहायक सद्म सामग्री के रूप में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु ग्रंथ नहीं मिल पाते तो उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि होना मुश्किल होना। अतः शिक्षकों व विद्यार्थियों को नोट्स गाइड्स पर निर्भर न होकर मौलिक ग्रंथों के अध्ययन से जुड़ना चाहिए, मौलिक ग्रंथों का अध्ययन ही शैक्षणिक मूल्यांकन का ठोस आधार हो सकता है।

स्वाधीनता के बाद के 15-20 वर्षों तक इस बात पर काफी कुछ ध्यान दिया गया कि मौलिक ग्रंथों से ही अध्ययन और अध्यापन हो ताकि शिक्षक एवं शिक्षार्थी गंभीर से गंभीर विषयों की गहराई में जाकर उसका पूरा ज्ञान पा सकें। उस वक्त कुन्जी को बुरा माना जाता था और जो शिक्षक कुन्जियों का सहारा लेकर पढ़ाते हैं उन्हें कमजोर शिक्षक माना जाता था। छात्रों में ऐसे शिक्षकों की छवि उज्ज्वल नहीं होती थी। जब किसी कोई विद्यार्थी यदि वक्षा में कुन्जी लेकर आता था तो या तो वक्षा शिक्षक कुन्जी फाड़ डालते या फिर कुन्जी पढ़ने के बावजूद विद्यार्थी को वक्षा से निकाल देते थे। इस प्रकार के अनुशासन में चलने वाली शिक्षा ने मौलिक चिन्तन व गंभीर साहित्य के अध्ययन को जन्म दिया

था किंतु आज हम देख रहे हैं कि नोट्स गाइड्स, गैम पैपर्स, गैजिट व प्रश्न बैंको की पुस्तिका के प्रकाशन ने मौलिक ग्रंथों का चयन से निवाल रखा है। विद्यार्थी तो क्या शिक्षक तक सरल अध्ययन माला व निर्माण में सहयोग कर रहे हैं और बाजार में इन ग्रंथों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता।

परिणाम यह हुआ है कि आज का विद्यार्थी अपने देश, समाज, सभ्यता, धर्म एवं मानव जीवन की बुनियादी बातों से कोसा दूर होता जा रहा है। उसे परीक्षा पास करना होता है ता वह व्याख्यान सीरीज, शोर्सनक्सेज, प्रश्न व रात भर की पढ़ाई से पास होने वाले नोट्स लेकर पढ़ लेता है। शिक्षक भी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकों की प्रश्नोत्तर पुस्तिकाओं से विद्यार्थियों की शिक्षण दे देते हैं और ग्रन्थालया में मौलिक तथा गम्भीर अध्ययन की पुस्तकें रखी रह जाती हैं।

जब प्रश्नोत्तर-साहित्य का युग आ पड़ा है तब विस्मृत और गम्भीर साहित्य अब दुकानों में सजावट व सामान और ग्रन्थालयों में इतिहास व अवशेष मान रह गये हैं। इनकी इस दशा का सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। ग्रंथों का ज्ञान शून्य होकर हम हमारी पीढ़ियों के ज्ञान अपनी मौलिक सामूहिक, साहित्यिक विरासत को खा बैठे और वर्तमान घटिया साहित्य ही ज्ञान के चमकदार हीर बनकर चमकते दिखेंगे।

इस बात से प्रकाशन बग, ग्रन्थालय जगत व बौद्धिक पालन बग निरिक्त ही चिंतित हैं परन्तु क्या करें जैसे जमाने की हवा बह रही है वह भी बहता पड़ रहा है। हमारे देश में कई बार शैक्षणिक परिवर्तन की दिशा में कदम उठाये गये, पुस्तक संस्कृति को प्राप्ति के लिए प्रयास किए गये पर औद्योगिक प्रगति ने देश को विकासशीलता की ओर धकेल दिया, शिक्षा की ऊँचाइयों को छूने में असमर्थ रहे। पाठ्यक्रम केन्द्रित पाठ्यक्रम बन, कक्षा अध्यापक केन्द्रित पाठ्यक्रम बन, स्थानीय बोलियों एवं भाषाओं को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। कम्प्यूटर टी वी व बीटिवि प्रणाली से अध्ययन के अवसर प्रदान किए गए किंतु गम्भीर साहित्य की दायनीय होती दशाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। गम्भीर चिन्तन के साहित्य को ग्रन्थालयों के माध्यम से घर द्वार तक योजनाओं के माफत पहुंचाया जाता तो आज देश का पुस्तकीय पर्यावरण का स्वप्न ही कुछ और होता।

राष्ट्रीय विकास के लिए ग्रन्थालय

ऐतिहासिक परिदृश्य—राष्ट्रीय विकास में ग्रन्थालयों का योगदान का हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पायेंगे कि प्राचीन भारत के ग्रन्थालय^१ भारतीय धर्म, दर्शन, शिक्षा राजनीति एवं समाज-व्यवस्था की सामूहिक विरासत का महत्वपूर्ण केन्द्र थे। मध्यकाल के प्रमुख ग्रन्थालय^{२, ३} ने भी राष्ट्र की तत्कालीन विकसित साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन, कला, वाणिज्य व्यापार एवं शिक्षा की परम्पराओं को उन्नत करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। “आधुनिक काल में वैज्ञानिक आविष्कार औद्योगिक क्रान्ति एवं पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव से शिक्षा एवं ग्रन्थालयों ने नया स्वरूप पाया है।”

प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति को चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ अधिविद्वानों का उल्लेख करना बनाने में ग्रन्थालयों के दुर्लभ-ग्रन्थों ने जो साहचर्य इन विद्वानों को दिया जिसका परिणाम ही था कि स्वर्ण भूमि होने की प्रमिद्धि प्राचीन भारत न पायी थी। भारतीय काव्यशास्त्र, राजनीति, विद्वत्ता, ग्रन्थालय, युद्धकला, नभश्चित्रज्ञान एवं वेद-वेदान्त के इन अंतराष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में भारत के भावी कण्ठधारियों ने अध्ययन अध्यापन का कार्य कर देश के विकास में सहयोग किया। इन्हीं त्यागी, तपस्वीयों एवं निस्वार्थ गुरुओं की कृपा में मानव दैवत्व पातक।

“व्याकरण का जनक पाणिनी, सुप्रसिद्ध राजनीतिक चारणक तथा ग्रन्थशास्त्र का रचयिता कौटिल्य भगवान् बुद्ध का व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक और प्रसिद्ध भारतीय शासक चन्द्रगुप्त और पुष्पमित्र य सभी तक्षशिला की पावन धरती की ही उपज थे।”^४

^१ तक्षशिला का पुस्तकालय, नागार्जुन के “रत्नोदधि” “रत्नसार” एवं “रत्नरत्नक” विद्वत्शिक्षा का ग्रन्थालय, वल्लभी वि. वि. का ग्रन्थालय, नागिया, आदिलपुरी, जगहला सरनाथ, मिथिला, काशी, काशी, कनोज एवं भोज का पुस्तकालय प्रमुख हैं।

^{२, ३} सत शेर निजामुद्दीन औलिया का ग्रन्थालय बलबन के पुत्र शाहजादा महमूद का पुस्तकालय, गाजीपुर का पुस्तकालय, फिरोजशाह के पुस्तकालय, लाहौर, औरंगजेब, हुमायूँ व अकबर द्वारा स्थापित।

नालन्दा में होने साग न बुद्ध प्रसिद्ध शिक्षकों के नाम इस प्रकार गिनाये हैं। (1) चन्द्रपाल (2) धर्मपाल (3) ज्ञानमति (4) श्रीमति (5) प्रभाभिष (6) स्थिरमणि (7) नागाजु न (8) शीलभद्र आदि।²

चूँकि अध्यापन वाय करने वाले शिक्षक आचार्य, भिक्षु धर्म प्रचारक सुधारक एवं पयटक भी होते थे, अतः अपने देश के बाहर जाकर भी धर्म व शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। इसी प्रभाव के कारण ही देश के इन विश्व विद्यालयों में "उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न केवल भारत के विभिन्न भागों से बल्कि विदेश, जहाँ तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, बर्मा, सुमात्रा, जावा, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों से भी विद्यार्थी नालन्दा विश्वविद्यालय में आते थे।³ इस प्रकार मध्य सभ्यता की वृत्ति से भारत आने वाला मे चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान 'विनय पिटक' की प्रतिर्था लेने भारत आया। ह्यू के शासन काल में ह्वेनसांग भारत आया। सातवीं शताब्दी में इस्लाम चीन से भारत आया, इन विद्वानों ने बौद्ध विहारों में रहकर विश्व विद्यालयों में जाकर बौद्ध धर्म और साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन काल में अनेक पुस्तकें व हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह किया। जब लौटे तो असंख्य मूल ग्रंथ व अनुवाद कर अपने-अपने देश ले गये। ग्रन्थालयों का बर्भव ग्रंथों के आने से समाप्त प्राय होता गया।

इन सारे विश्वविद्यालयों का पतन बाबर हुएणों, अरबों, एवं मुसलमानों के आक्रमण के साथ हो गया। नालन्दा मन्त्रालय के पतन के बाद मुस्लिम शासकों ने पूर्वी-बंगाल के नवद्वीप उच्च शिक्षा केन्द्र को सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास निरन्तर प्रदान किया। इसी "नादिया" की सुजला-सुकला धरती पर जयदेव जैसे प्रसिद्ध "गीत गोविन्द" के रचयिता ने शिक्षा पायी। उमापति द्वारा रचित "स्मृति विवेक" "यायशास्त्र" का विशिष्ट ग्रंथ माना जाता है जिसका निमाण विश्व विद्यालय में ही हुआ था।

श्रीमति सध्या मुखर्जी के अनुसार, "ऐसा कहा जाता है कि नदिया का एक प्रतिभावान विद्यार्थी वामुदेव सावभौम मिथिला में त्याग व तपश्चरित्र की शिक्षा प्राप्त करने गया था और वह तत्त्व चिन्तन "मणि" ग्रंथ को कठस्थ कर वापिस लौटा क्याकि मिथिला के पंडित अपने यहाँ की किसी भी पुस्तक को ले जाने, पत्तिनिधि करने व अनुवाद करने की अनुमति नहीं देते थे। नदिया लौटने पर उसी वामुदेव सावभौम ने नन्दिया में तपश्चरित्र का सूत्रपात किया और कालान्तर में उसके गिष्य रघुनाथ शिरोमणि ने याय की एक नवीन विचारधारा का सूत्रपात किया। नवद्वीप में याय शास्त्र के अध्ययन की व्यवस्था भी हुई। आग चनकर मधुरानाथ, रामचन्द्र और गदाधर भट्टाचार्य नामक प्रसिद्ध यायाचार्य हुए।⁴

उक्त स्थिति तो तब निर्मित हुई थी जब मुस्लिम आक्रमणकारियां न तमशिला एवं नानन्दा जैसे विशाल विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। विदेशी अपने साथ ग्रन्थालयों के महत्वपूर्ण ग्रन्थ ले गये। डा श्यामसुन्दर अग्रवाल के मतानुसार 'कहते हैं चीनी यात्री फाह्यान अपने साथ 520 भारतीय ग्रन्थों को बण्डल चीन ले गया था। ह्वेनसांग भारत में तीन वर्ष रहकर 657 ग्रन्थों की प्रतिलिपियां अपने साथ ले गया। एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग ने भी लगभग 500 बौद्ध ग्रन्थों की प्रतिलिपियां चीन भेजी थी। वह इसी काम के लिए लगभग दस वर्ष भारत में रहा।'⁵

यह युग शिक्षा के समान अवसर का युग था, सिर्फ ब्रूह्म को अध्ययन के अवसर कम थे। ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य सभी के लिए राजनीति धर्म, दशन, कला, साहित्य का अध्ययन जरूरी था। नालन्दा विश्वविद्यालय से भी अनेक विद्वान चीन गये इस बात की पुष्टि करते हुए डा पुष्करराज जैन ने लिखा है।

"बोधिद्वि 693 ई में दक्षिण भारत से चीन पहुँचा, जिसने लगभग 53 भारतीय ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। 8वीं शताब्दी में वज्रबोधि व भ्रमाध-वज्र चीन गए जिन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। भ्रमाध-वज्र अपने साथ लगभग 500 पुस्तकें ले गया जिन में से 77 का उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया। इस प्रकार प्रमुख विद्वान भारत से चीन गए जिन्होंने वहाँ भारतीय साहित्य का प्रचार किया।'⁶

बबर आक्रमण से जब भारतीय वैभवशाली उन्नति पर ग्रहण लगना शुरू हुआ, ब्राह्मणों, भिक्षुओं, सघाचार्यों व मठाधीशों ने दुर्लभ ग्रन्थों का संरक्षण अपने प्राणों से अधिक मानकर किया। यह आदेश संभवतः भविष्य पुराण की इन पक्तियों से मिला हो "पाण्डुलिपियां मठों में सारी जनता के उपयोग के लिए रखी जा सकती हैं और लिख, लिख या सूय के मंदिर में जो पुस्तकों के पढ़ने की व्यवस्था करता है तो वह काय गाय, भूमि या स्वर्ण के दान के समान है।'⁷

ऐसा करने राष्ट्र की सम्पदा को बचा सकने में व्यक्तिगत प्रयास बाण भट्ट, कुषाण राजा कनिष्क आदि ने ज्ञान के ग्रन्थों को व्यक्तिगत ग्रन्थालय बनाकर सुरक्षा दी। ये व्यक्तिगत ग्रन्थालय विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथ में लगे। कई फूँव दिए गये, कुछ बादशाहों ने व्यक्तिगत ग्रन्थालयों की शोभा बने। अरबी, फारसी, उर्दू, जुबानों के चलन से इनकी विषय-वस्तु उपयोगी नहीं हुई पर बाद में इन ग्रन्थों के अनुवाद काय, प्रतिलिप्यान्तर एवं दूसरी प्रतियाँ उर्दू में तैयार की गईं।

राजनीति, अथशास्त्र एवं ज्योतिष व दशन की बहुमूल्य पुस्तकें न शासन के काय में काफी मदद पहुँचाई। बादशाहों के दरबारों में नियुक्त मन्त्रियों राजगुरुओं, राज्यश्रित साहित्यकार व नवियों ने सहयोग से राजाओं न ग्रन्थालयों

की मूर्ति में विद्यमान स्ति दिगन्तात् । जिन्ना व क्षेत्र म मुस्लिम न धार्मिक जिन्ना पर विशेष जोर दिया ।

जिन्ना जगत् में मुगलमान विधान मन्त्रा न निवास करत थे प्रपञ्च बाद मुगलमान शासक था वही धार्मिक प्रवृत्तियां ता प्रेरणा गीत पावर इतरन मुस्लिम जिन्ना की धारा प्रवाहित जान मगी थी । '8

एक समय भारतीय भूत मूर्ति व चिह्न भुज प्राद जान मग और प्राचीन विद्यालय मूर्ति के छात्रों का क्या म मपन न हा मग । जैसे जग मुस्लिम व मुगल शासक भारत म जैसे मन्त्रा, मन्त्रों, मन्त्रि एव मन्त्ररा म जिन्ना बनने लगी तथा दान मन्त्रिण प्रधानता का अन्तिम भी सामने आया । अधिवाग प्रधानता राजशाही अधिकार म थे, जिन्ने व्यक्तिगत प्रधानता ही कहा जा सकता है । कुछ समाज मुधारता के मारजनिक पुस्तकालय मान्य समाज जिन्ना व विभाग म योमनन दिया । चूर्ति इर हग अरबी, पारसी, मुस्लिम एव मुगल व लगातार भारत की धरती पर आक्रमण म इगरी आधिप, सामाजिक, धार्मिक एव राजनयिक उन्नति की क्षति पहुँचनी गी । मात्र मा जिन्नी आतंकवादी प्रवृत्तियां न दम जिन्ना परमान है परन्तु आज की स्थिति से तब से बिलकुल निम्न है । तब जबकि जमाना म जागरण नहीं थी, दम विद्वानों म बड़ा हुदा था, एक राजा अपना ही राज्य का प्रमुख होता था । गरीबी और धार्मिक अन्धता ने प्रजा को अन्ध कर दिया था, जिन्ना का प्रचलन नहीं था, तब भी राज्य, रियासत, राजधानियां के प्रमुखों न जान के प्रकाश हनु जिन्ना केन्द्र की स्थापना की, उनके पुस्तकालयों की सम्पन्न किया, प्रचलित धार्मिकों म प्रथा का प्रनुवाद किया । कला, संगीत, साहित्य एव राजव्यवस्था जस विषयों की पुस्तकों का निर्माण करवाया । जब भारत निरन्तर मुस्लिम राजाओं, राजवंशों (नास-वश, निलजीवश, तुगलक वश एव सम्यद व लागी वगै) एव मुगल सम्राटों (बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ एव औरंगजेब) के अधीन लगभग 550 वर्ष तक पराधीन रहा इन्नि अपन शासनकाल में भारत की विकसित व समृद्ध सभ्यता को तहम-नहस किया । इसने बाबरूद उपरोक्त शासक न अपनी प्रजा की सुवधा, स्वयं की प्रगति एव शासन व्यवस्था म सुधार हनु बड़े-बड़े सुधारक काम किए जिनम प्रधानता का विकास भी प्रमुख है । मुगल काल के वाग्शाही, सम्राटों मनसबदारी, प्रधानमन्त्रिता एव सेना प्रमुखों व सगीतकता प्रेमिया व अपन व्यक्तिगत प्रधानता से जो उह राजव्यवस्था की देखभाल हनु मागदशन व मानसिक सात्वता प्रदान करत थे ।

यहमनी राज्य के मंत्री महमूद गवा व पास 6000 पुस्तकों का प्रच्छा मद्रह था । बाबर और हुमायूँ पृथ्व प्रेमी थे, जिन्होंने जेरगाह व आमोद गृह की ही पुस्तकालय व रूप म उपयोग किया था । बी के छाष्ट के बयानानुसार, बाबर व पुत्र हुमायूँ का पुरान विन म एक निजी प्रयालय था । अध्ययन तथा

नमय गुजारने का उसका अच्छा साधन था। राज व्यवस्था की देखभाल के उपरान्त वह अपने ग्रन्थालय में घण्टा समय बिताता था।⁹

“अकबर के पुस्तकालय में 25000 अच्छी पुस्तकों का संग्रह था। यह वह पुस्तकालय बहुमूल्य पाण्डुलिपियाँ से भरा हुआ था। उसका प्रबंध भी सुंदर ढंग से होता था। वे पुस्तकें कला और विज्ञान दो विभागों में विभक्त थीं।”¹⁰

इस बात से स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में ग्रन्थालयों के व्यवस्थापन, वर्गीकरण की कला ग्रन्थालय सचिवों को आती थी। बाद के बादशाहों ने भी उस परम्परा को कायम रखते हुए ग्रन्थालयों के संगठन, संचालन एवं व्यवस्थापन में रुचि ली। “जहाँगीर (सन् 1605 से 1621) ने शाही पुस्तकालय के विस्तार के लिए पाण्डुलिपियाँ खरीदी थीं। उनकी पत्नी नूरजहाँ का अपना एक व्यक्तिगत पुस्तकालय था। शाहजहाँ भी (सन् 1627-1658 ई.) पुस्तकालय में अभिरुची रखता था। रात्रि का पूरा भाग वह पुस्तकालय में व्यतीत करता था। उसके पुस्तकालय में विश्वकोश एवं शब्दकोश भी थे।”¹¹

ग्रन्थालयों की सुंदरता एवं पाण्डुलिपियों को सुरक्षित रखने हेतु “नाजिम”, “जिल्दसाज” अनुवादक एवं विद्वान-यक्तियों की ग्रन्थालय सेवाओं में रखा जाता था। अकबर ने अपने ग्रन्थालय के सुसंचालन के लिए विदेशों से वर्गाकार एवं जिल्द-साजों, पाण्डुलिपिकारों को बुलवाया था। इन शिक्षा के साथ ही साथ उसने शिक्षालयों में छोट-छोट ग्रन्थालय भी खोले। जब कागज का निर्माण प्रारम्भ हुआ तो पाण्डुलिपि संग्रहणों की संख्या बढ़ने लगी। स्याही का प्रयोग भी शुरू हुआ। नक्काशी युक्त जिल्दबंदी के लिए अकबर का काल प्रसिद्ध है। अबुल फजल ने “आईने अकबरी” में अकबर के इन क्रियाकलापों में भाग लेने का अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है।

भारत की अपनी प्रसिद्धि, उसकी सम्पन्नता एवं वैभवशाली सांस्कृतिक परम्परा को मुस्लिम मुगलाने बरबाद तो किया ही, लेकिन उनके ही द्वारा कुछ अच्छे कला, साहित्य एवं संगीत के घरानों का भी जन्म हुआ। अकबर के दरबार के “नव रत्ना” का इतिहास उजागर है। यद्यपि अकबर का काल कला, साहित्य एवं संगीत की उन्नति का उत्कृष्ट काल माना जाता है। इस काल में अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, बाइबिल एवं कुरान के भी अनुवाद इस काल में हुए।

बीजापुर में आदिलशाह का “आदिलशाही पुस्तकालय” एक राजकीय पुस्तकालय के रूप में था। औरंगजेब ने जब बीजापुर पर चढ़ाई की तो यह पुस्तकालय भी नष्ट हो गया।¹²

मुस्लिम एवं मुगलों की विध्वंसक एवं लूटपाट की वृत्ति के कारण उनकी यह शिष्यता का सामना इन पानागारों को करना, महना पड़ा। एक बादशाह या राजा एक स्थान पर ग्रन्थालय, शिक्षा संस्थान यहाँ की जनता की सेवा के लिये कोई काम करता था तो दूसरा उसे नष्ट कर अपनी विजयपताका सहाराता था। ऐसा

मुस्लिम आक्रमणकारियों एवं मुगल बादशाहों ने किया, जहाँ मन्दिर थे उनको मस्जिद या मकबरा में बदला दिया, उसी प्रकार जिन हिन्दू राजाओं के पास बहुमूल्य ग्रन्थसंग्रह था उसको लूट लिया गया। फिर भी व्यक्तिगत, राजकीय एवं लालच पुस्तकालयों के माध्यम से तत्कालीन जनता, व्यक्तिगत विकास, शिक्षा, साहित्य एवं ज्ञान के निर्माण में लाभान्वित होकर अपने देश का भाग बढ़ाने में सहयोग कर रही थी।

अंग्रेजी शासन-काल में ग्रन्थालय एवं राष्ट्रीय विकास—

मुगल साम्राज्य के क्रमशः पतन के बाद भारतीय जन जीवन कुछ समय तक सन्धि कालीन व्यवस्था से गुजरा। मुगल शासकों की प्रेम, शृंगार भोगातिष्या की प्रवृत्तियों से देश निरन्तर विघटन के कगार पर आ गया। इस विघटनकारी अवस्था से विदेशी साम्राज्यवादी राष्ट्र अनभिज्ञ नहीं थे। अतीतकाल से ही भारत का पड़ोसी राष्ट्रों में व्यापारिक सम्बन्ध था परन्तु मुगलकाल में सौन्ध्य प्रसाधन, कपड़ा एवं बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, मूँग मोता तथा रत्नजडित आभूषणों का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ा नाम था। अस्पाह एश्वय एवं सम्पदा के दश भारत का इस प्रकार समृद्ध होना विदेशियों को ललचा गया। निर्यात एवं आयात के इस व्यापार में विदेशों से भी मदिरा, चांदी एवं आरामगृह आकषक सामग्रियों का आयात भारत को होता था। इस प्रक्रिया में यूरोपीय देशों के व्यवसायी पैस वाले हो गए। उनका व्यापार के साथ एशियाई देशों पर विजय अभियान भी प्रारम्भ हुआ, परिणामस्वरूप "पन्द्रहवीं शताब्दी में तुर्कों की दक्षिणो-पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप की विजय के कारण भारत और यूरोप के मध्य प्राचीन स्थल मार्ग अस्तित्व में आ गया। इससे यूरोप के व्यापारियों का चिन्तित दलकर, वहाँ के नाविकों ने मार्ग खोजने का बीड़ा उठाया। इस कार्य का श्रेय पुर्तगाल नाविक वास्को डिगामा को प्राप्त हुआ। उसने 27 मई 1498 को भारत के पूर्वी तट पर कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह में अपनी जहाज को लगेर डालकर राखा किया।" 13

यद्यपि पोर्तगालीज, डच स्पनिश एवं अंग्रेज व्यापारिक उद्देश्य से भारत की ओर बढ़ते आ रहे थे तब भी देश का विकास रुका नहीं। मुगलों से मराठा ने युद्ध किया। शिवाजी ने मराठा राज्य कायम किया। मराठा शासनकाल में भारत का इतिहास भी लिखा जाता रहा। इतिहास लेखन में उस समय के ग्रन्थालयों ने काफी महत्त्वपूर्ण इतिहासकारों को पहुँचाई। बीजापुर बीदर, गोवा पूणे, सौराष्ट्र व विदर्भ आदि मराठी राज्यों में, ग्रन्थ-लेखन, अनुवाद कार्य व ग्रन्थालयों का काम त्वरित गति से हो रहा था। ग्रन्थशाला, पोथीशाला, सम्स्कृत ग्रन्थ भण्डार, पाण्डुलिपि संग्रहालयों में वेद पुराण, रामायण, महाभारत के ग्रन्थों का अनुवाद कार्य भी प्रारम्भ था।

पूना का भण्डारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तजीर सरस्वती महल उस समय के देश के प्रमुख शोध-कार्य के केंद्र बने रहे हैं। भारत की तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक दुबलताओं का लाभ उठाकर व्यापार करने वाले विदेशियों ने देश के विभिन्न समुद्र तटीय शहरों में अपनी काठिया स्थापित करना शुरू

कर दिया। मिशनरियो ने अपने धर्म प्रचार हेतु चर्च बनवाये, मुद्रण यंत्रों की स्थापना की। ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी पीछे नहीं रहो। एक भार हब, पुतणाली, स्पेनवामिया ने चर्च एक मुद्रण के द्वारा धर्म प्रचारक सामग्री छापी तो दूसरी ओर मन्नेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापार का क्षेत्र भारत में फैलाकर औद्योगिक शक्ति से अपनी सामग्रियों का प्रचार प्रसार व्यापार किया।

मुद्रण-मशीनों की स्थापना से भारत में प्रकाशन की नई संभावनाओं की शुरूआत हुई पर साथ ही ईसाई धर्म प्रचार का काम भी चँनता गया। धर्म मन्नेज भारत पर पूरी तरह छा गये तो उनके चहुँपने से निपटने में भारत को निरन्तर 200 वर्षों तक सपप करना पड़ा। मुद्रण मशीन घोषा, हुगली, मद्रास, बलवत्ता मिरामपुर, बम्बई में स्थापित हो गई।

“प्रेस के आविष्कार और प्रचार के साथ-साथ पुस्तक, समाचार-पत्रा आदि की संख्या बढ़ी। धीरे धीरे पुस्तकें रंगीन, सचित्र और आकर्षक बन से छपने लगी। प्रेम की सुविधा होने से पुरानी हस्तलिखित पुस्तकें छपवाई जाने लगी।”¹⁴

भारत में प्रेस के आगमन से प्रथा, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। प्रकाशन सामग्री से अधिभर धार्मिक प्रथा, धर्म प्रचार, पम्पलेट्स व राष्ट्रीय जागरण के उत्थान के पत्रा की भरमार रही। शिक्षा संस्थानों के खुलने से पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी, समाज शिक्षा को भी कुछ गहरा में प्रारम्भ किया गया। देश की प्रशासनिक राजनैतिक एवं आर्थिक नीति व निर्धारण हेतु मन्नेजों ने भारतीयों को मन्नेजी स्कूलों में प्रवेश देना प्रारम्भ किया ताकि मन्नेजों पढ़े लिखे लोग उनका सामान्य जीवन बचा सकें।

ग्रामीण व पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से प्रथाओं की स्थापनाओं भी हुई। राष्ट्रीय जागरण के उद्देश्य से बंगाल में मन्नेजी स्कूल एवं पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। बम्बई, मद्रास एवं बलवत्ता में राष्ट्रीय एकाता व विकास की दृष्टि से कई सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक संस्थाओं का गठन प्रथाओं की स्थापना के साथ हुआ।

“रायल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल के द्वारा सन् 1784 में स्थापित बलवत्ता-ल मन्नेरी की सन् 1820 में सावजनिक उपयोग के लिये घोषित कर दिया। मद्रास ‘निटरेरी-सोसायटी’ की स्थापना सन् 1812 में हुई जिसने एक सावजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। बम्बई में सन् 1846 में एक सावजनिक पुस्तकालय स्थापित हुआ।”¹⁵ इससे साथ ही देश भर में सावजनिक प्रथाओं की स्थापनाओं का दौर चल पड़ा।

मध्यप्रदेश के राज्य इन्दौर जनरल लायन्नेरी, नागर में सावजनिक प्रथाओं, खण्डवा में मारिस सार्वजनिक प्रथाओं एवं वाचनालय की स्थापनाएं हुई। उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु मन्नेजों ने सर्वप्रथम बलवत्ता में फोर्ट-विलियम कालेज की स्थापना की। कालेज की स्थापना का उद्देश्य भारत में आने वाले अपरिपक्व, अयोग्य एवं इतिहास, कानून व नीति में अप्रमाण मन्नेज नव जवान

नामकी या भारत की भाषा, मन्त्रि, धर्म एवं दर्शन की शिक्षा प्रदान करना आ
 वधानि सभाध्य अधिकारी व्याभिचार और धर्ममध्यता में पक्ष जाते थे मन्त्र उन्हें
 व्यावसायिकता बुद्धिमत्ता एवं सच्चरित्रता की गहरी नींव डालने का प्रयास था मन्त्र
 "लाट वनजनी ने इन सबका उपचार भुझाया था । उनमें शिक्षा, जिसकी मैं
 सोच विचार कर इंग्लैंड में डाली जाय और ऊपर की मजिम व्यवस्थित रूप से भारत
 में पुरी की जाय । इसके लिए उसमें भारत में एक कॉलेज की स्थापना पर बल
 दिया और बनवत्ता में फोटो विलियम वॉलेज की नींव डाल दी ।" 18 इस कॉलेज
 में भारतीय भाषाओं का एक अलग विभाग कायम किया गया । जिसमें हिंदुस्तानी,
 हिंदी, उर्दू, पारसी बंगाली, संस्कृत भाषाएँ प्रमुख थी । इन भाषाओं के अध्ययन
 हेतु पाठ्यलिपियाँ, ग्रंथों एवं पत्रिकाओं का संग्रह कर प्रयोग भी स्थापित किया
 गया । यह प्रयोगशाला साहित्य से भी परिपूर्ण किया गया । भारतीय भाषाओं
 की जागरूकी हेतु सत्रों में विद्यार्थियों ने भाषाओं की पढ़ाई के साथ-साथ अनुवाद काय
 में भी लगी थी । सत्रों के साथ हिन्दी, संस्कृत, उर्दू पारसी के विद्वान अधिकारी
 प्राप्तिपक्का न भी अनुवाद काय में मदद की । "प्रेस की सुविधा होने से पुरानी
 हस्तलिखित पुस्तकें उपलब्ध हो गईं । भारत सरकार ने पुरातत्व विभाग को
 स्थापित किया । उनके अन्वयन प्राचीन भारतीय महत्वपूर्ण सामग्रियों की खोज
 होना शुरू हुई । बहुत से सामग्र्य मिश्र, मुहर, अभिलेख, खिलालेख आदि का
 पता लगा, जिनसे भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश पड़ा ।" 19

राष्ट्रपति सभा और मन्त्रि की सहज न भारतीयों को भी जगाया ।
 बनवत्ता मन्त्र की तर्ज पर बनारस में मन्त्र कॉलेज, पञ्जाब में दमाद कॉलेज
 व दिल्ली में भी कॉलेजों की स्थापना हुई । 1836 में बनवत्ता पंथिक साधकों की
 स्थापना में लामा में पढ़ने के प्रति रुचि जागी जिसका प्रभाव देश के अन्य
 भागों पर पड़ा और मावजिक गुप्तकाल की पुनर्जागरण का प्रारंभ । बनवत्ता
 पुस्तकालय एवं पाठ-विनिर्देशक कॉलेज गुप्तकाल के संग्रह का भण्डार । इसी
 रिक्त साधकों की स्थापना की गई आ मावजिक प्रयोग के इतिहास में
 एक नया काम था । यही स्वीडिश साधकों के बाद में जाकर "राष्ट्रीय प्रयोगशाला"
 स्थापित किया गया । इस प्रयोगशाला का प्रारंभ 1903 में प्रकाशित "ग्रेट ऑफ
 इन्डिया" में प्रकाशित किया गया कि "यह पुस्तकालय मन्त्र के अध्यक्षों द्वारा बनवत्ता
 की स्थापना की ।" विद्यार्थियों के लिए काय स्थान के रूप में काय बनवत्ता मन्त्र
 के भारतीय विद्वानों द्वारा के लिए सामग्री संग्रहित करने का कार्य करना । इसमें
 दमाद मन्त्र के पुस्तक को भारत के मन्त्र में नहीं भी मिली गईं हैं। इसी
 कारणों से वह विद्वानों की समझ में आने के पड़ने के लिए उत्तरदायी की जाना
 पड़ा । पुस्तकों के संग्रह के मन्त्र में दमाद का काम बनवत्ता का किया कि 1867
 में विद्वानों द्वारा न मन्त्र में दमाद का काम पुस्तक संग्रहण विधि विधि के अनुसार
 भारत में भी यह विधि विधि बनवत्ता विधि के अनुसार मन्त्र में प्रकाशित प्रत्येक प्रकाशक
 की पुस्तक की एक प्रति मन्त्र में विधि विधि के अनुसार । इस विधि विधि में पुस्तक
 की विधि में इस विधि विधि के अनुसार मन्त्र में विधि विधि के अनुसार । मात्र यह दो

का सर्वाधिक साहित्य सम्पन्न “राष्ट्रीय ग्रन्थालय” बनकर दश की विविध गति विधियाँ म सतत् सहयोग प्रदान कर रहा है।

इस प्रकार अंग्रेजी शासन काल में सन् 1900 व पूर्व तक भारत में मुद्रण प्रेस और ग्रन्थों के प्रकाशन के माध्यम जिन सावजनिक ग्रन्थालयों का विकास हुआ उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार थे—

- | | |
|---|------|
| 1 कलकत्ता लायब्रेरी | 1784 |
| (1) फोर्ट-विलियम कॉलेज ग्रन्थालय, कलकत्ता— | 1800 |
| (2) बौनेमारा सावजनिक पुस्तकालय, मद्रास— | 1812 |
| (3) कलकत्ता पब्लिक लायब्रेरी, कलकत्ता— | 1836 |
| (4) सावजनिक पुस्तकालय, बम्बई— | 1846 |
| (5) इंदौर जनरल लायब्रेरी, इंदौर— | |
| (6) मारिस-लाइब्रेरी (भाषिकय स्मारक वाचनालय) मण्डवा— | |
| (7) सावजनिक ग्रन्थालय, सागर— | |
| (8) सावजनिक ग्रन्थालय, नावणगौर | |
| (9) सावजनिक ग्रन्थालय, कोचीन | |
| (10) सावजनिक ग्रन्थालय, गोवा | |

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे राज्य थे जिनमें रियासतों के शाही ग्रन्थालय अथवा व्यक्तिगत सग्रह से स्थापित ग्रन्थालय थे जैसे—

- (1) टीपू सुल्तान का पुस्तकालय—1799 तथा
- (2) हैदरअली का ग्रन्थालय—

उपरोक्त दोनों ग्रन्थालय अंग्रेजों के हाथ लग गये और उन्होंने इन पुस्तकालयों की दुर्लभ पुस्तकों से लंदन में ‘इण्डिया ऑफिस लायब्रेरी’ की स्थापना की। बाद के वर्षों में जब तक अंग्रेजों का राज्य रहा इस लायब्रेरी में भारत से हजारों पाण्डुलिपियाँ व दुर्लभ ग्रन्थें ले जाये गये। प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की इस खूट ने भारत का अद्भुत संपदा से वंचित कर दिया। इण्डिया ऑफिस लायब्रेरी ‘जो भारतीय-साहित्य सस्कृति एवं शिक्षा की समृद्धि के उद्देश्य से गोली गई थी’ अभी तक भी इस अमूल्य सग्रह को ब्रिटिश सरकार ने भारत का वापस नहीं किया है। इंग्लैंड के अतिरिक्त बर्लिन तथा पेरिस के ग्रन्थालयों में भी अनेक भारतीय ग्रन्थें ले जाये गये।”¹⁸

“इण्डिया ऑफिस लायब्रेरी” के भारतीय-ग्रन्थ सग्रह व बार में कई बार वापस भारत लौटाने के सम्बन्ध में कायवाही की गई परन्तु कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं मिला।

भारतीय-साहित्य, सस्कृति एवं इतिहास की इस अमूल्य धरोहर का प्राप्ति करने में भारत सरकार को पुनः जनमहयाग लेकर प्रयास करना चाहिए।

भारतीय विकास की उपरोक्त मध्यवर्ती कड़ी में ग्रन्थालयों में राष्ट्रीय लाभ व हानि हुई इसका सार गंभीर विवेचन देने पाठकों के लिए प्रस्तुत है।

भविष्य में राष्ट्रीय विकास की इसी परम्परा में हम स्वतंत्रता के बाद ग्रन्थालयों का विकास एवं राष्ट्रीय प्रगति में उनके योगदान पर विस्तार पूर्वक विचार करेंगे।

सन्दर्भ —

- 1 रावत (दीपक) इत्यादि भारतीय शिक्षा का इतिहास, लखनऊ प्रकाशन केन्द्र, 1986 पृ 62
- 2 रावत (दीपक) इत्यादि भारतीय शिक्षा का इतिहास, लखनऊ प्रकाशन केन्द्र, 1986 पृ 62
- 3 रावत (दीपक) इत्यादि भारतीय शिक्षा का इतिहास, लखनऊ प्रकाशन केन्द्र, 1986 पृ 59
- 4 मुखर्जी (सध्या) देखिए—रावत, दीपक।
- 5 अग्रवाल (श्याम सुन्दर) ग्रन्थालय संचालन तथा प्रशासन, आगरा, श्रीराम मेहरा, 1976, पृ 1
- 6 जैन (पुनराज) भारत की सांस्कृतिक विरासत, आगरा, साहित्य भवन, 1986, पृ 198
- 7 सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एवं समुदाय, पटना, बिहार, हि प्र प्र का, 1975 पृ 37
- 8 जोहरी तथा पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा, विनोद प्रकाशन 1981 पृ 33
- 9 Apte (B K) Libraries under the Mughals and the Maratha in Readings in Library science, Edited by Balwant Singh Lachyana, Loyal Book Depot 1968 P 9
- 10 हैसल (ग्लैफ़ैंड) पुस्तकालय का इतिहास परिशिष्ट पृ 265, भोपाल, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1974, अनुवादक, मदनमोह परिहार।
- 11 महाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एवं समुदाय, पटना, बिहार, हि प्र प्र का, 1975 पृ 49
- 12 परिहार (मदनसिंह) देखिए हैसल (ग्लैफ़ैंड) पृ 266
- 13 पाठक (पी डी) तथा त्यागी (जी एस डी) भारत में शिक्षा दशक और शैक्षणिक समस्याएँ, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1984-85, पृ 231-32
- 14 परिहार (मदनसिंह) देखिए ग्लैफ़ैंड (हैसल) पृ 267
- 15 सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एवं समुदाय, 1975 पृ 53
- 16 गुप्ता (चन्द्रावली) येलेजली बालीन भारत, भोपाल, म प्र हि प्र अकादमी, 1971 पृ 145
- 17 ग्लैफ़ैंड (हैसल) यह भी देखिए परिहार (मदनसिंह) पृ 267
- 18 अग्रवाल (श्याम सुन्दर) ग्रन्थालय संचालन तथा प्रशासन, 1976 पृ 1-2

पुस्तकालयो मे हिन्दी पुस्तकें और उनका चयन

पुस्तकालय एक पुस्तकें दोना एक दूसरे के पूरक अवयव है। जहा पुस्तकें होगी और बचानिक आधारों पर व्यवस्थापित की जानी हागी प्रथवा सस्थाओं में कमचारियों के पढ़ने योग्य होगी पुस्तकालय के अंग रूप में हो होगी। राष्ट्र में पुस्तकालयों का कार्यक्षेत्र सिर्फ पुस्तकों का संग्रह एवं उनका फलका पर प्रदर्शन एवं व्यवस्थापन मात्र नहीं है। पुस्तकालय अपनी परिभाषा में व्यापक होकर स्वाध्याय अध्ययन, शोध अनुसंधान एवं तकनीकी अडचना में आने वाला ऐसा उपकरण हो गया है जो प्रत्येक व्यक्ति समाज, राज्य राष्ट्र एवं परराष्ट्र में निकटस्थ हो गया है। हम यह मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का विकास बड़ा की शैक्षणिक साहित्यिक कला, संस्कृति एवं पुरातात्विक सामग्री से युक्त संग्रहालयों एवं वैज्ञानिक आगारों में पायी जाती है।

राष्ट्रीय विकास में यह भी जरूरी है कि उस देश का साहित्यिक एवं भाषायी स्तर क्या है। देश की एकता उसकी भाषा, लिपि एवं उसके साहित्य पर बहुत कुछ निर्भर करती है। इसी बात को मायता देते हुए भारतीय गणतंत्रक संविधान में नागरी लिपि को हिन्दुस्तानी भाषा का श्रेष्ठ माध्यम बनाया गया है।

आज सम्पूर्ण देश हिन्दी भाषा साहित्य व संस्कृति के कारण ही हिन्दुस्तान के नाम से जाना जाता है। भले ही यहाँ धर्म, जाति, रंग भेद में मनुष्य विविधता मानता रहा हो। अनेकताओं में एकता के इस देश में आज भी अभिक्षा (20 करोड़) युवक युवतियाँ, बूढ़ा एवं बच्चा का अभिक्षाप है। इस भयंकर अनानता को दूर करने एवं अर्थजीयत में पीछा छुड़ाने के लिए मेरी यह मायता है कि यदि लोक पुस्तकालय आन्दोलन तथा पुस्तकालय अधिनियम सम्पूर्ण राष्ट्र में तेजी से चलाये जाये और गाँव गाँव में पुस्तकालय स्थापित किये जाये तो हिन्दी भाषा के साथ साथ साक्षरता अभियान का भी प्रगति मिलेगी।

जिस प्रकार मनुष्य के लिए भोजन, हवा, पानी एवं आवास आवश्यक है उसी प्रकार जीवन विकास के लिए उसका बौद्धिक होना भी अनिवार्य है। इस हिसाब से शिक्षा मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। स्वाध्याय मनुष्य की प्रकृति है किन्तु अधिक अभाव एवं उचित अध्ययन सामग्री के अभाव में वह अच्छे साहित्य से

वचन रह जाना है। यद्यपि भारत सरकार ने देशवासियों के लिए देशभर में 120 (एक सौ बीस) विश्व विद्यालय 5000 से अधिक कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य एवं अनुसंधान सम्मान के महाविद्यालयों की व्यवस्था कर रखी है। हजारों विद्यालयों के माध्यम से राष्ट्र की विशाल पीढ़ी शिक्षित हो रही है। फिर भी परिणाम अपेक्षित नहीं है।

देशवासियों को शिक्षा एवं स्वाध्याय की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के पुस्तकालय जैसे ग्राम, जिला राज्य, क्षेत्रीय, केन्द्रीय एवं राष्ट्रीय पुस्तकालय के साथ-साथ सामाजिक संगठनों एवं शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय खोले गये हैं।

उनके अतिरिक्त भी दश में ऐसे पुस्तकालय हैं जो सेना एवं अस्पताल से सम्बद्ध हैं। अपाहिज, बहरे गुरु एवं अन्ध लोगों के लिए विशेष प्रकार के पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई है।

उपरोक्त सभी प्रकार के पुस्तकालयों में पुस्तकों का चयन किस आधार पर होता है इसका एक विवेचनात्मक विवरण देने का यत्न मैं कर रहा हूँ। यद्यपि पुस्तकालयों में सभी प्रकार की पुस्तकें होना चाहिये, किन्तु यह भी देखा जाता है कि पुस्तकालय किस प्रकार का है। पुस्तकालयों के प्रकारानुसार विभिन्न विषयों का उपयोगी एवं सम्बन्धित पुस्तकें पुस्तकालयों में क्रय कर रखी जाती हैं। सभी प्रकार की पुस्तकें एक ही पुस्तकालय में हो यह भी सम्भव नहीं है।

आज प्रकाशन सामग्री का उत्पादन की अतिशयता इतनी बढ़ गई है कि यह युग "साहित्य प्रकाशन का विस्फोटक युग" माना जाता है। भारत "पुस्तक क्रांति" का द्वार पर पहुँच रहा है। अध्ययन सामग्री के विस्फोट के साथ-साथ शोध अनुसंधान के साथ भी आश्चर्यजनक प्रगति कर रहा है। साहित्य विज्ञान एवं अन्वेषण की अनोखी क्रांति ने प्रकाशन जगत में भी होड़ा होड़ी की क्रांति पैदा कर दी है। भारतवर्ष में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का वार्षिक प्रकाशन लगभग 20,000 है। इस उत्पादन समस्या के मुकाबले भारतवर्ष में इनकी खपत का प्रतिशत कम है। इसका कारण भारतीय परिवारों की अशिक्षा, आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ न होना अध्ययन रुचि में कमी अविकसित पुस्तकालय सेवाएँ तथा पुस्तक प्रकाशन के उपरान्त उनका उचित माध्यम से पाठकों तक न पहुँचाया जाना इत्यादि हैं।

पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय देश की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति पर प्रत्यक्ष निर्भर होता है। मुद्रा चक्रण एवं मुद्रा स्थिति के कारण भी अथवा क्रय करने की क्षमता पर असर पड़ता है। हमारे देश में सांख्यिक पुस्तकालयों की कमी है। ग्राम पुस्तकालय जो विशेष प्रकार के हैं अधिकांशतः उन्हीं पुस्तकों को खरीदते हैं जिनका उनके पाठकों के लिये उपयोग होता है।

पुस्तक क्रय करने का तरीका पुस्तकालय प्रकार एवं उनकी आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। पुस्तकालयों में पुस्तकें क्रय करते समय यह देखना आवश्यक

शक्य हो जाता है कि अमुक पुस्तक किस स्तर तक उपयोगी है। पाठकों की मांग के अनुरूप है या नहीं तथा निर्धारित राशि के अंतर्गत प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं और बाजार में उपलब्ध है या नहीं। अर्थात् पुस्तक शारीरिक, आत्मिक एवं उपलब्धता की दृष्टि से पूर्ण है अथवा नहीं। आज उक्त तीनों तत्त्वों की दृष्टि से पूर्ण, पुस्तक का पुस्तकालय में रखा जाना युक्तिसंगत एवं 'यायिक' होगा।

यदि पुस्तक अपने भौतिक स्वरूप में आकर्षक नहीं है, आत्मीय (विषय की दृष्टि से) रूप से प्रसिद्ध नहीं है माय हो पाठकों की मांग के अनुसार बाजार में उपलब्ध नहीं है तो वह प्रकाशन, अध्ययन, अनुसंधान एवं पुस्तकालय जगत में अपनी महती भूमिका नहीं निभा सकती। पुस्तक का उपर दशविध स्वरूप में परिपूर्ण होना ही उसके निर्माण की उपलब्धि है।

इन्हीं उपलब्धियों के कारण पिछले दो दशक से लिखी जा रही हिन्दी की पुस्तकों ने हिन्दी-भाषी तथा हिन्दी अनुरागी पाठकों के मन में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। राष्ट्र भाषा हिन्दी में लिखी, प्रकाशित हुई तथा पुस्तकालयों एवं पुस्तक विक्रेताओं से उपलब्ध सभी विषयों की पुस्तकों ने पाठकों का अभ्रंजी क मकट से उबार दिया है। विदेशों में भी अर्थ भाषा की पुस्तकों के साथ-साथ हिन्दी पुस्तकों की मांग बढ़ रही है।

पिछले दस वर्षों में भारतीय साहित्य, कला संगीत, नाट्य एवं विविध अकादमिया ने हिन्दी भाषा में पुस्तकें प्रकाशित करने की जो तत्परता दिखाई है वह वाक्य प्रमत्ता के काबिल है। प्रकाशक सचो ने यह निष्कर्ष लिया है कि निकट भविष्य में ग्रामीण जन जीवन तक पाठकों को हिन्दी की सुगम सस्ती एवं अच्छी पुस्तकें प्रदान करने के लिए हमें ग्रामीण साहित्य का प्रकाशन करना होगा। ग्रामीण साहित्य प्रकाशित कर ग्राम पुस्तकालयों तक पहुँचाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। हम कार्य को प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर पर करना चाहिये।

'अभी तक 25 करोड़ की धनराशि व्यय करने पर देश की साक्षरता का प्रतिशत 70% है। देश के केवल 20 करोड़ लोग साक्षर हैं और 38 करोड़ लोग निरक्षर हैं जबकि सन् 1969 में निरक्षरों की संख्या 30 करोड़ ही थी।'

(भादश परिवार—हरिकृष्ण तेलंग) जून 1973 पृ 31

इस प्रकार की भीषण अज्ञानता का दूर करने के लिए हिन्दी भाषा के प्रकाशन व माय ही प्रादेशिक एवं स्थानीय लोक भाषा में भी साहित्य प्रकाशित करना नितान्त आवश्यक है। शासन का ध्यान इस ओर भी पहुँचा है। अन्वो का प्रादेशिक भाषा या लोक भाषा में अनुवाद भी हो रहा है इससे भारत की हिन्दी प्रेमी जनता को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। देश भर में हिन्दी भाषा में पुस्तकें प्रकाशित करने वाली कुछ प्रमुख प्रकाशन संस्थायें इस प्रकार हैं—

(1) मागरी प्रचारणी सभा (2) हिन्दी साहित्य मन्मलन प्रयाग (3) राज-मल प्रकाशन (4) राष्ट्रीय प्रकाशन (5) राजपान एण्ड सन्स (6) राज्यप्रय

अकादमियों (7) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (8) राष्ट्रीय पुस्तक याम (9) ग्रामा राम एण्ड सन्स (10) हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद (11) मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (12) बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना (13) राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (14) हिन्दी पानपीठ प्रकाशन (15) नेशनल बुक ट्रस्ट आदि ।

उपरोक्त सभी संस्थायें हिन्दी भाषा एवं साहित्य की पुस्तक के साथ उचित याम कर रहे हैं । प्रायः यह देखन में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी "ग्रामीण पुस्तकालय" अथवा "रिपोजिटरी सेन्टर" स्थापित हैं उनमें 77% पुस्तकें चाहे वे साहित्य की हों, राजनीति, ग्रन्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, कला, धर्म, दर्शन, कृषि एवं स्वास्थ्य की हों सभी हिन्दी भाषा की ही होती हैं । किन्तु एक बात हमें सोचन के लिए बाध्य होना पड़ता है कि क्या ये 77% हिन्दी पुस्तकें पाठकों की रुचि के अनुसार ही हैं । इस बात पर हमारे मनमें भिन्न भिन्न होंगे । प्रादशिक भाषाओं व साहित्य ने इस प्रतिशत को कम कर दिया है । फिर क्या ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता है जिन्हें अधिकाधिक पाठक पढ़ते हों उन्हें ही पुस्तकालयों में खरीदा जाय । यह बात पाठकों की रुचि के अनुसार पुस्तकें, प्रकाशित करने की प्रेरणा देती है ।

ग्रन्थालयों के पास एक निश्चित धनराशि होती है जिसकी पुस्तकें आदि पाठ्य सामग्री खरीदने में खर्च किया जाता है । दूसरी ओर सभी ग्रन्थालयों के पास न तो सब पुस्तकें खरीदने हेतु राशि ही होती है और न सभी पुस्तकें खरीदने योग्य ही होती हैं ।¹ इस बात को ध्यान रखत हुए प्रकाशकों का भी विनिष्ट विषय की अर्न्तर्गत पुस्तकें जिनकी मांग पाठकों में है प्रकाशित करना चाहिये । व्यवसायिक लाभ को यदि देखें तो जासूसी उपयोग का प्रकाशित करना बेहतर है । लेकिन मात्र उपयोग को छापन से प्रकाशन का प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी । अतः क्षेत्रों में भी अपना वचस्व बढ़ाना चाहिये ।

वर्तमान में जिनासु पाठकों की रुचि को ध्यान में न रखकर जिन पुस्तकें राशियों में पुस्तकें खयन हो रहा है वह एक दम एक तरफा एवं सग्रह करने की दृष्टि से अनुपयोगी भी हो रहा है । अकादमियों से खरीदी गई हिन्दी विषय की पुस्तकें के लिए श्री जयप्रकाश भारती लिखते हैं "विभिन्न ग्रंथ अकादमियों ने इस दिशा में जो कुछ किया है उसमें से अधिकांश पर सिर ध्यान के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी नेशनल बुक ट्रस्ट के कामकाज से स्पष्ट है कि वह सफेद हाथी बनकर रह गया है ।"²

इससे जाहिर होता है कि ऐसी पुस्तकें का खयन नहीं करना चाहिये । किन्तु मैं यह कहूँगा कि इसमें कुछ अनुवादित पुस्तकें सग्रह योग्य हैं जिन्हें पाठक भले ही न पढ़ें हों लेकिन हिन्दी भाषा के अनुसन्धितुओं के लिए ये महत्वपूर्ण हैं । हिन्दी भाषा में उच्च स्तरोंय ग्रंथ लिखन एवं प्रकाशित करने से विश्व

बाजार में हमारी प्रनिष्ठा कम नहीं होगी। घटिया, अश्लील एवं चालू साहित्य प्रकाशित करने से तो बहुत ही है इनका प्रकाशन बंद कर देना।

इससे पहले कि मैं पुस्तक चयन प्रणाली एवं उसका सैद्धान्तिक पहलुओं पर जोर दूँ, लेखक एवं प्रकाशक से यह अपेक्षा रखूँ कि वे पुस्तक लिखते समय यह ध्यान रखें कि वे जो ग्रंथ लिख रहे हैं वह पाठकों की रुचि एवं पसंद के विषया-नुरूप है अथवा नहीं। दूसरे प्रकार का जो विशेष ज्ञान देने वाला साहित्य प्रकाशित होता है, उसका भी अचालया में होना अनिवार्य है।

आज अनुवाद विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि विश्व की किसी भी भाषा लिपि को हम अपनी भाषा लिपि में बदल कर अपना काम सम्पन्न कर सकते हैं, फिर हमें हिन्दी लेखन, अध्ययन एवं ग्रंथ निर्माण से क्षुब्ध न होकर उसे अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये। इस हिन्दी भाषा के ग्रंथों के विकास हेतु प्रकाशन जगत, लेखक-वृत्त, शिक्षा संस्थायें एवं सभी प्रकार के पुस्तकालय जवाबदार हैं। पुस्तकालय-साध्यता पर यह दायित्व आता है कि वह अपने पुस्तकालय हेतु किस प्रकार की पुस्तकें खरीद कर रहे हैं।

- (1) क्या पाठकों की मांग के अनुसार है।
- (2) या शिक्षकों की मांग के अनुसार है।
- (3) पुस्तकालय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित हैं।
- (4) या फिर बाजार में उपलब्ध साहित्य से खरीदी जाती है।

उपरोक्त चारों स्थितियों के अतिरिक्त कुछ पुस्तकालय ऐसे भी हैं जहाँ उनके प्रकार के अनुसार पुस्तकें चयन की एवं खरीदी जाती हैं।

(अ) पाठशाला पुस्तकालयों में पुस्तक चयन—प्रायः यह देखा गया है कि पाठशालाओं में अधिकतर पुस्तकालय “पाठ्य ग्रंथों” एवं “जीवन चरित्र” विषयक पुस्तकों के सङ्कलन में पुस्तकालय होते हैं। ऐसे पुस्तकालयों में विद्यार्थी पाठकों की मांग का अवलोकन नहीं किया जाता। प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों के अलावा सभी प्रकार की सामान्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध साहित्य से खरीदी जाती हैं। आज जबकि देश में सभी अविभाजित राज्यों में हिन्दी माध्यम से शिक्षण को अपनाया जा रहा है, अंग्रेजी विषय का बहिष्कार किया जा चुका है, तब पाठशालाओं के लिए अधिकाधिक पाठकों की रुचि को देखते हुए अधिकतम हिन्दी भाषा की पुस्तकों का चयन कर खरीद किया जाना चाहिये। अनावश्यक अंग्रेजी में छपी पुस्तकों का भगाना पैसों एवं समय का दुरुपयोग करना है। प्रथम तो पाठशालाओं में पुस्तकालयों का प्रनिर्गत ही बहुत कम है। विद्यार्थी ग्रंथों के सत्संग से दूर ही रहते हैं, उनमें अध्ययन रुचि पैदा ही नहीं होती और न ही ग्रंथालय इतना आकर्षक है कि सहज रूप से विद्यार्थी उनसे प्रभावित होकर कुछ समय पढ़ने में दें।

“भारत में शिक्षण प्रणाली बकाया भाषणों तक ही सीमित रह गई है। विद्यार्थी का केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ने का सुभाव दिया जाता है, या बकाया में शिक्षक

द्वारा लिखा दिया जाता है। इस प्रणाली से विद्यार्थी को पुस्तकों के प्रति कोई रुचि ही नहीं रह जाती है¹। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक बुन्जियों एवं गैस पंपरो को पढ़कर सिर्फ परीक्षा पास करता है। यह गलत है उह भय पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, इससे उनका ज्ञान क्षत्र विकसित होगा तथा व जीवन में अध्ययन के महत्व को समझ सकेगा।

शाळा स्तर पर हिन्दी भाषा की पुस्तकें अधिकारिक पढ़ाई एवं सपहित की जाती है, पुस्तकालया में भी इनके प्रतिष्ठित का बढ़ाया जा सकता है। यद्यपि कि प्रत्योदय व आधार पर छोटी-छोटी पाठशालाया में पुस्तकालयो की स्थापना हो और पुस्तकें (पाठ्यग्रन्थ व अलास) विद्यार्थी पाठकों, शिक्षकों एवं ग्रन्थालयो तीनों की रुचि अनुसूच चयन का श्रय की जाय।

(प्रा) महाविद्यालय पुस्तकालयों में पुस्तक चयन—भारत देश में महाविद्यालयीन स्तर पर शिक्षण व तरीका में पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी का प्रयोग व चलन क्रमशः बढ़ता चला गया है। साथ ही राष्ट्र भाषा हिन्दी में विभिन्न विषयों की पुस्तकें राज्य प्रकाशमया एवं प्रकाशका द्वारा प्रकाशित करने की योजनायें भी बड़े पैमाने पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा नियमित की जा रही है। लेखकों को प्रमोवा द काय हेतु पुरस्कार भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ताकि हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन मिले। देश में हिन्दी भाषा के लिए यह एक अच्छा काम है साथ ही राष्ट्रीय एकता का विकास में सहायक है। राष्ट्र में महाविद्यालय द्वितीय श्रेणी के शिक्षा विकास के ऐसे पानागार है एस प्रालाक स्तभ है जहा दश की युवा पीढ़ी का बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास होता है। यही युवा पीढ़ी देश के विकास में सहयोग कर राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाती है।

इन्हीं छात्रों के लिए हिन्दी भाषा में सभी विषयों पर पुस्तकें छापी जा रही है, जिसके अध्ययन से व अपनी परीक्षायें में पास करें और अग्रेजा भाषा में लिखी पुस्तकों की पक्षोदगीयो से बचे रहें।

किन्तु हम देख रहे हैं कि एस शिक्षा व आधार स्तभ महाविद्यालय एवं उनके ग्रन्थालय इतने कमजोर हैं कि, पाठशाला ग्रन्थालयो से भी बदतर हैं, जिन्हें हम महाविद्यालय पुस्तकालया की श्रेणी में कल्पि नहीं रख सकते। जो समृद्ध पुस्तकालय है उनमें 50% साहित्य ऐसा पढा होता है जो या तो उपयोग नहीं किया जाता या फिर विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में न रखकर मनमाने ढंग से खरीद लिया जाता है। व्यवस्था भी इस काय के लिए दायी होती है। महाविद्यालय के प्राध्यापकगण अपनी काम आने वाली पुस्तकें विशेषकर अंग्रेजी की, स्वयं व अध्ययन एवं अध्यापन की दृष्टि से चयन करवा कर श्रय करने की अनुमति प्रकट कर देते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष एवं छात्र पाठकों की मांगों का यहाँ नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्राचार्य द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है। ग्रन्थालयो जो छात्रों की मांग को अच्छी तरह जानते हैं चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता।

है। ऐसे समय वाञ्छित हिन्दी पुस्तक के साथ ग्रन्थ हो जाता है। ऐसे समय ग्रन्थ विषयो की अंग्रेजी भाषा में उड़ी पुस्तकें भी अनाविहित रूप में बटनी जाती है। इस पर रोक लगानी चाहिये।

कभी कभी शासन द्वारा दिया जाने वाला अनुदान इतन कम समय में उपयोग करना होता है कि शीघ्रता में “बाजार में जा पुस्तकें उपलब्ध होती है उन्हें ही खरीदना पड़ता है, चाहे फिर वे भी अंग्रेजी भाषा ही की क्यों न हों, किन्ती भी कीमत में क्यों न लेना पड़े। बाद में भले ही ये सिर्फ अलमारिया की शोभा ही बढ़ाते रहें। ऐसा मौका प्रायः सभी प्रकार के पुस्तकालयों के साथ आना सम्भव होता है। इस प्रकार का समय आ पड़ता स्वयं पुस्तकालयाध्यक्ष को पाठकों की रुचि अनुकूल हिन्दी भाषा-पुस्तकों का चयन कर क्रय करना चाहिये तभी हम अच्छे ग्रन्थों के चयन में सफल हो सकते हैं।

(इ) विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकों का चयन—वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हिन्दी भाषा से शिक्षण का महत्व दिया जा रहा है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ हिन्दी से अध्ययन को आवश्यक कर दिया है। जहाँ हिन्दी भाषा नहीं बोली जाती उन प्रदेशों में हिन्दी की विशेष कक्षाएँ विश्वविद्यालयों में चल रही हैं। हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु विश्वविद्यालयीन स्तर की हिन्दी भाषा में ग्रन्थ निर्माण योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। अकादमियाँ इन ग्रन्थों का 40% प्रतिशत खर्च पर ग्रन्थालयों को एवं छात्र छात्राओं को देती हैं। विद्यालयों में इन ग्रन्थों से हिन्दी के अध्ययन में रुचि बढ़ी है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय एवं अकादमियाँ इस कार्य को पिछले 8—9 वर्षों से सतत आ रहे हैं। पत्र-स्वरूप परिणाम अच्छे निकले हैं। अकादमियाँ विश्वविद्यालय स्तर की सदाएँ एवं पाठ्य पुस्तक पाठकों की भाव पर सम्यक् दामों पर पुस्तकालयों को भेजती हैं। इस प्रकार की पुस्तकों का चयन विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए आवश्यक है।

विश्वविद्यालय कुलपतियों द्वारा तत्कालीन लिये निर्णय में यह स्पष्ट कहा गया है कि चार वर्ष के अन्दर विश्वविद्यालयों में पूर्णतः हिन्दी में ही शिक्षण कायम होगा। इनके अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ है। अतः विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में भी पुस्तकों का चयन करते समय सफुल्लित नीति का अनुसरण न कर अपितु मुले हृदय से पुस्तक चयन कर क्रय करना चाहिये। सस्था प्रमुखों, विभागाध्यक्षों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों का यह कर्तव्य हो जाता है कि भारत की एकता को बनाये रखने एवं शिक्षा व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये हिन्दी पुस्तकों का चयन को महत्व दे।

(ई) सामाजिक पुस्तकालयों में—शिक्षण संस्थाओं व पुस्तकालयों व बाद सामाजिक पुस्तकालय ही ऐसे पुस्तकालय हैं जहाँ बड़े-छोटे ग्रन्थों का छोटा-मोटा प्रायः सभी प्रकार के विषयों की हिन्दी पुस्तकें चयन भी करते हैं और पुस्तकालय में ग्रन्थ रखने भी हैं।

सावजनिक ग्रन्थानयन सूची सभी प्रकार के पाठकों की पानवृद्धि हेतु होता है। अतः इन पुस्तकालयों में उनकी रुचि की हिन्दी पुस्तकें अधिकाधिक तादात्म्य में मरीदी जानी चाहिये। हम देखते हैं समाज का 60% वगैरह ऐसा है जो कृषि, उद्योग एवं मजदूरी में लगा होता है। वह अपने पुस्तक के समय हिन्दी मनोरंजन, हार्मर, धर्म, कहानी उपन्यास व विविध विषयों की पुस्तकें पढ़कर अपना समय व्यतीत करते हैं। अंग्रेजी में रुचि रखने वाले बहुत कम पाठक ऐसे पुस्तकालयों में मिलते हैं। उदाहरण के लिये यदि एक सावजनिक पुस्तकालय में यदि 50 पाठक पढ़ने आते हैं तो उनमें 3 या 4 पाठक ही ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से अंग्रेजी विषय की पुस्तकें पढ़ने या घर ले जाने के इच्छुक होते हैं। यहाँ 46 व्यक्ति हिन्दी को ही चाहते हैं। इस उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि एक सावजनिक पुस्तकालय के लिए हिन्दी की पुस्तकें चयन करने से कितने पाठक उन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं।

फिर भी हिन्दी पुस्तकों के चयन में हम निम्न सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिये।

1 पाठकों से मांग पत्र लेकर उनकी रुचि अनुसार पुस्तकों का चयन हो।

2 हिन्दी भाषा में प्रकाशित सभी विषयों की पुस्तकें चयन करने से हिन्दी भाषा के साथ पुस्तकालय का महत्त्व बढ़ेगा।

3 पाठकों का अधिकतम लाभ पहुँचाने वाली सस्ती एवं अच्छी पुस्तकों का चयन करना चाहिये।

4 साधारण एवं विशेष दोनों प्रकार के महत्त्व की पुस्तकें जो पुस्तकालय के उद्देश्यों को फलीभूत करें एवं पाठकों की मांग पूर्ण करें, पुस्तकालय हेतु चयन करना ही जानी चाहिये।

5 पुस्तकालयों को अश्लील, कामुक, जाममी सूनी हत्याकाण्ड से युक्त डकैनी एवं छिछले स्तर के साहित्य में बचाव सुरक्षित रखना पुस्तक चयन सिद्धांतों की गरिमा कायम रखना होता है।

अतः उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखते हुए भारतीय गणतन्त्र की राष्ट्रभाषा हिन्दी को पुस्तकालयों की उन तमाम विषयों में महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिये जो विदेशों से हमारे प्रकाशकों द्वारा भेजी जाती हैं। उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर विज्ञान हेतु वाज्य में भेजना चाहिये। वैसे भी हिन्दी प्रकाशन एवं अनुवाद काय में भारत आज निःसन्देह बहुत आगे बढ़ गया है। भारतीय मानव संस्था, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी एवं कृषि विश्वविद्यालय तनगर ने हिन्दी विषय में प्रचुर मात्रा में प्रकाशन काय किये हैं। सैनिक विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान में भी हिन्दी विषयों की पुस्तकों पर जोर दिया जा रहा है। बाल साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हो रहे हैं। फिर भी हिन्दी के विकास हेतु प्रकाशन के साथ साथ पुस्तकालयों में भी सूक्ष्म-सूक्ष्म पूर्ण ग्रन्थों का चयन होना चाहिये तभी हिन्दी का प्रचार प्रसार एवं विकास होगा।

अध्ययन और स्वास्थ्य

एक ओर शिक्षा राष्ट्र का आधार होती है, तो दूसरी ओर स्वस्थ जन-मानस की उपस्थिति भी राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण बड़ी हानी है। शिक्षा से मानस मस्तिष्क कुशाग्र हाथ है और एक अनुशासना बद्ध राष्ट्रीय चरित्र की ग्रह-मियत देखने को मिलती है। कोई भी देश औद्योगिक वातावरण में अपने राष्ट्र का सर्वांगीण विकास कराने में सक्षम होता है, परन्तु यदि उस देश के नागरिक शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो अपने देश का गुलाम होने से नहीं बचा पायेंगे।

यह बात सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है।" जो नहीं जानते उन्हें जान लेना चाहिये। जो शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ होते हैं वे निश्चय शरीर के लाग माने जाते हैं। ऐसी लाग मानसिक रूप से सामान्य बुद्धि के होते हैं। लेकिन यह बात बड़ा सब युक्ति संगत मालूम पड़ती है कि स्वस्थ शरीर के लोग ही मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं? कहते हैं भौट और बजरंगी शरीर के व्यक्तियों की पुष्टि में बदल जाती है। इस बात की पुष्टि के लिये हम प्रजनी पुत्र हनुमान का वह प्रसंग याद आता है जब सागर तट पर जामवत द्वारा हनुमान जी का अपनी शक्ति का आभास कराया गया था। यदि उन्हें वाकई बुद्धि की शक्ति होती तो वानर समूह के भयभीत होने के पहले ही वे समुद्र का साथ कर लका पहुँच जाते।

उन उदाहरण से स्पष्ट व्यक्तियों में ही बुद्धि का हाना अपवाद सा जान पड़ता है। राष्ट्रपिता गांधी स्वयं शारीरिक रूप से इतने हट्ट पुष्ट नहीं थे कि वे लाठी और बंदूक से अंग्रेजों को अपने देश से भगा दते, किन्तु मानसिक स्वास्थ्य उनका इतना प्रबल था कि उन्होंने विश्व के बड़े बड़े महारथियों को अपने सामने झुका दिया था। इस बात की पुष्टि गांधीजी एवं पंचम जाज की घर पर हुई मुलाकात से होती है।

मैं उक्त प्रसंग का जिक्र यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण समझता हूँ कि पाठक स्वयं यह निष्कर्ष करें कि स्वास्थ्य प्रमुख है या अध्ययन का क्षेत्र। बुद्धि और शरीर का महत्व अपनी अपनी जगह है। यह जरूर मानना चाहिये कि शरीर तन्त्र से ही मानसिक तन्त्र चलता है। यदि मानसिक तन्त्र में किसी तरह का विचार उत्पन्न हो जाता है तो शरीर असहाय एवं निष्क्रिय होने लगता है। इससे जाहिर होता है कि शरीर से अधिक मन का स्वास्थ्य हाना जीवन के लिये अनिवाय है, राष्ट्र हितकारी है। मन को स्वस्थ रखना है तो धर्म दशन तथा

ज्ञान-विज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन सर्वोपरि है। अध्ययन, शिक्षा सुविधाओं, पुस्तकालयों एवं पारिवारिक व सामाजिक जीवन-सम्बन्धों पर निर्भर करता है।

देश जितना थोड़ा-सा वातावरण में युक्त होगा उसकी समृद्धि उतनी ही ठीक होगी। विज्ञान व सुगम भावविचारों, एवं साहित्यिक प्रकाशनों ने विश्व के विस्तारित क्षेत्रों को सभी दृष्टियों से समृद्ध कर दिया है। स्वाध्याय के सुगम तरीके घर बैठ प्राप्त हो जाते हैं। आज सप्ताहों की मर्यादा में प्रति सप्ताह पुस्तकें विभिन्न विषयों में प्रकाशित होनी हैं प्रत्येक दिन उच्च स्तर की दैनिक, मासिक और पाश्चात्य एवं समासिक परिवर्तनों दृष्टिगोचर होती हैं। इससे प्रतिरिक्त हजारों की संख्या में पुरानी उच्च कालों की पुस्तकें हैं जिनकी हम व्यवहेलना नहीं कर सकते। फिर जगतव्यापी साहित्य की अत्युत्तम रचनाओं के प्रतिविद्याल भण्डार हैं। जिन्हें देखकर एक सच्चे मन से प्रगति को मनोकामना करने वाला स्तम्भित हो जाता है।

इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाठकों की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। इसका सबसे प्रमुख कारण उचित पथ प्रदर्शक की कमी है। भिन्न भिन्न अध्ययन कक्षाओं को उनके मन भाषिक साहित्य पढ़ने का नहीं मिलता तो वे क्षोभ और ग्लानि से उत्पीडित हो जाते हैं। देश के नागरिकों का मानसिक स्वास्थ्य प्रबल करता है तो हम सभी प्रकार के पाठकों की पूर्ति सुबोध किंतु सस्ते साहित्य से करना होगा। 80% ग्रामीण इलाकों के लिए ग्राम पुस्तकालयों में ग्रामीण विकास साहित्य वितरित करना होगा। ग्राम विद्यार्थी एवं बच्चों के लिये चरित्र निर्माण सम्बन्धी साहित्य व यूनेस्को की सहायता से बाल-पुस्तकालयों की सहायता करनी होगी। इसी प्रकार युवकों को भी उद्योग एवं रोजगार के साधन उपलब्ध करने हेतु उत्तम साहित्य दिया जाना चाहिये।

वर्तमान में देखा गया है कि सस्ते अश्लील एवं कामोत्तेजक साहित्य ने मानव-स्वभाव में वासनावृत्ति, दुश्चलन, कामुकता, मानसिक विकृति, चोरी-डकती, बलावाजारी, घनाचार एवं राष्ट्र विरोधी दृष्टियों के पडावों को फैला रखा है। देश के प्रति 10 व्यक्तियों में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित हैं इन तीनों में भी एक व्यक्ति ऐसा है जो पुस्तक पढ़ने का महत्त्व नेता है। दो अन्य केवल अपने हस्ताक्षर करने में योग्य हैं। 30 बगल जनता ऐसी है जो पढ़ना नहीं जानती। इनके अध्ययन की सुविधा जुटाना राष्ट्र का परम कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को मद्देनजर रख कर 2 अक्टूबर 1978 से अखिल भारतीय प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। इन नव-साक्षरों के लिये जीवन विकास साहित्य रचना बाँटो को प्रस्तुत करना चाहिये।

देश में बढ़ रहे गंदे व हलके फुलके साहित्य से देश के महान साहित्यकार एवं राष्ट्र निर्माता चिन्तित हैं। प्रत्येक परिवार के मा-बाप इस बात से पीडित हैं कि इनके उच्च इस घटिया साहित्य के कारण विद्रोह कर रहे हैं प्रेम साहित्य

एव चटपट ग्रंथो मे उलभ रह हैं। इम बात क लिये ऐसे ग्रंथो के रचनाकारो अथवा प्रस्ताताओ को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये। तदुपरा त प्रकाशको एव पाठको पर भी अगत जवाबदारी ह। दुरावृत्तिया स छुटकारा पाने एव स्वस्थ बौद्धिक धरातल प्राप्त करन हतु मनुष्य का सदैव मत्साहित्य का अध्ययन एव मनन करता चाहिये। अध्ययन का शरीर, आत्मा एव मन पर गहरा प्रभाव पडता है। चढ़ती जवानी, रात की बाहों मे रगीली रातें, प्यार की सोगात एव चुम्बन की पीडा, इत्यादि पुस्तको को पढ कर यदि पाठक को स्वस्थ मानसिक उपलब्धि होती है तो चंद्रलेखा, गोदान, दिव्या परती परिक्था, मुगनयनी, मानस का हस, परिणीता एव झूठा-सच आदि श्रेणो के उपयासा को पढकर क्या उपलब्ध होता है ?

स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण सदैव महान साहित्य के निर्माण एव अध्ययन मे हुमा है। जिस राष्ट्र का साहित्य (चाह वह लोक साहित्य ही क्यों न हो) मानव के लिये श्रेष्ठ रहा है वह राष्ट्र सदैव विजय चाहिनी पर सवार हो विश्व की सत्कृति और सम्मना का पोषक रहा है। भारत का नाम इसमे प्रथम लिया जावे तो अपवाद नहीं होगा। मिश्र और सिक्खदरिया को तत्पश्चात रख सकते हैं। सप्त संधि के दश भारत की अनूठी प्रसिद्धि विश्व भर मे सांस्कृतिक एव पुरातात्विक रूप मे फैली हुई है।

शिक्षा की स्वस्थ परम्परा एव ग्रंथ निर्माताओ के विषय प्रस्तुतीकरण की ऊचाइया का ही प्रतिफल था कि बंद, उपनिषद महाभारत, गीता एव रामायण जम दुर्लभ ग्रंथो ने सामाजिक एव धार्मिक चेतना जगायी। गीता के अध्ययन ने जिसके प्रस्तोता महाभारत के सरसब्जकर्ता महान कमयोगी कृष्ण थे, शंकराचार्य पद्महंस, विवेकानंद एव महर्षि अरविंद तथा गुरुदेव जैसे तत्त्वज्ञ पाठक दिये। यह स्वस्थ ग्रंथ प्रस्तुतीकरण का ही परिणाम था।

तात्पर्य यह कि (अश्लील काम-वासना, डाका-जनी, भ्रष्टाचार इत्यादि) साहित्य यदि रचनाकार के मनोवैचारिक पृष्ठभूमि की ही उपज है तो आम पाठका की अध्ययन वृत्ति कितनी सशक्त हो सकती है, इसका अंदाजा बलमान मे छप रहे कामोत्तेजक, अपराध साहित्य, जासूसी छूनी एव फूहड़ वृत्तियो से परिपूर्ण प्रकाशन से लगाया जा सकता है।

यदि एक स्वस्थ अथवा अश्लील साहित्य प्रस्तोता एक शिक्षा प्रब सामाजिक उपयास प्रस्तुत करता ह तो उसकी दौड मे हलके फुलके किन्तु अधिक बिकने वाले इस साहित्य के लेखक ऐसे होते हैं जो सामाजिक कोड को उधेड कर रख देने वाले जीवन के रंगारंग जवाबाज उपन्यास लिख देते हैं जो अर्थोपाजन की दृष्टि से प्रकाशकी एव घरलू पुस्तकालयो के लिये भी महत्वपूर्ण होत है। पाठको को ऐसे उपयास अच्छे व हृदयग्राही लगते हैं। और फिर जनता की मांग पर बिनी सुने आम होने लगती है। इस प्रकार के सस्ते कामुक ग्रंथ देश के शहरो (मार्जकल

स्वस्थ एवं अस्वस्थ साहित्य कौनसा है ? इसका फैसला लेखक स्वयं करें जिसे उसे प्रस्तुत करना है। साहित्य पर भी मेन्मरशिप हो जाये तो आधी समस्या अपने आप हल हो जायेगी। मनुष्य यदि श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन अपने पारिवारिक जीवन से ही करे तो निश्चय ही उसका जीवन सुधर सकता है। यदि इस प्रकार के साहित्य से अनुछुआ रह कर वह अश्लील तथा वाजारू घटिया साहित्य का अध्ययन करता एवं करता है तो निश्चित ही अपने साथ औरों का भी इहलोक बिगाड़ता है। लेखका को ऐसे साहित्य प्रस्तुतीकरण पर अवश्य परलोक की यात्रा का लाभ मिलता है।

साहित्य का परिणाम स्वस्थ मानसिक पृष्ठभूमि का निमाण है और अश्लील, गन्दे और योनवृत्ति का साहित्य मन में असयमित कुविचारों को जन्म देता है। अच्छा अध्ययन अच्छे मस्तिष्क की पहचान व खुराक है। सामान्य मस्तिष्क सदैव निम्न श्रेणी के साहित्य को अधिक पसंद करता है। कहीं-कहीं अधिक जटिल साहित्य भी स्वच्छ मानस के लिये घटिया सिद्ध हो जाता है क्योंकि वह साहित्य स्वस्थ मस्तिष्क के ऊपर स गुजर जाता है और समझ नहीं आता। अतः मनुष्य को सदैव स्वस्थ साहित्य का अध्ययन कर स्वस्थ बने रहना चाहिये। स्वास्थ्य प्रद साहित्य के अध्ययन से वैचारिक स्थिति डाबाडोल नहीं हो पाती और स्वास्थ्य भी सुधर बना रहता है।

जब अच्छे साहित्य का अध्ययन मानव करेगा तो मन स्वस्थ होगा और जब मन स्वस्थ होगा तो दुरावृत्तियाँ उससे सहज ही दूर भागेगी। कामुक चल चित्रों का पाठका पर जो प्रभाव पड़ता है उससे कहीं अधिक तत्सम साहित्य का पढ़न से होता है। भारत भूमि के मनीषिया पर एक समय आक्रामकों का ऐसा पहाड़ दड़ा कि उन्हें हिंदू देव-साहित्य अर्थात् सद्ग्रन्थों का गिरी कंदराओं में ले जाकर छिपाना पड़ा था। ऐसे ही अवसर पर कविवर श्रेष्ठ तुलसीदास ने लिखा 'सद्ग्रन्थ पढत कंदरहि महु जाई तेहि अवसर दुरे।' वर्तमान में प्रचलित बाजारू साहित्य के सामने भी शायद हमारे सद्ग्रन्थ ऐसे ही ग्रीहों में छुप गये हैं। क्योंकि अस्वस्थ साहित्य ने आक्रामक हाकर समाहित्य पर हमला बोल दिया है।

गात्रो म भी) के हर गली कूचो, पान ठला, छाट-छोट पाकिट बुक पुस्तकालया एव घरेलू व्यवसायिक पुस्तकालया म ।। पैस प्रतिदिन के मूल्य पर पढ़न को मिनते है । ऐसे पुस्तकालया मे हजारो प्रकार के विविध समम्याग्रा पर प्रकाश डालन वाले सस्त उपयास मिल जाते ह । आज दश मे इस प्रकार के उपयासो का शहर के प्रत्येक माहल्सो म प्रवचन अत्यधिक मात्रा म हा रहा है । इसकी चपेट मे आसपास के गाव भी आ जात है । वर्तमान म प्रकाशन व्यवसाय इतना महगा पड रहा है कि फिर भी घटिया साहित्य का प्रचार बढ रहा है । अध्ययन पाठक भा बढ रहे है ।

ऐसे साहित्य के अध्ययन म स्वच्छ कहलाने वाले पाठक भी पढकर डकती, अपहरण, खूनी एव ए कलास के स्मगलर बन जाते है । इसके पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा अध्ययन से प्राप्त जीवन की अनेक सफलताओ के रास्त मिन जाते है जिनका अनुकरण कर मनुष्य अपने जीवन को बरबाद कर देता है । बालका एव अपरिपक्व युवक युवतिया म प्रेमपत्रो का आदान प्रदान, घर से भाग निकलना चोरी करना आदि अनेक कुसस्कार आ रहे ह । असफलता के बाद और कोई दूसरा रास्ता बचने का नही मिलता तो स्वय आत्मदाह कर अपना जीवन समाप्त कर लेते ह । ऐसी पीढी का स्वस्थ रखने के त्रिय उपरोक्त साहित्य को प्रकाशन होने से रोकना चाहिये । यह सरकार का उत्तरदायित्व है । यदि हम प्रकार के साहित्य पर प्रतिबन्ध नही लगता तो दश की पीढी का भविष्य अधकारमय और जीवन सङ्कटमय होता जावेगा ।

स्वस्थ साहित्य घर घर पहुचान के लिय अध्ययन की सुविधा अर्थात् पुस्तकालयो का प्रसार हाना अतिआवश्यक होगा । इन अध्ययन मडला या केन्द्रो पर हल्का फुल्का साहित्य न पहुचे इसका ध्यान अर्थपाल रखें । प्रकाशन व्यवसाय के लोग अपने देश की पीढी अस्वस्थ न हाने दे । लेखक अपनी लेखनी पर नियन्त्रणमाय यदि व अस्वास्थ्य की साहित्य के निर्माण म लगे है । ऐसे साहित्य क अध्ययन से दश की बाल एव युवा पीढी विमडेयी । सावित्री, हवा देखकर सुघरें सरीके इस्तेमाल करो । पैसो की आधी म अर्धे न हो नही तो मारा देश अधकार से भर जावेगा ।

ऐसा साहित्य जो रुचिकर किन्तु अस्वास्थ्य प्रद है जिसका प्रकाशन असोमित हो रहा है आम पाठको न अध्ययन का अंग हो रहा है । यहा मानव का नजरिया कोई मान नही रखता । अच्छी भावना, अच्छे विचार वाले भी "कुछ पान की ठहापाह" म भटक कर स्वस्थ विचारो का दाहसंस्कार कर देते है और अपने जीवन की मायकता को न समझ जल्नी ही धरती से अपना दामन नीच लेन हें । ऐसा गीन सम्बन्धी साहित्य की पढ कर उत्पन्न हुने मामलो म अधिक होता है ।

स्वस्थ एवं अस्वस्थ साहित्य कौनमा है ? इसका फैसला लेखक स्वयं करें जिस उमे प्रस्तुत करना है। साहित्य पर भी सेन्सरशिप हो जाय तो आधी समस्या अपने आप हल हो जायगी। मनुष्य यदि श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन अपने पारिवारिक जीवन से ही करे तो निश्चय ही उसका जीवन सुधर सकता है। यदि इस प्रकार के साहित्य से अनुछुआ रह कर वह अश्लील तथा बाजार घटिया साहित्य का अध्ययन करता एवं बगता है तो निश्चित ही अपने साथ औरों का भी इहलोक बिगाडता है। लेखकों को ऐसे साहित्य प्रस्तुतीकरण पर अवश्य परलोक की यात्रा का लाभ मिलता है।

साहित्य का परिणाम स्वस्थ मानसिक पृष्ठभूमि का निमाण है और अश्लील, गन्दे और योनवृत्ति का साहित्य मन में अमयमित कुविचारों को जन्म देता है। अच्छा अध्ययन अच्छे भस्तिष्क की पहचान व खुराक है। सामान्य भस्तिष्क सदैव निम्न श्रेणी के साहित्य को अधिक पसंद करता है। कहीं-कहीं अधिक जटिल साहित्य भी स्वच्छ मानस के लिये घटिया सिद्ध हो जाता है क्योंकि वह साहित्य स्वस्थ भस्तिष्क के ऊपर से गुजर जाता है और समझ नहीं आता। अतः मनुष्य को सदैव स्वस्थ साहित्य का अध्ययन कर स्वस्थ बने रहना चाहिये। स्वास्थ्य प्रद साहित्य के अध्ययन से वैचारिक स्थिति डाबाडोल नहीं हो पाती और स्वास्थ्य भी सुदर बना रहता है।

जब अच्छे साहित्य का अध्ययन मानव करेगा तो मन स्वस्थ होगा और जब मन स्वस्थ होगा तो दुरावृत्तिमा उससे सहज ही दूर भागेगी। कामुक चल चित्रों का पाठका पर जो प्रभाव पड़ता है उससे वहीं अधिक तत्सम साहित्य क पढ़ने से होता है। भारत भूमि के मनीषिया पर एक समय आन्नामकी का ऐसा पहाड़ टूटा कि उन्हें हिंदू देव साहित्य अथात सद्ग्रन्थों की गरी कदराओं में जाकर छिपाना पड़ा था। ऐसे ही अवसर पर कविवर श्रेष्ठ तुलसीदास ने लिखा "सद्ग्रन्थ पवत कदरहि महु जाई तेहि अवसर दुरे।" वर्तमान में प्रचलित बाजारू साहित्य के सामने भी शायद हमारे सद्ग्रन्थ ऐसे ही खोहों में छुप गये हैं। क्योंकि अस्वस्थ साहित्य ने आक्रामक होकर सत्साहित्य पर हमला बोल दिया है।

21

मध्य प्रदेश में लोक ग्रन्थालयों का संचालन व संगठन

ग्रन्थालय एक ऐसा स्थान है जहाँ नानाविध विषयों के ग्रन्थों, पत्र पत्रिकाओं, मानचित्र, निर्देशिका चित्र, दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ, सूची एवं सन्दर्भ सूचना स्रोतों का संग्रह होता है। इनका उद्देश्य अध्ययन शोध, अनुसंधान एवं साक्षरता में वृद्धि करना होता है। जो वच्चे अक्षर जान कर चुके ह और उनमें ज्ञान को पाने प्रयत्न नवीन वस्तु (जानवर पक्षी पेड़, फूल, पत्ती, मशीनें यन्त्रादि) के बारे में जाने की इच्छा को पूर्ण करने हेतु बाल ग्रन्थालय व वाचनालयों की सुविधा होती है। बाल साहित्य से युक्त ग्रन्थालय पाठशालाओं एवं सावजनिक क्षेत्रों की सस्याओं द्वारा स्थापित होते हैं।

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के वच्चे भी इनका लाभ लेकर शिक्षा व गुणात्मक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरे और चौथे प्रकार के ग्रन्थालय महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन स्तर की शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान प्रक्रियाओं को निपटाने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष प्रकार के ग्रन्थालय औद्योगिक सम्मानों, प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान केन्द्रों में होते हैं जिनकी मदद से वैज्ञानिक अपने शोध कार्य पूर्ण करते हैं। इस सबके बावजूद ग्राम नागरिकों की पढ़ने की वृत्ति को सन्तुष्ट करने तथा देश में साहित्यिक, सांस्कृतिक, प्राथमिक, राजनैतिक व सामाजिक परिवर्तन की सूचना देन सम्बन्धी जानकारी के लिए प्रत्येक जिले में सरकारी व गैर-सरकारी ग्रन्थालय खोले जाते हैं।

हमारे प्रदेश में भी ग्रन्थालयों व विकास उनके संगठन एवं सुचारु संचालन पर सरकार व जनता ध्यान देती रही है। इसका उदाहरण है, प्रदेश के सभी जिलों में जिला ग्रन्थालयों का सावजनिक उपयोग हेतु खुला रहना। सावजनिक क्षेत्रों में भी ग्रन्थालयों की परम्परा प्रदेश में बड़ी पुरानी रही है।

‘सावजनिक ग्रन्थालय संगठन का स्वरूप’

स्वाधीनता के पूर्व से ही लोगों में शिक्षा व अध्ययन की सुविधा जुटान हेतु समाज सेवी संस्थाओं व व्यक्तिगत लोगों ने शहरी व नगरीय स्तरों में लोक पुस्तकालय खोले थे जिनमें इन्दौर, सागर, खान्पुर, मदनसौर, खण्डवा सतना व जबलपुर शहरों के ग्रन्थालय प्रमुख हैं। ये लोक पुस्तकालय किसी संस्था द्वारा, किसी की स्मृति में या किसी एक व्यक्ति द्वारा दान की गई ग्रन्थों की संस्था से निर्मित किए गए। इन्दौर शहर की “द इन्दौर जनरल लायब्रेरी” श्रीमत् तुकोजीराव

हात्कर द्वारा "किताब घर" के नाम से 1854 में स्थापित की गई थी जो इंदौर शहर के शैक्षणिक इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इसी प्रकार खण्डवा शहर में 1883 में "मौरिम मेमोरियल लायब्रेरी" के नाम (अब भाणिक्य सम्राट के वाचनालय) से स्थापित ग्रन्थालय यहां की साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियां का प्रमुख केंद्र है। इस ग्रन्थालय को भी अपनी मर्यादा 104 वर्षों का है। 1887 में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ के राज्यारोहण के सम्मान में इंदौर शहर में ही इंदौर के तत्कालीन एजेन्ट टू द गवर्नर जनरल ने तीस हजार फुट जमीन पारसियों को देकर "विक्टोरिया लायब्रेरी" की स्थापना कराई। तत्कालीन की दृष्टि से ग्रन्थालय भवनो की दशा ठीक नहीं है परन्तु प्रयास चल रहा है कि ग्रन्थालय भवनो को भी औद्योगिक विकास के अनुरूप अत्याधुनिक बनाया जाय। विक्टोरिया लायब्रेरी को 1983 से रोटरी क्लब द्वारा संचालित किया जा रहा है।

सतना का तुलसी विद्यापीठ "रामभवन" ग्रन्थालय का स्थापना 1939 में की गई थी। इस ग्रन्थालय पर प्रकाश डालते हुए दृष्टान्त राजवंश ने लिखा है कि "यह पुस्तकालय बिना आचार्य का विश्वविद्यालय है जो मूक भाषा में बोलते हुए युगों का सन्देश और आज के जमाने की प्रेरणा पाठकों को पहुँचाता है। यज्ञ की मूल और बालेज की शिक्षा के बाद स्वाध्याय ही शेष बचता है, जिसकी पूर्ति पुस्तकालय द्वारा ही हो सकती है। यह एक ऐसा पुस्तकालय है जो प्रदेश तो क्या देश के अन्य भागों में भी दुर्लभ है।

मन्मौर शहर से 20 किलोमीटर दूर सीतामऊ कस्बे में स्थापित "नट नागर राय सत्यान" एक अत्यन्त दुर्लभ ऐतिहासिक पाण्डुलिपियां फोटो प्रतियां का प्रयास है जिसे "रघुवीर ग्रन्थालय" के नाम से जाना जाता है। यह इतिहास विद् एवं साहित्यकार डा. रघुवीर मिह के अथक प्रयास का फल है। इस विशाल ग्रन्थालय में 1759 से 1830 तक फारसी के हस्तलिखित अखबारों का संग्रह है जो ग्रन्थालय की प्रमुख निधि है। वस्तुतः यह ग्रन्थालय मुसलमान इतिहास के अध्ययन हेतु बहुत सहायक है।

प्रदेश में ऐसे ही कई सावजनिक ग्रन्थालय हैं जिनका संचालन एवं संगठन अपने अपने तरीके से हो रहा है। प्रशिक्षित अधिकारियों व कमचारियों का अभाव, अनुदान की समस्या और सबसे बड़ी समस्या है पाठकों की सेवाएं देने की समस्या। बढते ग्रन्थालय ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों के चपेट में हैं, परिणामस्वरूप अध्ययन के प्रति गम्भीर पाठक इनका समुचित उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि इनमें कार्यरत कर्मचारी उम्र, भावना से नहीं जुड़े रहते हैं जिनसे पूर्णकालिक सेवा भावी भवक जुड़ा होता है। फिर प्रदेश सरकार द्वारा इन पर ना कोई अनुदान है और न इनका विकास का कार्यक्रम। थोड़े बहुत अनुदान के अलावा इन्हें सरकार से कुछ नहीं मिलता। सावजनिक ग्रन्थालय अधिनियम के अभाव में जो जैसे हैं चल रहे हैं।

दूसरी और सरकार द्वारा स्थापित लोक ग्रंथालय है जिनका काय 1948 में प्रारम्भ हुआ था। भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित 1959 की ग्रंथालय सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 4 केन्द्रीय पुस्तकालय इंदौर भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में स्थापित थे तथा जिला के द्वा पर भी सावजनिक जिला ग्रंथालय खोले गये। वर्तमान में विशाल मध्यप्रदेश राज्य में पांच क्षेत्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय एवं 45 जिला ग्रंथालय हैं। सभी ग्रंथालयों में प्रशिक्षित ग्रंथपाल सेवारत हैं। इन ग्रंथालयों का संचालन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रमुख ग्रंथालयों की देखरेख में चलता है। जिला ग्रंथालयों के प्रशासनिक अधिकार जिला शिक्षा अधिकारियों (अथवा उप संचालक शिक्षा) को दे रखे हैं। जिला ग्रंथालयों का कार्य सम्पूर्ण जिले में जनता की अध्ययन रुचि को प्रोत्साहित करना और साहित्य व ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें उन्हें पढ़ने हेतु मुहैया कराने का है। इसके अतिरिक्त ग्रंथ प्रदर्शनी महापुरुषों के भाषणों का आयोजन, ग्रंथालय गोष्ठी एवं विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना प्रमुख है।

चूंकि जिला ग्रंथालयों के पास इतना अनुदान नहीं होता है कि वह विचारण पर, गोष्ठी आयोजना पर व प्रतिष्ठित विद्वानों का बुलाने पर पसा खर्च कर सकें अतः यह सब जनहित के कार्य जिला-ग्रंथालय नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर इन जिला ग्रंथालयों के भवन इतने छोटे व असुविधापूर्ण हैं कि किसी भी प्रकार के आयोजन सम्भव नहीं है। जब लोक ग्रंथालय जनता की रुचियों के उद्घुष्ट केन्द्र होने का दम्भ भरते हैं तब यह जानकर बड़ा ही अपमान होता है कि 75% ग्रामीण जनता यह नहीं जानती है कि उनके जिला प्रमुख शहर में कोई सावजनिक ग्रंथालय भी है। ग्रंथपाल के पास इतने अधिकार नहीं होते हैं कि ग्रंथालय के प्रचार-प्रसार हेतु व्यक्तिगत समता से हटकर कुछ कर सकें। अतः वह सिर्फ ग्रंथों के आदान-प्रदान व जिले के स्कूल ग्रंथालयों में पुस्तकें दान लेने काय भर करता है। स्कूल के ग्रंथालय प्राप्त पुस्तकों का क्या उपयोग करते हैं इससे जिला ग्रंथालय बेगबर रहते हैं। जब जिला ग्रंथालयों में केन्द्रीय खरीद की पुस्तकें, व राजा राममोहनराय फाउंडेशन की पुस्तकें आती हैं और ग्रंथालय में उन्हें रखने की व्यवस्था नहीं होती तब उन्हें जिले के विभिन्न स्कूलों में भेज दिया जाता है। जिला ग्रंथालयों में प्रशिक्षित कमचारियों का भी अभाव सतत बना हुआ है। जिला ग्रंथालयों का कोई संगठित संघ न होने के कारण भविष्य की विकास योजनाएं मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष एवं लोक शिक्षण संचालनालय तक ही सिमट कर रह जाती हैं।

तीसरे प्रकार के ग्रंथालय गांवों की पंचायतों में चल रहे हैं जिनका संचालन पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग सम्हाल रहा है। इन ग्राम पंचायतों में खोले गये ग्रंथालयों का उद्देश्य था कि ग्रामीण जनता को सतत अध्ययन की सुविधा जुटाना, खेती, गृहस्थी स्वास्थ्य व चिकित्सा, पशुपालन व लघु उद्योग धंधा सम्बन्धी

॥ मध्य प्रदेश में प्रकाशित सूचनानुसार "राज्य में 14691 ग्राम पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं पाठक हरिशंकर, मध्यप्रदेश संदेश, जुलाई 1986 पृ 35 एवं ।

पान की पुस्तकें घर तक पठन को देना। ग्रामा में निरक्षर जनता का माधुर बनाने में मदद करना आदि। इन सब ग्रन्थालया की गतिविधियाँ सावजनिक आन्दोलन की निष्प्रीयता एवं ग्रन्थालय अधिनियम की उपगा के कारण आजागी के 40 वर्ष बाद भी बहुत की चाल से चल रही है। जबकि यह माना जाता है कि राष्ट्रीय विकास में लोक-ग्रन्थालया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है पर हमारा प्रश्न व ग्रन्थालया की शा सगठन व संचालन की दृष्टि में इतनी कमजोर है कि नई व्यक्तिगत व्यावसायिक सार्वरी (पावट बुक, स्टार) ग्रन्थालय जगत में उभरकर आ चुकी है जिनमें जासूसी, अपराध कथा, सेक्स व रामाच की किताबें ग्राम जनता को प्रभावित कर रही है। इन व्यावसायिक ग्रन्थालया ने नव ग्रन्थालया व भविष्य का खतरे में डाल दिया है। इस परिवर्तन पर ग्रन्थालय जगत के विचारका का ध्यान देना चाहिए।

प्रश्न में ग्रन्थालय आन्दोलन अधिनियम व सावजनिक ग्रन्थालयो के सुसंचालन एवं सगठन को ध्यान में रखते हुए सबसे प्रथम 1957 में डा एस भार रगनाथन व श्री व्ही जी मोथ के प्रयास से मध्यप्रदेश ग्रन्थालय मण की स्थापना की गई। मण की ईवाइयाँ सभागीय स्तर पर कार्यरत हैं जैम इंदौर मन्भाग ग्रन्थालय सच, भापाल सभाग ग्रन्थालय सच। सच ने प्रदेश में ग्रन्थालय अधिनियम की प्रभावशाली बनाने हेतु अनक प्रयत्न किए किन्तु सगठनात्मक एकरता व राजनैतिक सहायता व सभाव में सफलता नहीं मिल सकी। इसी उद्देश्य में सच का प्रांतीय अधिवेशन 1974 में भोपाल में किया गया। प्रदेश में साव निक ग्रन्थालय सच की स्थापना भी की गई जिनका प्रथम अधिवेशन लण्डवा जिले के बुरहानपुर तहसील में सम्पन्न हुआ। तत्कालीन मंत्रिया श्री ओमप्रकाश रावल एवं क हैयालाल दू गन्नाल व सभापतित्व में दूसरा अधिवेशन भी सम्पन्न हुआ। स्वास्थ्य शासन मंत्री श्री तत्वतसिंह कीर व मुखीधर मण के सद् प्रयास से मध्यप्रदेश सावजनिक ग्रन्थालय अधिनियम का प्रारूप भी विधानसभा पटल पर लाया गया किन्तु कुछ खामिया व कारण यह अधिनियम अभी तक अपना विधिक स्वरूप प्राप्त नहीं कर सका है।

सच पूछा जाय तो सावजनिक ग्रन्थालय अधिनियम प्रश्न में तभी सफल हो सकता है जब सावजनिक क्षेत्रों के ग्रन्थालया से दलीय हस्तक्षेप समाप्त हो, मन मानी नरुम हो और सरकारी तंत्र द्वारा इनका सगठन व संचालन पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षित कमचारिया द्वारा करवाया जाए। बहुततर ग्रन्थालय कुर्सी, पद एवं प्रतिष्ठा व स्वाय में जन अस तोष का कारण बने हुए हैं। इन कारणों का दूर करन व वाद ही ग्रन्थालय अधिनियम की माथकता सिद्ध होगी।

माना कि सावजनिक ग्रन्थालयो- शैक्षणिक विकास में आशातीत सहयोग प्रदान कर प्रदेश की ग्रन्थालय विकास परम्परा का बढ़ाने में सहयोग किया है किन्तु आजकल इन ग्रन्थालया का जा वातावरण बना हुआ है उसे समाप्त करन में शासन का आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय नोपाल एवं ग्वानियर में 6 वीं माह का ग्रन्थालय विमान प्रशिक्षण भी इसी उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया है कि ग्रन्थालय आन्दोलन को एक सुनिश्चित दिशा मिले। जैसे भा प्रदेश के सात विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं दो विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान की जाती है। इन प्रशिक्षित व्यक्तियों का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से भी प्रदेश में ग्रन्थालय अधिनियम जरूरी है। अंतिम रूप में प्रदेश में ग्रन्थालय अधिनियम लागू कर दिया जावे तो अलग अलग स्तर पर चला रहे, अलग अलग विभागों द्वारा संचालित ग्रन्थालय एवं-भूत म बंधन धर्म करने लगे और आज जो भी विद्वानों, विद्वानों ग्रन्थालय क्षेत्र में पड़ी हुई है वे समाप्त होगी।

ग्रन्थालय सभा, कर्मचारियों एवं सरकार को मिलकर प्रदेश की ग्रन्थालय विभाग योजनाओं पर माचना चाहिए ताकि लाइ ग्रन्थालयों का वर्तमान स्वरूप वैज्ञानिक संगठन के रूप में विकसित होकर प्रदेश की जनता का अपनी सेवाएँ देने में सक्षम हो सके। वृहत्तर ता होगा यदि शिक्षा विभाग में चल रहे ग्रन्थालयों के संगठन संचालन हेतु स्वतंत्र संचालनालय हो और लाइ-ग्रन्थालयों के लिए भी लाइ पुस्तकालय संचालनालय बनाए जायें। प्रदेश ग्रन्थालय अधिनियम के सहित इन संचालनालयों को अधिकार व शक्तियाँ प्रदान कर भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्रन्थालयों का केंद्रीय विभाग द्वारा संचालित व संगठित किया जा सके।



अश्लील साहित्य का फैलता जहर

आये दिन समाचार-पत्रों में, रेडियो पर पुस्तक प्रदर्शनियों में एवं गोष्ठियों में अश्लील साहित्य पर चर्चा, परिचर्चा लेख एवं इंटरव्यू घडाघड़ प्रकाशित एवं प्रसारित हो रहे हैं किंतु समाधान के नाम पर हासिल कुछ भी नहीं हो पा रहा है।

आज हम बात से क्यापि इन्कार नहीं किया जा सकता कि अश्लील साहित्य, जैसे बलात्कार एवं यौनवृत्ति के प्रसंगा से युक्त कथाएँ, इंद्रजाल कामिक्स, जासूसी उपन्यास मत्स्यकथा तथा श्रीग्रेजी से अनुवादित कई रोमांच एवं रोमांस से युक्त साहित्य बाजार में बिना रोकटोक घड़त्ले से जिक्र रहा है।

ऐसा साहित्य जो कामुकता जगाता हो युवा दिवा का पथभ्रष्ट एवं दुराचारी बनाता हो व्यभिचार को जन्म देता है और अपराधी वृत्ति जैसे जुआरू व असामाजिक क्रम का प्रथय देना हो, दण के प्रत्येक शहर के गली, माहल्लो, बुक स्टाला तथा मुककड़ों के छोटे-छोटे ठेला रखे अथवा कमरों में बुरी तरह से भरा हुआ देखा जा सकता है। कुछ बड़े शहरों में इस प्रकार के साहित्य को विशेष कक्षों में प्रदर्शित कर रखा जाता है। इस प्रकार का सबसे सस्ता सुलभ एवं कम खर्च का चटपटा साहित्य मुककड़ दुकानों के मिनी पुस्तकालयों से पढ़ने का उपलब्ध हो जाता है। ऐसे साहित्य को अर्धेड उम्र के रंगीले स्त्री पुरुष तो पढ़ते ही हैं साथ ही बच्चे भी इनसे अनछुए नहीं रह पाने परिणाम यह होता है कि पढ़े हुए साहित्य के चित्रित पात्रों को जीने की कल्पना वे करना लगते हैं और कुमारा की ओर बढ़ते जाते हैं। यह क्रम युवा अग्रस्था तक चलते रहने से उनके चरित्रों का निर्माण भी क्या के घटनाक्रम के अनुसृत होना लगता है और अपराध की दुनियाँ में क्रमशः अपराध बढ़ने लगने हैं।

उपरोक्त प्रकार के साहित्य को मुककड़ साहित्य, घासलेटी साहित्य अथवा अस्वाभाविक जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला साहित्य कहा जा सकता है।

इस प्रकार साहित्य को लिखने एवं प्रकाशन करने के पार्श्व में, अथर्वोलुपता सस्ती प्रसिद्धि एवं पाठकों की नमकीन मनोरंजक रूचि का परिचय मिलता है। इस साहित्य में कोई मौलिक वस्तु अथवा ठोस विषय की स्पर्खा का मृजन नहीं होता। लेखक प्रकाशक यह जानते हैं कि वर्तमान में आम लोग किस प्रकार का साहित्य पढ़ने में रूचि रखते हैं बस उसी प्रकार की कथा मार्मिक प्रसंगों से भरपूर उपन्यास, कहानी व प्रेम कथाओं की घटना पर आधारित पुस्तकें छपाने लगती हैं।

पाठकों की कमजोरी को वे अच्छी तरह समझते हुए उनकी मानसिक एवं शारीरिक दुधा का प्रबंध कर देते हैं। रातों रात लेखक प्रशासक एवं पाठक अपने अपने ढंग से ऐसे साहित्य से अपनी हवश पूरी करने में सफल हो जाते हैं। प्रश्न है कि तीना बग के लोग क्या इतन बेपरवाह एवं अनजानी कूपमडुबता का लवादा छोड़े राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, देशवासियों के चरित्र निर्माण एवं साहित्यिक गरिमा का उपहास कर रहे हैं गंधवा पारश्चात्य संस्कृति, कला, साहित्य एवं जीवन विकास की प्रगतिशील परम्परा को भारतीयता का रक्षा कवच बनाना चाहते हैं पर क्या यह सब पनदायी होगा ?

जब ग्रंथों के माध्यम से लेखक चादनी रात, भात का विनारा, सावन की अधुमाती साँझ, वन्द कमरे में प्रेमालाप, बाग बगीचे, आन्नकुज अथवा छबिगृह आदि कथानकों से अपनी रचना का साहित्यिक शृंगार करता है तो पढ़ने वाला के दिल में सहज रूप में एक अजीबो-नारीब कोतुहल पैदा होने लगता है जिसकी परिणति दैनिक क्रिया-कलापों में हानि लगती है। जब परिवार में अघेड माता पिता की खूबि अपने जवान बेटे-बेटियों से लुप्त छिपकर कामुक व अपराध साहित्य पढ़ने की होती है तो कौतुकवश बच्चों के ऊपर मन में इस प्रकार के साहित्य की पढ़ने का सतक जाग उठना स्वाभाविक है।

आज तो इस प्रकार के साहित्य का प्रचलन इतना चरमोत्कर्ष पर है कि समाज का शासक ही कोई बग इसके साहचर्य से बच पाया हो ? इस प्रकार का साहित्य फैशन में जुमार होकर मानसिक विकृति एवं सामाजिक व नैतिक पतन का मूल कारण होता जा रहा है।

फिरमी संस्कृति के बढ़ते स्वरूप ने प्रेम-रोग का जा उपहार हमारी आधुनिक पीढ़ी को दिया है उसकी पीड़ा को हर मा बाप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग रहे हैं। फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित एवं प्रदर्शित होने वाले नारी के मासल दह युक्त अर्ध नग्न चित्रों के मॉडर्न को व बलात्कार के दृश्यों को देखकर अनायास ही युवक युवतियों का कोमल मन एक बारगी मनोवैज्ञानिक प्रभावों से विचलित होकर मचल उठता है, तड़प उठता है। यही तड़प उन्हें प्रियमिलन हेतु आतुर कर देती है और कमसिन भावना में बड़े बाले प्रेमी प्रेमिका अपने नतिक कृत्यों से बखवर अपनी लाज शर्म से बेहया होकर समस्या के दलदल में फसे जाते हैं। यह फिल्मी स्टाइल का प्रेम रोग जिसकी जड़े जड़भर मजबूत होती जा रही है। हर शहर नगर एवं हर गांव में फैल रही है, यहाँ तक की गली-गली मोहल्ला मोहल्ला इस बीमारी से बेइतहा प्रसित है।

इस जीवन सघर्ष में जो जूझकर बच निकलते हैं व अपना सखार बसाने में लग जाते हैं और जो सफल नहीं हो पाते अथवा कि ही कारणों से असफल हो जाते हैं अपराध की दुनिया में पहुँच जाते हैं। एक अपराध अनेक अपराधों को जन्म देता है। इसी में कोई हत्या, कोई शराबी व कोई घणित अपराध करने

का अनुगामी हो जाता है। अपराध एवं सत्यव्याप्ता में जो कुछ घटनाओं के तथ्य होते हैं उन्हीं में अपराधियों को नया माग मिलता है। किसी ग़ुलामी उपास एवं नाटक में चोरी डकैती, प्रेम, व्यापार की नयी तकनीक का उपयोग किया गया हो तो फोरन इस काय को करने वाले अभियुक्त उसे कुछ ही दिनों में प्रयोग में ले आते हैं, परिणाम चाहे उसका कुछ भी हो परन्तु अपने मन की वे कर ही लेते हैं।

इस प्रकार समाज में विकृतियाँ पैदा करने वाला यौनवृत्ति व अपराधी घटनाओं से परिपूर्ण जामूसी तथा रामानी विद्या का साहित्य लिखा ही नहीं जाना चाहिए। प्रकाशक मध्य द्वारा ऐसे साहित्य के प्रकाशन पर आपत्ति उठाकर रोक लगाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। पाठकों को भी ऐसे साहित्य से बचना चाहिए अथवा इस प्रकार के अश्लील साहित्य का पलना जहर मानव समाजरूपी शरीर में घुसकर समाज की बाल बिशार एवं युवा पीढ़ी का जहरीला कर देगा और फिर घम, मस्कुति, सम्यता, इतिहास एवं साहित्य के नाम पर कुछ अवशेष भी नहीं रह पायेगा।

23

पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉ रंगनाथन

भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पितामह के रूप में पूजनीय एवं प्राण स्मरणीय पद्मश्री डॉ सियाली रामामृत रंगनाथन का दिवंगत हुए आज पूरे पत्र-पत्र हो रहे हैं। आज उनकी पद्महवीं पुण्य तिथि है। भारतीय ग्रन्थालय-जगत शासन तथा जनता की ओर से तो धनाय था ही आज अपने जनक से भी धनाय हा गया था। भारत में पुस्तकालय आन्दोलन के एक स्वर्णिम युग का सूर्य अस्त हो गया। ये महान कमठ तपस्वी परिश्रमी, लगनशील, कुशाग्र बुद्धि व पारंगत पुरुष डॉ सियाली रामामृत रंगनाथन थे, जिन्होंने मद्रास राज्य के सियाली नामक स्थान पर 9 अगस्त 1897 का जन्म लिया था।

इनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा सियाली के हिंदू हाई स्कूल में पूर्ण हुई। 1909 में मद्रास के त्रिनिचियन कॉलेज में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लिया। स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों ही परीक्षाओं आपने प्रथम श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त कर पास की।

जीवन के 25 वसन्त पार कर मद्रास राज्य के शासकीय महाविद्यालय में गणित के व्याख्याता हुए। आपने विद्यार्थियों के मध्य एक विशेष स्थान बना लिया। कुछ दिनों बाद 1924 में आपका मद्रास विश्वविद्यालय के प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। ग्रन्थपाल के पद पर कामरत रहते हुए आपका पुस्तकालय विज्ञान के प्रसार हेतु “ब्रिटिश म्यूजियम” पुस्तकालय जो विश्व के महान पुस्तकालयों में से एक है की ग्रन्थालय प्रणाली का अध्ययन करने हेतु लंदन आने का सुयश मिला।

डा साहब ने अपने लंदन प्रवास के दौरान विभिन्न शैक्षणिक, व्यवसायिक, तकनीकी एवं शोध संस्थाओं के पुस्तकालयों का सूक्ष्म अध्ययन एवं अवलोकन किया। तत्कालीन विभिन्न वर्गीकृत प्रणाली न उनकी गरिमा को आघात पहुँचाया और ये उन वर्गीकरण प्रणालियाँ से सतुष्ट नहीं हुए अतः उन्होंने स्वनिर्मित वर्गीकरण प्रणाली बनाने का निश्चय कर लिया।

यूरोपीय देशों की यात्रा से अपने देश आने समय उनकी उत्कृष्ट बुद्धि में किन्हीं अज्ञात सूत्रों, नियमों सिद्धांतों, ने जन्म लिया। फिर क्या था, बस ग्रन्थालय विज्ञान के प्रथम पंच सूत्रों का प्रतिपादन जहाँ से आत-आत ही हा गया। पुस्तकालय वर्गीकरण की रूपरेखा का पूरा खाका इनके दिला दिमाग पर खिंच

गया। इह पच दाशनिक सूत्र ही कह जाने चाहिए, जिन्तान विश्व के ग्रन्थालय ग्रन्थालयन एव पुस्तकालय विज्ञान को एक नया मोड़ दिया। उनका कहना था ग्रन्थालय म पुस्तकें (1) उपयोग क लिये ह। (2) प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। (3) प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक हो। (4) पाठक का एव कमचारियों का समय बचाओ। (5) ग्रन्थालय एव विज्ञानशील निकाय है।

राष्ट्र एव परराष्ट्र वासिया के दिलो दिमाग पर इन पांच नियमों का प्रभाव छोड़ना उनके क्रियाशील मस्तिष्क के भोज्य पदार्थ 'पुस्तक' के महत्व का जनता म लाना एव प्राचीन सिद्धांत "पुस्तकें सुरक्षा क लिये है" का खण्डन करना ही उनका एक मात्र लक्ष्य था।

ससार भर म प्रचलित विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियाँ जैसे दशमलव वर्गीकरण विस्तारणीय वर्गीकरण, लायब्रेरी आफ ब्रिगेस क्लासीफिकेशन, विषय वर्गीकरण पद्धतियाँ का आपने सूक्ष्म एव गहनतापूर्ण अध्ययन किया और वतमान ज्ञान-जगत क विभिन्न आधुनिक विषयों की शाखा, प्रशाखायाँ को इन पद्धतियों में समाहित करने की प्रसमयता का दखत हुए रचनायन न मद्रास विश्व-विद्यालय म 1925 ई. म स्वनिर्मित (ड्विन्डु वर्गीकरण) पद्धति का प्रन्वपण किया एव प्रारम्भ म 20,000 ग्रन्थों का वर्गीकरण कर कायदप में परिणित किया। एस पद्धति ने सफलता प्राप्त की। डा साहब के नेत्रों म अद्वितीय चमक आ गई।

अथक प्रयत्नों से चमत्कार पर चमत्कार हुए ग्रन्थालय विज्ञान विषय पर आपकी मौलिक कृतियाँ प्रकाशित होने लगी। कुछ प्रमुख पुस्तकों का नाम य हैं।

(1) फाइव लाज आफ लाइब्रेरी साइंस, 1931 (2) लायब्रेरी डवलप-मेंट प्लान। (3) क्लासीफाइड कैटलॉग कोड। (4) लायब्रेरी मनुअल। (5) लायब्रेरी एडमिनीस्ट्रेशन। (6) सदभ सेवा (7) डाक्यूमेंटेशन।

इसके अलावा राज्या में सभा की स्थापना, ग्रन्थालय विज्ञान के शैक्षणिक सत्र सावजनिक पुस्तकालयों की ग्रन्थालय, चल ग्रन्थालयों का निर्माण, सभी एक के बाद एक प्रारम्भ हुए। धीरे धीरे इनकी रयाति भारत के सभी क्षेत्रों म हुई। भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व० डा० राधाकृष्णन के कहने पर 1945 म बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय म ग्रन्थपाल एव प्राध्यापक के पद पर कायदत रहे। 1946 में दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष का भार एव शिक्षण काय सम्हाला-पुस्तकालय विज्ञान विषय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया। अखिल भारतीय पुस्तकालय सघ की 1946 से 1953 तक आपने अध्यक्षता की ओर भारत सरकार की कई पत्र पुस्तकालय विकास क सम्बन्ध में प्रस्तुत किये।

1956 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुस्तकालय विज्ञान विभाग के पदेन विभागाध्यक्ष रह। बाद म भी उन्हीं की देख रेख में विचारानुसार पुस्तक

पानय भवन का निर्माण काय भी करवाया गया। 1962 में बलकृष्ण में इण्डियन स्टूडेंट्स क्लब इन्स्टीट्यूट एव बंगलौर में डी आर टी सी की स्थापना की जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डी आर टी सी की स्थापना के बाद से आज तक आप आनन्दरी प्राध्यापक के पद पर सेवारत थे।

यशस्वी पदों की नियुक्ति एवं विशिष्ट सम्मानों की स्थापना के साथ ही आपका लेखन काय भी प्रारम्भ रहा। 1939 में फाइव लाज ऑफ लायब्रेरी साइंस मूल ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। 1933 में ट्विब्लु वर्गीकरण ग्रन्थ दो अत्यन्त सूक्ष्म खण्डों में प्रकाशित हुआ। तब से आज तक इस ग्रन्थ के सात संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अभी तक आप कई पत्रिकाओं का सम्पादकत्व एवं हजारों पत्र पत्रिकाओं में लेखनीय काय सम्पन्न कर चुके हैं। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान विषय पर ही लगभग 50 से अधिक मौलिक ग्रन्थों की रचना की जिनका उपयोग देश विदेश के पुस्तकालय एवं पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के विद्वान अध्ययन कर रहे हैं।

अपनी आयु के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपके शिष्या, शुभचिन्तको, एवं हितैषियों "अभिनन्दन ग्रन्थ" विभिन्न सभा एवं संस्करणों के माध्यम से प्रकाशित किया था। पुस्तकालय आन्दोलन जगत के इस कमठ योगी ने अपने जीवन में कई सर्वोत्कृष्ट पदों को प्राप्त किया। सन् 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको 'डॉ आफ लेटर्स' की उपाधि से विभूषित किया। 1957 में भारत सरकार ने 'डॉ पद्मश्री' की उपाधि से अलङ्कृत किया। भारत में ग्रन्थालय विज्ञान के जनक को उनकी विशेष सेवा हेतु 1965 में ग्रामन द्वारा 'नगनल रिसर्च प्रोफेसर आफ लायब्रेरी साइंस' से सम्मानित किया। इन प्रकार बहते हुए सम्मान एवं उपाधियाँ की श्रेणी में भारत के अलावा विदेशों में भी इनका काफी मान सम्मान एवं प्रभुत्व रहा।

अमेरिका के पीटमबर्ग विश्वविद्यालय ने आपको "डॉक्टरेट" की उपाधि दी। अमेरिकन पुस्तकालय संघ द्वारा आपका पुस्तकालय विज्ञान का महत्वपूर्ण पदक "मार्येट मन अवार्ड" प्रदान किया गया। आप अमेरिकन पुस्तकालय संघ के सत्रिय सदस्य हैं। एवं ब्रिटिश पुस्तकालय संघ के आप आजीवन उपाध्यक्ष रहे हैं।

जब भी आप विदेश भ्रमण हेतु आमन्त्रित किये जाते, आपका समय आपण लेखमाला, विचार-विनिमय, वाद विवाद एवं पत्रग्रहण में ही व्यतीत होता था।

अनेकानेक पद एवं अलङ्करणों से सम्मानित डॉ रघुनाथन ने अपना सार्वभौम जीवन पुस्तकालय विज्ञान के विकास में लगा दिया। त्याग और तपस्या की दिग्गमिनी ने अपने जीवन की अजित राशि में से 1 लाख रुपये 1965 में मद्रास

विश्वविद्यालय को "शारदा रगनाथन चैयर" की स्थापना के लिए दान दिया। इस प्रकार पुस्तकालयों के द्वारा देश में अनेक स्वाध्याय एवं शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का बीड़ा आपने उठाया। अपनी अति वृद्धावस्था में भी आप 12-13 घंटे निरंतर कार्यरत रहे। कार्यरत रहते हुए दश में अनेक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जिससे आने वाली नव-सीढ़ी दश के विकास के इस आंदोलन को आग बढ़ाय।

ऐसे मधुर भाषी, अंग्रेजी के पण्डित, गणित के समझ डॉक्टर रगनाथन जो कि ज्ञान गया के भागीरथ थे, मनीषी थे, अपने ज्ञान गीता की शतधार विश्व के पुस्तकालय आंदोलन जगत में बिखर गये।

तेज और प्रकाश के इस पुंज ने योजना आयोग, वेतन आयोग एवं कमेटियों को अपनी प्रखर बुद्धि से एवं समरूप प्रदान किया। अनेक शिक्षा-प्रद लेख, हितोपदेश दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक लेख एवं ग्रंथों का निमाण किया। मद्रास, आंध्र प्रदेश मैसूर एवं महाराष्ट्र राज्यों में ग्रंथालय अधिनियमों को स्वीकृत कराने का पूरा श्रेय भी आपको ही था।

व चाहते थे कि पुस्तकालयों का प्रचार एवं प्रसार इतना हो कि कोई भी राज्य बिना पुस्तकालय संग्रह एवं अधिनियमों के न रहे। वे जानते थे कि इन्हीं पुस्तकालयों में देश की अथाह ज्ञान राशि सुप्त है जिसका उपयोग हमारी ग्रामीण एवं शहरी जनता को करना चाहिये। उनका यह स्वप्न था कि मकमूलैटिंग लायब्रेरीज के द्वारा ग्राम-ग्राम को पुस्तकालयों से जोड़ दिया जाये ताकि ग्रामीण निरक्षरता का अन्त पुस्तकालयों में उपलब्ध नवीन ग्रंथों को पढ़कर, सुनकर या चलचित्र दिखाकर किया जा सके।

इधर प्रौढ़ शिक्षा का माध्यम भी पचायता द्वारा चलाये जाने वाले पुस्तकालयों का बनना था, जिससे समाज कल्याण का नया रूप स्पष्ट होता, किंतु यह सब कुछ एक दिवा स्वप्न ही रहा। पुस्तकालय जगत के "कुलदीप" के अघकार में विलीन हो जाने से देश की भारी क्षति पहुँची है जिसकी पूर्ति करना तो कठिन है, किंतु शासन एवं उनका अनुयायियों के सहयोग से कुछ क्षतिपूर्ति कर डॉ. रगनाथन जस कमठ विद्वान पुरुष के सपनों को पूरा किया जा सकता है।

पचवर्षीय योजनाओं में प्रौढ शिक्षा एवं पुस्तकालय

(1)

ईश्वर पर भट्ट विश्वास तथा भाग्य के भरोसे जीवन यापन करने वाले भारतीयों की आत्मीय, अज्ञानता एवं पिछड़पन के अभिशाप न यदि भारत को सदियों पूर्व गुलामी की जजीरो में जकड़ा था तो वर्तमान ज्ञान व शिक्षा के 'यापक' प्रचार-प्रसार ने भी उसे प्रजातन्त्रीय शासन के अनुरूप विचारों से पूर्ण स्वाधीन नहीं बनाया है। 37 वर्ष के विस्तृत युवा काल तक राष्ट्र की 30 करोड़ आबादी शिक्षित होने की ऊँचापोह में जनतन्त्रीय प्रणाली की विशेषताओं का लाभ पाने में बचिन रह रही है।

इसी अशिक्षा की वचकता को दूर करने के प्रयास 1947 के बाद से भारत में शुरू हो गये थे और बहुत हद तक करांडा रूप 'समाज शिक्षा' के नाम पर आज तक पानी की तरह बहाया गया। 'फिर भी आज हमारे देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में निरक्षरों की संख्या 20 करोड़ से भी अधिक है। लगभग 80% महिलाएँ निरक्षर हैं। जबकि पुरुषों की निरक्षरता तबरीबन 52% है। इन सबको बुद्धि सम्पन्न बनाने का बीड़ा अखिल भारतीय प्रौढ शिक्षा मण्डल एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को ने उठाया है। भारतीय पुस्तक-प्रकाशक संघ ने भी यह स्वरूप किया है कि सन् 2000 तक देश से निरक्षरता को समाप्त कर दिया जावेगा किन्तु यह कैसे होगा इस पर हम आगे विचार करेंगे।

स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त राष्ट्र को नई दिशा मिली। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति खूब हुई। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रौढ शिक्षा को 'समाज शिक्षा' मुहिम घोषित किया।

'शिक्षा मंत्री आजाद ने स्पष्ट घोषणा की कि प्रौढ शिक्षा के अतगत सामाजिक चेतना के विकास पर भी बल दिया जाय। फलतः समाज शिक्षा का एक 'पंच सूत्री कार्यक्रम बनाया गया।¹ तिस पर भी शिक्षा का प्रतिशत मन्त्रोपजनक नहीं हुआ। निरक्षरों का साक्षर बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ही कई संकल्पनाओं ने जन्म लिया। जैसे क्रियात्मक साक्षरता, अनवरत शिक्षा तथा

अनीपचारिक शिक्षा आदि। "1951 में यूनेस्को के सहयोग से दिल्ली सांख्यिक पुस्तकालय में ग्रामीण वयस्का के लिए चन्ते फिरन पुस्तकानया की योजना आरम्भ की गई।² इसने अतिरिक्त कई प्रौढ पाठशालायें मुलवाई गई, पचायतो को ये काय सौंपे गये किन्तु परिणाम सतोपजनक नहीं निकले। सन् 1951 की तुलना में देश में 1961 तक निरक्षरों की मर्या में वृद्धि ही हुई है। सन् 1951 में 20 करोड़ लोग निरक्षर थे, सन् 1961 में 36 करोड़ लोग निरक्षर हो गये जबकि सामरता का प्रतिशत 1951 में 16.6 था और 1961 में 24% तथा 1966 में 28.6% तक बढ़ गया।"³ यह अनुपात घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है जिससे यह विदित होना है कि सरकार द्वारा घोषित प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों को सम्बन्धित विभागों ने या तो गम्भीरता से नहीं लिया, या फिर निरक्षर जनता ने साक्षर बनना स्वीकार नहीं किया। यदि नाग्न की अशिक्षित जनता ने इसमें रुचि दिखाई तो फिर अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं हो सका। इससे स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्र भारत के योजनाकारों ने ही इनको आगे फलने फूलने से रोका और स्वयं को अधिक साधन सम्पन्न व सुशहान किया।

योजनाकार बबरराय ने अपने लेख 'वे अपने नियमों का खेल खेलते हैं' में योजनाकार का याजना से कितना वास्ता होता है इस सम्बन्ध में लिखत है "देहात के गरीबों के नाम पर योजनाएँ बनाना आजकल फैशन सा बन गया है। इसमें "माडलो" का खेल दिखाकर और बड़े बड़े घाट टाग कर विश्वास के साथ यह जताया जाता है कि याजनाकारों द्वारा माची गई खास-खास परिस्थितियों में लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। अनपढ़ गरीब किसान और उससे थाल-थच्चो के फायदे के लिए झोची गई योजना पर उस किसान की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह बताना तो योजनाकारों का बायें हाथ का खेल है। पर असलियत एवढम अलग है।"⁴ यह है हमारे योजनाकारों की योजनाएँ। ऐसी दशा में हम कैसे अविश्वास न करें कि स्वातन्त्रोत्तर भारत में प्रौढ-शिक्षा का योजनाकारों ने 80% जरूरतमंद ग्रामवासियों के लिए दिल्ली, बम्बई, मद्रास व बलबत्ता में बैठकर योजना बनाई। किन्तु पुस्तकालय विज्ञान (बता) के क्षेत्र में तथ्याधिकृत योजनाकार डा रंगनाथन ने ऐसा कुछ होना से अपने आप को बचाया था। उन्होंने सम्पूर्ण देश के लिए प्रांत वार अलग अलग पुस्तकालय विभागों की योजनाएँ सरकार के समक्ष प्रस्तुत कीं। स्वयं के मद्रास राज्य में पुस्तकालय अधिनियम का सवप्रथम शुभारम्भ करवाया। ग्राम ग्राम घूमकर ग्रामीणों की मनोदशा, उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन किया और मार प्रदेश में चल ग्रन्थालयों की व्यवस्था का प्रावधान किया। इसी प्रकार की सिफारिशें हर राज्य के लिए पुस्तकालय सलाहकार समिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने की थी किन्तु शासन के उच्चाधिकारियों ने उनका वह मनना पूरा नहीं होने दिया। अब वह मनना ही है। इसी प्रकार भारत की सामुदायिक विकास एवं पंचवर्षीय योजनाओं

कहानियाँ हैं जिनके अध्यक्षा ने योजनाओं को साकार करने की अनुमतायें तो की किन्तु सम्बंधित विभाग के वायपालन अधिकारियाँ न क्या उद्देश्य पूरा करने में अपनी राष्ट्रीयता का स्वस्थ परिचय दिया ? नहीं। इसका एकमात्र पुष्ट उदाहरण है सम्पूर्ण भारत के गाँवों की पंचायतों में खाली गये पुस्तकालयों जिनका सम्बंध जिला-पुस्तकालय से रखा गया था, किन्तु इसी बीच पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा भी कुछ योजनाएँ प्रस्तावित की गई थी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत पुस्तकालयों में ग्रामीण नागरिकों को उनकी जरूरत की अध्ययन सामग्री पढ़ने हेतु दी जानी थी। अतः जिला प्रशासकों के अधिकार-क्षेत्र समाप्त हो गये। इसका सीसरा कारण यह था कि जिला शिक्षा अधिकारियों ने ग्रामालयों को दी गई बाह्य (जीप) अपने अधिकार में कर ली तब जिला प्रशासकों का सम्भव ग्रामीण पुस्तकालयों से समाप्त प्रायः हो गया और पंचायत विभाग ने पंचायत पुस्तकालयों को अपना अधीन रखा। इन पुस्तकालयों में ही प्रौढ़-शिक्षा कक्षाएँ क्रियावित्त करना प्रस्तावित थी। पंचायत व समाज कल्याण विभाग ने कुछ समय तो इन्हें चलाया लेकिन सन् 1958-59 के आत आत तक ये सभी समाप्त हो गये और लगभग 1978 तक उनकी वही दशा रही। 1978 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बाद फिर से इस और योजनाकारों व शिक्षाविदों का ध्यान गया है। फिर भी कोई बड़ी पहल में आती हुई अब भी छोड़ दी गई है वह है गाँव-पुस्तकालयों के विस्तार व राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति व बारे में, जिसके सूत्र में पूरा-दश वैधता है पूरा प्रौढ़ शिक्षा-कार्यक्रम सम्पन्न हो सकता है परन्तु अब जिन लोगों ने इस कड़ी को पकड़ा है उन्हें ही यह जानकारी देनी है कि पंचवर्षीय योजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के साथ पुस्तकालयों की क्या भूमिका थी।

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956)—यह देश की प्रथम योजना थी जिसमें 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर से प्रत्येक विकास खण्ड तक दो समाज शिक्षा अधिकारी (एक पुरुष एक महिला) नियुक्त किये गये (जो सम्भवतः ग्राम सेवक एवं ग्राम सेविका थे) दोनों अधिकारियों के मुख्य कार्य निम्न थे —

(अ) साक्षरता आंदोलन चलाना (ब) ग्रामों में वाचनालय स्थापित करना (स) प्रदर्शनियों का आयोजन तथा सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना था।

उपरोक्त आयोजनानुसार शिक्षा प्रसार में सक्रीय सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे देश में सन् 1955 में “ग्रामालय सुधार योजना” कार्यावित्त की गई। जिला एवं ग्राम स्तर पर वाचनालय एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को शिक्षित बनाना एवं पुस्तकालयों के माध्यम से शिक्षाप्रद पुस्तकों प्रदान करना था।

पुस्तकालय मुधार योजना से साक्षरता वृद्धि में काफी सफलता प्राप्त हुई। बाद में यह योजना सिर्फ बागज पर ही रह गई "प्राप्त आंकड़ सिद्ध करते हैं कि 14 वर्ष से अधिक के आयु-वर्ग में अशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या जो वर्ष 1959 में 17.68 करोड़ थी, दिसंबर वर्ष 1977 में अनुमानित 22.65 करोड़ हो गई।" जनता कानून की स्थापना से भी कई विशेष लाभ नहीं हुआ। निरक्षरों को साक्षर बनाने का काम पुस्तकालयों (जिला पुस्तकालय) व अधिकार समाप्त कर दिया गया। ग्राम सेवक कृषि कार्य में लगा दिये गये। महिला ग्राम सेविकाओं को सांस्कृतिक एवं मनोरंजनार्थक कार्यक्रमों में उतारा दिया गया। लम्बे समय से शुरू हुई योजनाएँ एवं वे बाद एवं शुरू हुई और शीघ्र समाप्त होकर पुनः नयी समस्या के माध्यम पदा हो गई। प्रौढ़ शिक्षा अभियान जो सही मायने में जिला प्रशासन को चलाने व वह शिक्षा अधिकारी समाज सेवा विभाग, पंचायत विभाग और अब विभिन्न समस्याओं के भ्रम हो गये।

अतः 'यह कहना सम्भवतः अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि सुव्यवस्थित पुस्तकालय सेवा की और सभी सम्बंधित पक्षों की उदासीनता के कारण प्रौढ़-शिक्षा तथा शिक्षा के गुणात्मक विकास की अन्य योजनाएँ अपने अपने निर्धारित लक्ष्यों के भौतिक पक्षों को प्राप्त न कर पायी और इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति तथा संसाधनों का वांछित उपयोग नहीं किया जा सका।'"

इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा का बुनियादी नींव का ढहना पुस्तकालयों की उपेक्षा से शुरू हुआ।

(2) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा व पुस्तकालय (1957-1961)—यह योजना प्रथम योजना से कहीं विशाल थी जिसमें समाज शिक्षा की कक्षाओं का और अधिक विस्तार किया गया। समाज-शिक्षा के कार्यक्रमों एवं संगठन कर्मियों का प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा साहित्य का प्रकाशन किया जाने लगा। मध्य प्रदेश राज्य में केन्द्रीय शासन की मदद से इंदौर में प्रथम समाज शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई।

यूनेस्को एवं अमेरिका के सहयोग से 1956 में ही दिल्ली में "राष्ट्रीय मूल-भूत शिक्षा केन्द्र" खोला गया। 1958 में पुस्तकालय अध्यक्षा के आभाव की पूर्ति हेतु दिल्ली विश्व विद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान का केन्द्रीय संस्थान खोला गया। नव साक्षरों के लिए दिल्ली में ही "राष्ट्रीय पुस्तक-त्रास (National Book Trust) की स्थापना भी की गई। यह सब इसलिए किया गया ताकि ग्राम-ग्राम फने तत्कालीन ग्रामीण पुस्तकालयों में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित प्रशासकों का निर्माण किया जा सके। इसी भावना से प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र खोले गये। आज पूरे देश में 48 विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय

विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है फिर भी ग्रन्थपाल लोक-पुस्तकालय अथवा राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के अभाव में साक्षरता अभियान में सहयोग देने में वंचित है।

निश्चित ही "द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस योजना को समुन्नत किया गया था। 1960-61 में प्रौढ विद्यालया की संख्या 62,895 और पाठकों की संख्या 94,74,606 थी। इस वर्ष प्रत्येक प्रौढ की शिक्षा पर 6.22 रुपये व्यय किए गये"। 1951 की तुलना में 1961 में साक्षरता 17 से 24 प्रतिशत हो गई किंतु निरक्षरों की संख्या 29.8 करोड़ से बढ़कर 33.4 करोड़ हो गई। इस प्रकार साक्षरता के प्रतिशत बढ़ने के साथ ही निरक्षरों की संख्या भी बढ़ती ही गई।

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रौढ शिक्षा एवं पुस्तकालय (1962-66)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में योजनाकारों शिक्षाविदों व राजनीतिज्ञों से प्रौढ शिक्षा के लिए जो काम हुए थे वह तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में विचारणीय नहीं बन पाये और योजना की मूलभूत दिशा ही बदल गई। देशकाल की परिस्थितियां ने इसे प्रभावित किया। भारत-चीन युद्ध के कारण, सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा पाया फिर भी देश की समाज सेवा संस्थाओं ने 'ग्राम शिक्षण मोहिम' जैसी संस्थाओं के द्वारा निरक्षरों को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया।

तृतीय योजना में यह काम और आगे बढ़ा और 1965-66 में प्रौढ विद्यालय 2,16,812 तथा इनके पाठकों की संख्या 16,47,541 हो गए। प्रत्येक प्रौढ पर इस वर्ष 3.39 रुपये शिक्षा हेतु व्यय किया गया।¹⁸ अब तक यह दलील दी जाती रही कि जो अभी तक साक्षर बन रहे उनके लिए वाचनालय एवं पुस्तकालय खोले गये। किन्तु उनमें जाने वाले पाठक नहीं मिल अथवा ग्रन्थालयों पर ध्यान नहीं दिया गया अतः उन्हें बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि शिक्षा आयोग ने अपनी सिफारिशों में पुस्तकालयों के विकास पर जोर दिया किन्तु उन सिफारिशों का क्रियान्वयन ही नहीं हो सका। शिक्षकों को मालूम था कि यदि ग्रन्थपालों का महत्त्व बढ़ गया तो विद्यार्थियों की हमारे प्रति श्रद्धा क्या होगी, अतः ग्रन्थालयों के द्वार अधिक दिन तक खुलने ही नहीं दिए गये।

(4) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रौढ शिक्षा एवं पुस्तकालय (1967-74)—जब दिन-दिन निरक्षरों की संख्या अधिक बढ़ने लगी तो साक्षरता का प्रभावशाली बनाने के लिए ग्रामीण-क्षेत्रों में पुस्तकालय खोलने की अनुशंसा पर जोर दिया गया। फलस्वरूप देश भर में पुस्तकालय खुले। किन्तु इनका कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं बनाया गया। राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाकर प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को भी इनके साथ जोड़ा गया होता और जिला ग्रन्थपाल के हाथ में यह पूरा काम सौंपा

गया होता तो निश्चित ही कुछ अच्छे परिणाम आ सकते थे। खेद है, यह नहीं हो सका। इस याजना काल में ही साक्षरता का प्रभाव बनाने के लिए "समाज शिक्षा के कार्यक्रमों और पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।" 1969 में एक ऐसी परियोजना चलाई गई जिसका उद्देश्य 10 प्रतिशत जिला में शत प्रतिशत निरक्षरता का उन्मूलन था। 1969-70 में समाज शिक्षा-समस्याओं की संख्या 209,701 थी जिनमें 21,85,795 प्रौढ़ पाठक थे। प्रति प्रौढ़ शिक्षा के लिए किया गया व्यय 2 89 रु० था।¹⁰

चूँकि अभी तक गांवों में पुस्तकालयों का अस्तित्व पहले की तुलना में कम हो गया था फिर भी ग्रामपंचायतों का प्रशिक्षण प्रारम्भ रहा साथ ही गांवों में प्रौढ़ पाठशालाएँ चली ही नहीं तब भी समाज शिक्षा के कार्यक्रमों प्रशिक्षण पात रहे और देश की आर्थिक हानि होती रही। योजना के उद्देश्यों के अनुसार जिस प्रकार ग्रामीण जनता को साक्षर बनाने का उपक्रम था वह उतना सफल नहीं हुआ जितना होना था। जब तक सामुदायिक कार्यक्रम एवं विकास खण्ड थे तभी तक ये रहे बाद में समाप्त हो गये। समाज कल्याण विभाग ने पंचायतों को जो ग्रामालय सौंप रखे वे शासन की गलत नीतियों का शिकार होकर बंद पड़े रहे।

यूनेस्को जैसी अंतराष्ट्रीय संस्था ने इस क्षेत्र में अवश्य ही प्रशंसनीय काम किया। संस्था को विश्व में शिक्षा के बढ़ते राक्षस का आभास हो गया अतः उसने प्रत्येक देश को सहयोग प्रदान करने का मकल्प लिया। नव साक्षरों के लिए विभिन्न भाषा व लिपियों में पुस्तकों का भारी संख्या में प्रकाशन किया। इसके विपरीत भारत की समाज सेवा संस्थाओं एवं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद को थोड़ा-थोड़ा कमीशन¹¹ मिले जो उत्तरदायित्व सौंपा था उस और इन्होंने काइ ठोस कदम नहीं उठाये।

वर्ष 1959 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति तथा वर्ष 1965 में योजना आयोग, भारत सरकार के कार्यकारी दल द्वारा की गई। विभिन्न समितियों में इस पक्ष पर विशेष बल दिया गया था और जन साधारण में शिक्षा के विकास, प्रबुद्ध नागरिकता, सामाजिक तथा राजनैतिक जागरूकता के उद्देश्य से पुस्तकालयों के महत्व को बार-बार दोहराया गया है। दुभाग्यवश इनमें से किसी भी समिति की समितियाँ, किसी न किसी कारणवश यथावत् कार्यान्वित नहीं हो सकी। अतः देश की इस एकांगी शिक्षा का स्वरूप हमारे सामने है।¹²

पिछले कुछ वर्षों से भारत-सरकार ने महाविद्यालयों एवं विश्व विद्यालयों में एन सी सी तथा एन एम एस (राष्ट्रीय सेवा योजना) ईवाद्यों की स्थापना कर साक्षरता कार्यक्रम को अवश्य प्रगतिशील बनाया है किन्तु इनकी सफलता

सफलता पर भी विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा "राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा भी विद्यार्थी प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में महान् कार्य कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों को और अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए तथा इस योजना का विस्तार गावों में अधिक किया जाना चाहिए।"¹

यहां यह बात विचारणीय है कि योजनायें सदैव ग्राम नागरिका के लाभदायक होनी चाहिए किन्तु उसका व्यवहारिक पहलू वित्तना उपयोगी है यह उस योजना का भी क्रियाव्ययन पर निर्भर करता है। यह हम मानते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हमारे विश्व विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी युवक युवतियां गांव-गांव गयीं। उन्होंने गांव और शहर की उस गहरी खाई को भी दबाया जो ग्रामीरी एवं गरीबी रेखा बन कर ऊंच एवं नीच का भेदभाव अपना कर व्यक्ति, व्यक्ति में निरन्तर अलग-अलग पैदा कर रही है। फिर भी भारत के युवा विद्यार्थियों ने सेवा भावना में उन्हें घर-परिवार, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं साक्षरता की जानकारी दी। परन्तु क्या माध्यम में दो या तीन और वह भी अलग-अलग गावों में दस दिन के शिविर लगा कर हस्ताक्षर करना सिखाने से निरक्षर ग्रामीण साक्षर हो सकेंगे या कि उनकी साक्षरता को पुष्पा बनाया जा सकेगा। उत्तर होगा नहीं? इस प्रकार के शिक्षण से सिर्फ नाम लिखना सिखाया जा सकता है, निरन्तर शिक्षा पाने की प्रेरणा नहीं। अतः मैं कहूंगा कि बेहतर यह होगा कि साक्षरता अभियान के सारे कार्य लोक पुस्तकालयों के माध्यम से माध्यमिक पाठशालाओं के पुस्तकालयों से चलाए जायें तो सफलता अधिक मिलेगी। पुस्तकालयों से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में देश के अनेक ग्रामीणों व शिक्षा-विद् कह चुके हैं किन्तु राजनीतिक दलों के सदस्यों के व्यक्तिगत प्रलोभन व अधिकारियों की लिप्ता न इसे कभी पूरा नहीं होने दिया, यही कारण है कि भारत में साक्षरता की वृद्धि एक प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से हो रही है।"²

इस प्रकार की प्रगति से साक्षरता अभियान में कई दशक लग सकते हैं जो विश्व साक्षरता की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तदनुसार कार्यक्रम में कुछ अधिक आशाएँ बैठी हैं, आशा है पांचवी योजना कुछ बेहतर परिणाम दें सके।

5 पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालय—(1975-79)
विश्व की निरक्षरता का एक निहाई जनमरुता वाला भाग भारत में ही है जो शिक्षा में पिछड़ेपन का प्रतीक है। पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रायः सतत रूप से प्रभाव हो रहा है फिर भी साक्षरता की वृद्धि की तुलना में निरक्षरों का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। 'पांचवी योजना के समाप्त होने के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।' पांचवी योजना समाप्त होने के पूर्व ही छठी योजना का आधारित कार्य प्रारम्भ हुआ जिसने नदियों पर हम आगामी

शोधकों में चर्चा करेंगे। पाँचवी योजना में निरक्षरों के लिए विभिन्न भाषाभाषा में पुस्तकें नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया जो पूर्णता की ओर अग्रसर है परंतु क्या यह साहित्य उन 80% ग्रामीण तथा निरक्षरों के पास तक पहुँच रहा है, अभी तक प्रश्नचिह्न बना है।

जिला पुस्तकालयों की स्थापना व विचार म अवश्य ही प्रगति हुई है और इनके संग्रहों को बढ़ाने में राजाराम मोहनराय फाऊण्डेशन लायब्रेरी में पुस्तकों की प्रति भर अपने प्रशासनिक कर्तव्यों की निभाया है। परंतु इन पुस्तकों का अर्थ प्रौढ़ पुस्तकालयों अथवा पाठशालाओं से कम ही सम्पर्क हुआ क्योंकि ग्रामीण व विकास खण्डों के स्तर पर लोक पुस्तकालयों की स्थापनाएँ ही नहीं हुईं जिनका सम्पर्क जिला प्रणालियों से हो सके। पुस्तकालय अधिनियम पारित राज्यों में यह हुआ हो तो बात मानी जा सकती है परंतु अर्थ राज्य इस प्रक्रिया से दूर ही है। प्रौढ़ शिक्षा अभियान की यह दशा है कि कुछ राज्यों (मद्रास आ अंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व उड़ीसा) को छोड़कर देश के अर्थ राज्यों के प्रत्येक जिला में पूर्णतः जिला प्रणालियों की स्थापनाएँ नहीं हुई हैं और न ही उनका प्रौढ़ पुस्तकालयों के रूप में उपयोगी सम्बन्ध ही है। जिला प्रणालय शिक्षा विभाग के अन्तर्गत है और सम्पूर्ण जिलों के स्कूल से इसका सम्बन्ध है ना कि ग्रामीण लाक (पंचायत अथवा सावजनिक) पुस्तकालयों व वाचनालयों से। किसी भी ग्रामीण पुस्तकालय जो कि प्रौढ़ शिक्षा के उपयोग हेतु खोला गया है। जिला प्रणालय से उन्हें कोई पुस्तकीय सहायता प्राप्त नहीं होती। प्रौढ़ शालाओं का अधिकाधिक सम्बन्ध राजनीतिक दलों की सत्रीय समाज-सेवी संस्थाओं, पंचायत एवं समाज सेवा विभाग तथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद् से ही है। इसके ही कार्यक्रमों के अनुसार अभी तक का यह जटिलतम योजना कार्य चल रहा है। योजना की असफलताओं व बढ़ती हुई शिक्षा की दर ने तत्कालीन शासन को प्रभावित किया। अतः तत्काल 2 अक्टूबर 1978 को पाँचवी पंचवर्षीय योजना काल के अन्तिम वर्ष में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का वृहद् कार्यक्रम व द्वितीय शासन में घोषित किया।

"2 अक्टूबर, 1978 से 40 000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलकर 1978-83 की अवधि में 15 से 35 आयु वर्ग के 65 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाने का संकल्प किया गया है। इस कार्य के लिए दो अरब रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक प्रौढ़ की शिक्षा पर लगभग 80 रुपये व्यय होगा और आयामी पाँच वर्षों में 6 अरब 86 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान किया गया है।"¹⁵

निरक्षरता के दैत्य का एक सबसे बड़ा कारण हमारे देश की बढ़ती जन संख्या भी है। जब तक हम देश के तमाम निरक्षरों को साक्षर बनाने का संकल्प करते हैं तब तक करोड़ों उम्मीदवारों की लाईन पढ़न वाला भे लग जाती है, इन्हीं में कुछ बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसी भीड़ में बचने के लिए उन तमाम निरक्षरों को साक्षर बनाना जरूरी है जो जनसंख्या बढ़ाने में अपना योगदान देने-

अनजान दे रहे हैं। दिनमान में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, "साक्षरता जनसंख्या का सबसे कारगर अस्त है। अपने देश में करके इसका साजबाब उदाहरण है जहां साक्षरता शत प्रतिशत है और जन्म दर भारत में सबसे कम। 1951-1981 के बीच हमारे देश में साक्षरता दुगुनी तो हो गयी है लेकिन अभी भी प्रतिशत महिषाएँ निरक्षर हैं।"¹⁶

इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रजनन के लिए जिम्मेदार महिलाओं का साक्षात्कार बहुत जरूरी है सभी के जनसंख्या के साथ साथ गरीबी, भुखमरी व निरक्षरता के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। संविधान में हमने उन्हें बराबर अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान किये हैं। इस हिसाब से उन्हें "कहने की हम कहें हैं कि परिवार व समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है किंतु जब तक मुविधायें दान का प्रश्न उठता है तो हम अपना योजनाओं में कोई स्थान नहीं देते किंतु पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में तो मुख्यमंत्री अनुनासिंह ने स्नातक स्तर तक महिलाओं की शिक्षा को निशुल्क घोषित कर दिया है। अखिल भारतीय महिला परिषद् भी। और त्रिपाठी हैं। बंगलौर में सम्पन्न दो दिवसीय प्रथम महिला कांग्रेस में केन्द्र शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती श्रीला कौल ने महिलाओं को समान भागीदारी हेतु प्रस्ताव पेश किया (15-16 सितम्बर, 1984)

इन बातों से यह उम्मीद और बढ़ी है कि भारतीय महिलाएँ भी आर्थिक विकास से उभरने का प्रयत्न कर रही हैं जो एक साहसिक प्रयास है। इसी साथ सम्पूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम 1978 में घोषित बना है उससे अतगत प्रतिवर्ष निम्नानुसार प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।¹⁷

1978-79—15 लाख

1979-80—45 लाख

1980-81—90 लाख

1981-82—190 लाख

1982-83—320 लाख

1983-84—350 लाख

(6) छठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा एवं प्रयातय- यह योजना 1980 से 1985 तक चली जिसमें शिक्षा एवं सभ्यता के विकास हेतु 2,52 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। 1981 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता का प्रतिशत 36.17 आका गया। 1980 तक देश में 108 विश्वविद्यालय थे जो 1986 तक 12 हो गए। महाविद्यालय 2376 से बढ़कर 5000 तक हो गए। जैसा कि शिक्षा आयोग (कोठारी समीक्षण) 1964-66 ने प्रौढ़-शिक्षा

(Adult Education) की देश के लिए आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता देकर उल्लेख किया।

- (1) निरक्षरता का उन्मूलन।
- (2) अनवरत शिक्षा।
- (3) पत्राचार पाठ्यक्रम।
- (4) पुस्तकालय।
- (5) प्रौढ शिक्षा में विश्व-विद्यालयों का कार्य।
- (6) प्रौढ-शिक्षा का संगठन तथा प्रशासन।

उपरोक्त कार्यक्रमों में ग्रंथालय के कार्यों के सदर्भ में भी आयोग ने सुझाव दिये थे कि—

- 1 पुस्तकालय-मलाहकार समिति (Advisory Committee on Libraries) ने सम्पूर्ण देश में पुस्तकालयों का एक जाल-विछाने का जो सुझाव दिया है, उसे कार्यान्वित किया जावे।
- 2 विद्यालयों के पुस्तकालयों को सावजनिक पुस्तकालयों के रूप में संगठित किया जाय और उनमें बच्चों तथा नव-साक्षरों (New Literates) की रुचियाँ के अनुसार पठन-सामग्री को स्थान दिया जाय।¹⁸

यह तो देश में नहीं हो सक्ता किंतु देश में “राष्ट्रीय-पुस्तक न्यास” ने पुस्तक प्रदर्शनियों के माध्यम से नागरिकों में पढ़ने की रुचि बढ़ाने के प्रयत्न शुरू किए। राजाराम मोहनराय फाउण्डेशन ग्रंथालय ने लोक-ग्रंथालयों को पुस्तकें वितरित कर अध्ययन प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया एवं ग्रंथ भी कर रहा है। उधर राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के विस्तार हेतु नेहरू-युवक केन्द्रों की स्थापना पूरे देश में की गई। विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय प्रौढ-शिक्षा में सहयोग देने हेतु विश्व विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय प्रौढ एवं सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई। इन केन्द्रों में सम्बद्ध महाविद्यालय इकाईयों को प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोलने की जिम्मेदारी दी गई जिन्हें चलाने में महाविद्यालय विचारियों का सहयोग भी लिया जा रहा है।

14 जून, 1982 को प्रधानमंत्री द्वारा नवीन घोषित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 16वें सूत्र के अन्तर्गत वयस्कों में निरक्षरता दूर करने के काम में स्वयंसेवी सम्पादा और छात्रों से सहयोग लेना निर्धारित किया गया। वार्षिक योजना वर्ष 1981-82 में योजना आयोग ने भी प्रौढ शिक्षा के विस्तार के लिए “प्रौढ शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन और पर्यवेक्षण तंत्र को बढ़ाने के प्रयत्नों के बारे में लिखा। इस कार्यक्रम का विश्व विद्यालयों और नेहरू युवक केन्द्रों के जरिए विस्तार किया जाता रहेगा। मुंबईयात स्वैच्छिक अभियंताओं को इस कार्यक्रम से सम्बद्ध किया जाता रहेगा। साक्षरता कार्यक्रम के अलावा ग्रामीण पुस्तकालयों और नव-साक्षरों

के लिए उपयुक्त साहित्य तैयार करके उपयुक्त अनुवर्ती कायबाही सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे।”¹⁹

इन प्रयासों से सम्भावनायें प्रचल होती दिखाई पड़ती है और सातवीं पंच-वर्षीय योजना (1985-90) में लाक पुस्तकालयों के व्यापक विकास पर योजना आयोग के कायकारी दल ने जो ग्रन्थालय एवं सूचना सवाओं के आधुनिकीकरण के सदभ में अपना मत व्यक्त किया है।²⁰ उसने यह विश्वास और भी मजबूत हा जाता है कि, देश में शिक्षा के स्तर का उन्नत करने हेतु जब खुले विश्व-विद्यालया, पत्राचार-पाठ्यक्रम विश्वविद्यालया एवं सतत् शिक्षा केन्द्रों का निरन्तर जाल फैलता जा रहा है, तब ग्रन्थालय एवं सूचना केन्द्रों की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा रही है।

हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि उपरोक्त सभी साधना के लिए ग्रन्थालय साधनों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन्हें जितना अधिक उपक्षित रखा गया है उतनी ही अधिक इनकी आज आवश्यकता पूरे देश का है। इनके विकास पर अतिशीघ्र गम्भीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है तभी हम शिक्षा के मापदण्डों को पा सकेंगे और राष्ट्रीय विकास में सफल हा सकेंगे।

संदर्भ —

- 1 जायसवाल (सीताराम) प्रौढ-शिक्षा की पृष्ठ भूमि प्रौढ शिक्षा विशेष पाक, आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर, 1978 पृ 27
- 2 पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्यायें, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा 1982, पृ 464
- 3 वर्मा (मोरघ्वज) प्रौढ शिक्षा दर्शन प्रौढ शिक्षा विशेषपाक, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1978 पृ 36-37,
- 4 याजना, (मा) नयी दिल्ली, योजना भवन, अंक 12-13 वष 28 अगस्त 1984
- 5 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद, बोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्री-ब्यूटर्स 1980, पृ 118 सम्पादक भास्करनाथ तिवारी
- 6 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय इलाहाबाद बोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 1980, पृ 118 सम्पादक भास्करनाथ तिवारी
- 7 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय इलाहाबाद, बोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 1980, पृ 34 सम्पादक भास्करनाथ तिवारी
- 8 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद, बोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 1980 पृ 34 सम्पादक भास्करनाथ तिवारी
- 9 पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1982 पृ 467
- 10 तिवारी (भास्करनाथ) सम्पादक प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, 1980 पृ 34

- 11 कोठारी बंधीशन (1964-66) मुभाव (1) पुस्तकालय सलाहकार ममिनि के मुभावा का क्रिया-वया पूरे देश मे हो (2) विद्यालय पुस्तकालया का सावजनिक उपयोग तथा (3) पुस्तकालय गतिशील हो ।
 - 12 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय पृ 119
 - 13 साहित्य-मन्त्रिचय (मा) का प्रौढ शिक्षा विशेषांक, आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर, 1678 पृ 204
 - 14 भारतीय शिक्षा एवं उनकी समस्याया म डा मुक्जो व ओड के उद्धत विचार आगरा विनाद पुस्तक मन्दिर, 1982 पृ 467
 - 15 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, 1980, पृ 34
 - 16 दिनमान (साप्ताहिक) नयी दिल्ली, हि टा हा (18 24) 9-15 सितम्बर 1984, पृ 23
 - 17 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय 1980 पृ 35
 - 18 जीहरी (जी एम डी) तथा पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा का इतिहास आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर 1981, पृ 455-56
 - 19 योजना आयाग (1981-82) भारत सरकार वार्षिक योजना, पृ 126
 - 20 India (Planning Commission) Modernisation of Libraries and formatics (working Group for 7th Five year plan 1985-90) Report 1984 New Delhi P V
-

25

वर्तमान भारत में ग्रामीण-पुस्तकालयों का भविष्य

इस ग्रन्थ को प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही भारत में ग्रामीण पुस्तकालयों का भविष्य पर विचार करने का रहा है। पिछले अध्यायों में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार योजनाओं की गिरफ्त में आकर ग्रन्थालय विकास सम्बन्धी विचार शैक्षणिक विकास के प्राथमिक स्तरों से हटते गये और समाज शिक्षा की व्यापक तैयारियों में ग्रन्थालयों को केन्द्रीय शिक्षा संसाधन के रूप में महत्व दिया, फिर भी जब प्रौढ-शिक्षा कार्यक्रमों को समाज-व्यापक विभाग विकास खण्ड व सामुदायिक विकास विभाग को सौंपा गया तब से सावजनिक ग्रन्थालयों की विकास सम्भावनाओं को काफी क्षति पहुँची। यद्यपि ग्रन्थालयों की कमी को ध्यान में भी प्रत्येक गाँव शहर व शिक्षा मन्त्रालयों में महसूस किया जा रहा है, शिक्षण नीतियों के बदलाव में ग्रन्थालयों की अनिवार्यता का ध्यान रखा जाने के कारण ग्रन्थालय-सेवा व उनके विकास की गति सन्तोषप्रद वृद्धि नहीं करी जा सकती। डा. श्रीनाथ सहाय ने इस बात पर टिप्पणी करन हुए लिखा है कि "दश से निरक्षरता दूर करने और शिक्षित जनसमुदाय में पठन रूचि प्रोत्साहित करने की भारत सरकार की स्वीकृत और घोषित नीति के बावजूद पुस्तकालय विकास से सम्बद्ध विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकार की क्रियाशीलता उत्साहवर्धक नहीं रही है।"¹

मानव की पढ़ने की लालसा और शिक्षा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ग्रन्थालयों की आवश्यकता को अवधारणा को पुष्ट किया है साथ ही कुछ प्रयासों से सगठनों व समाज सेवा संस्थाओं ने अपने व्यक्तिगत त्याग और परिश्रम से सावजनिक ग्रन्थालय सुविधाओं का जुटान में प्रयास किए। जहाँ की राज्य सरकारों ने पुस्तकालय विधान पारित कर अपने प्रदेश की जनता की अध्ययन रुचियों, व निरक्षरता के प्रतिष्ठान को घटाने का लक्ष्य सामने रखा, व शैक्षणिक समस्याओं के प्रभाव से मुक्त हैं। किन्तु ऐसे राज्य दशभर में सिर्फ पाँच हैं। अतः इनमें वृद्धि की आवश्यकता है। प्रौढ शिक्षा का कार्य राष्ट्र की निरक्षर जनता को साक्षर समझदार और जागरूक बनाना है ताकि परिवार व्यापक कार्यक्रम जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से समाज में सन्तुलन व श्रद्धा बनाये रखने में पढ़े लिखे लोगों का सहयोग लिया जा सके।

जिस रफ्तार से गावा की काया कृषि परिवहन खाद, बीज परिवार-कल्याण, सामुदायिक विकास एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 40 वर्ष से बढ़ती जा रही है उसी विकास की निशा में पढ़ने का और वाचनालय खोलने व साहित्य गांव गांव पहुंचाने का कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। “विभिन्न दशों की सरकारें अपने अपने दश में शिक्षा के प्रसार में लगी हुई है। पुस्तकालय और पुस्तकालयाध्यक्ष उसे कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दे सकते हैं व दे रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जनसम्पर्क बढ़ाया जा रहा है। पुस्तकालय प्रौढ़ शिक्षा-अधिकारियों व जनता के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी है। सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा वे एक ओर तो प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों से सहयोग करते हैं तथा दूसरी ओर जनता में प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं।”²

हमारे देश में ‘राजाराज मोहनराय फाउण्डेशन लायब्रेरी’ तथा नेशनल बुक-ट्रस्ट इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं किन्तु राज्यों में ग्रन्थालय विधान के नियमान्वन के अभाव में उक्त संस्थाओं का सहयोग द्वार में द्वार तक नहीं हो पा रहा है। सावजनिक ग्रन्थालयों के मुख्य केन्द्रीय ग्रन्थालयों में फाउण्डेशन की पुस्तकें आती हैं पर उन्हें ग्राम पंचायतों की लाइब्रेरियों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा जितने भी पुस्तक मले व प्रशानिया संग्रहीत रही हैं, उनकी सीमारे बड़े शहरों तक ही रही हैं। ग्रामों की जनता ने अभी तक ग्रन्थ मेलों, उत्सवों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के दर्शन तक नहीं किये हैं। उनमें अध्ययन की रुचि प्रोत्साहन हेतु ही राष्ट्रीय-पुस्तक-न्यास पुस्तक मेला का आयोजन करता आया है, किन्तु विचारणीय बात यह है कि ग्रामीणों के पास वे माध्यम ही नहीं हैं जिनसे ग्रामीणों को देश भर में प्रकाशित ग्रन्थों को पढ़ने का अवसर मिल सके। ऐसे सशक्त माध्यम हैं ग्राम-ग्रन्थालय, पंचायत वाचनालय एवं ग्राम विद्यालयों के ग्रन्थालय। गावा तक ग्रन्थों को पहुंचाने में राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास को क्या करना चाहिए इसके सन्दर्भ में हिंदी प्रकाशक के “सम्पादक” का कथन है कि ‘नेशनल बुक ट्रस्ट को बड़ नगरों का मोह छोड़कर छोटे नगरों, कस्बों और गावों की ओर तभी से भुल जाना चाहिए। जिन लोगों में पढ़ने की आदत डालनी है और जिनकी पढ़ने की रुचि का विकास करना है व वास्तव में इन्हीं स्थानों पर रहते हैं।’³ यदि इन्हीं स्थानों (ग्रामों में) पर पूव से ग्रन्थालय हों और उनमें ट्रस्ट की सभी प्रकाशित पुस्तकें पूव से ग्रामवासियों को पढ़ने का मिलती रही हो तो मेले लगाने का और अधिक लाभ ट्रस्ट का होगा, साथ ही जनता भी लाभान्वित होगी। इसका मतलब यह हुआ कि गांव में पुस्तक-प्रदर्शनियों, मेले अथवा पुस्तक-समारोह आयोजित किए भी जाय परन्तु यदि ग्रामीणों की श्रम-श्रमता ग्रन्थों के लागत मूल्य से भी कम हुई तो ग्रामवासी ग्रन्थ श्रम से वंचित रह जायेंगे। क्योंकि आजकल ग्रन्थों की कीमतें भी आसमान का छू रही हैं। सामान्य पाठकों की श्रम शक्ति के बाहर ही इनका मूल्य होता है, अतः बहुत

होगा कि ग्रामीण जनता को ग्रन्थालयों के माफ़न ही अच्छा साहित्य पढ़ने को प्रदान किया जाये।

अब प्रश्न है गावों में ग्रन्थालय कैसे खुले क्या सिर्फ पचायतों ही इन्हें स्थापित करें या जिला पचायत, कार्यालय अथवा विकास खण्ड अधिकारी या फिर जिला ग्रन्थालय गावों में ग्रन्थालय खोलने की पहल करें? कौन सा विभाग ग्रन्थालय को विकसित करने का काम करें? ग्राम पचायतें, पचायत विभाग के अन्तर्गत होती हैं। प्राइमरी शिक्षा विश्वविद्यालय के सन्त प्रीट शिक्षा एवं क्रियात्मक साक्षरता विभाग समाज कल्याण विभाग अथवा ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता विभाग से चलनी है और जिला ग्रन्थालय, शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। एसी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ग्रामीण पुस्तकालयों का संगठन किस विभाग पर हो यह निश्चित कर पाना कठिन है। केन्द्रीय प्रीट शिक्षा निदेशालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमों में ग्रन्थालय खोलकर प्रीट-कक्षाएँ चलाने के स्पष्ट संकेत नहीं हैं फिर भी जिन उपायों को अपनाकर निरक्षरों को साक्षर बनाया जा रहा है, अर्द्ध साक्षरों को खुले विश्वविद्यालयों द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधाएँ दी जा रही हैं और जो पढ़े-लिखे हैं उन्हें मूल्य शिक्षा व अध्ययन की मामूली जुटाने का उपक्रम दिया जा रहा है, ग्रन्थालयों व चल पुस्तकालयों का विकास इन सब अनिवार्यताओं के लिए आवश्यक है।

“रात्रि पाठशालाओं और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ साथ जन पुस्तकालय भी खोलना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक स्तर जैसे—राज्य, जिला तहसील, ब्लॉक तथा पचायत सभी स्तरों पर पुस्तकालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनमें अशिक्षित प्रीट व्यक्तियों को उपयुक्त पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएँ उपलब्ध हों। यदि चल पुस्तकालय का प्रबंध हो सके तो और भी उत्तम होगा।”⁴ इस तरह के प्रबंध से अध्ययन की प्रोत्साहन व पुस्तक-संस्कृति (Book Culture) का विकास किया जा सकता है। ग्रन्थालयों के विकास पर बार-बार जोर देने का तात्पर्य यही है कि आज हमारे गावों तथा गावों के विद्यालय ग्रन्थालय बिहीन हैं जिनके न होने से शिक्षा संस्कृति संगठनीय चल रही है।

शिक्षा के लक्ष्यपत्रों को ग्रन्थालय रूपी बसाखी का सहारा बहुत जरूरी है। गावों का जो भी माहौल बनता जा रहा है उसमें परिवर्तन लाने का यह एक मुन्नम तरीका होगा। आधुनिक जीवन-स्तर के साथ आधुनिक विचारों का समावेश एक अच्छे वैचारिक वातावरण से ही आ सकता है। यह वैचारिक मान-ग्रन्थों में युक्त ग्रन्थालयों से ही निर्मित होगा। गावों में बसी 70% जनता शिक्षा विकास का स्थायी हल बिना सावजनिक ग्रन्थालयों के प्राप्त नहीं कर सकती। लाखों-करोड़ों शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने का सरल माध्यम ग्रन्थालय है जिन्हें दश विदेश की सरकारों ने भी मायता प्रदान कर अपनाया है।⁵

भारतीय ग्रामीण परिवेश एवं शिक्षा व गिरत मूल्य का दखन हुए ग्रन्थानुसंग ग्रामानुसंग को तीव्र करने की बात साचना चाहिए व राज्य सरकार को चाहिए कि व शीघ्र ग्रामीण विकास की तत्प्राप्त योजनाओं व साथ ग्रामालयों को भी जोड़ और ग्रामालय विधान हतु प्रयत्न करें। वस भी ग्रामीण जन जीवन में क्रमशः बढ़ती जा रही आधुनिकता, फैशन, वैज्ञानिकता एवं रहन-सहन की नवीनता के कारण जहां एक ओर लोगो व दैनिक क्रियावत्ताओं में अन्तर आया है वही दूसरी ओर उनकी मात्र उनके कार्य करने के ढंग, उनकी बातचीत का तीव्र-तरीका और उनकी पढ़ने की रुचिया भी बढ़ी है। उनकी रुचिया एवं मानसिकता के अनुकूल उह ज्ञानाजन सम्बन्धी माहित्य ग्रामालयों के अभाव के कारण नहीं मिल पा रहा है। इसलिए शहरी सम्पत्ति व परिणामस्वरूप गाँवों की युवा-पीढ़ी फिल्मी पत्रिकाओं, प्रेम व अपराध कथाओं, सत्यकथाओं व यौन विकृतियों को प्रोत्साहित करने वाली पत्रिकाओं को खरीदकर पढ़ते हैं, यह एक दुर्गुण गाँवों में घुस गया है।

श्री मुश्ताक अहमद न नवसाक्षरों के लिए ग्रन्थों के बारे में लिखा है कि "एक दफा मेरे यहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। मैं उनसे पूछा—क्या तुम्हारे पास बाइ ऐसी पुस्तकें हैं, जिससे तुम अपने खुद अपने पसंदीदा हो। उनमें से एक बोला—हाँ साहब मेरे पास है। मैं बल लेकर दिसाऊँगा। दूसरे दिन जो पुस्तकें वह लाया, वे थी—डोलामार का गीता बल्क बुखारा की लड़ाई, सैला मजनु उदल हरण महिला हरण, किसान की लड़की और सुपमा देवी (एक प्रथमरी स्कूल टीचर की कहानी) ये सबकी सब पुस्तकें पीले कागज पर छपी थीं। उन्हीं पुस्तकों को न केवल वह मजदूर बल्कि उनके साथी भी बड़ चाव से पढ़ते थे।" इसका कारण भी ग्रामालयों की सुविधाओं का न होना ही है। स्वाधीनता काल से ही इन बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद आज जो गाँवों में अपराध, चोरी, टक्कती मनमुटाव व गरीबी व निधनता की छाया देखने का मिल रही है उसका कुछ प्रतिशत तो कम होना। कृषि विकास के क्षेत्र में जिस तरह कृषि अनुसंधान व नानिका ने कृषि प्रसार शिक्षा एवं विस्तार योजनाओं को कृषकों के खेतों तक पहुँचाकर कृषि उत्पत्ति को एक नया मोड़ दिया और कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान निरन्तर इस ओर प्रगति कर रहा है। 1979 में 'प्रयोगशाला में खेत तक' राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि प्रयोगशाला और किसानों के खेतों के परिणामों में भारी अंतर को कम किया जाये। विशेषकर छोट किसानों के मामले में। दूसरा उद्देश्य यह था कि भूमिहीन और गरीब किसानों को मुर्गी खरगोश, बकरी, गाय, भैंस तथा मछली पालन और घुँची उगाने जैसे आसान वैज्ञानिक उपायों द्वारा अधिक आमदनी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस कार्यक्रम में कृषि अनुसंधान संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को भी शामिल किया गया।" इस योजना का लाभ ग्रामीण कृषकों को मिलेगा और व कृषि-विकास में तरक्की करेंगे ही, पर साथ में किसानों को ग्रामालयों

के माध्यम से कृषि व खेती गृहस्थी का साहित्य भी पढ़ने को मिलता रहे तो वैज्ञानिक को समझने में जो कठिनाइयाँ होती होंगी वे नहीं हो पायंगी ।

दूसरी ओर पसी प्रकार का प्रयास निरक्षरता निवारण हेतु शिक्षा का मूलभूत केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा प्रौढ-साक्षरता कार्यक्रम में किया जाता तो 40 वर्ष में निश्चित ही अशिक्षा रूपी समस्या भारत से समाप्त हो गई होती । “राष्ट्रीय पुस्तक न्यास स्थापित कर पुस्तक के प्रकाशन और पुस्तकालय विज्ञान के मस्यान द्वारा ग्रन्थपालों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ।”⁸

जिस उद्देश्य में ग्रन्थालय-विज्ञान व सूचना के मूलभूत केन्द्र की दिल्ली में स्थापना की गई थी उसका लक्ष्य था कि वहाँ से प्रशिक्षण पाकर जो पुस्तकालयाध्यक्ष निकलेगें उन्हें सावजनिक ग्रन्थालयों में नियुक्त कर ग्राम पुस्तकालयों में भेजकर प्रौढ-शिक्षा कार्यक्रम में सहयोग लिया जायेगा, किन्तु यह नहीं हो सका । आज देश भर के लगभग 65 विश्वविद्यालयों व संस्थानों में पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाता है किन्तु ये सारे के सारे प्रशिक्षित होकर भी अपनी सेवाएँ नहीं दे पाते । इसका एकमात्र कारण यहाँ है कि प्रौढ शिक्षा अथवा ग्रामीण शिक्षा के विकास कार्यक्रम में ग्रन्थालयों को राष्ट्रीय नीति के अभाव में शामिल नहीं किया गया है । इही कारणों ने ग्रन्थालयों की उपयोगिता का निरक्षरता निवारण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बताते हुए दत्तात्रय नागशंकरराव⁹ का यह विश्वास है कि इस भयंकरतम बाध को ग्रामीणों एवं आदिवासी लोगों के बीच सिर्फ पुस्तकालय ही अच्छी तरह से कर सकते हैं । इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति या सन्देह नहीं है गाँवों की प्रगति में ग्रन्थालयों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है बशर्ते कि हर ग्राम-पंचायत में नागरिका के लिए और ग्राम-विद्यालय में बालकों के अध्ययन हेतु सत्साहित्य से युक्त श्रेष्ठ ग्रन्थालय खोले जायें । शिक्षा एवं युवक कल्याण मंत्रालय द्वारा 1954 में प्रकाशित ग्रन्थालय परामर्श समिति के प्रतिवेदन और उनकी अनुशामाओं को ही भारत सरकार व राज्य सरकारें व्यावहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास करें तो लोक ग्रन्थालयों की दशाएँ व दिशाएँ सुधर सकती हैं । डा एस आर दत्तात्रय न ग्रन्थालयों को जिन दायित्वा का निर्वाह कर अपनी सेवाओं से पाठकों को प्रभावित करने की बात कही है उसका उद्देश्य ग्रन्थालयों को लोकप्रिय बनाने से है । उसका यह विश्वास रहा है कि “ग्रन्थालय एक जन-संस्था अथवा सम्स्थापन है जिस पर ग्रन्थ संग्रह की देखरेख का भार है । उसको पुस्तकों का उन व्यक्तियों के लिए मुलभ बनाना चाहिए जिनकी उनको आवश्यकता है । अपने पड़ोस के प्रत्येक व्यक्ति को ग्रन्थालय आने का अभ्यस्त तथा पुस्तकों के पाठक के रूप में उसको समर्पित कर देने का कार्य करना उसका कर्तव्य है ।”¹⁰

इस कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ग्रन्थालय एवं ग्रन्थालयों दोनों को ही सेवा के अवसर मिलन चाहिए । यदि ग्राम ग्राम ग्रन्थालय हो, समाज शिक्षा के साथ

साथ ग्रंथपाल का भी ग्रंथालय प्रचार प्रसार व प्रौढ़ शिक्षा में ग्रन्थ्यापन सेवा का भवसर मिले तो ग्रामीण ग्रन्थिक्षा के वातावरण को मज्जा करने में सहयोग दे सकेंगे। साथ ही भारत के राज्य, ग्रन्थालय विधान पारित कर अपने प्रदेशों में ग्रन्थालयों का जाल बिछा देते हैं तो अभी तक जितने भी प्रशिक्षित ग्रन्थालय व्यवसायी हैं उन्हें भी ग्रन्थ व रोजगार युवकों की तरह ग्रन्थ्यापी (दैनिक वेतनमान सेवा का भवसर मिलेगा और गाँव-गाँव जाकर व ग्रन्थालय प्रचार प्रसार के साथ लोक साक्षरता के विकास में मदद पहुँचायेंगे। किसी भी राष्ट्र को अपने विकास के प्रारम्भिक चरणों में अपने नागरिकों को जा मुविधायें, व्यवस्थायें एवं अनुकूल वातावरण देने की आवश्यकता पड़ती है उसमें सबसे प्रथम ध्येय योग्य नागरिकों का निर्माण होता है। योग्य नागरिक तभी बनाये जा सकते हैं जब राज्या में जनता की सुख-समृद्धि, शिक्षा व जीवन-यापन के अवसर समान हों। शिक्षा का स्थान मानवीय विकास की दृष्टि से प्रमुख होता है। शिक्षा का ध्येय ही ऐसा होना चाहिए कि वह नागरिकों के समग्र विकास में सहयोगी हो और राष्ट्रीय विकास कार्यों में शिक्षा प्राप्त व्यक्ति का उपयोग किया जा सके। प्रत्येक नवोदित राष्ट्र ऐसा उपक्रम करते हैं। हमारा देश भी 1947 के बाद यही उपक्रम किया और उसमें वह निरन्तर भाग बढ़ता जा रहा है। ग्रन्थालय विकास की कड़ी निश्चित ही कहीं ग्राम स्तरों पर छुट रही है जिसे पूरा करने का प्रयास होना चाहिए।

अपने प्रारम्भिक वर्षों से सोवियत रूस ने भी ऐसे कई प्रयास किये। इससे सम्बद्ध विचार राष्ट्रीय विकास की कार्यप्रणाली पर शिक्षा के कार्य भार की, पहनी रूस ग्रन्थ्यापक कार्यक्रम की रिपोर्ट में दिये गये जिसका जिक्र अनातोली लुनाचास्की ने अपनी पुस्तक 'शिक्षा का ध्येय' की टिप्पणी में लिखा "ग्रामीण सामुदायिक मन्था का एक रूप जो (ग्राम वाचनालय) सोवियत सत्ता के प्रारम्भिक वर्षों में प्रकट हुआ। गाँव में ऐसे वाचनालयों की स्थापना का विचार लेनिन ने पेश किया था। तीसरे और चौथे दशकों में गाँव वाचनालय दहानों में ज्ञान प्रसार कार्य के केन्द्र थे। उन्होंने निरक्षरता के उन्मूलन, देशों में सबके लिए प्रारम्भिक शिक्षा को यथायथ बनाने और कृषि के सामूहिकीकरण को पूरा करने में सोवियतों और पार्टी काया की सहायता की।"¹¹ सन् 1940 तक इस देश से निरक्षरता लगभग समाप्त हो चुकी थी।¹²

भारत में भी प्रारम्भिक पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम पुस्तकालयों पर बराबर ध्यान दिया गया। अब जबकि प्रौढ़ व सतत शिक्षा का कार्यक्रम विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने विश्व विद्यालयों की राष्ट्रीय सेवा योजनाओं तथा क्रियात्मक प्रौढ़ शिक्षा ईकाईयों को साप दिया है। गाँव के पुस्तकालय व वाचनालय की ओर शायद किसी का ध्यान नहीं जायेगा। इसका कारण है कि जब तक ग्रन्थालयों को प्रौढ़ साक्षरता का सशक्त माध्यम बनाने की पहल नहीं की जाती इसका महत्व समाप्त होता जावेगा।

भविष्य में ग्रन्थालय विकास की सम्भावनायें प्रकट करने हेतु हम हर बार पिछले योजना आयोग, शिक्षा सलाहकार बोर्ड, शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा विभाग, राधाकृष्ण कमीशन विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग एवं राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा निदेशालयों की सस्तुतियां, प्रतिवेदनो एवं प्रलेखों का उल्लेख करते रहते हैं किंतु इनका असर कहाँ तक योजनाकार व शिक्षा प्रणाली निर्माताओं पर पड़ सकता है यह आज तक प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रंथों व प्रलेखों के विवरणों से मिलता है। सिर्फ बार-बार उही बातों का दोहराते रहने से ही हम सतोष कर लेते हैं।

भविष्य की चिन्ता उन राज्यों को नहीं है जिन्होंने कारगर कदम तत्काल उठा लिए हैं और जिनके प्रदेशों की शैक्षणिक यात्रा बखूबी चल रही है। परंतु एक लेखक होने के नाते और ग्रन्थालय व्यवसायी होने के नाते कुछ पीड़ा तो होगी, स्वाभाविक है। जहाँ एक और पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा को व्यापक पैमाने पर विश्वविद्यालयों में चलाया जा रहा है और इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य ही है कि प्रशिक्षित ग्रन्थपाल निकल कर अपने देश की ग्रन्थालय व्यवस्था को सन्हालने में अपना योगदान दें, किंतु जब ग्रन्थालय नहीं होंगे और इन्हीं ग्रन्थालय सेवा का अवसर नहीं मिलेगा तब उन्हें बेकार होकर भटकने के अवसर ही प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति एक व्यावसायिक युवक के लिए दुःखदायी है और सरकार के लिए उसका बेराजगार रहना चिन्ता का विषय है।

एक और यदि हम यह मानकर सतोष कर लें कि देश भर के विश्व विद्यालय, महाविद्यालय, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों जिला ग्रन्थालयों एवं विज्ञान व अनुसंधान केन्द्रों, औद्योगिक व तकनीकी संस्थानों के ग्रन्थालय हमारे प्रशिक्षित ग्रन्थपालों की समस्याओं का निदान कर देते हैं तो यह नाकाफी होगा। क्योंकि देश की 70% ग्रामीण जनसंख्या गांवों में रहती है और 30% शहरी क्षेत्रों में तब अनुमान लगाइयें कि क्या 30% शहरी क्षेत्र में स्थापित उक्त संस्थान इस कमी को पूरा करते हैं। जहाँ 70% ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयीन ग्रन्थालय नहीं हैं और ना ही सावजनिक पुस्तक वितरण प्रणाली और न ग्राम पुस्तकालय, तब हम कैसे विश्वास कर लें कि पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई में प्रशिक्षित ग्रन्थालय व्यवसायियों का भविष्य सुखकर होगा। ऐसी व्यावसायिक शिक्षा जो 50 विश्वविद्यालयों व 15 माध्यमता प्राप्त संस्थाओं तथा व ग्रन्थालयों में दी जा रही है उन्हें व्यवसाय स जोड़ने हेतु देश भर में शैक्षणिक, सामाजिक-ग्रामीण स्तर पर व शोध अनुसंधान केन्द्रों में ग्रन्थालयों का होना अत्यंत आवश्यक है।

आज जिन सावजनिक ग्रन्थालयों का बिना भू-संचालन व मगठन हो रहा है उनमें स्थानीय अग्रिमियों को यदि अधिनियम सभी राज्यों में लागू हो जावे तो वेरोजगार मुश्किल युवकों की सेवा का अवसर

ग्रन्थालयों के विकास एवं भविष्य को भारतीय वातावरण में सक्षम व श्रेष्ठ बनाने के लिए अभी तक विद्यमान प्रयास विशेष तौर पर ग्रामीण अंचलों को विक्सित करने व ग्रन्थालयों का नाम देने की दृष्टि से नहीं के बराबर है। आज हम प्रौढ़ शिक्षा, मत्त शिक्षा एवं मुले विश्वविद्यालयों की शिक्षा मायाय जन को मुहैया कराने की बात कर रहे हैं तब “वर्तमान में ग्रन्थालय का कोई स्वतंत्र मन्त्रालय ना तो केन्द्र में है ना ही राज्य में।” ज्ञान के गहन विकास एवं विश्व में चल रही परस्पर की दृष्टिगत रम्यते हुए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार केन्द्र एवं राज्य में ग्रन्थालयों का स्वतंत्र मन्त्रालय स्थापित करें। राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय शासन को राष्ट्रीय ग्रन्थालय अधिनियम को लागू करना चाहिए जिससे राष्ट्रीय ग्रन्थालय प्रणाली की स्थापना की जा सके।¹³ यह सिर्फ उन लोगों की सुविधा के लिए ही उपयोगी नहीं होगा जो नव माक्षर ह अर्द्ध माक्षर ह अथवा अनपढ़ हैं बल्कि उन ममस्त भारतवासियों के हित में होगा जो ज्ञान विज्ञान में रुचि रखते हैं, ग्राम, नगर या शहर के हैं, व्यापार, उद्योग या खेती किसानों में रहे हैं और कई वर्षों से जो ग्रन्थालय-व्यवसाय में लग होकर सुलभ भविष्य की कामना करते हैं। इस तरह यदि देश में सीखने, पढ़ने, वाता-मोष्ठी मनोरजन, देश विदेश की राजनीति तथा वनानिक उपलब्धियों की चर्चा हम करनी है तो हमें पुस्तक संस्कृति के साथ-साथ भारत में ग्रन्थालय प्रान्ति लाना होगा तभी हम ज्ञान के विस्फोट का सुव्यवस्थित भेल सवेंगे, सूचना और मचार माध्यमों में विकास कर सकेंगे। जब सारा देश एक ग्रन्थालय प्रणाली के तन्त्र में जुड़ जायेगा, तब कोई भी सूचना एक छोर से दूसरे छोर, एक गांव से दूसरे गांव व शहर तक पहुँचने में व्यवधान नहीं बन पायेगी। जनता को खुशहाल एवं वैचारिक स्तर प्रदान करने के लिए ग्रन्थालयों के गिरते स्तर को हमें सुधारना है जिसमें ग्रन्थालय सेवा में लगे लोगों व संगठनों का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। राजाराम मोहनराय फाउण्डेशन लायब्रेरी ने विगत वर्ष राष्ट्रीय ग्रन्थालय नीति के निमाण में जो पहल की है वह निश्चित ही स्वागत योग्य है। लायब्रेरी ने जो अनुशसा¹⁴ प्रस्तुत की है वह “राष्ट्रीय ग्रन्थालय एवं सूचना नीति प्रायोजन से सम्बन्धित है।”

राजाराम मोहनराय फाउण्डेशन लायब्रेरी द्वारा प्रस्तुत अनुशसा निश्चित ही देश में ग्रन्थालय विकास की दिशा में एक बेहतर कदम है फिर भी जब तक राज्य-सरकारें अपने प्राप्ता में ग्रन्थालय अधिनियम पारित नहीं करनी तब तक उक्त अनुशसाओं का व्यापक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के पुस्तकालयों व स्वायत्तशासी संस्थाओं के ग्रन्थालय उपयोगकर्ताओं को मिल पाना कठिन होगा। मैसूर राज्य पुस्तकालय के मुख्य अधिकारी रहे नागप्पा दासप्पा बगरी ने भारत में पुस्तकालयों का भविष्य के बारे में लिखा है कि “इस समय प्रदेशों में (जहाँ पुस्तकालय धातून नहीं बना है) दो प्रकार के सावजनिक पुस्तकालय हैं। एक तो प्रदेशीय सरकार के सरकारी सावजनिक पुस्तकालय हैं जसे प्रदेशीय केन्द्रीय पुस्तकालय

और उससे सम्बद्ध जिला पुस्तकालय तथा इसी प्रकार के ग्राम पुस्तकालय। दूसरे व सावजनिक पुस्तकालय है जो सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान तथा अपनी सीमित आय से चलाये जाते हैं। छोटे सावजनिक पुस्तकालयों को नगरपालिकाएँ और जिला परिषद् अपने अपने क्षेत्र में अनुदान देती हैं। सरकारी सावजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था तथा अनुदान वितरण का काय प्रदेशों में ग्राम शिक्षा विभाग के अंतर्गत है।¹⁵

ऐसे सावजनिक ग्रन्थालयों के बीच में फैली भिन्नता व ग्राम की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने वास्तव में फाऊण्डेशन को अपनी नीतियाँ सरकार के समक्ष स्पष्ट कर देनी चाहिए ताकि जनता के सहयोग से चल रहे सावजनिक ग्रन्थालय भी अपनी सेवाएँ राष्ट्रीय ग्रन्थालय की नीतियों के अनुसार देने में सक्षम हो सकें। यह काय उतना ही आवश्यक है जितना ग्रन्थालय विकास के लिए अधिनियमों का पारित होना। आज हमारा देश विश्व के ग्राम देशों के मुकाबले आर्थिक एवं राजनैतिक मामलों में काफी कुछ उन्नतशील व आत्मनिर्भर हो गया है। ज्ञान विज्ञान व अनुसंधान के क्षेत्र में भी यहाँ थोड़ा तकनीकी का उपयोग कर राष्ट्रीय विकास में योगदान किया जा रहा है किंतु निरक्षरता के अभिशाप से हम मुक्त नहीं हो पाये हैं। संभवतः यह दोष हमारी प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं का रहा जिसमें हमने ग्रन्थालयों के महत्त्व को कोई स्थान नहीं दिया।

अब समय व परिस्थितियाँ में काफी परिवर्तन आ गया है। हमें 21वीं सदी की ओर बढ़ना है। दूर-दशन, कम्प्यूटर व स्वचालित यंत्रों द्वारा हमें शिक्षा-कार्यक्रमा को चलाना है, नई शिक्षा प्रणाली को पूरे देश में शिक्षा की चुनौती के रूप में लागू करना है तब हम ग्रन्थालयों तथा सूचना-केन्द्रों के बिना अपने सक्षमता में पूर्णतः सफल नहीं हो सकते। आजीवन शिक्षा (Continuing Education) के सुझावों पर सिर्फ ग्रन्थालयों से ही मिल सकता है। अतः ग्रन्थालयों हेतु विकसित भारतीय-राष्ट्रीय ग्रन्थालय नीति आज की महती आवश्यकता है।¹⁶ ग्रन्थालयों का भविष्य इसी राष्ट्रीय-नीतिमा पर निर्भर होगा।

* राजाराम मोहनराय फाऊण्डेशन लाइब्रेरी, कलकत्ता।

सन्दर्भ ग्रन्थ -

- 1 सहाय (श्री नाथ) पुस्तकालय एवं समुदाय, पटना, बिहार हिन्दी ग्राम अकादमी 1975 पृ 326
- 2 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाष चन्द्र) पुस्तकालय संगठन एवं संचालन, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्राम अकादमी 1972 पृ 3-4
- 3 हिन्दी प्रकाशक (भा) दिल्ली, अ भा हिन्दी प्रकाशक संघ 20 (4) जून 1983, सम्पादकीय
- 4 श्री वास्तव (प्रेमलता) प्रौढ शिक्षा समस्या और समाधान, साहित्य

- परिचय (भा) के प्रौढ शिक्षा विशेषांक से आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, अक्टूबर दिसम्बर 1978 पृ 61
- 5 SAFI (SM) Adult Education and role of Libraries in ILA, Bulletin, New Delhi, Vol XVII No 3-4, Jul Dec 1981, p 242
 - 6 ग्रहमद (मुस्ताक) कुर्मी पर बठकर या पैदल चलकर साहित्य-परिचय (भा) के प्रौढ शिक्षा विशेषांक से आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1978 पृ 157
 - 7 सिंह (अपभ्रंश) ग्रामीण विकास में वैज्ञानिकों का योगदान योजना (भा) नयी दिल्ली, योजना भवन, 1-15 जनवरी, 1988 पृ 25
 - 8 मिश्र (आत्मानन्द) भारत में प्रौढ शिक्षा का विकास-साहित्य परिचय (भा) प्रौढ शिक्षा विशेषांक आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर अक्टूबर दिसम्बर 1978 पृ 137
 - 9 RAO (Dattakavi Nagshankara) Library Services for the underserved ILA Bulletin, New Delhi Indian Library Association, XVII, No 2, Apr-Jun 1981 P 136
 - 10 RANGANATHAN (SR) Library Administration, London Asia Publishing House, 2nd impression, 1960 P 355
 - 11 लुनाचान्स्की (अनातोली) शिक्षा का ध्येय टिप्पणियाँ, मास्को प्रगति प्रकाशन 1984 पृ 319, टिप्पणियों के लेखक—ये दनेप्रोव, अनुवादक, ददन उपाध्याय
 - 12 भारत शिक्षा मंत्रालय टीचर्स हैण्ड बुक ऑफ सोशन एजुकेशन, नई दिल्ली 1955 पृ 105
 - 13 Dalal (MJ) and Limaye (CB) A Second Look at the Library legislation, ILA Bulletin XVII No 1 Jan-March 1981 P 4
 - 14 GIRJA KUMAR Towards a National information policy ILA Bulletin VXX No 3 4 March 1985 P 175
 - 15 बगरी (एन डी) भारत में पुस्तकालयों का भविष्य, लेखक की पुस्तक, 'पुस्तकालय-विकास' से इलाहाबाद, नीलम प्रकाशन, 1973 पृ 131-32
 - 16 GUPTA (Pawan K) and Pawan (Usha) Education Policy and Public Libraries in ILA Bulletin XXI No 3-4 Oct 1985-March 1986 P 117
-

परिशिष्ट-1

1 भारत में ग्रन्थालय अधिनियम वाले राज्य —

क्र.सं.	राज्यों के नाम	अधिनियम पारित वर्ष
1	तमिलनाडु	1941
2	आंध्र प्रदेश	1960
3	कर्नाटक	1965
4	महाराष्ट्र	1967
5	पश्चिम बंगाल	1979

2 अधिनियम पारित वाले राज्यों में पुस्तकालयों की स्थिति —

क्र.सं.	राज्य	अधिनियम पारित होने का वर्ष	राज्य पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय	टाऊन पुस्तकालय	बॉक्स पुस्तकालय	ग्राम पुस्तकालय	विशिष्ट ने पुस्तकालय	कुल पुस्तकालय
1	तमिलनाडु	1941	1	15	—	374	3427	1	4 3822
2	आंध्र प्रदेश	1960	1	22	207	324	1623	2	4 2190
3	कर्नाटक	1965	1	19	230	175	1498	1	6 1930
4	महाराष्ट्र	1967	1	26	257	195	285	5	2 751
5	पश्चिमी बंगाल	1979	1	16	61	48	531	6	8 671

3 भारत के प्रमुख राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत —

(अ) ग्रन्थालय अधिनियम वाले राज्यों में साक्षरता प्रतिशत —

1	केरल	69.75
2	महाराष्ट्र	45.77
3	तमिलनाडु	45.40
4	कर्नाटक	31.33
5	आंध्र प्रदेश	28.52

(ब) बिना ग्रन्थालय अधिनियम वाले राज्यों में साक्षरता प्रतिशत —

1	राजस्थान	22.57
2	बिहार	23.35

3	उत्तर प्रदेश	25 44
4	मध्य प्रदेश	26 71
5	हरियाणा	31 91

4. भारत में पुस्तकालय सेवा प्रति व्यक्ति औसत व्यय —

1	आंध्र प्रदेश	15 पैसे
2	केरल	15 पैसे
3	कर्नाटक	10 पैसे
4	महाराष्ट्र	6 पैसे
5	आसाम	4 पैसे
6	राजस्थान	3 पैसे
7	उत्तर प्रदेश	1 पैसे

5 भारत में शहरी एवं ग्रामीण जनता में साक्षरता प्रतिशत —

राज्य	साक्षर ग्रामीण जनता का प्रतिशत	साक्षर शहरी जनता का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	22 30	54 28
आसाम	31 26	67 02
बिहार	20 9	51 82
गुजरात	33 31	63 25
हरियाणा	25 92	58 89
हिमाचल प्रदेश	34 87	68 69
जम्मू व कश्मीर	16 57	53 55
केरल	68 54	75 92
मध्य प्रदेश	20 08	58 12
महाराष्ट्र	36 09	66 56
पंजाब	32 08	51 91
राजस्थान	16 44	50 81
तमिलनाडु	36 03	64 56
उत्तर प्रदेश	21 29	50 53

परिशिष्ट-2

भारत में पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान

(अ) विश्वविद्यालय —

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	प्रारम्भ वर्ष
1	आंध्र विश्वविद्यालय, बालुदेवर	1935
2	भद्राम विश्वविद्यालय, भद्रास	1937
3	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1941
4	बॉम्बे विश्वविद्यालय, बम्बई	1944
5	बलरत्ता विश्वविद्यालय, बलरत्ता	1945
6	देहली विश्वविद्यालय, देहली	1947
7	एम एस विश्वविद्यालय, बडोदा	1956
8	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	1956
9	विश्वम विश्वविद्यालय, उज्जैन	1957
10	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	1958
11	पूना विश्वविद्यालय, पुणे	1958
12	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1959
13	पंजाब विश्वविद्यालय, लुधियाना	1960
14	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1960
15	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	1961
16	कनाटक विश्वविद्यालय, धारवार	1962
17	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	1962
18	एस एन डी टी बूमन विश्वविद्यालय बम्बई	1962
19	सागर विश्वविद्यालय, सागर	1962
20	वदमान विश्वविद्यालय, वदमान	1964
21	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	1964
22	जगदेवपुर विश्वविद्यालय, बलरत्ता	1965
23	जोधाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	1965
24	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	1965
25	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	1965
26	गोहाटी विश्वविद्यालय, गुहाटी	1966

27	मस्त्रुत विश्वविद्यालय चाराणसी	1967
28	मराठवाडा विश्वविद्यालय, श्रीरगावाद	1967
29	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	1968
30	ए पी एस विश्वविद्यालय, रीवा	1968
31	पजाची विश्वविद्यालय, पटियाना	1969
32	सागर विश्वविद्यालय भागर	1971
33	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	1971
34	शम्भोर विश्वविद्यालय श्रीनगर	1971
35	जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर	1971
36	भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर	1973
37	बैंगलौर विश्वविद्यालय बैंगलौर	1973
38	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर	1973
39	मदुरई विश्वविद्यालय मदुरई	1974
40	एस बी विश्वविद्यालय तिरुपति	1974
41	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर	1975
42	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	1975
43	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	1976
44	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	1978
45	पटना विश्वविद्यालय पटना	1980
46	आंध्र प्रदेश गुला विश्वविद्यालय	(पत्राचार द्वारा) 1984

(ब) महाविद्यालय—

1	आई टी कॉलेज, लखनऊ (उ प्र)
2	एन एल कॉलेज, ग्वालियर (म प्र)
3	ए ई सी कॉलेज पचमढी (म प्र)
4	बी आर कॉलेज, आगरा (उ प्र)
5	टी आर एस कॉलेज, रीवा (म प्र)
6	एल बी एस कॉलेज, जयपुर (राजस्थान)
7	सत्य साई कॉलेज, जयपुर (राजस्थान)
8	दधिमति कॉलेज गयानगर
9	वी टी सी कॉलेज, सरदार शहर
10	आय विद्यापीठ ब-या महाविद्यालय, मुसावर
11	ग्रामोत्थान विद्यापीठ, मागरिया
12	महिला पॉलीटेक्नीक, बैंगलौर
13	ब्रूमेन पॉलीटेक्नीक दिल्ली

- 14 राजकीय पालीटक्नीक फॉर वूमैन, चण्डीगढ़
- 15 महिला बिद्यापीठ इलाहाबाद
- 16 राजकीय टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट फॉर वूमन, राऊरकेला
- 17 वूमैन पॉलीटक्नीक, हुवली

(स) विनिष्ठ संस्थान—

- 1 डी भार टी सी बगलोर
- 2 आई एन एस डी ओ भी, दिल्ली
- 3 आई एम आई, दिल्ली
- 4 नेशनल आशका इन्ज, दिल्ली
- 5 सुपरिटेण्डण्ट आफ लायन्स रीज, बिहार

(ब) ग्रन्थालय सघ—

- 1 दिल्ली पुस्तकालय सघ
- 2 उ प्र पुस्तकालय सघ
- 3 बंगाल पुस्तकालय सघ
- 4 आंध्र प्रदेश पुस्तकालय सघ
- 5 बिहार पुस्तकालय सघ
- 6 आईस्लिक पुस्तकालय सघ
- 7 गुजरात पुस्तकालय सघ
- 8 बम्बई पुस्तकालय सघ
- 9 महाराष्ट्र ग्रन्थालय सघ
- 10 विन्ध ग्रन्थालय सघ

(ई) राज्य केन्द्रीय ग्रन्थालयों द्वारा—

- 1 मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय, भापाल
- 2 सावजनिक केन्द्रीय ग्रन्थालय, ब्वालिमर
- 3 सिंहा पुस्तकालय पटना
- 4 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, अगरेतला
- 5 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, चण्डीगढ़

परिशिष्ट-3

(1) भारत में पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय केन्द्र¹

जो लोग विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उनके लिए देशभर के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों ने विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों में पत्राचार द्वारा परीक्षा में बैठने की व्यवस्था की है —

पत्राचार पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय

अनुक्रम	विश्वविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम प्रारम्भ वर्ष	पाठ्यक्रम अवधि	1981-82 में बैठे छात्रों की संख्या	
					1	6
1	दिल्ली	बी ए	1962	3 वर्ष	2920	
		बी बाम	1971	"	2656	
		बी काम (ग्रान्स)	1971	"	691	
		एम ए (हिन्दी)	1977	2 वर्ष	275	
		एम ए (राज)	1977	"	229	

1	2	3	4	5	6
2	मेरठ	बी ए	1969	2 वर्ष	543
3	भोपाल	बी ए	1975	3 वर्ष)	2925
		बी काम	1975	")	
4	भी वैद्येश्वर	बी ए	1972-73	"	227
		बी काम	"	"	269
5	लखनऊ	आई ए	1975	2 वर्ष	403
		आई काम	1976	"	83
		बी ए	1975	"	228
		बी काम	1979	"	82
6	अम्बू	बी ए	1976	2 वर्ष	169
		बी काम		"	
		बी एड		14 माह	413
		एल एल बी		2 वर्ष	571
7	मधुराई कामराज	पी यू सी	1971-72	1 वर्ष	
		बी ए		3 वर्ष	
		एम ए (अर्थशास्त्र)	1976-77	2 वर्ष	
		बी काम		3 वर्ष	
		एम ए (इतिहास)		"	

8 पञ्चाव

एम ए (तमिल)	2 वर्ष		
एम ए (अंग्रेजी)	"		
एम ए (अंग्रेजी)	"		
बी जी एल (प्रोफेशनल)	"		
बी एस सी	3 वर्ष	1979	1037
एम ए (राजनीति शास्त्र)	2 वर्ष	1979	3927
श्री यूनिवर्सिटी	1 वर्ष	1971-72	918
बी ए	3 वर्ष	1971-72	903
बी एम	"	1973-74	508
एम ए (अंग्रेजी)	2 वर्ष	1976-77	255
एम ए (अंग्रेजी)	2 वर्ष		265
एम ए (इतिहास)	"		777
एम ए (राजनीति शास्त्र)	"		228
एम ए (लोक प्रशासन)	"		127
एम ए (हिन्दी)	"	1979-80	718
एम ए (पञ्जाबी)	"		1979
श्री यूनिवर्सिटी	1 वर्ष	1968	
बी ए	3 वर्ष	1968-69	

पञ्चावी

1	2	3	4	5	6
		एम ए (पञ्जाबी)	1974-75	2 वर्ष	318
		एम ए (इंग्लिश)	1976-77	"	302
		एम ए (राजनीति शास्त्र)	"	"	229
		एम ए (इतिहास)	"	"	196
		एम ए (संस्कृत शास्त्र)	1980	"	325
10	मैसूर	पी यू सी	1969-70	1 वर्ष	
		बी ए	1969-70	3 वर्ष	
		बी बीएस	1972-73	"	
		बी एड	1975-76	18 माह	
		बी जी एल	1974-75	2 वर्ष	
		एम ए (कानून)	1973-74	"	
		एम ए (इंग्लिश)	1973-74	"	
		एम ए (इतिहास)	1974-75	"	
		एम ए (राजनीति शास्त्र)	1975-76	"	
		एम ए (समाज शास्त्र)	1975-76	"	
		एफ वाई (घाटस)	1979-80	1 वर्ष	844
		इंटर घाटस	1972-73	"	
		एफ वाई नॉर्मस	1979-80	"	571
11	बम्बई				

1	2	3	4	5	6
		इटर कॉमर्स	1972-73	1 वष	
		बी ए	1973-74	2 वष	
		बी कॉम	1973-74	"	
		एम ए	1975-76	"	1167
		एम कॉम	1975-76	"	1976
		बी एफ एम	1975-76	1 वष	420
		डी मो प्रार एम	1975-76	"	84
12	सी प्राई ई एल एल हैदराबाद	पी जी सी टी ई	1973	1 वष	528
		पी जी सी टी ई	1978	"	128
		एम ए (फैच)	1977	3 वष	23
		एम ए, (जर्मन)	1977	"	6
		एम ए (रशियन)	1976	"	35
13	उद्यमानिया	सी ए	1977-78	3 वष	
		बी कॉम	1977-78	"	
14	प्रनामलई	बी ग्राम	1979	3 वष	280
		बी एड	1979	1 वर्ष	6000
		डिप्लोमा इन लॉ	1979	"	1571
		बी ए	1980-81	3 वष	187

1	2	3	4	5	6
		बी सीट	1980-81	3 वर्ष	136
		बी ए एल	1981-81	"	576
		एम ए	1980-81	2 वर्ष	2637
		एम एम सी	"	"	1902
		एम काम	"	"	473
		एम एड	'	1 वर्ष	2193
15	परल	प्री-डिग्री	1977-78	2 वर्ष	776
		बी ए	1979-80	3 वर्ष	1408
		बी काम			971
16	इलाहाबाद	बी ए	1978-79	2 वर्ष	473
		बी काम		"	183
17	कन्नौर	बी ए	1976	3 वर्ष	287
		बी काम			
		बी एड			
		एल एल बी	1977	14 माह	252
		पी यू सी	1978	2 वर्ष	176
18	प्राध प्रदेश	बी ए	1972-73	2 वर्ष	
		बी काम	1972-73	3 वर्ष	7336
				"	2378

1	2	3	4	5	6
19	हिमाचल प्रदेश	एम ए (अर्थशास्त्र)	1978-79	2 वर्ष	315
		एम बीएम		"	590
		बी ए	1971-72	3 वर्ष	1436
		एम एड		1 वर्ष	4566
		एम कॉम		2 वर्ष	1380
		एम ए (इग्निस)		"	737
		एम ए (इतिहास)		"	422
		एम ए (अर्थशास्त्र)		"	1075
		एम ए (राजनीति शास्त्र)		"	704
		एम ए (हिन्दी)		"	472
		एम ए (संस्कृत)		"	121
		पी यू सी		'	788
20	उदयपुर	बी ए	1979 80	3 वर्ष	216
21	राजस्थान	बी ए	1976	3 वर्ष	
		एम बीएम	1976	2 वर्ष	
		बी कॉम	1968	3 वर्ष	
		एम ए (हिन्दी)	1976	2 वर्ष	
		एम ए (इतिहास)	1968	"	

1	2	3	4	5	6
		एम ए (समाज शास्त्र)	1976	2 वर्ष	
		एम ए (राजनीति शास्त्र)	1968	"	
		एम ए (लोक प्रशासन)	1976	"	
		एम ए (ग्राम शास्त्र)	1976	"	
		बी एड	1976	14 माह	
22	एस एन डी बी ब्रूमेस यूनिवर्सिटी	बी ए	1978-79	2 वर्ष	

1* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1981-82 के पृष्ठ 146 से 150 से प्रवृत्ति ।

2. भारत में सतत् शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय²

क्रमांक	विश्वविद्यालयों के नाम
1	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
2	आंध्र यूनिवर्सिटी
3	बॉम्बे यूनिवर्सिटी
4	जादवपुर यूनिवर्सिटी
5	जम्मू यूनिवर्सिटी
6	कश्मीर यूनिवर्सिटी
7	कुमाव यूनिवर्सिटी
8	मद्रास यूनिवर्सिटी
9	एम एस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदा
10	पंजाब यूनिवर्सिटी
11	पूना यूनिवर्सिटी
12	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी
13	एस एन डी टी वूमन्स यूनिवर्सिटी
14	श्री वकटेश्वर यूनिवर्सिटी
15	नाथ ईस्टन हिल यूनिवर्सिटी
16	गुजरात विद्यापीठ ³
17	इण्डियन स्कूल ऑफ माईंस ⁴

- 2 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन रिपोर्ट 1981-82 पेज 145 से ।
 * विश्वविद्यालय मान्य संस्थाएं ।

3 भारत में खुले-विश्वविद्यालय (Open Universities in India)

- 1 आंध्र-प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, हैदराबाद—1982⁵
- 2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली—1985 *
- 3 म० प्र० खुला विश्वविद्यालय, भोपाल—घोषित **
- 4 महाराष्ट्र राज्य खुला विश्वविद्यालय—घोषणा ** *
- 5 केरला, राज्य-खुला विश्वविद्यालय—घोषित ** *1

- * स्रोत—यूनिवर्सिटी ग्राज—अंक 16 मार्च, 1987 पृ 7 से
 ** " " " " अंक 16 जुलाई, 1986 पृ 16 से
 1* * " " " " विशेषांक 8 नवम्बर, 1986 पृ 6 से

1	2	3	4	5	6
		एम ए (समाज शास्त्र)	1976	2 वर्ष	
		एम ए (राजनीति शास्त्र)	1968	"	
		एम ए (लोक प्रशासन)	1976	"	
		एम ए (ग्राम शास्त्र)	1976	"	
		बी एड	1976	14 माह	
22	एल एन डी बी इमे स यूनिवर्सिटी	बी ए -	1978-79	2 वर्ष	

1% विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1981-82 के पृष्ठ 146 से 150 से व्यवस्थित।

2 भारत में सतत शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय²

क्रमांक	विश्वविद्यालयों के नाम
1	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
2	आंध्र यूनिवर्सिटी
3	बाम्बे यूनिवर्सिटी
4	जादवपुर यूनिवर्सिटी
5	जम्मू यूनिवर्सिटी
6	कश्मीर यूनिवर्सिटी
7	कुमाव यूनिवर्सिटी
8	मद्रास यूनिवर्सिटी
9	एम एस यूनिवर्सिटी ऑफ बडोदा
10	पंजाब यूनिवर्सिटी
11	पूना यूनिवर्सिटी
12	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी
13	एस एन डी टी वूमन्स यूनिवर्सिटी
14	श्री वैकटेश्वर यूनिवर्सिटी
15	नाथ ईस्टन हिल यूनिवर्सिटी
16	गुजरात विद्यापीठ*
17	इण्डियन स्कूल आफ माईस*

2 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन रिपोर्ट 1981-82 पेज 145 से।

* विश्वविद्यालय माय सस्थाए।

3 भारत में खुले-विश्वविद्यालय (Open Universities in India)

- 1 आंध्र-प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, हैदराबाद—1982*
- 2 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली—1985*
- 3 म० प्र० खुला विश्वविद्यालय, भोपाल—घोषित**
- 4 महाराष्ट्र राज्य-खुला विश्वविद्यालय—घोषणा**
- 5 केरला, राज्य-खुला-विश्वविद्यालय—घोषित**

* स्रोत-यूनिवर्सिटी न्यूज—अंक 16 मार्च, 1987 पृ 7 से

** " " " अंक 16 जुलाई, 1986 पृ 16 से

1** " " " विशेषांक 8 नवम्बर, 1986 पृ 6 से

